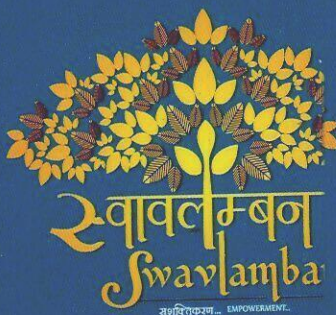


वार्षिक रिपोर्ट 2017



सत्यमेव जयते



भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिािमंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विषय सूची

अध्याय / खंड	वर	पृष्ठ
1.	ना	1-2
2.	लोव	3-4
3.	िक	5-8
4.	ाजनेकार अधिनियम, 2016	9-43
5.	मतापत्रों का मुद्दा	44
6.	औतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं	45-48
7.	के सांविधिक निकाय	49-62
7.1	देव्यन आयुक्त	49
7.2	न्य	49
7.3	पुनवरिषद	59
8.	कीन्न स्कीमें	63-108
8.1	कीमें; एक सिंहावलोकन	63
8.2	कीगी स्कीमें	63-83
8.3	ेन्द्रत्र स्कीमें	84-104
8.4	विव पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)	105-108

9.	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	109-127
9.1	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)	109
9.2	भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको)	119
10.	राष्ट्रीय संस्थान एवं केन्द्र	128-171
11.	नई पहलें, विशेष उपलब्धियां एवं घटनाएं	172-183
12.	राष्ट्रीय पुरस्कार	184

अनुबंध

अनुबंध	विषय	पृष्ठ
1.	विकास सकरण विभाग को कार्य आवंटन	184-186
2.	2016-17 के अनुसार विकलांगजनों की राज्यवार जनसंख्या	187-188
3.	2016-17 नव्व जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्रों की स्थिति	189-190
4.	एनआर वर्गत 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दैनिकजेंसियों/राष्ट्रीय संगठनों/एएलआईएमसीओ को जई फा विवरण	191-193
5.	वर्ग 17 रान एडिप स्कीम के अंतर्गत कैंप/मुख्यालयी ग हेतुतीओ/राज्य निगमों/आईआरसीएस को जारी आयत राज्यवार विवरण (31.12.2016 तक)	194
6.	वर्ग 17 रान (31.12.2016 तक) एडीआईपी योजना के अंतर्गत एन/सीएस/एलिमको की विभिन्न गतिविधियों के लिए जई फा	195-197
7.	2016-17 दं(31.12.2016 तक) एडिप योजना के अंतर्गत अवशेष	198-201
8.	2016-17 दंसिपडा स्कीम के तहत विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रवाधावातावरण के लिए जारी निधि	202-203
9.	(क) 17 रान सिपडा स्कीम के तहत बाधामुक्त वातावरण के लियों/नों के लिए जारी निधि	204
	(ख) स्के तहत 2016-17 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु गनुदान सहायता	205-207
	(ग) स्के तहत 2016-17 के दौरान यूडीआईडी परियोजना केरी ल	208-213
	(घ) स्के तहत 2016-17 के दौरान समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (स्को) निधियां	214-216

	(ड़) सिपडा स्कीम के तहत 2016-17 के दौरान डीडीआरसी को जारी निधियां	217
	(च) सिपडा स्कीम के तहत 2016-17 के दौरान सुगम्य ऑडिट हेतु जारी निधियां	218
	(छ) सिपडा स्कीम के तहत 2016-17 के दौरान विविध गतिविधियों के लिए जारी निधियां	219
10.	वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के तहत एनजीओ को जारी की गई अनुदान सहायता के ब्यौरे	220-280
11.	वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के तहत एनजीओ को अनुदान सहायता के राज्यवार ब्यौरे का सार	281-282
12.	वर्ष 2016-17 के दौरान सिपडा/डीडीआरएस के तहत डीडीआरसी को जारी की गई अनुदान सहायता	283-284
13.	राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा चलाए गए अल्पावधि पाठ्यक्रमों (वर्ष की अवधि में एक या उससे अधिक) के ब्यौरे	285-290
14.	ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकिकरण / क्षमता बढ़ाने की सहायता हेतु स्कमी के तहत जारी की गई निधियों के ब्यौरे	291-292
15.	राष्ट्रीय पुरस्कार, 2016 के प्राप्तकर्ताओं की सूची	293-299
	शब्दावली	300-316

1

अध्याय

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिविधियाँ सार्वजनिक करने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करवाकर ब्रेलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08.12.2014 को इस विभाग का नाम बदलकर जनशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। इसके बाद 17 मई, 2016 से विभाग का नाम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में परिवर्तित किया गया है। यह विभाग विभिन्न पणधारकों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सार्वजनिक सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के बीच प्रभावी करीबी समन्वयन सहित विकलांग विद्यार्थियों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.2 विभाग के उद्देश्य

- 1.2.1 भारत (आवंटन) नियमावली के अनुसार विभाग के लिए आबंटित कार्य अनुबंध-1 (पृष्ठ 1) में दिए हैं। विभाग को मुख्य रूप से विकलांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।
- 1.2.2 विकलांग समाज बनाना जिसमें विकलांग व्यक्तियों की उन्नति और विकास के लिए समान प्रयास होते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
- 1.2.3 मिशन विधिनियमों / संस्थाओं / संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से विकलांग सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण सृजित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर और उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करे और उन्हें समाज के उत्तम सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए सक्षम बनाए।
- 1.2.4 अपने प्रारंभिक एवं मिशन को सफल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रयास करेगा—

- (क) पुनर्वास के लिए नीचे उल्लिखित उपाय करना—
- (i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें जल्दी पता लगाना तथा शीघ्र हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा विकलांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक तंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है:
 - (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक पुनर्वास
 - (iii) आर्थिक पुनर्वास और
 - (iv) सामाजिक सशक्तिकरण
- (ख) पुनर्वास व्यावसायिकों / कर्मियों को तैयार करना।
- (ग) आंतरिक कार्य-दक्षता / प्रतिक्रियाशीलता / सेवा प्रदायगी में सुधार।
- (घ) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता सृजन के माध्यम से विकलांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1.3 लक्ष्य समूह: दिव्यांगजन

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(न), (जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के रूप में भी जाना जाता है) “विकलांगजन” को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत पीड़ित है।

यह विकलांगता (क) दृष्टिबाधिता (ख) कम दृष्टि (ग) कुष्ठ रोग उपचारित (घ) श्रवण बाधिता (ङ) चलन विकलांगता (च) मानसिक रोग (छ) मानसिक मंदता (ज) स्वलीनता (ऑटिज्म), (झ) प्रमस्तिष्क अंगघात (सेरेब्रल पाल्सी) अथवा (ज) (छ), (ज) में से दो या अधिक का संयोजन, हो सकता है और (ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 (ज) के साथ पठित विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 2 (झ)

2

अध्याय

सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की केंद्रीय जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ विकलांगजन हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं)। कुल में से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ स्त्रियां हैं। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक्य बोलने में बाधित, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता, बहु निःशक्तता तथा अन्य निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं।

जबकि जनगणना आँकड़ों के अनुसार, विकलांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण अनुलग्नक 2 (पृष्ठ-187) दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार विकलांगता के प्रकार के अनुसार, उनकी संख्या का विवरण निम्नवत है:

लांगजनों की श्रेणी-वार संख्या: जनगणना: 2011 के अनुसार			
निशक्तता के प्रकार	5 और प्रतिशत	पुरुष एवं प्रतिशत	स्त्री एवं प्रतिशत
	1	2	3
देखने में	0,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	0,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	9,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	4,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	5,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रोगी	1,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	9,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु विकलांगता	1,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	38,14,994	1,49,885,93(55.89)	11,8264,01(44.1)

आवास भारत, 2011 द्वारा निशक्तजन जनसंख्या			
आवास	व्यक्ति	पुरुष	महिला
कुल	26,810,557	14,986,202	11,824,355
ग्रामीण	18,631,921 (69.49%)	10,408,168	8,223,753
शहरी	8,178,636 (30.5%)	4,578,034	3,600,602

*स्रोत: महापंजीकार एवं जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय

3

अध्याय

सांविधिक ढांचा

3.1 संबद्ध संवैधानिक

भारतीय संविधान प्रभा के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आ राज्क न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर के निश्चित करता है।

संविधान का सभी रेंकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। शामिल हैं: समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिकता अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी दिगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं, तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशेष नहया गया है।

संविधान के भा राज्नीति के निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये गैर न्यायाधीन हैं, इन्हें देश के शासन के घंकिया गया है। इन सिद्धांतों का राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना आशयित है। ये सभी विधायकों और कार्यपालकों के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों स्वरूप हैं।

“अनुच्छेद 41 आक्रम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

“राज्य अपनी सामर्थ विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी क्तरा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभा करे इसके अलावा, अनुच्छेद 243—छ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243—ब की 12वीं अनुसूचिकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित क्रमशः पंचायतों एवं नाओंक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में विकलांगजनों का उनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत है:

अनुच्छेद 243 1वीं सूची: “विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्क्षेष्ट)।

अनुच्छेद -243ब की 12वीं अनुसूची: "विकलांग और मानसिक रूप मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण" (प्रविष्टि सं 09)।

विभाग विकलांगता के विभिन्न पहलुओं और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नलिखित विधानों का कार्यान्वयन करता है :-

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
2. विकलांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, और
3. स्वलीनता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999.

इन अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं:-

3.2 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत समिति के रूप में स्थापित किया गया था। इसे संसद अधिनियम नामतः भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 द्वारा सांविधिक अस्तित्व प्रदान किया गया था। इसे व्यापक आधारित बनाने के लिए अधिनियम को वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसको मॉनीटर करता है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

- (i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।
- (ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्रविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।
- (iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना
- (iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।
- (v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण।
- (vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचार को निर्धारित करना।

3.3 निशक्तजन अर् अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

एशिया और प्रहेतुक और समाज आयोग द्वारा 1-5 दिसम्बर, 1992 में, बीजिंग में आयोजित, विकलांगजनों ई शांत दशक 1993 - 2002 को शुरू करने हेतु बैठक में अंगीकृत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जनोपूर्ण सहभागिता और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकारलां (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम), 1995 अधिनियमित त्त उद्घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

विकलांगजनों पुननियोजन, गैर भेदभाव और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले इस अधिनियम में "विकलांगतृष्टि, न्यून दृष्टि, श्रवण बाधिता, चलन संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णुष्ट से मुक्त हो चुके व्यक्तियों में उत्पन्न विकलांगता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह "जन" चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के पति करता है।

चूँकि "विकलांगत ...विषय सूची II की मद सं.9 : संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता हैधेनिगे सूची। की मद संख्या 13: संघ सूची: "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिसंघों और अन्य निकायों की और इनमें लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करना" के साथ पठित अनुच्छेद 253 के अंतर्गतमिला गया है, जो संसद को "अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान" अधिनियम त्त देता है।

3.3.1 इस अधिनियम विषे बदलने के प्रयास

विकलांगजन (सरकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, के उपबंधों के सामंजस्य और साथ ही बेनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ सरकार ने राज्य सभा में 07.02.2014 को विकलांग धेकधेयक 2014 प्रस्तुत किया था। विधेयक को संसदीय समिति को जांच और रिपोर्ट हेतु भेजसंस्थायी समिति ने दिनांक 07.05.2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने संसद की सिफारिशों पर विचार किया और तदनुसार कुछ अधिकारिक संशोधनों के साथ विधेयक नि एत करने के लिए संसद गई। विधेयक 14.12.2016 को अधिकारिक संशोधनों के साथ-साथ धा धारित किया गया। बाद में विधेयक 16.12.2016 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। नि अधिधिनियम, 2016, 28.12.2016 को अधिसूचित किया गया है।

निशक्तजन अधिधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और 28 दिसंबर, 2016 को 'निशक्तजन अधि, 2016' के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अधिनियम कीवनासार अलग से अध्याय-04 में प्रस्तुत किया गया है। (निशक्तजन अधिकार अधि016हेन्दी रूपांतरण, राजभाषा विधायी विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।)

3.4 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संसद के वर्ष 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- (i) विकलांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।
- (ii) विकलांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- (iii) विकलांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।
- (iv) विकलांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।
- (v) विकलांगजनों के माता-पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।
- (vi) जिन विकलांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरूरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।
- (vii) विकलांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।
- (viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

4

अध्याय

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

रजि. नं.—0007/2003—16

REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16



भारत का राजपत्र Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 07, 1938 (शक)
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSHA 07, 1938 (SAKA)

यह अधिनियम धिन्ध्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
This Part is hereby published in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 28th December, 2016/Pausha 17, 1938 (Saka)

The Bill of Parliament received the assent of the President on the 28th December, 2016 and is hereby published for general information:—

RIGID PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016

(No. 49 OF 2016)

[27th December, 2016]

Agave to the United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental

As the Nations General Assembly adopted its Convention on the Rights
of Persons with Disabilities on the 13th day of December, 2006;

Whereas the said Convention lays down the following principles for
the persons with disabilities,—

- (a) respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make choices, and independence of persons;
- (b) non-discrimination;
- (c) full and effective participation and inclusion in society;
- (d) respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity;

(e) equality of opportunity;

(f) accessibility;

(g) equality between men and women;

(h) respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities;

AND WHEREAS India is a signatory to the said Convention;

AND WHEREAS India ratified the said Convention on the 1st day of October, 2007;

AND WHEREAS it is considered necessary to implement the Convention aforesaid.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “appellate authority” means an authority notified under sub-section (3) of section 14 or sub-section (1) of section 53 or designated under sub-section (1) of section 59, as the case may be;

(b) “appropriate Government” means,—

(i) in relation to the Central Government or any establishment wholly or substantially financed by that Government, or a Cantonment Board constituted under the Cantonments Act, 2006, the Central Government;

(ii) in relation to a State Government or any establishment, wholly or substantially financed by that Government, or any local authority, other than a Cantonment Board, the State Government.

(c) “barrier” means any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social, attitudinal or structural factors which hampers the full and effective participation of persons with disabilities in society;

(d) “care-giver” means any person including parents and other family Members who with or without payment provides care, support or assistance to a person with disability;

(e) “certifying authority” means an authority designated under sub-section (1) of section 57;

(f) “communication” includes means and formats of communication, languages, display of text, Braille, tactile communication, signs, large print, accessible multimedia, written, audio, video, visual displays, sign language, plain-language, human-reader, augmentative and alternative modes and accessible information and communication technology;

(g) “competent authority” means an authority appointed under section 49;

(h) “discrimination” in relation to disability, means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field and includes all forms of discrimination and denial of reasonable accommodation;

41 of 2006.

(i) 'establishment' includes a Government establishment and private establishment;

(j) " " means the National Fund constituted under section 86;

(k) 'Government establishment' means a corporation established by or under a State Act or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government, a local authority or a Government company as defined in section 2 of the Companies Act, 2013 and includes a Department of the Government;

18 of 2013.

(l) 'support' means an intensive support, physical, psychological and financial which may be required by a person with benchmark disability for daily activities to make independent and informed decision to access facilities and participate in all areas of life including education, employment, family and community and rehabilitation and therapy;

(m) 'Inclusive education' means a system of education wherein students with benchmark disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to the learning needs of different types of students with disabilities;

(n) 'Information and communication technology' includes all services and facilities relating to information and communication, including telecom services, postal services, electronic and print services, digital and virtual services;

(o) 'Institution' means an institution for the reception, care, protection, education, rehabilitation and any other activities for persons with disabilities;

41 of 2006.

(p) 'Local authority' means a Municipality or a Panchayat, as defined in clause (e) and clause (d) of article 243P of the Constitution; a Cantonment Board constituted under the Cantonments Act, 2006; and any other authority established under an Act of Parliament or a State Legislature to administer the civic affairs;

(q) 'Notification' means a notification published in the Official Gazette and the expression 'notified' or 'notified' shall be construed accordingly;

(r) 'Person with benchmark disability' means a person with not less than forty per cent specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority;

(s) 'Person with disability' means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others;

(t) 'Person with disability having high support needs' means a person with benchmark disability certified under clause (a) of sub-section (2) of section 58 who needs support;

(u) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act;

(v) 'Private establishment' means a company, firm, cooperative or other society, association, trust, agency, institution, organisation, union, factory or such other institution as the appropriate Government may, by notification, specify;

(w) 'Public building' means a Government or private building, used or accessed by the public at large, including a building used for educational or vocational purposes, work, commercial activities, public utilities, religious, cultural, leisure or recreational activities, medical or health services, law enforcement agencies, reformatories or judicial or way stations or platforms, roadways bus stands or terminus, airports or water;

(x) 'Public facilities and services' includes all forms of delivery of services to the public at large, including housing, educational and vocational trainings, employment

and career advancement, shopping or marketing, religious, cultural, leisure or recreational, medical, health and rehabilitation, banking, finance and insurance, communication, postal and information, access to justice, public utilities, transportation;

(y) "reasonable accommodation" means necessary and appropriate modification and adjustments, without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise of rights equally with others;

(z) "registered organisation" means an association of persons with disabilities or a disabled person organisation, association of parents of persons with disabilities, association of persons with disabilities and family members, or a voluntary or non-governmental or charitable organisation or trust, society, or non-profit company working for the welfare of the persons with disabilities, duly registered under an Act of Parliament or a State Legislature;

(za) "rehabilitation" refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to attain and maintain optimal, physical, sensory, intellectual, psychological environmental or social function levels;

(zb) "Special Employment Exchange" means any office or place established and maintained by the Government for the collection and furnishing of information, either by keeping of registers or otherwise, regarding—

(i) persons who seek to engage employees from amongst the persons with disabilities;

(ii) persons with benchmark disability who seek employment;

(iii) vacancies to which persons with benchmark disabilities seeking employment may be appointed;

(zc) "specified disability" means the disabilities as specified in the Schedule;

(zd) "transportation systems" includes road transport, rail transport, air transport, water transport, para transit systems for the last mile connectivity, road and street infrastructure, etc.;

(ze) "universal design" means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialised design and shall apply to assistive devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities.

CHAPTER II

RIGHTS AND ENTITLEMENTS

Equality and non-discrimination.

3. (1) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.

(2) The appropriate Government shall take steps to utilise the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment.

(3) No person with disability shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

(4) No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability.

(5) The appropriate Government shall take necessary steps to ensure reasonable accommodation for persons with disabilities.

4. (1) Government and the local authorities shall take measures to ensure that persons with disabilities enjoy their rights equally with others.

Women and children with disabilities.

(2) Government and local authorities shall ensure that all children with disabilities shall have equal basis to freely express their views on all matters affecting them and appropriate support keeping in view their age and disability."

5. (1) Persons with disabilities shall have the right to live in the community.

Community life.

(2) Government shall endeavour that the persons with disabilities are,—

(a) not confined to any particular living arrangement; and

(b) access to in-house, residential and other community support services and assistance necessary to support living with due regard to age and

6. (1) Government shall take measures to protect persons with disabilities from torture, cruel, inhuman or degrading treatment.

Protection from cruelty and inhuman treatment.

(2) No person shall be a subject of any research without,—

(i) free informed consent obtained through accessible modes, means and of communication; and

(ii) a Committee for Research on Disability constituted in the prescribed form by the appropriate Government in which not less than half members shall be either persons with disabilities or Members of the Council as defined under clause (z) of section 2.

7. (1) Government shall take measures to protect persons with disabilities from abuse, violence and exploitation and to prevent the same, shall—

Protection from abuse, violence and exploitation.

(a) identify incidents of abuse, violence and exploitation and provide legal redress against such incidents;

(b) identify such incidents and prescribe the procedure for its reporting

(c) to protect and rehabilitate victims of such incidents; and

(d) arrange to make available information among the public.

(2) Any person or organisation who or which has reason to believe that an act of abuse, violence or exploitation has been, or is being, or is likely to be committed against any person with disability give information about it to the Executive Magistrate within the local jurisdiction in which such incidents occur.

(3) The Magistrate on receipt of such information, shall take immediate steps to stop the offence, as the case may be, or pass such order as he deems fit for the protection of person with disability including an order—

(a) the issue of such act, authorising the police or any organisation working with disabilities to provide for the safe custody or rehabilitation of such person as the case may be;

(b) placing in safe custody to the person with disability, if such person so desires

(c) to provide such person with disability.

(4) Any person who receives a complaint or otherwise comes to know of abuse, violence or exploitation of person with disability shall inform the aggrieved person of—

(a) his or her right to apply for protection under sub-section (2) and the particulars of the Executive Magistrate having jurisdiction to provide assistance;

(b) the particulars of the nearest organisation or institution working for the rehabilitation of persons with disabilities;

(c) the right to free legal aid; and

(d) the right to file a complaint under the provisions of this Act or any other law dealing with such offence:

Provided that nothing in this section shall be construed in any manner as to relieve the police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence.

(5) If the Executive Magistrate finds that the alleged act or behaviour constitutes an offence under the Indian Penal Code, or under any other law for the time being in force, he may forward the complaint to that effect to the Judicial or Metropolitan Magistrate, as the case may be, having jurisdiction in the matter.

45 of 1860.

Protection and safety.

8. (1) The persons with disabilities shall have equal protection and safety in situations of risk, armed conflict, humanitarian emergencies and natural disasters.

(2) The National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authority shall take appropriate measures to ensure inclusion of persons with disabilities in its disaster management activities as defined under clause (e) of section 2 of the Disaster Management Act, 2005 for the safety and protection of persons with disabilities.

53 of 2005.

(3) The District Disaster Management Authority constituted under section 25 of the Disaster Management Act, 2005 shall maintain record of details of persons with disabilities in the district and take suitable measures to inform such persons of any situations of risk so as to enhance disaster preparedness.

53 of 2005.

(4) The authorities engaged in reconstruction activities subsequent to any situation of risk, armed conflict or natural disasters shall undertake such activities, in consultation with the concerned State Commissioner, in accordance with the accessibility requirements of persons with disabilities.

Home and family.

9. (1) No child with disability shall be separated from his or her parents on the ground of disability except on an order of competent court, if required, in the best interest of the child.

(2) Where the parents are unable to take care of a child with disability, the competent court shall place such child with his or her near relations, and failing that within the community in a family setting or in exceptional cases in shelter home run by the appropriate Government or non-governmental organisation, as may be required.

Reproductive rights.

10. (1) The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities have access to appropriate information regarding reproductive and family planning.

(2) No person with disability shall be subject to any medical procedure which leads to infertility without his or her free and informed consent.

Accessibility in voting.

11. The Election Commission of India and the State Election Commissions shall ensure that all polling stations are accessible to persons with disabilities and all materials related to the electoral process are easily understandable by and accessible to them.

Access to justice.

12. (1) The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities are able to exercise the right to access any court, tribunal, authority, commission or any other body having judicial or quasi-judicial or investigative powers without discrimination on the basis of disability.

(2) The appropriate Government shall take steps to put in place suitable support measures for persons with disabilities specially those living outside family and those disabled requiring high support for exercising legal rights.

39 of 1987.

(Constitutional Services Authority and the State Legal Services Authorities constitute the Services Authorities Act, 1987 shall make provisions including reasonable measures to ensure that persons with disabilities have access to any scheme, form or service offered by them equally with others.

(The Government shall take steps to—

ensure that all their public documents are in accessible formats;

ensure that the filing departments, registry or any other office of records are equipped with necessary equipment to enable filing, storing and referring to the documents in accessible formats; and

provide all necessary facilities and equipment to facilitate recording of decisions, orders or opinion given by persons with disabilities in their preferred mode of communication.

The Government shall ensure that the persons with disabilities have the right to own or inherit property, movable or immovable, control their finances and have access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit.

Legal capacity.

(The Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy legal capacity on a par with others in all aspects of life and have the right to equal recognition before the law.

In the event a conflict of interest arises between a person providing support and a person in a particular financial, property or other economic transaction, then such person shall abstain from providing support to the person with disability in that transaction.

There shall not be a presumption of conflict of interest just on the basis that the person is related to the person with disability by blood, affinity or adoption.

(A person may alter, modify or dismantle any support arrangement and secure for:

that any alteration, modification or dismantling shall be prospective in nature and shall not affect any third party transaction entered into by the person with disability before the support arrangement.

A person providing support to the person with disability shall not exercise undue influence and respect his or her autonomy, dignity and privacy.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on the commencement of this Act, where a district court or any designated authority, aided by the State Government, finds that a person with disability, who has provided adequate and appropriate support but is unable to take legally binding decisions, may provide further support of a limited guardian to take legally binding decisions in consultation with such person, in such manner, as may be prescribed in the Statement:

Provision for guardianship.

The District Court or the designated authority, as the case may be, may grant support to a person with disability requiring such support or where the limited guardian is not satisfied, in which case, the decision regarding the support to be provided by the Court or the designated authority, as the case may be, to the person and manner of support to be provided.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, “limited guardianship” means a system in which the guardian operates on mutual understanding and trust between the guardian and the person with disability which shall be limited to a specific period and for specific decision and shall be in accordance to the will of the person with disability.

(2) On and from the date of commencement of this Act, every guardian appointed under any provision of any other law for the time being in force, for a person with disability shall be deemed to function as a limited guardian.

(3) Any person with disability aggrieved by the decision of the designated authority appointing a legal guardian may prefer an appeal to such appellate authority, as may be notified by the State Government for the purpose.

Designation of
authorities to
support.

15. (1) The appropriate Government shall designate one or more authorities to mobilise the community and create social awareness to support persons with disabilities in exercise of their legal capacity.

(2) The authority designated under sub-section (1) shall take measures for setting up suitable support arrangements to exercise legal capacity by persons with disabilities living in institutions and those with high support needs and any other measures as may be required.

CHAPTER III

EDUCATION

Duty of
educational
institutions.

16. The appropriate Government and the local authorities shall endeavour that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall—

(i) admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others;

(ii) make building, campus and various facilities accessible;

(iii) provide reasonable accommodation according to the individual's requirements;

(iv) provide necessary support individualised or otherwise in environments that maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion;

(v) ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of communication;

(vi) detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them;

(vii) monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability;

(viii) provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs.

Specific
measures to
promote and
facilitate
inclusive
education.

17. The appropriate Government and the local authorities shall take the following measures for the purpose of section 16, namely:—

(a) to conduct survey of school going children in every five years for identifying children with disabilities, ascertaining their special needs and the extent to which these are being met;

Provided that the first survey shall be conducted within a period of two years from the date of commencement of this Act;

(b) to establish adequate number of teacher training institutions;

(c) to train and employ teachers, including teachers with disability who are qualified in sign language and Braille and also teachers who are trained in teaching children with intellectual disability;

(d) to train professionals and staff to support inclusive education at all levels of school education;

(c) establish a number of resource centres to support educational institutions; school education;

(d) use the appropriate augmentative and alternative modes including means of communication, Braille and sign language to supplement the use of one's hand to the daily communication needs of persons with speech, communication disabilities and enables them to participate and contribute to their community;

(e) provide both learning materials and appropriate assistive devices to students with disabilities free of cost up to the age of eighteen years;

(f) provide scholarships in appropriate cases to students with benchmark disabilities;

(g) make modifications in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disabilities such as extra time for completion of examination, facility to scribe or amanuensis, exemption from second and third language;

(h) use the same to improve learning; and

(i) use the same, as may be required.

18. The Government and the local authorities shall take measures to promote, protect and participation of persons with disabilities in adult education and continuing education on a par with others.

Adult education.

CHAPTER IV

DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

19. (1) The Government shall formulate schemes and programmes including provision of incentives to facilitate and support employment of persons with disabilities for vocational training and self-employment.

Vocational training and self-employment.

(2) The schemes referred to in sub-section (1) shall provide for—

(a) provision of facilities for persons with disability in all mainstream formal and non-formal vocational training schemes and programmes;

(b) ensure that persons with disability has adequate support and facilities to avail training;

(c) skill training programmes for persons with disabilities with active links with the market, including developmental, intellectual, multiple disabilities and autism;

(d) financial rates including that of microcredit;

(e) encourage the participation of persons with disabilities; and

(f) collect and aggregate data on the progress made in the skill training and self-employment of persons with disabilities.

20. (1) The Government shall not discriminate against any person with disability in employment:

Non-discrimination in employment.

Provided that the Government may, having regard to the type of work carried on in the establishment and subject to such conditions, if any, exempt any establishment from the provisions of this section.

(2) The Government shall provide reasonable accommodation and appropriate working environment to employees with disability.

(3) No person shall be denied to a person merely on the ground of disability.

(4) No Government establishment shall dispense with or reduce in rank, an employee who acquires disability during his or her service:

Provided that, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits:

Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

(5) The appropriate Government may frame policies for posting and transfer of employees with disabilities.

Equal
opportunity
policy.

21. (1) Every establishment shall notify equal opportunity policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of this Chapter in the manner as may be prescribed by the Central Government.

(2) Every establishment shall register a copy of the said policy with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be.

Maintenance
of records.

22. (1) Every establishment shall maintain records of the persons with disabilities in relation to the matter of employment, facilities provided and other necessary information in compliance with the provisions of this Chapter in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.

(2) Every employment exchange shall maintain records of persons with disabilities seeking employment.

(3) The records maintained under sub-section (1) shall be open to inspection at all reasonable hours by such persons as may be authorised in their behalf by the appropriate Government.

Appointment
of Grievance
Redressal
Officer.

23. (1) Every Government establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 and shall inform the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, about the appointment of such officer.

(2) Any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 20, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate it and shall take up the matter with the establishment for corrective action.

(3) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints in the manner as may be prescribed by the Central Government, and every complaint shall be inquired within two weeks of its registration.

(4) If the aggrieved person is not satisfied with the action taken on his or her complaint, he or she may approach the District-Level Committee on disability.

CHAPTER V

SOCIAL SECURITY, HEALTH, REHABILITATION AND RECREATION

Social security.

24. (1) The appropriate Government shall within the limit of its economic capacity and development formulate necessary schemes and programmes to safeguard and promote the right of persons with disabilities for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community:

Provided that the quantum of assistance to the persons with disabilities under such schemes and programmes shall be at least twenty-five per cent. higher than the similar schemes applicable to others.

(2) The appropriate Government while devising these schemes and programmes shall give due consideration to the diversity of disability, gender, age, and socio-economic status.

(3) The schemes under sub-section (1) shall provide for,—

(a) community centres with good living conditions in terms of safety, sanitation, health care and counselling;

(b) facilities for persons including children with disabilities who have no family or have been abandoned, or are without shelter or livelihood;

(c) support during natural or man-made disasters and in areas of conflict;

(d) to with disability for livelihood and for upbringing of their children

(e) to sinking water and appropriate and accessible sanitation facilities in slums and rural areas;

(f) to stand appliances, medicine and diagnostic services and correct free to persons with disabilities with such income ceiling as may be

(g) to persons with disabilities subject to such income ceiling as may be

(h) to persons with disabilities registered with Special Employment more than two years and who could not be placed in any gainful ;

(i) to persons with disabilities with high support needs;

(j) to insurance scheme for persons with disability, not covered under the Insurance Schemes, or any other statutory or Government-sponsored ;

(k) to match the appropriate Government may think fit.

25. (1) The Government and the local authorities shall take necessary measures for the disabilities to provide,— Healthcare.

(a) to have vicinity specially in rural area subject to such family income ;

(b) to be in all parts of Government and private hospitals and other health centres ;

(c) to attend and treatment.

(2) The Government and the local authorities shall take measures and make schemes to promote healthcare and prevent the occurrence of disabilities and for the safety of

(a) to be undertaken surveys, investigations and research concerning occurrence of disabilities;

(b) to methods for preventing disabilities;

(c) to be done at least once in a year for the purpose of identifying "at-risk"

(d) to facilitate training to the staff at the primary health centres;

(e) to be sponsored awareness campaigns and disseminate or cause to be information for general hygiene, health and sanitation;

(f) to be prenatal, perinatal and post-natal care of mother and child;

(g) to be through the pre-schools, schools, primary health centres, village health workers ;

(h) to be amongst the masses through television, radio and other mass media ;

(i) to be during time of natural disasters and other situations of risk;

(j) to be facilities for life saving emergency treatment and procedures; and

(k) to be to provide healthcare especially for women with disability.

26. The Government shall, by notification, make insurance schemes for their employees ; Insurance schemes.

27. (1) The Government and the local authorities shall within their economic capacity and to be undertaken services and programmes of Rehabilitation.

rehabilitation, particularly in the areas of health, education and employment for all persons with disabilities.

(2) For the purposes of sub-section (1), the appropriate Government and the local authorities may grant financial assistance to non-Governmental Organisations.

(3) The appropriate Government and the local authorities, while formulating rehabilitation policies shall consult the non-Governmental Organisations working for the cause of persons with disabilities.

Research and
development.

28. The appropriate Government shall initiate or cause to be initiated research and development through individuals and institutions on issues which shall enhance habilitation and rehabilitation and on such other issues which are necessary for the empowerment of persons with disabilities.

Culture and
recreation.

29. The appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote and protect the rights of all persons with disabilities to have a cultural life and to participate in recreational activities equally with others which include,—

(a) facilities, support and sponsorships to artists and writers with disability to pursue their interests and talents;

(b) establishment of a disability history museum which chronicles and interprets the historical experiences of persons with disabilities;

(c) making art accessible to persons with disabilities;

(d) promoting recreation centres, and other associational activities;

(e) facilitating participation in scouting, dancing, art classes, outdoor camps and adventure activities;

(f) redesigning courses in cultural and arts subjects to enable participation and access for persons with disabilities;

(g) developing technology, assistive devices and equipments to facilitate access and inclusion for persons with disabilities in recreational activities; and

(h) ensuring that persons with hearing impairment can have access to television programmes with sign language interpretation or sub-titles.

Sporting
activities.

30. (1) The appropriate Government shall take measures to ensure effective participation in sporting activities of the persons with disabilities.

(2) The sports authorities shall accord due recognition to the right of persons with disabilities to participate in sports and shall make due provisions for the inclusion of persons with disabilities in their schemes and programmes for the promotion and development of sporting talents.

(3) Without prejudice to the provisions contained in sub-sections (1) and (2), the appropriate Government and the sports authorities shall take measures to,—

(a) restructure courses and programmes to ensure access, inclusion and participation of persons with disabilities in all sporting activities;

(b) redesign and support infrastructure facilities of all sporting activities for persons with disabilities;

(c) develop technology to enhance potential, talent, capacity and ability in sporting activities of all persons with disabilities;

(d) provide multi-sensory essentials and features in all sporting activities to ensure effective participation of all persons with disabilities;

(e) allocate funds for development of state of art sport facilities for training of persons with disabilities;

(f) promote and organise disability specific sporting events for persons with disabilities and also facilitate awards to the winners and other participants of such sporting events.

CHAPTER VI

PROVISIONS FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES

35 of 2009.

Notwithstanding anything contained in the Rights of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, every child with benchmark disability between the age of six to fourteen years shall have the right to free education in a neighbourhood school, or in a special school.

Free education for children with benchmark disabilities.

The Government and local authorities shall ensure that every child with benchmark disability has access to free education in an appropriate environment till he attains eighteen years.

Government institutions of higher education and other higher education institutions in the Government shall reserve not less than five per cent. seats for persons with benchmark disabilities.

Reservation in higher educational institutions.

Persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years in institutions of higher education.

The Government shall—

Identification of posts for reservation.

identify in the establishments which can be held by respective category of persons with benchmark disabilities in respect of the vacancies reserved in accordance with the provisions of section 34;

constitute an expert committee with representation of persons with benchmark disabilities for identification of such posts; and

conduct periodic review of the identified posts at an interval not exceeding three years.

The appropriate Government shall appoint in every Government establishment, not less than five per cent. of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts filled with persons with benchmark disabilities of which, one per cent. shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and the remaining four per cent. for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely—

Reservation.

(a) persons with low vision;

(b) persons with deaf and hearing;

(c) persons with physical disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acidosis and muscular dystrophy;

(d) persons with intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) persons with multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including persons who are identified for each disabilities:

The promotion in promotion shall be in accordance with such instructions as are issued by the appropriate Government from time to time:

The appropriate Government, in consultation with the Chief Commissioner, as the case may be, may, having regard to the type of work in Government establishment, by notification and subject to such conditions, as may be specified in such notifications exempt any Government establishments from the provisions of this section.

(In recruitment year any vacancy cannot be filled up due to non-availability of person with benchmark disability or for any other sufficient reasons, such vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in the succeeding recruitment year also suitable person with benchmark disability is not available, it may be changed among the five categories and only when there is no person available for the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appointing a person other than a person with disability:

Provided that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the five categories with the prior approval of the appropriate Government.

(3) The appropriate Government may, by notification, provide for such relaxation of upper age limit for employment of persons with benchmark disability, as it thinks fit.

Incentives to employers in private sector.

35. The appropriate Government and the local authorities shall, within the limit of their economic capacity and development, provide incentives to employer in private sector to ensure that at least five per cent. of their work force is composed of persons with benchmark disability.

Special employment exchange.

36. The appropriate Government may, by notification, require that from such date, the employer in every establishment shall furnish such information or return as may be prescribed by the Central Government in relation to vacancies appointed for persons with benchmark disability that have occurred or are about to occur in that establishment to such special employment exchange as may be notified by the Central Government and the establishment shall thereupon comply with such requisition.

Special schemes and development programmes.

37. The appropriate Government and the local authorities shall, by notification, make schemes in favour of persons with benchmark disabilities, to provide,—

(a) five per cent. reservation in allotment of agricultural land and housing in all relevant schemes and development programmes, with appropriate priority to women with benchmark disabilities;

(b) five per cent. reservation in all poverty alleviation and various developmental schemes with priority to women with benchmark disabilities;

(c) five per cent. reservation in allotment of land on concessional rate, where such land is to be used for the purpose of promoting housing, shelter, setting up of occupation, business, enterprise, recreation centres and production centres.

CHAPTER VII

SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES WITH HIGH SUPPORT NEEDS

Special provisions for persons with disabilities with high support.

38. (1) Any person with benchmark disability, who considers himself to be in need of high support, or any person or organisation on his or her behalf, may apply to an authority, to be notified by the appropriate Government, requesting to provide high support.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the authority shall refer it to an Assessment Board consisting of such Members as may be prescribed by the Central Government.

(3) The Assessment Board shall assess the case referred to it under sub-section (1) in such manner as may be prescribed by the Central Government, and shall send a report to the authority certifying the need of high support and its nature.

(4) On receipt of a report under sub-section (3), the authority shall take steps to provide support in accordance with the report and subject to relevant schemes and orders of the appropriate Government in this behalf.

CHAPTER VIII

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF APPROPRIATE GOVERNMENTS

Awareness campaigns.

39. (1) The appropriate Government, in consultation with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, shall conduct, encourage, support or promote awareness campaigns and sensitisation programmes to ensure that the rights of the persons with disabilities provided under this Act are protected.

(2) The programmes and campaigns specified under sub-section (1) shall also,—

(a) promote values of inclusion, tolerance, empathy and respect for diversity;

(b) advance recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities and of their contributions to the workforce, labour market and professional fee;

(c) specific decisions made by persons with disabilities on all matters relating to family relationships, bearing and raising children;

(d) orientation and sensitisation at the school, college, University and profession in the human condition of disability and the rights of persons with disabilities;

(e) orientation and sensitisation on disabling conditions and rights of persons with disabilities to employers, administrators and co-workers;

(f) that persons with disabilities are included in the curriculum in Universities and schools.

40. The Government shall, in consultation with the Chief Commissioner, formulate rules and regulations laying down the standards of accessibility for the physical environment, information and communications, including appropriate telecommunications, and other facilities and services provided to the public in urban areas. Accessibility.

41. (1) The Government shall take suitable measures to provide,— Access to transport.

(a) for persons with disabilities at bus stops, railway stations and airports in accordance with accessibility standards relating to parking spaces, toilets, ticketing and lifting machines;

(b) public transport that conform to the design standards, including retrofitting of transport, wherever technically feasible and safe for persons with disabilities and without entailing major structural changes in design;

(c) road address mobility necessary for persons with disabilities.

(2) The Government shall develop schemes and programmes to promote the personal mobility of persons with disabilities at affordable cost to provide for,—

(a) concessions;

(b) subsidies; and

(c) other assistance.

42. The Government shall take measures to ensure that,— Access to information and communication technology.

(i) texts are in audio, print and electronic media are in accessible format;

(ii) persons with disabilities have access to electronic media by providing audio description and interpretation and close captioning;

(iii) goods and equipment which are meant for every day use are available at affordable prices.

43. The Government shall take measures to promote development, production and nationally designed consumer products and accessories for general use for persons with disabilities. Consumer goods.

44. (1) No person shall be granted permission to build any structure if the building plan does not conform to the rules formulated by the Central Government under section 40. Mandatory observance of accessibility norms.

(2) No person shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building unless he has adhered to the rules formulated by the Central Government.

45. (1) All buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification. Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose.

Provided that the Government may grant extension of time to the States on a case to case basis on the basis of provision depending on their state of preparedness and other related factors.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritisation, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centres, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops.

Time limit for accessibility by service providers.

46. The service providers whether Government or private shall provide services in accordance with the rules on accessibility formulated by the Central Government under section 40 within a period of two years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government in consultation with the Chief Commissioner may grant extension of time for providing certain category of services in accordance with the said rules.

Human resource development.

47. (1) Without prejudice to any function and power of Rehabilitation Council of India constituted under the Rehabilitation Council of India Act, 1992, the appropriate Government shall endeavour to develop human resource for the purposes of this Act and to that end shall,—

34 of 1992.

(a) mandate training on disability rights in all courses for the training of Panchayati Raj Members, legislators, administrators, police officials, judges and lawyers;

(b) induct disability as a component for all education courses for schools, colleges and University teachers, doctors, nurses, para-medical personnel, social welfare officers, rural development officers, ashra workers, *anganwadi* workers, engineers, architects, other professionals and community workers;

(c) initiate capacity building programmes including training in independent living and community relationships for families, members of community and other stakeholders and care providers on care giving and support;

(d) ensure independence training for persons with disabilities to build community relationships on mutual contribution and respect;

(e) conduct training programmes for sports teachers with focus on sports, games, adventure activities;

(f) any other capacity development measures as may be required.

(2) All Universities shall promote teaching and research in disability studies including establishment of study centres for such studies.

(3) In order to fulfil the obligation stated in sub-section (1), the appropriate Government shall in every five years undertake a need based analysis and formulate plans for the recruitment, induction, sensitisation, orientation and training of suitable personnel to undertake the various responsibilities under this Act.

Social audit.

48. The appropriate Government shall undertake social audit of all general schemes and programmes involving the persons with disabilities to ensure that the scheme and programmes do not have an adverse impact upon the persons with disabilities and need the requirements and concerns of persons with disabilities.

CHAPTER IX

REGISTRATION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND GRANTS TO SUCH INSTITUTIONS

Competent authority.

49. The State Government shall appoint an authority as it deems fit to be a competent authority for the purposes of this Chapter.

Registration.

50. Save as otherwise provided under this Act, no person shall establish or maintain any institution for persons with disabilities except in accordance with a certificate of registration issued in this behalf by the competent authority:

Provided that an institution for care of mentally ill persons, which holds a valid licence under section 8 of the Mental Health Act, 1987 or any other Act for the time being in force, shall not be required to be registered under this Act.

14 of 1987.

51. (1) Every certificate of registration shall be made to the competent authority in such form as may be prescribed by the State Government.

Application and grant of certificate of registration.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the competent authority shall make such enquiry as it deems fit, and on being satisfied that the applicant has complied with the requirements of the Act and rules made thereunder, it shall grant a certificate of registration to the applicant within ninety days of receipt of application and if not satisfied, the competent authority may, by order, refuse to grant the certificate applied for:

Provided that in order refusing to grant a certificate, the competent authority shall give an ample opportunity of being heard and every order of refusal to grant a certificate shall be communicated to the applicant in writing.

(3) No certificate shall be granted under sub-section (2) unless the institution with which application has been made is in a position to provide such facilities and amenities as may be prescribed by the State Government.

(4) The certificate granted under sub-section (2),—

(a) shall remain in force for such period as may be prescribed by the Government;

(b) may be renewed from time to time for a like period; and

(c) shall be subject to such conditions as may be prescribed by the Government.

(5) An applicant for a certificate of registration shall be made not less than sixty days before the expiry period of validity.

(6) A copy of the certificate of registration shall be displayed by the institution in a conspicuous place.

(7) Every certificate granted under sub-section (1) or sub-section (5) shall be disposed of by the competent authority within such period as may be prescribed by the State Government.

52. (1) The Government may, if it has reason to believe that the holder of a certificate of registration under sub-section (2) of section 51 has,—

Revocation of registration.

(a) made a false statement in any application for the issue or renewal of the certificate or made a false statement in material particulars; or

(b) committed any breach of rules or any conditions subject to which the certificate was granted,

it may, after making such enquiry as it deems fit, by order, revoke the certificate:

Provided that the order shall be made until an opportunity is given to the holder of the certificate to show why the certificate of registration shall not be revoked.

(2) Where the registration in respect of an institution has been revoked under sub-section (1), the institution shall cease to function from the date of such revocation:

Provided that an appeal under section 53 against the order of revocation, such institution shall continue to function,—

(a) where an appeal is preferred immediately on the expiry of the period prescribed for filing an appeal; or

(b) where an appeal has been preferred, but the order of revocation has been upheld, from the date of the order of appeal.

(3) On the revocation of registration in respect of an institution, the competent authority may direct any person with disability who is an inmate of such institution on the date of such revocation, shall be—

(a) the holder of his or her parent, spouse or lawful guardian, as the case may be.

(b) transferred to any other institution specified by the competent authority.

(4) Every institution which holds a certificate of registration which is revoked under this section shall, immediately after such revocation, surrender such certificate to the competent authority.

Appeal.

53. (1) Any person aggrieved by the order of the competent authority refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within such period as may be prescribed by the State Government, prefer an appeal to such appellate authority, as may be notified by the State Government against such refusal or revocation.

(2) The order of the appellate authority on such appeal shall be final.

Act not to apply to institutions established or maintained by Central or State Government.

54. Nothing contained in this Chapter shall apply to an institution for persons with disabilities established or maintained by the Central Government or a State Government.

Assistance to registered institutions.

55. The appropriate Government may within the limits of their economic capacity and development, grant financial assistance to registered institutions to provide services and to implement the schemes and programmes in pursuance of the provisions of this Act.

CHAPTER X

CERTIFICATION OF SPECIFIED DISABILITIES

Guidelines for assessment of specified disabilities.

56. The Central Government shall notify guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person.

Designation of certifying authorities.

57. (1) The appropriate Government shall designate persons, having requisite qualifications and experience, as certifying authorities, who shall be competent to issue the certificate of disability.

(2) The appropriate Government shall also notify the jurisdiction within which and the terms and conditions subject to which, the certifying authority shall perform its certification functions.

Procedure for certification.

58. (1) Any person with specified disability, may apply, in such manner as may be prescribed by the Central Government, to a certifying authority having jurisdiction, for issuing of a certificate of disability.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the certifying authority shall assess the disability of the concerned person in accordance with relevant guidelines notified under section 56, and shall, after such assessment, as the case may be,—

(a) issue a certificate of disability to such person, in such form as may be prescribed by the Central Government;

(b) inform him in writing that he has no specified disability.

(3) The certificate of disability issued under this section shall be valid across the country.

Appeal against a decision of certifying authority.

59. (1) Any person aggrieved with decision of the certifying authority, may appeal against such decision, within such time and in such manner as may be prescribed by the State Government, to such appellate authority as the State Government may designate for the purpose.

(2) On receipt of an appeal, the appellate authority shall decide the appeal in such manner as may be prescribed by the State Government.

CHAPTER XI

CENTRAL ADVISORY BOARD ON DISABILITY AND DISTRICT LEVEL COMMITTEE

60. (1) The Govt shall, by notification, constitute a body to be known as the Central Board of Disability to exercise the powers conferred on, and to perform the functions, under this Act.

Constitution of Central Advisory Board on Disability.

(2) The Board shall consist of,—

(a) the Secretary of Department of Disability Affairs in the Central Government, *ex officio*;

(b) the officer in charge dealing with Department of Disability Affairs in the Ministry of Government, Vice Chairperson, *ex officio*;

(c) members of whom two shall be elected by Lok Sabha and one by the members, *ex officio*;

(d) the Secretary of Disability Affairs of all States and Administrators or Lieutenant Governors of Union territories, Members, *ex officio*;

(e) the Secretary of Government of India in charge of the Ministries or Departments of Pensions, Social Justice and Empowerment, School Education and Literacy, Women and Child Development, Expenditure, Personnel, Administrative Reforms and Public Grievances, Health and Family Welfare, Panchayati Raj, Industrial Policy and Promotion, Urban Development and Urban Poverty Alleviation, Science and Technology, Communication Technology, Legal Affairs, Public Enterprises, Youth Affairs and Sports and Highways and Civil Aviation, Members, *ex officio*;

(f) the Director of Institute of Transforming India (ITI) Aayog, Member, *ex officio*;

(g) the Chairman, National Council of India, Member, *ex officio*;

(h) the Director, National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Multiple Disabilities, Member, *ex officio*;

(i) the Managing Director, National Handicapped Finance Development Corporation, Member, *ex officio*;

(j) the Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing Corporation, Member, *ex officio*;

(k) the Director, Member, *ex officio*;

(l) the Director, Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, Member, *ex officio*;

(m) the Director, National Council for Educational Research and Training, Member, *ex officio*;

(n) the Director, National Council of Teacher Education, Member, *ex officio*;

(o) the Director, University Grants Commission, Member, *ex officio*;

(p) the Director, National Council of India, Member, *ex officio*;

(q) the following Institutes:—

(i) the Institute for the Visually Handicapped, Dehradun;

(ii) the Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad;

(iii) the Dayal Upadhyay Institute for the Physically Handicapped,

(iv) the Ali Jung National Institute for the Hearing Handicapped,

- (v) National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata;
- (vi) National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack;
- (vii) National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai;
- (viii) National Institute for Mental Health and Sciences, Bangalore;
- (ix) Indian Sign Language Research and Training Centre, New Delhi,

Members, *ex officio*;

(r) Members to be nominated by the Central Government,—

- (i) five Members who are experts in the field of disability and rehabilitation;
- (ii) ten Members, as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-Governmental Organisations concerned with disabilities or disabled persons organisations:

Provided that out of the ten Members nominated, at least, five Members shall be women and at least one person each shall be from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(iii) up to three representatives of national level chambers of commerce and industry;

(s) Joint Secretary to the Government of India dealing with the subject of disability policy, Member-Secretary, *ex officio*.

Terms and
conditions of
Service of
members.

61. (1) Save as otherwise provided under this Act, a Member of the Central Advisory Board nominated under clause (r) of sub-section (2) of section 60 shall hold office for a term of three years from the date of his nomination:

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) The Central Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under clause (r) of sub-section (2) of section 60, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) A Member nominated under clause (r) of sub-section (2) of section 60 may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

(4) A casual vacancy in the Central Advisory Board shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated.

(5) A Member nominated under sub-clause (i) or sub-clause (iii) of clause (r) of sub-section (2) of section 60 shall be eligible for renomination.

(6) The Members nominated under sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (r) of sub-section (2) of section 60 shall receive such allowances as may be prescribed by the Central Government.

Disqualifications.

62. (1) No person shall be a Member of the Central Advisory Board, who —

- (a) is, or at any time has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or
- (c) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or
- (d) is, or at any time has been, convicted of an offence under this Act, or
- (e) has so abused his position in the opinion of the Central Government as a Member so as to render his continuance in the office is prejudicial interests of the general public.

(2) No order of removal shall be made by the Central Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Notwithstanding as contained in sub-section (1) or sub-section (5) of section 61, a Member when elected under this section shall not be eligible for renomination as a Member.

63. If a Member of the Central Advisory Board becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 62, his seat shall become vacant.

64. The Board shall meet at least once in every six months and shall observe such procedure as may be prescribed regarding the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

65. (1) Subject to the provisions of this Act, the Central Advisory Board on disability shall be the national co-ordinating and advisory body on disability matters, and shall facilitate the formulation of a comprehensive policy for the empowerment of persons with disabilities in all spheres of rights.

(2) In pursuance of the foregoing provisions, the Central Advisory Board shall perform the following functions, namely:—

(a) to advise the Government and the State Governments on policies, programmes and projects with respect to disability;

(b) to frame a national policy to address issues concerning persons with disabilities;

(c) to coordinate the activities of all Departments of the Government and other Central Governmental Organisations which are dealing with matters relating to persons with disabilities;

(d) to co-ordinate persons with disabilities with the concerned authorities and the local organisations with a view to provide for schemes and projects for the persons with disabilities in the national plans;

(e) to ensure accessibility, reasonable accommodation, non-discrimination of persons with disabilities vis-à-vis information, services and the built environment and their participation in social life;

(f) to evaluate the impact of laws, policies and programmes to achieve full participation of persons with disabilities; and

(g) to perform such functions as may be assigned from time to time by the Central Government.

66. (1) The Government shall, by notification, constitute a body to be known as the State Advisory Board on disability to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned, under this Act.

(2) The Board shall consist of—

(a) one member of the Department in the State Government dealing with disabilities, *ex officio*;

(b) one member for the Deputy Minister in charge of the Department in the State Government dealing with disability matters, if any, Vice-Chairperson, *ex officio*;

(c) one member of the Government in charge of the Departments of Disability Affairs, Education, Literacy and Higher Education, Women and Child Development, Skill Development and Training, Health and Family Welfare, Rural Development, Industrial Policy and Promotion, Labour and Employment, Urban Development, Urban Poverty Alleviation, Science and Technology, Information Technology, Enterprises, Youth Affairs and Sports, Road Transport and any other department which the State Government considers necessary, Members, *ex officio*;

(d) members of the State Legislature of whom two shall be elected by the Legislative Assembly and one by the Legislative Council, if any, and where there is no Legislative Council, all the members shall be elected by the Legislative Assembly, Members.

Vacation of seats by Members.

Meetings of the Central Advisory Board on disability.

Functions of Central Advisory Board on disability.

State Advisory Board on disability.

(e) Members to be nominated by the State Government:—

(i) five Members who are experts in the field of disability and rehabilitation;

(ii) five Members to be nominated by the State Government by rotation to represent the districts in such manner as may be prescribed:

Provided that no nomination under this sub-clause shall be made except on the recommendation of the district administration concerned;

(iii) ten persons as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-Governmental Organisations or associations which are concerned with disabilities:

Provided that out of the ten persons nominated under this clause, at least, five shall be women and at least one person each shall be from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(iv) not more than three representatives of the State Chamber of Commerce and Industry;

(f) officer not below the rank of Joint Secretary in the Department dealing with disability matters in the State Government, Member-Secretary, *ex officio*.

Terms and conditions of service of Members.

67. (1) Save as otherwise provided under this Act, a Member of the State Advisory Board nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 66, shall hold office for a term of three years from the date of his nomination:

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) The State Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 66, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) A Member nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 66 may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the State Government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

(4) A casual vacancy in the State Advisory Board shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated.

(5) A Member nominated under sub-clause (i) or sub-clause (iii) of clause (e) of sub-section (2) of section 66 shall be eligible for renomination.

(6) the Members nominated under sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (e) of sub-section (2) of section 66 shall receive such allowances as may be prescribed by the State Government.

Disqualification.

68. (1) No person shall be a Member of the State Advisory Board, who—

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or

(c) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude, or

(d) is, or at any time has been, convicted of an offence under this Act, or

(e) has so abused in the opinion of the State Government his position as a Member as to render his continuance in the State Advisory Board detrimental to the interests of the general public.

(2) No order of removal shall be made by the State Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Notwithstanding contained in sub-section (1) or sub-section (5) of section 67, a Member elected under this section shall not be eligible for renomination as a Member.

69. If a Member of the State Advisory Board becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 68 his seat shall become vacant.

Vacation of seats.

70. The Board shall meet at least once in every six months and shall observe such order regarding the transaction of business at its meetings as may be prescribed in the State Government.

Meetings of State Advisory Board on disability.

71. (1) Under the provisions of this Act, the State Advisory Board shall be the State-level coordinating body on disability matters, and shall facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy for the empowerment of persons with disabilities and their rights.

Functions of State Advisory Board on disability.

(2) In pursuance of the provisions of the foregoing provisions, the State Advisory Board shall perform the following functions, namely:—

(a) Statement on policies, programmes, legislation and projects with respect to persons with disabilities;

(b) Statute to address issues concerning persons with disabilities;

(c) Coordination of the activities of all Departments of the State Government and other Governmental Organisations in the State which are dealing with persons with disabilities;

(d) Cooperation with persons with disabilities with the concerned authorities and the organisations with a view to provide for schemes and projects for the persons with disabilities in the State plans;

(e) To ensure accessibility, reasonable accommodation, non-discrimination of persons with disabilities, services and the built environment and their participation on an equal basis with others;

(f) To evaluate the impact of laws, policies and programmes designed to achieve the objectives of persons with disabilities; and

(g) To perform such other functions as may be assigned from time to time by the State Government.

72. The Government may constitute District-level Committee on disability to perform such functions as may be prescribed by it.

District-level Committee on disability.

73. Notwithstanding Central Advisory Board on disability, a State Advisory Board on disability and District Committee on disability shall be called in question on the ground merely on account of any vacancy in or any defect in the constitution of such Board or Committee as may be.

Vacancies not to invalidate proceedings.

CHAPTER XII

CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

74. (1) The Government may, by notification, appoint a Chief Commissioner for Persons with Disabilities (referred to as the "Chief Commissioner") for the purposes of this Act.

Appointment of Chief Commissioner and Commissioners.

(2) The Government may, by notification appoint two Commissioners to assist the Chief Commissioner and one of the Commissioners shall be a person with disability.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the Chief Commissioner or Commissioner unless he has special knowledge or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation.

(4) The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Chief Commissioner and Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government.

(5) The Central Government shall determine the nature and categories of officers and other employees required to assist the Chief Commissioner in the discharge of his functions and provide the Chief Commissioner with such officers and other employees as it thinks fit.

(6) The officers and employees provided to the Chief Commissioner shall discharge their functions under the general superintendence and control of the Chief Commissioner.

(7) The salaries and allowances and other conditions of service of officers and employees shall be such as may be prescribed by the Central Government.

(8) The Chief Commissioner shall be assisted by an advisory committee comprising of not more than eleven members drawn from the experts from different disabilities in such manner as may be prescribed by the Central Government.

Functions of
Chief
Commissioner.

75. (1) The Chief Commissioner shall—

(a) identify, *suo motu* or otherwise, the provisions of any law or policy, programme and procedures, which are inconsistent with this Act and recommend necessary corrective steps;

(b) inquire, *suo motu* or otherwise, deprivation of rights of persons with disabilities and safeguards available to them in respect of matters for which the Central Government is the appropriate Government and take up the matter with appropriate authorities for corrective action;

(c) review the safeguards provided by or under this Act or any other law for the time being in force for the protection of rights of persons with disabilities and recommend measures for their effective implementation;

(d) review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with disabilities and recommend appropriate remedial measures;

(e) study treaties and other international instruments on the rights of persons with disabilities and make recommendations for their effective implementation;

(f) undertake and promote research in the field of the rights of persons with disabilities;

(g) promote awareness of the rights of persons with disabilities and the safeguards available for their protection;

(h) monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes meant for persons with disabilities;

(i) monitor utilisation of funds disbursed by the Central Government for the benefit of persons with disabilities; and

(j) perform such other functions as the Central Government may assign.

(2) The Chief Commissioner shall consult the Commissioners on any matter while discharging its functions under this Act.

Action of
appropriate
authorities on
recommendation
of Chief
Commissioner.

76. Whenever the Chief Commissioner makes a recommendation to an authority in pursuance of clause (b) of section 75, that authority shall take necessary action on it, and inform the Chief Commissioner of the action taken within three months from the date of receipt of the recommendation:

Provided that where an authority does not accept a recommendation, it shall convey reasons for non-acceptance to the Chief Commissioner within a period of three months, and shall also inform the aggrieved person.

5 of 1908.	<p>Commissioner shall, for the purpose of discharging his functions under the powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—</p> <p>issuing process and enforcing the attendance of witnesses;</p> <p>compelling the discovery and production of any documents;</p> <p>examining any public record or copy thereof from any court or office;</p> <p>receiving evidence on affidavits; and</p> <p>causing the examination of witnesses or documents.</p>	Powers of Chief Commissioner.
45 of 1860.	<p>Proceedings before the Chief Commissioner shall be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Chief Commissioner shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Civil Procedure, 1908.</p>	
2 of 1974.	<p>The Commissioner shall submit an annual report to the Central Government and may also submit special reports on any matter, which, in his opinion, is of such urgent importance that it should not be deferred till submission of the annual report.</p> <p>The Government shall cause the annual and the special reports of the Chief Commissioner to be laid before each House of Parliament, along with a memorandum of action to be taken on his recommendations and the reasons for non-acceptance of his recommendations, if any.</p> <p>Special reports shall be prepared in such form, manner and contain such details as may be prescribed by the Central Government.</p> <p>The Government may, by notification, appoint a State Commissioner for Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the "State Commissioner") for the purposes of this Act.</p> <p>A person shall be qualified for appointment as the State Commissioner unless he has acquired practical experience in respect of matters relating to rehabilitation.</p> <p>The allowances payable to and other terms and conditions of service (including, but not limited to, pension and other retirement benefits) of the State Commissioner shall be such as may be prescribed by the State Government.</p> <p>The Government shall determine the nature and categories of officers and other employees to assist the State Commissioner in the discharge of his functions and provide the State Commissioner with such officers and other employees as it thinks fit.</p> <p>The officers and employees provided to the State Commissioner shall discharge his functions under the supervision and control of the State Commissioner.</p> <p>The allowances and other conditions of service of officers and employees shall be such as may be prescribed by the State Government.</p> <p>The Commissioner shall be assisted by an advisory committee comprising of not more than five members drawn from the experts in the disability sector in such manner as may be prescribed by the Government.</p> <p>The Commissioner shall—</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise, provision of any law or policy, programme or scheme, or any other measure, is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities or any other measure is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities or any other measure is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p>	Annual and special reports by Chief Commissioner.
	<p>The Commissioner shall—</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise, provision of any law or policy, programme or scheme, or any other measure, is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities or any other measure is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities or any other measure is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p>	Appointment of State Commissioner in States.
	<p>The Commissioner shall—</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise, provision of any law or policy, programme or scheme, or any other measure, is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities or any other measure is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p> <p>advise the Government, if <i>motu</i> or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities or any other measure is in consistent with this Act, and recommend necessary steps to be taken therefor;</p>	Functions of State Commissioner.

(c) review the safeguards provided by or under this Act or any other law for the time being in force for the protection of rights of persons with disabilities and recommend measures for their effective implementation;

(d) review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with disabilities and recommend appropriate remedial measures;

(e) undertake and promote research in the field of the rights of persons with disabilities;

(f) promote awareness of the rights of persons with disabilities and the safeguards available for their protection;

(g) monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes meant for persons with disabilities;

(h) monitor utilisation of funds disbursed by the State Government for the benefits of persons with disabilities; and

(i) perform such other functions as the State Government may assign.

Action by appropriate authorities on recommendation of State Commissioner.

81. Whenever the State Commissioner makes a recommendation to an authority in pursuance of clause (b) of section 80, that authority shall take necessary action on it, and inform the State Commissioner of the action taken within three months from the date of receipt of the recommendation:

Provided that where an authority does not accept a recommendation, it shall convey reasons for non-acceptance to the State Commissioner for Persons with Disabilities within the period of three months, and shall also inform the aggrieved person.

Powers of State Commissioner.

82. (1) The State Commissioner shall, for the purpose of discharging their functions under this Act, have the same powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

5 of 1908.

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(b) requiring the discovery and production of any documents;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(d) receiving evidence on affidavits; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(2) Every proceeding before the State Commissioner shall be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the State Commissioners shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

45 of 1860.

2 of 1974.

Annual and special reports by State Commissioner.

83. (1) The State Commissioner shall submit an annual report to the State Government and may at any time submit special reports on any matter, which, in its opinion, is of such urgency or importance that it shall not be deferred till submission of the annual report.

(2) The State Government shall cause the annual and the special reports of the State Commissioner for persons with disabilities to be laid before each House of State Legislature where it consists of two Houses or where such Legislature consist of one House, before that House along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendation of the State Commissioner and the reasons for non-acceptance the recommendations, if any.

(3) The annual and special reports shall be prepared in such form, manner and contain such details as may be prescribed by the State Government.

CHAPTER XIII

SPECIAL COURT

86. For providing speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the High Court, by notification, specify for each district, a Court to be a Special Court to try the offences under this Act.

Special Court.

87. Every Court, the State Government may, by notification, specify a Public Prosecutor or an advocate, who has been in practice as an advocate for not less than five years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.

Special Public Prosecutor.

(1) A Special Prosecutor appointed under sub-section (1) shall be entitled to receive remuneration as may be prescribed by the State Government.

CHAPTER XIV

NATIONAL FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

88. There shall be constituted a Fund to be called the National Fund for persons with disabilities, the amount of which shall be credited thereto—

National Fund for persons with disabilities.

(a) the sum payable under the Fund for people with disabilities, constituted by the Government of India by Notification O. 573 (E), dated the 11th August, 1983 and the Trust Fund for Persons with Disabilities, constituted vide notification No. 30-03/2006 dated 21st November, 2006, under the Charitable Endowment Act, 1890.

6 of 1890.

(b) the sum payable by banks, corporations, financial institutions in pursuance of the order dated 6th April, 2004 of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 5 of 2000;

(c) the sum received by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequests or other contributions;

(d) the sum received from the Central Government including grants-in-aid;

(e) the sum from such other sources as may be decided by the Central Government.

(2) The funds with disabilities shall be utilised and managed in such manner as may be prescribed.

89. The Government shall maintain proper accounts and other relevant records and an annual statement of accounts of the Fund including the income and expenditure thereon in form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

Accounts and audit.

(3) The Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or any person authorised by him and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable from the Fund to the Comptroller and Auditor-General of India.

(4) The Comptroller and Auditor-General of India and any other person appointed by him in connection with such audit shall have the same rights, privileges and immunities in connection with the audit of the Government accounts, and in particular the right to demand production of books of account, connected vouchers and documents and to inspect any of the offices of the Fund.

(5) The Fund as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be laid before the House of Parliament by the Central Government.

CHAPTER XV

STATE FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

State Fund for persons with disabilities.

88. (1) There shall be constituted a Fund to be called the State Fund for persons with disabilities by a State Government in such manner as may be prescribed by the State Government.

(2) The State Fund for persons with disabilities shall be utilised and managed in such manner as may be prescribed by the State Government.

(3) Every State Government shall maintain proper accounts and other relevant records of the State Fund for persons with disabilities including the income and expenditure accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(4) The accounts of the State Fund for persons with disabilities shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable from the State Fund to the Comptroller and Auditor-General of India.

(5) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the State Fund for persons with disabilities shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India generally has in connection with the audit of the Government accounts, and in particular, shall have right to demand production of books of accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the State Fund.

(6) The accounts of the State Fund for persons with disabilities as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be laid before each House of the State Legislature where it consists of two Houses or where such Legislature consists of one House before that House.

CHAPTER XVI

OFFENCES AND PENALTIES

Punishment for contravention of provisions of Act or rules or regulations made thereunder.

Offences by companies.

89. Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or of any rule made thereunder shall for first contravention be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and for any subsequent contravention with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees.

90. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanatory of this section,—

(a) 'mea body corporate and includes a firm or other association of individuals

(b) 'in reto a firm, means a partner in the firm.

91. Whoever entls or attempts to avail any benefit meant for persons with benchmark disabilities, shpunishable with imprisonment for a term which may extend to two ye fine may extend to one lakh rupees or with both.

Punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with benchmark disabilities.

92. Whoever

Punishment for offences of atrocities.

(a) intimidates with intent to humiliate a person with disability in public view;

(b) abuses to any person with disability with intent to dishonour him or outcast woman with disability;

(c) hltuige or control over a person with disability voluntarily or knowingly does to him or her;

(d) betitominates the will of a child or woman with disability and uses that poxpcsexually;

(e) vtjurages or interferes with the use of any limb or sense or any support of an with disability;

(f) pendirects any medical procedure to be performed on a woman with whids to or is likely to lead to termination of pregnancy without her nserpt in cases where medical procedure for termination of pregnancy n senses of disability and with the opinion of a registered medical prand ith the consent of the guardian of the woman with disability,

shall be punishable isorfor a term which shall not be less than six months but which may extend rs ah fine.

93. Whoeverodu book, account or other documents or to furnish any statement, informaticuhich, under this Act or any order, or direction made or given thereunder, undoduce or furnish or to answer any question put in pursuance of the pf this or any order, or direction made or given thereunder, shall be punishable whiv extend to twenty-five thousand rupees in respect of each offence, and ontailure or refusal, with further fine which may extend to one thousand ru ch dcontinued failure or refusal after the date of original order imposing pu f fin

Punishment for failure to furnish information.

94. No Court cognie of an offence alleged to have been committed by an employee of the ap over under this Chapter, except with the previous sanction of the appropriate nt oplaint is filed by an officer authorised by it in this behalf.

Previous sanction of appropriate Government.

95. Where a nissnstitutes an offence punishable under this Act and also under any oth or Sct, then, notwithstanding anything contained in any other law for the tin foroffender found guilty of such offence shall be liable to punishment only h Arovides for punishment which is greater in degree.

Alternative punishments.

CHAPTER XVII

MISCELLANEOUS

Application of other laws not barred.

96. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

Protection of action taken in good faith.

97. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the appropriate Government or any officer of the appropriate Government or any officer or employee of the Chief Commissioner or the State Commissioner for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Power to remove difficulties.

98. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be, after it is made, before each House of Parliament.

Power to amend Schedule.

99. (1) On the recommendations made by the appropriate Government or otherwise, if the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the Schedule and any such notification being issued, the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(2) Every such notification shall, as soon as possible after it is issued, shall be laid before each House of Parliament.

Power of Central Government to make rules.

100. (1) The Central Government may, subject to the condition of previous publication, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the manner of constituting the Committee for Research on Disability under sub-section (2) of section 6;

(b) the manner of notifying the equal opportunity policy under sub-section (1) of section 21;

(c) the form and manner of maintaining records by every establishment under sub-section (1) of section 22;

(d) the manner of maintenance of register of complaints by grievance redressal officer under sub-section (3) of section 23;

(e) the manner of furnishing information and return by establishment to the Special Employment Exchange under section 36;

(f) the composition of the Assessment Board under sub-section (2) and manner of assessment to be made by the Assessment Board under sub-section (3) of section 38;

(g) rules for person with disabilities laying down the standards of accessibility under section 40;

(h) the manner of application for issuance of certificate of disability under sub-section (1) and form of certificate of disability under sub-section (2) of section 58;

(i) the allowances to be paid to nominated Members of the Central Advisory Board under sub-section (6) of section 61;

(j) the rules of procedure for transaction of business in the meetings of the Central Advisory Board under section 64;

(k) the allowances and other conditions of services of Chief Commissioners under sub-section (4) of section 74;

(l) the allowances and conditions of services of officers and staff of the Chief Commissioner sub-section (7) of section 74;

(m) the manner of appointment of experts in the advisory committee sub-section (3) of section 74;

(n) the content of annual report to be prepared and submitted by the Commissioner sub-section (3) of section 78;

(o) the mode of utilisation and management of the Fund under sub-section (1) of section 87;

(p) the preparation of accounts of Fund under sub-section (1) of section 87.

(3) Every Bill shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House when it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which the Bill is so laid, or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the Bill should not be made, it shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the Houses may decide; provided that any such modification or annulment shall be without prejudice to any Bill previously passed under that rule.

101. (1) The Government may, subject to the condition of previous publication, by notification, modify or vary the provisions of this Act, not later than six months from the commencement of this Act.

Power of State Government to make rules.

(2) In pursuance of the powers conferred by the foregoing provisions, such rules may provide for the following matters, namely:—

(a) the constitution of the Committee for Research on Disability under sub-section (1) of section 10;

(b) the grant of support of a limited guardian under sub-section (1) of section 11;

(c) the manner of making an application for certificate of registration under sub-section (1) of section 51;

(d) the conditions and standards to be met by institutions for grant of certificate of registration under sub-section (3) of section 51;

(e) the form of certificate of registration, the form of, and conditions attached to, certificate of registration under sub-section (4) of section 51;

(f) the form of application for certificate of registration under sub-section (1) of section 51;

(g) the manner in which an appeal to be made under sub-section (1) of section 53;

(h) the manner of appealing against the order of certifying authority under sub-section (1) of section 59; and the manner of disposal of such appeal under sub-section (2) of section 59;

(i) the manner of nomination of Members of the State Advisory Board under sub-section (1) of section 67;

(j) the manner of transaction of business in the meetings of the State Advisory Board under sub-section (1) of section 67;

(k) the manner of actions of District Level Committee under section 72;

(l) salaries, allowances and other conditions of services of the State Commissioner under sub-section (3) of section 79;

(m) the salaries, allowances and conditions of services of officers and staff of the State Commissioner under sub-section (3) of section 79;

(n) the composition and manner of appointment of experts in the advisory committee under sub-section (7) of section 79;

(o) the form, manner and content of annual and special reports to be prepared and submitted by the State Commissioner under sub-section (3) of section 83;

(p) the fee or remuneration to be paid to the Special Public Prosecutor under sub-section (2) of section 85;

(q) the manner of constitution of State Fund for persons with disabilities under sub-section (1), and the manner of utilisation and management of State Fund under sub-section (2) of section 88;

(r) the form for preparation of accounts of the State Fund for persons with disabilities under sub-section (3) of section 88.

(3) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such State Legislature consists of one House, before that House.

Repeal and savings.

102. (1) The Persons with Disabilities (Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 is hereby repealed. 1 of 1996.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Act, anything done or any action taken under the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 up to 10 degree.

aringment—

(a) 'means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in ea

(b) 'f hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in n fries in both ears;

eeelanguage disability" means a permanent disability arising out of cchyngectomy or aphasia affecting one or more components of slangue to organic or neurological causes.

2al dty, a condition characterised by significant limitation both in intelconironing, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which age cy day, social and practical skills, including—

becirning disabilities" means a heterogeneous group of conditions ve is:it in processing language, spoken or written, that may manifest iffic comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical cs anudes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, cdysa, dyspraxia and developmental aphasia;

utisrum disorder" means a neuro-developmental condition typically al thethree years of life that significantly affects a person's ability to cie, uand relationships and relate to others, and is frequently associated vior spical rituals or behaviours.

3hav-

al il means a substantial disorder of thinking, mood, perception, or mthat grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise ralityt the ordinary demands of life, but does not include retardation vnditrrested or incomplete development of mind of a person, specially cel byrmality of intelligence.

4) caue to—

roniological conditions, such as—

(i) "le sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in the 1 sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal re dd, leading to demyelination and affecting the ability of nerve n the and spinal cord to communicate with each other;

(ii) nson's disease" means a progressive disease of the nervous a may tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly ing r-aged and elderly people associated with degeneration of the gangthe brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

ood er—

(i) "bphilia" means an inheritable disease, usually affecting only out titted by women to their male children, characterised by loss or emene normal clotting ability of blood so that a minor would may sin fæding;

(ii) isemia" means a group of inherited disorders characterised by d out amounts of haemoglobin.

(iii) e cell disease" means a hemolytic disorder characterised by c ar painful events, and various complications due to associated

THE SCHEDULE

[See clause (zc) of section 2]

SPECIFIED DISABILITY

1. Physical disability.—

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditons, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

and damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell
and blood cells resulting in the release of hemoglobin.

Multiple (more than one of the above specified disabilities) including
deafness means a condition in which a person may have combination of
hearing impairments causing severe communication, developmental, and
educational problems.

Category as may be notified by the Central Government.

DR. G. NARAYANARAJU,
Secretary to the Govt. of India.

5

अध्याय

निशक्तता प्रमाणपत्रों का मुद्दा

दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 उन दिव्यांगजनों के लिए कुछ लाभों की व्यवस्था करता है जो, एक चिकित्सा प्रभारी द्वारा प्रमाणित किए अनुसार, 40 प्रतिशत से कम किसी प्रकार की निशक्तता नहीं रखते हैं। इस प्रकार, एक निशक्तता वाला ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के तहत लाभांश लेने की कामना करता है को उद्देश्य हेतु अधिसूचित चिकित्सा प्रभारी से एक निशक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ता है। प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

निशक्तजनों से प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। 20.01.2017 को जनगणना 2011 की तुलना में निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने की तुलनात्मक राज्यवार स्थिति अनुबंध-3 (पृष्ठ 189) पर दी गई है। 20.01.2017 को दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त के कार्यालय से उपलब्ध डाटा के अनुसार 55.57 प्रतिशत दिव्यांगजनों को 2011 जनगणना के अनुसार निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

6

अध्याय

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं

6.1 विकलांगजन ए रय नीति, 2006

यह मानते हुए कि अंगरक्ष के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास मिले तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं, सरकार ने, उनकी रक्षण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समान भागीदारी प्रदान कर सके, विकलांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार और प्रकाशित की।

विकलांगता रोकने वाले पुनर्उपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

I. विकलांगता

II. पुनर्वास

क. शारीरिक क्षमता:

- शारीरिक परीक्षण और हस्तक्षेप करना
- शारीरिक क्षमता पुनर्वास
- शारीरिक क्षमता
- शारीरिक क्षमताओं का विकास

ख. विकलांगता

ग. विकलांगता के पुनर्वास

- शारीरिक क्षमताओं में नियोजन
- क्षेत्रीय श्रमिक आधारित रोजगार
- रोजगार

- III. विकलांग महिलाओं के लिए प्रावधान
- IV. विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान
- V. बाधामुक्त परिवेश
- VI. विकलांगता प्रमाणपत्र का निर्गम
- VII. सामाजिक सुरक्षा
- VIII. गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन
- IX. विकलांगजनों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन
- X. अनुसंधान
- XI. खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन
- XII. विकलांगजनों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तदनुसार, इस नीति के अंतर्गत हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र हैं: रोकथाम, जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप, पुनर्वास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, विकलांगजनों की शिक्षा, नियोजन, बाधारहित परिवेश, सामाजिक संरक्षण, अनुसंधान, खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं :

- i) इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।
- ii) पणधारकों के प्रतिनिधित्व वाली केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।
- iii) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, युवा कार्य एवं खेलकूद, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, श्रम, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, लोक उद्यम, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों की भी पहचान की गयी है।
- iv) पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

- v) विकलांगों के केन्द्र स्तर पर मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी सांविधिक अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

6.2 विकलांगजनो के संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, 2006

यह संधिपत्र 13/200 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को राष्ट्र पक्षों द्वारा हस्ताक्षर। इस संधिपत्र के अंगीकरण ने विकलांगजनों को पूरे विश्व में अपने अधिकारों की मांग करने और अधिक लाभ उठाने के लिए राज्य, निजी और नागरिक समाज की एजेंसियों को जवाबदेह बनाने में मदद किया है।

भारत कुछ चुनिंदा देशों में एक है, जिसने इस संधिपत्र की अभिपुष्टि की है। 30 मार्च 2007 को भारत द्वारा संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने और बाद में इसकी अभिपुष्टि किए जाने के परिणामस्वरूप देश में यह कानून 3 मई 2007 को लागू हुआ। यह संधिपत्र प्रत्येक राष्ट्र पक्ष को निम्नलिखित तीन दायित्व देता है:

- क. संधिपत्र के कार्यान्वयन,
- ख. देश के कानून के अनुकूल बनाना और
- ग. राष्ट्रपति

इस संधिपत्र के कार्यान्वयन के लिए ठोस उपाय करते हुए, सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से इस संधिपत्र के प्रावधानों में से प्रत्येक पर लागू हो, कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया। उनसे संबंधित करने वाले व्यक्तित्व, जो उन पर लागू हैं और उनसे संबंधित हैं। 15 महिलाओं एवं बच्चों पर ध्यान केन्द्रित एकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा मंत्रालयों से उन विधानों और आदेशों की पहचान, जिस संधिपत्र के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में संशोधन करना अपेक्षित है, और अपेक्षित संशोधन के लिए शुरु करने का भी अनुरोध किया गया।

इसी प्रकार, सभी मंत्रालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से भी इस संधिपत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों / दायित्वों, जिसे संबंधित हो सकते हैं, जांच करने और उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से, इस संबंध में स्थिति प्रतिवेदन के लिए कहा गया ताकि उनका उपयोग राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करने में किया जा सके। इस संधिपत्र को पूर्ण करने के लिए इस संबंध में कड़ी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

इस संधिपत्र के दायित्वों, कि प्रत्येक राष्ट्र पक्ष को संधिपत्र लागू होने के दो वर्षों के पश्चात राष्ट्र रिपोर्ट प्रस्तुत है, गुरुप राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित कदम भी उठाए गए। पहली राष्ट्र रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए अप्रैल, 2010 में, विकलांगता अध्ययन केन्द्र, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद में आयोजित किया गया। तदनुसार, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों / संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों और राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों/जानकारियों को विधिवत शामिल करते हुए राष्ट्र रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया गया। इस प्रारंभिक मसौदे पर जनवरी, 2012 में, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में और बाद में मार्च, 2012 में नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में विधिवत चर्चा की गयी।

विचार विमर्श, टिप्पणियों इत्यादि के आधार पर नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा राष्ट्र रिपोर्ट का एक संशोधित मसौदा तैयार किया गया, जिसकी विदेश मंत्रालय (विधि एवं संधि प्रभाग और यूएनईएस प्रभाग) के परामर्श से इस विभाग में विधिवत जांच की गयी। विदेश मंत्रालय के सलाह के आधार पर जनवरी, 2014 में मसौदा राष्ट्र रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा सुझाए गए और परिवर्तनों को इस रिपोर्ट में शामिल करने के बाद इस रिपोर्ट को पुनरीक्षण हेतु विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया। राष्ट्र रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। बाद में, राष्ट्र रिपोर्ट नवंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र व्यक्ति अधिकार समिति को प्रस्तुत कर दी गई है।

सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने जून, 2016 में आयोजित दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में भाग लिया। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में की गई प्रगति से संयुक्त राष्ट्र निकाय को सूचित कर दिया गया था।

7

अध्याय

विभाग के अंतर्गत सांविधिक निकाय

7.1 दिव्यांगजन आयुसीसीपीडी)

7.1.1 सिंह

विकलांगजनों के आयुक्त कार्यालय की स्थापना, निशक्त (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत की गयी है। मुख्य आयुक्त को विकलांगजनों के लिए राज्य आयुक्तों के कमिन्केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग पर निगरानी और विकलांगजनों को उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए उपाय करने के कार्य सौंपे गए हैं। मुख्य अपवप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर अथवा अन्यथा विकलांगजनों को या अथवा विकलांगजनों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए जा जारी किए गये, नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों इत्यादि के कार्यान्वयन नहीं संबंधितों की जांच करते हैं और संबंधित प्राधिकारियों से मामले को उठाते हैं। विकलांगजनों के आयुक्त तरह की किसी भी गैर अनुपालन की अपनी ओर से भी नोटिस ले सकते हैं और संबंधित प्रश्न को उठा सकते हैं। विकलांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को अपना कार्य प्रभावी ढंग से काम के लिए एक सिविल कोर्ट की कतिपय शक्तियां दी गयी हैं।

7.2 ऑटिज्म, प्रमंअंग, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ

7.2.1 प्रस्ता

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1995 के अंतर्गत, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ के लिए एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार

- (i) विकलांगों को तापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकटोपन में समर्थ और सशक्त बनाना
- (ii) विकलांगों के अचय के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

- (iii) विकलांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।
- (iv) विकलांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।
- (v) विकलांगजनों के माता-पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।
- (vi) जिन विकलांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरूरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।
- (vii) विकलांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।
- (viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो मूलभूत कर्तव्यों— विधिक और कल्याण को निभाने के लिए की गई है। विधिक कर्तव्य स्थानीय स्तर समिति के माध्यम से और विधिक अभिभावकत्व प्रदान करके निभाए जाते हैं। कल्याण कर्तव्य स्कीमों के माध्यम से निभाए जाते हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा आश्रय, देख-रेख प्रदान करना एवं सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत विकलांगजन को समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.2.1.1 संगठनों का पंजीकरण—

राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, विकलांगजनों के संघ और विकलांगजनों के माता-पिता के संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। नई स्कीम प्रबंधन प्रणाली में देश में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 425 पंजीकृत संगठन हैं।

7.2.1.2 स्थानीय स्तर समिति

राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत, एक स्थानीय स्तर समिति देश के प्रत्येक जिले में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, गठित की जानी अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं हो।
- राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि और
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित विकलांगजन

स्थानीय स्तर पर अधिक संरक्षकों की जांच, नियुक्ति और निगरानी करना है। स्थानीय स्तर समिति जागरूक, अण और विकलांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किए जाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित है। तब, देश के लगभग सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) को शामिल करते हुए स्थानीय समितियां गठित की जा चुकी हैं।

7.2.1.3 विधिवत कृति

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 धारा 14-17 स्थानीय स्तर समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुरि से व्यक्तियों को दिए जाने वाले संरक्षण की व्याख्या करती है। संरक्षण एक आवश्यकता आर्थिकवधान है। संरक्षण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है-

1. अनुरोधवादेखभाल
2. अचल प्र
3. चल संबंध
4. कोई

7.2.1.4 राज्य जेंस्र (एसएनएसी)

राज्य स्तर पर भावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के कार्यान्वयन और राज्य सरकाराधन्व करने एवं संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित एंनोडल अभिकरण केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में देश में एसएनएसी हैं और इसकी सूची हमारे वेबसाइट लिंक http://www.thetrust.in/content/registered_organization.php पर दी गई है। राष्ट्रीय न्यास, संस्थागतियां, यथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ बैठक कर एन के साथ नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के बैठक, के लिए निधि प्रदान करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान जनवरी, 2017 तक 15,61 रूपराशि एसएनएसी को जारी की गई है।

7.2.1.5 राज्य संय ते (एसएलसीसी)

राष्ट्रीय न्यास स्वावीन्वयन एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य स्तरीय समिति करने का अनुरोध किया गया है। विकलांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य में सके अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होते हैं। अबतक 26 राज्यों / संघों में एलसीसी का गठन कर दिया गया है।

7.2.2 राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्य गतिविधियां :-

- (i) **दिशा (शीघ्र हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी स्कीम)**— यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल चार निःशक्तताओं वाले 0-10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक शीघ्र हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी स्कीम है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से विकलांगजनों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। आरओ द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ-साथ दिन में कम से कम 4 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) विकलांगजनों के लिए दिवस-देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्र में देखभालकर्ता और आयाओं के अलावा विकलांगजनों के लिए एक विशेष शिक्षक या शीघ्र हस्तक्षेप उपचारकर्ता, फीजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए।

संशोधित शीघ्र हस्तक्षेप स्कीम में, पूर्व स्कीम में यथाउल्लिखित 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के स्थान पर 0-10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किए जाने का उपबंध होगा। स्थापना लागत 50,000 रुपये से बढ़कर 1.55 लाख रुपए की गई है।

इसमें 80 दिशा केन्द्र हैं जिनमें 2,11,81,552 /—रुपए जारी किए गए हैं। इसमें 47 केन्द्रों की स्वीकृति और 2016-17 के दौरान 16.01.2016 तक 1,60,66,552 /—रुपए की निर्मुक्ति शामिल है।

- (ii) **विकास (दिवस-देखभाल)** — यह विकलांगजनों के लिए, जब कि वे उच्चतर आयु वर्गों में शामिल होने की स्थिति में हों, अंतर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढ़ाने हेतु मुख्यतया उन्हें उपलब्ध अवसरों के दायरे को बढ़ाने के लिए एक दिवस-देखभाल स्कीम है। जिस समय के दौरान विकलांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस-देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगजनों के परिवार के सदस्यों को अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए समर्थन देने में भी मदद करता है। आरओ द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ-साथ दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) विकलांगजनों के लिए दिवस-देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दिवस-देखभाल सुविधा एक माह में कम से कम 21 दिन खुली होनी चाहिए।

इसमें 95 केन्द्र हैं जिनमें 4,61,79,806 /—रुपए जारी किए गए हैं। इसमें 67 केन्द्रों की स्वीकृति और 2016-17 के दौरान 16.01.2016 तक 4,09,14,806 /—रुपए की निर्मुक्ति शामिल है।

- (iii) **समर्थ (राहत देखभाल)** — समर्थ स्कीम का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फंसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के दायरे में आने वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित विकलांगजनों को राहत गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। यह स्कीम सभी आयु वर्गों के लिए, पेशेवर चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण

देखभालाहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना करने का भी उद्देश्य।

संशोषिकेन्त्र का प्रावधान होगा। प्रति लाभार्थी मासिक आवर्ती लागत को 1600 प्रतिमाह कर दिया गया है। यह स्कीम क्रमिक-ह्रास (टेपरिंग) अनुदान के स्थान पर लिपयता रखेगी।

इसमें केन्त्रेनमें 1,61,70,479 /—रुपए जारी किए गए हैं। इसमें 19 केन्द्रों की स्वीकृति और 2 के 16.01.2016 तक 1,08,50,479 /—रुपए की निर्मुक्ति शामिल है।

- (iv) **घरों की होमूहिक गृह) —** घरोंदा स्कीम का उद्देश्य ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अहुविकलांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और पेशेवर चिकित्सा मू चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गैर सेवा वाली न्यूनतम देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। घरोंदा केन्द्र द्वारा व्यावस्थित पूर्व-व्यावसायिक गतिविधियां और आगे प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाेगी।

संशोषि स्में निम्न आय वर्ग (बीपीएल समेत) और निम्न आय वर्ग से ऊपर के विकलांगों प्रीकृत संगठनों के भुगतान आधारित सीटें होंगी) के लिए 5:1 के स्थान पर 1:1 के होगलाख रुपये प्रति निःशक्तजन के एककालिक भुगतान के स्थान पर 10,000 रुपये शक्तकी मासिक आवर्ती निधि होगी। इसके अलावा, 2.50 लाख रुपये की एककमापधे, 10 लाख रुपये की संकट निधि और 25,000 से 1,00,000 रुपये तक की कार्य रूना ाधि होगी।

इसमें के जिनमें 2,33,80,000 /— रुपए जारी किए गए हैं। इसमें 23 केन्द्रों की स्वीकृति 16-के दौरान 16.01.2016 तक 1,99,00,000 /—रुपए की निर्मुक्ति शामिल है।

- (v) **निराम्थ्य स्कीम—** यह स्कीम ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकी व्यक्तियों को वहनीय स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए है। नामांकित लाभार्थी शुल्दा करके 1.0 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त करते हैं। शुल्क ढांचा शोफिया गया था जो नीचे दिया गया है:—

नामांकन एवं नवीकरण शुल्क

दिव्यांगजन श्रेणी	नामांकन शुल्क (रु० में)	नवीकरण शुल्क (रु० में)
बीपीएल	रु. 250/-	रु. 50/-
गैर बीपीएल	रु. 500/-	रु. 250/-
वैधानिक अभिभावक वाले पीडब्ल्यूडी (प्राकृतिक रूप से अन्य)	निशुल्क	निशुल्क

वे शीर्ष जिनके तहत लाभार्थी लाभ उठा सकता है (लाभ चार्ट) नीचे दिए अनुसार है :-

निरामय* स्वास्थ्य बीमा स्कीम संशोधित लाभ चार्ट				
(अप्रैल, 2015 से केवल प्रतिपूर्ति आधार पर)				
खंड	उप खंड	ब्यौरा	उपसीमा	खंड की समग्र सीमा
I	चिकित्सा की समग्र सीमा			रु. 70,000/-
	A	आकस्मिक निशक्तता सहित विद्यमान निशक्तता के लिए सुधारात्मक सर्जरियां	रु. 40,000/-	
	B	गैर-सर्जिकल / चिकित्सा	रु.15,000/-	
	C	निशक्तता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सर्जरी	रु.15,000/-	
II	ओपीडी के लिए समग्र सीमा			रु. 14,500/-
	A	ओपीडी उपचार औषधियां लैब डायग्नोस्टिक जांच सहित	रु.8,000/-	
	B	नॉन आइलिंग डिसेबल के लिए नियमित चिकित्सा जांच	रु. 4,000/-	
	C	दंत संरक्षण डेंटिस्ट्री	रु. 2,500/-	
III	निशक्तता के प्रभाव, निशक्तता संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए चल रही थेरेपियां			रु. 10,000/-
IV	वैकल्पिक औषधि			रु. 4,500/-
V	परिवहन लागतें			रु. 1,000/-
एक व्यक्ति के लिए कवरेज की समग्र सीमा रु. 1,00,000/-				

2016-17 के दौरान 20% स्कीम के तहत कुल व्यय 2,54,31,309/- रु. है।

- vi) **सहयोगी प्रशिक्षण स्कीम)** — इस योजना का उद्देश्य विकलांगजनों और उनके परिवारों के लिए आवश्यकता होती है, पर्याप्त और पोषक देखभाल प्रदान करने के लिए डॉक्टरों की प्रशिक्षण प्रदान करने और एक इनका एक कौशल युक्त कार्यबल बनाने हेतु देखभाल को सीजीसी की स्थापना करना है। यह माता-पिताओं को, यदि वे चाहें, देखभाल के वं प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करता है। यह स्कीम ऐसे डॉक्टरों बनाने के लिए, जो विकलांगजनों के परिवारों तथा विकलांगजनों की जरूरत वाली अन्य संस्थाओं (गैर-सरकारी संगठनों, कार्य केन्द्रों इत्यादि) दोनों के साथ सकारात्मक हों, प्राथमिक और उच्च दो स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विनियमन करता है।

प्राथमिक रूप से 4,200 प्रति प्रशिक्षक की और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 8,000 रुपये की प्रशिक्षण लागत है। साथ ही, इस स्कीम में प्राथमिक के लिए 5000 रुपये और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 1 रुपये की दर से प्रशिक्षकों हेतु अध्येतावृत्ति को भी लागू किया गया है।

इसमें अभी स्वीकृत किए गए हैं और 2016-17 के दौरान 16.01.2016 तक 31,000 रुपये की लागत शामिल है।

- vii) **ज्ञान सहायता)**— ज्ञान प्रभा स्कीम ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविध विकारों को स्नातक पाठ्यक्रमों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षणों का, डिजाइन रोजगार मिलता है, अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय न्यास योजना प्रति पाठ्यक्रम एक विशिष्ट धनराशि प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत सामान, कपड़े, पुस्तकें, स्वयं वहनीय खर्च (ओपीई) इत्यादि आएंगे।

संशोधन में, व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल विकास पाठ्यक्रमों के स्थान पर अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों को चलाया गया है। संशोधित स्कीम में, 1000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर विशेषज्ञों के नियत आवर्ती राशि होगी जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम शुल्क, परिवहन, पुस्तकें और शामिल होंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1600 रुपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह होंगे। इसी प्रकार, पेशेवर पाठ्यक्रम के लिए 1600 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति की उच्चतम राशि भत्ता होगा।

2016-17 के दौरान 1.2016 तक इस स्कीम के तहत 6 दिव्यांगजनों को 88,416/- रुपये की लागत निर्मित हैं।

- viii) **प्रेरणा (विपणन सहायता)** – प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की एक विपणन सहायता स्कीम है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और सेवाओं के विक्रय के लिए व्यवहार्य और व्यापक चैनलों का सृजन करना है। यह स्कीम विकलांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शनियों, मेलों, इत्यादि जैसे आयोजनों में भाग लेने के लिए निधियां प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह स्कीम विकलांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विक्रय टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत संगठनों (आरओ) को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय न्यास विकलांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं के विपणन और विक्रय के लिए मेलों, प्रदर्शनियों, इत्यादि जैसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के आयोजनों में आरओ की प्रतिभागिता के लिए निधियां प्रदान करेगा। किंतु, इन कार्य केन्द्रों के कम से कम 51 प्रतिशत कर्मचारी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगजन होने चाहिए।

इसमें 2016-17 के दौरान 2 प्रेरणा केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

- ix) **सम्भाव (सहायक यंत्र और सहायक डिवाइसें)**– यह युक्तियों के प्रदर्शन के प्रावधान के साथ विकसित सहायताओं, सॉफ्टवेयर तथा अन्य प्रकार की सहायक युक्तियों की तुलना और संग्रहण करने के लिए 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले (2011 की जनगणना के अनुसार) देश के प्रत्येक नगर में एक-एक अतिरिक्त संसाधन केन्द्र स्थापित करने की स्कीम है। इस स्कीम में, राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट पर, संभव केन्द्र पर उपलब्ध सहायताओं और सहायक युक्तियों से संबंधित सूचनाओं का रखरखाव किया जाना भी शामिल है। इन केन्द्रों का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास की निःशक्तताओं वाले विकलांगजनों की खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए सूचनाएं प्रदान करना और युक्तियों, उपकरणों, सहायताओं, सॉफ्टवेयर इत्यादि को आसानी से उपलब्ध कराना है। पूर्व में, दिल्ली में एक गैर-सरकारी संगठन को संभव केन्द्र चलाने के लिए पहचाना गया था। अब, इसे स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है।

अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक एनजीओ सम्भाव केन्द्र चलाने के लिए अभिज्ञात किया गया था। अब यह स्कीम में परिवर्तित किया गया है।

- x) **बढ़ते कदम (जागरूकता और सामुदायिक विचार-विमर्श)**– यह स्कीम राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) को ऐसी गतिविधियां करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास विकलांगताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित हों। स्कीम का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, संवेदीकरण, विकलांगजनों का सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। राष्ट्रीय न्यास प्रति वर्ष प्रत्येक आरओ के लिए अधिकतम 4 आयोजन को प्रायोजित करेगा। प्रत्येक आरओ को एक वर्ष में कम से कम 1 आयोजन (समुदाय, शैक्षिक संस्थाओं या चिकित्सा संस्थानों के लिए) अवश्य करना चाहिए।

बढ़ते कदम पहले राष्ट्रीय न्यास की एक पहल थी जिसे अब एक स्कीम में बदल दिया गया है।

इसमें 81 आरओ स्कीम में पंजीकृत किए गए हैं। स्कीम के तहत कुल व्यय 62,55,742/- रूपए है।



आयोजक शुभ आरंभ करते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत

7.2.3 बजट और

वर्ष 2016-17 के लिए न्याय का बजट 34.19 करोड़ रुपये है। इसमें से 24.19 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आयोगों से मिलेंगे और 10.00 करोड़ रुपये एसएफसी द्वारा यथा अनुमोदित विकलांग विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से मिलने प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय इतिहास के दौरान अब तक 4.50 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया है। 2016-17 में 1016 तक राष्ट्रीय ट्रस्ट ने 14.46 करोड़ रु० का व्यय किया है।

7.2.4 राष्ट्रीय अन्तर्विधियां

- (i) 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला – आईएनसीएलईएन

न्याय 31 अगस्त, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ऑटिज्म प्रशिक्षण पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। माननीय राज्य मंत्री (एसजेएंडई) श्री गुरी उपस्थिति में माननीय मंत्री (एसजेएंडई) श्री थावरचंद गेहलोत द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान, प्रशिक्षण के लिए मॉडलों के ऑटिज्म पर 03 पुस्तकें माननीय मंत्री (एसजेएंडई) द्वारा प्रारंभ की गई।

प्रोफेसर एमसी मिश्रा, निदेशक, एआईआईएमएस और प्रो0 वीके पाल, पीडियाट्रिक्स विभाग के अध्यक्ष भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए और यह पहल करने के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रयास की सराहना की। प्रो0 मिश्रा ने राष्ट्रीय ट्रस्ट और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ उनके जुड़ाव एवं लंबी अवधि सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत ने कार्यशाला में उत्शुक्ता के साथ रुचि ली और प्रशिक्षण सत्र के दौरान 01 सितंबर, 2016 को पुनः दौरा किया तथा व्यवसायिकों से विचार विमर्श किया। उन्होंने देश में व्यवसायिकों की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षित करने के विषय में जोनल स्तर पर और अधिक ऐसी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऑटिज्म में प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक मैडिकल कॉलेज के लिए 02 डॉ0 को आमंत्रित किया जाए और मैडिकल कॉलेजों को शामिल किया जाए। यदि आवश्यक हो, तो वह इन गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए एवं सहायता हेतु माननीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री से भी बात करेंगे। 18 राज्यों से 78 व्यवसायिकों ने भाग लिया जिसमें पीडियाट्रीसियन, मनेचिकित्सकों एवं क्लीनिकल मनोवैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण कार्यशाला में भागीदारी की तथा ऑटिज्म निदान एवं मूल्यांकन के लिए आईएनसीएलईएन और आईएसएसए का प्रयोग किया तथा मास्टर प्रशिक्षक बन गए। ये मास्टर प्रशिक्षक ऑटिज्म के लिए प्रमाणपत्र जारी करना सुकर बनाने के लिए अपने संबंधित राज्यों में आगे अन्य आवश्यक व्यवसायिकों को प्रशिक्षित करेंगे।

हालांकि सरकार ने 2001 में ऑटिज्म को निशक्तता के रूप में अधिसूचित किया था, इसने प्रमाणपत्र जारी नहीं किए थे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2016 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए जिससे कि ऑटिज्म के लिए निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए और बोर्डों का गठन किया जा सके। यह 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला ऑटिज्म व्यक्तियों को प्रमाणन सुकर बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। वर्तमान में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी में ऑटिज्म व्यक्तियों के डायग्नोज एवं समुचित रूप से प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की बहुत अधिक कमी है। ऑटिज्म का मूल्यांकन संभव नहीं है क्योंकि इसमें वैद्य मानक रेटिंग प्रणाली नहीं है। आईएनसीएलईएन और आईएसएसए का यह मूल्यांकन औजार उच्च स्तर एकरूपता कायम रखने के लिए देश के सभी भागों में प्रयोग किया जा सकता है। मास्टर प्रशिक्षकों को सलाह दी जाती है प्रशिक्षण सामग्री का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करें और पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा संबंधित राज्यों में अन्य व्यवसायिकों को प्रशिक्षित करें। सभी मास्टर प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सहमति दी। अध्यक्ष राष्ट्रीय ट्रस्ट ने मास्टर प्रशिक्षकों को प्रमाणपत्र वितरित किए।

- (ii) **सं० 16 को राष्ट्रीय ट्रस्ट फाउंडेशन दिवस पर 'समावेशन समारोह' :**
 30 दिसंबर, 2016 को माउलंकर हाल, कंस्टीचयूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली-11 में इसका फाउंडेशन दिवस मनाया। माननीय सामाजिक न्याय और श्रम विभाग के सचिव श्री थावरचन्द गेहलोत ने समारोह का उद्घाटन करने की सहमति दी।
 उपस्थित थे न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री आर. वेंकटेश्वर आ ने भी अवसर की शोभा बढ़ाई। श्री एनएस कंग, सचिव दिव्यांगजन कल्याण ने भी अवसर की शोभा बढ़ाई।

7.3 भारतीय पुनर्वादि (सीआई)

भारतीय पुनर्वास पशुरु जुलाई, 1986 के संकल्प संख्या 22-17/83 -एच डब्ल्यू-III के तहत सोसाइटी पंजीकरण 1980 का गग के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संसद में पारित एक अधिनियम नामतः अनवरिषद अधिनियम, 1992(1992 की सं. 34) दिनांक 1 सितंबर, 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा 1000 में (2000 का सं. 38) इस अधिनियम को अधिक व्यापक आधार वाला बनाने के लिए इसी किया। परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों व कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉनीटर करने एवं पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और केन्द्रीय प्रोस्ट रखखाव के लिए जिम्मेवार है।

परिषद के उद्देश्य

1. विकलांग पुनर्वसन क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मानीटर करना।
2. विकलांग संबंधिभिन्न वर्गों के पेशेवरों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक विहित करना।
3. देश भर में जाते लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों को विनियमित करना।
4. भारत में पेशेवरों के लिए विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा संस्वीकृत योग्यताओं की मान्यता हेतु मंत्रालय निर्देश देना।
5. भारत के पेशेवरों प्रदत्त योग्यताओं की मान्यता के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश करना।
6. मान्यता प्राप्तता धारण करने वाले व्यक्तियों का केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना।
7. विकलांग क्षेत्र कार्य कर रहे संगठनों के साथ सहयोग कर सतत पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
8. पुनर्वास में शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना।

परिषद के कार्य

1. भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त योग्यताएं जो अनुसूची में शामिल हैं, पुनर्वास पेशेवरों के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताएं होंगी।
2. कोई भी विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्था जो पुनर्वास पेशेवरों को योग्यता प्रदान करती है परंतु अनुसूची में शामिल नहीं है, इस प्रकार की योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है और केन्द्र सरकार, परिषद से सलाह लेकर अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना में यह निदेश दिया जा सकता है कि किसी विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात, केवल संस्वीकृति मिल जाने पर ही, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में कोई प्रविष्टि की जाएगी।
3. परिषद किसी भी अन्य देश में एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण के साथ योग्यता की मान्यता के लिए पारस्परिकता की एक योजना स्थापित करने के लिए समझौता कर सकता है। ऐसी योजना के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को जिसे परिषद ने मान्यता देने का निर्णय लिया है इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना में यह निदेश दे सकती है कि किसी विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात, केवल संस्वीकृति मिल जाने पर ही, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि यह योग्यता मान्यता प्राप्त है।
4. इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के केन्द्रीय पुनर्वास पेशेवर रजिस्टर में पुनर्वास पेशेवर के रूप में पंजीकरण।
5. भारत के विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता देने के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
6. पेशेवरों के लिए मानदंड, पुनर्वास पेशेवरों के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार और आचार संहिता निर्धारित करना।
7. पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं / विश्वविद्यालयों का आकलन और संस्वीकृति प्रदान करना और सरकार द्वारा उनकी मान्यता देने और मान्यता वापस लेने को सुगम करना।
8. परिषद जैसा अपेक्षित समझे, किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का निरीक्षण करने के लिए, जहां पुनर्वास पेशेवरों को शिक्षा दी जाती है, कितने भी निरीक्षकों नियुक्त कर सकता है अथवा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता प्रदान करने के प्रयोजन से किसी भी परीक्षा का निरीक्षण कर सकता है।

परिषद की प्रमुखी 16-17)

- (i) प्रायोगिक पआईपीएमडी, चैन्नई ने 04 नए पाठ्यक्रम विकसित/मानकीकृत एवं अनुमोदित। पाठ्यक्रमों का सेलेबस संशोधित किया गया। वर्तमान में आरसीआई को आबंटित बच्चों/कार्मिकों की सभी 16 श्रेणियों को कवर करते हुए नियमित पद्धति के माध्यम से प्रचालित हैं।
- (ii) 623 और 1.1 विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल/एचएच तक आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।
- (iii) केन्द्रीय रजि (सीआरआर) में 3494 व्यवसायिक और 3757 कार्मिक पंजीकृत किए गए और 33 तबाराआर में संचय योग 1,20,059 तक पहुँच चुका है।
- (iv) 272 नए पुनः शिक्षा (सीआरआई) कार्यक्रम स्वीकृत किए गए और 135 संगोष्ठीयों को सीआरआईका अस्तित्व प्रदान किया गया है। 296 अल्पावधि कार्यक्रम दिव्यांगता विभाग के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों के लिए स्वीकृत किए गए थे।
- (v) मीडिया (शियाएलए) के सहयोग से परिषद द्वारा दिव्यांगता पर "पुनर्भव" नेशनल इंटरैक्टिव 3.2017 तक आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया पोर्टल एकल प्लेटफॉर्म दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। व्यांग, व्यवसायिकों, नीति निर्माताओं छात्रों, अभिभावकों, सामुदायिक कामगारों और अभियंताएँ बहुत लाभकारी है।
- (vi) पुनर्वास्य बोर्ड (बीईआर) ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारों सहित कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, त्यावर जंग वाक् एवं श्रवण दिव्यांगता राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई, राष्ट्रीय दिव्यांगता संस्थान, देहरादून राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगता संस्थान, कोलकाता और राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद के माध्यम से प्रमाणपत्र और डिप्लोमा (सेमैस्टर, वार्षिक और अनुपूरक) की परीक्षा संचालित की।
- (vii) एससी के विशेष घटक योजना (एससीपी) के तहत, आरसीआई अनुमोदित संस्थानों में अध्ययन करने वाले एससी छात्रों और 46 एसटी छात्रों लैपटॉप खरीदने के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित है।

(viii) उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष घटक योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई हैं :

- (क) आरसीआई प्रशिक्षण संस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों के पणधारी विभाग की क्षमता निर्माण पर एक दिवसीय संगोष्ठी 01 मई, 2016 को गुवाहटी में आयोजित की गई।
- (ख) उत्तर पूर्व में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास व्यवसायिकों की क्षमता निर्माण पर संगोष्ठी 07 एवं 08 सितंबर, 2016 को नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई।
- (ग) उत्तर पूर्व में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास व्यवसायिकों की क्षमता निर्माण पर संगोष्ठी 04 एवं 05 अक्टूबर, 2016 को आईजोल, मिजोरम में आयोजित की गई।
- (घ) उत्तर पूर्व क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर में आरसीआई अनुमोदित संस्थानों में अध्ययन करने वाले 115 छात्रों को ट्यूशन शुल्क रिफण्ड किए गए हैं।

(ix) कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्तियों के दिव्यांगता प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए स्कीमें विकसित की गई हैं।

- (क) स्कीम I (क एवं ख) कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजनों (ग्रेड I एवं II) को दिव्यांगता प्रबंधन प्रशिक्षण (डीबीटी) हेतु
- (ख) स्कीम II (क एवं ख) कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजनों (ग्रेड II एवं उससे ऊपर) के व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रबंधन प्रशिक्षण (डीबीटी) और स्वास्थ्य जांच हेतु

(x) दूरस्थ शिक्षा सैल

विशेष शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए परिशद द्वारा वर्ष 2001 में दूरस्थ शिक्षा सैल स्थापित किया गया था। प्रथम समझौता ज्ञापन आरसीआई एवं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (एमपीबीओयू), भोपला के बीच हस्ताक्षर किया गया था। जिससे कि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से बीएड-एसईडीई पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकें और आज दूरस्थ पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम कराने हेतु निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं।

8

CHAPTER

विभाग की विभिन्न स्कीमें

8.1 सिंहावलोकन

विभाग विकलांग सशरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न स्कीमें संचालित कर रहा है। स्कीम के उद्देश्य विकलांगों की जीवन को बढ़ाने तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए भौतिक, मन, शक्ति, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। विकलांगजन सशक्तिकरण स्कीमें हैं :

- (i) विकलांगों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता की स्कीम (एडीए)
- (ii) विकलांगों के कार्यान्वयन की स्कीम (एसआईपीडीए)
- (iii) दीनकला पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस)

8.2 केंद्रीय क्षेत्र की

8.2.1 साधन खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)

स्कीम का उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/मिश्र क्षेत्रीय केंद्रों/केंद्र अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)/राज्य विकलांग विकास निगम/प्रान्त/एनजीओ) को सहायतानुदान प्रदान करना है ताकि विकलांगजनों की अनेक समस्याएँ घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी सामान्य और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा स्थायी रूप निर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों की प्राप्ति में जरूरतमंद विकलांगों को सा करने की स्थिति में हो सके। विकलांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुविधा को रोकने तथा माध्यमिक अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहायता दी जाती है। स्कीम के अंतर्गत दिए गए साधन तथा उपकरण का विधिवत प्रमाणपत्रों में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सही शल्य चिकित्सा की भी परिकल्पना की गई है।

लाभ के लिए पात्र व्यक्ति

- 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 15000 रु० प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 15001 से 20000 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।?
- नई सहायक डिवाइसें केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 03 वर्ष के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।
- तथापि, 12 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए आपूर्ति 01 वर्ष बाद की जा सकती है।

अनाथालयों एवं हाफ-वे होमस में रहने वाले लाभार्थियों के आय प्रमाणपत्र जिला क्लैक्टर या संबंधित संगठन के मुखिया के प्रमाणन पर स्वीकार किए जा सकते हैं।

सहायक यंत्र एवं डिवाइस की अधिकतम लागत सीमा

- सहायक यंत्र एवं उपकरण 10000 रु० से अधिक की लागत के नहीं।
- दिव्यांग छात्र के मामले में, नवी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी के लिए सीमा 12000 रु० है।
- बहु निशक्ता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा व्यक्तिगत मद पर अलग से लागू होगी।
- आय सीमा के अधीन, स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र, 20,000 रु० से ऊपर महंगी लागत वाली मदें, विभाग द्वारा अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। भारत सरकार लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष या तो राज्य सरकार द्वारा या एनजीओ या अन्य किसी अन्य एजेंसी या लाभार्थी द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ योगदान दिया जाएगा।

स्कीम के तहत, जिलावार दिव्यांगता कैंप आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से, कैंप आयोजित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्ताव की सिफारिश करते समय, यह भी अपेक्षा की जाती है कि बिना पहुँच किए जाने योग्य एवं बिना सेवित क्षेत्रों की कवरेज पर केन्द्रीत करें।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्राक्कलन 130.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 128.50 करोड़ रुपए का व्यय दिनांक 31.12.2016 तक स्कीम के अंतर्गत किया गया है। एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत निधि निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई है :

(क) एएलआईएमसीओ शिविर आयोजित करने हेतु

उपकरण तथा उपकरण 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आयोजित अभियान स्कीम के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को वितरित किए गए। मंत्रालय के साथ करार के अनुसार, एएलआईएमसीओ, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा एएलआईएमसीओ के प्राधिकरणों द्वारा व्यय की 40 प्रतिशत राशि तथा एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत न के माध्यम से व्यय की 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय दिव्यांग अभियान (आरएमएसए) स्कीम हेतु एडीआईपी - एसएसए प्रबंधन की तर्ज पर प्राथमिक आधार पर 9-12 कक्षाओं (14-18 आयु वर्ग) में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थी साधन और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी मामला मंत्रालय के अधीन है।

वर्ष के, विगत 02 वर्षों और चालु वर्ष के दौरान सम्पूर्ण देश में प्राथमिक स्कूलों में एएलआईएमसीओ अभियान (एसएसए) के तहत 2906 केंद्रों के माध्यम से विशेष शैक्षणिक एवं 1.96 लाख दिव्यांग बच्चों (डीसीडब्ल्यूडीएसएम) बच्चों को लगभग 54 करोड़ की लागत के सहायक यंत्र एवं सहायक डिवाइसों उपलब्ध कराई गई।

(ख) क्रीलापों हेतु

संस्थागतताओं के अनुसार समय-समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं।

(ग) आय कलापों हेतु

राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एएलआईएमसीओ संस्थान अथवा उनके संबंधित राज्य केंद्रों में प्रस्ताव देने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एडीआईपी अनुदान देता है।

प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के केंद्र/उप-केंद्र हैं जो विकलांगजनों को ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सही शल्य चिकित्सा संबंधी परामर्श करते हैं। बहुत से विकलांगजन सहायता साधनों तथा उपकरणों के लिए अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडीआईपी अनुदान उनके संबंधित प्रालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

वर्ष के तहत, विगत 02 वर्षों और चालु वर्ष के दौरान लगभग 6.35 लाख विद्यार्थी लाभ पहुँचाते हुए 4702 केंद्रों के माध्यम से 380.71 करोड़ रु० की अनुदान प्रस्ताव एवं प्रयुक्त की गई।

वर्ष के तहत, विगत 02 वर्षों और चालु वर्ष के दौरान लगभग 2.10 लाख दिव्यांग विद्यार्थी लाभ पहुँचाते हुए लगभग 169.56 करोड़ रु० की लागत के सहायक यंत्र एवं

सहायक डिवाइसों के वितरण हेतु 27 राज्यों को कवर करते हुए 197 मेगा कैप/विशेष कैप आयोजित किए गए।

वर्ष 2015-16 (दिनांक 29.02.2016 तक) के दौरान विभिन्न कार्यकलापों हेतु निधि की निर्मुक्ति और विवरण नीचे दिया गया है :-

एडिप स्कीम के तहत 2016-17 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों/राष्ट्रीय संस्थानों/एलिमको को निधियों की निर्मुक्ति दर्शाते हुए विवरण (31.12.2016 तक)			
क्र.सं.	एजेंसी का प्रकार	एजेंसियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)
1	एनजीओ/आईआरसीएस/ डीडीआरसी	1	100,00
2	राज्य सरकार के निगम	-	-
3	राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केन्द्र	12	1931,00
4	एलिमको	1	10819,00
	कुल	14	12850,00

स्कीम के अंतर्गत 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वर्ष की वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	ब.अ. आबंटन करोड़ में	स.अ. आबंटन करोड़ में	निर्मुक्त राशि करोड़ में	लाभार्थियों की संख्या
2014.15	110,00	110,00	101,28	2,39,560
2015.16	125,50	151,40	151,16	2,05,614
2016.17 (31.12.2016 तक)	130,00	128,50	1,90,521

विगत 02 वर्षों और चालु वर्ष के दौरान आयोजित किए गए राज्यवार कैपों की संख्या, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-4 पर है (पृष्ठ संख्या 191)। वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान एडिप स्कीम के अंतर्गत कैप/मुख्यालय गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों/डीडीआरसी/आईआरसीएस/डीआरसी/राज्य निगमों को जारी अनुदान सहायता के एजेंसिवार ब्यौरे अनुबंध-5 (पृष्ठ संख्या 194) पर है। वर्ष 2016-17 के दौरान एनआई/एलिमको/सीआरसी को जारी अनुदान सहायता अनुबंध-6 (पृष्ठ संख्या 195) पर हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान मांग पर आयोजित किए गए विशेष शिविरों/शिविरों का ब्यौरे अनुबंध-7 (पृष्ठ संख्या 198) पर दिए गए हैं।

मॉनीटरिंग तंत्र

स्कीम के कार्यान्वयन की के निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है :

- (i) विभाग की विकलांगों (विशेषकर एडीआईपी, डीडीआरएस तथा डीडीआरसी) के कार्यान्वयन की निगरानी के वेबसंयुक्त सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन।
- (ii) विकलांगजन सेवा विभाग अधिकारियों को तथा मंत्रालय की विकलांगता संबंधी स्कीमों के अंतर्गत गारंटी संगठनों, मंत्रालय तथा मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन।
- (iii) एडीआईपी स्कीमों, विशेष कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित राज्य सरकारों पर अनुदान जारी किया जाता है। अनुशंसाकर्ता प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान प्राप्तिप्रार्थियों की 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की जांच/प्रतिदर्श जांच भी आयोजित करता है।
- (iv) संगठन को उन्हें अनुदान के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना भी अपेक्षित है।
- (v) 01.04.2014 से रजिष्ट्रार के तहत, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को एक व्यवसायिक कायम रखनी चाहिए और प्राप्त अनुदान और फोटो एवं राशन कार्ड संख्या/वोटर आईडी संख्या/आधार संख्या, जो भी मांगी हो। साभार्थियों की सूची के ब्यौरे अपलोड किए जाएं।

एडीआईपी स्कीम पर सशक्तिकरण

एडीआईपी स्कीम विभाग 1.4 संश की गई है।

संशोधित एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत नीचे यथाविनिर्दिष्ट हैं :

- (i) मौजूदा 6,500 (रुपये से) 10 रुपए प्रतिमाह 100 प्रतिशत छूट हेतु सीमित आय पात्रता में संवर्धन तथा प्रतिमाह 15,000 (रुपये से) 10,000 रुपए प्रतिमाह में 50 प्रतिशत छूट।
- (ii) दृष्टिहीन छत्रों (18 इंच अधिक आयु) को सुलभ मोबाइल फोनों का प्रावधान 5 वर्षों में एक बार तथा स्कूल जाने वाले बच्चों को गेट टेकर तथा ब्रेलर, लैपटॉप, 10 वर्ष में एक बार।
- (iii) एकल विकलांगता साधन उपकरणों के लिए लागत सीमा 6000 रुपए से संशोधित कर 10,000 रुपए तथा विकलांग विधवा 10 रुपए से 12,000 रुपए।
- (iv) चिकित्सा/मार्गदर्शन की वर्तमान सीमा 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए है, की लागत सीमा में संशोधन किया गया है।

- क) श्रवण तथा वॉक विकलांगता हेतु 500 रुपए से 1000 रुपए तक
- ख) दृष्टिहीन विकलांगों के लिए 1000 रुपए से 2000 रुपए तक
- ग) अस्थि विकलांगजनों को 3000 रुपए से 5000 रुपए तक। बाद में 10,000 रुपए तक संशोधित
- (v) गंभीर रूप से विकलांगों के लिए तथा लोकोमोटर विकलांगों जैसे कि क्वाड्रिपलेजिक (एससीआई), मांसपेशीय कुपोषण, आघात, प्रमस्तिष्किय पक्षाघात, अर्धागघात तथा इसी प्रकार की स्थितियों वाला कोई अन्य व्यक्ति जिनमें तीन/चार अंग अथवा शरीर का एक पक्ष गंभीर रूप से विकृत हो, के लिए मोटरयुक्त तिपहिया और पहियायुक्त कुर्सियों हेतु रियायत की सीमा वर्तमान 6,000 रुपए बढ़कर 25,000 रुपए करना। यह 16 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों को 10 वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी।
- (vi) प्रति इकाई 6 लाख रुपए की सीमा के साथ स्कीम के अंतर्गत श्रवण अपंगता के लिए प्रति वर्ष 500 बच्चों के लिए कोचलीयर आरोपण हेतु प्रावधान। लाभार्थियों की आय सीमा समान अर्थात् 15,000 रुपए प्रतिमाह से लेकर 20,000 रुपए प्रतिमाह रहेगी।
- (vii) कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन तथा अनुवर्तन शिविर आयोजित करने के लिए प्रशासनिक/ओवरहेड व्यय के रूप में सहायतानुदान का 5 प्रतिशत उपयोग कर सकती है।

एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत, विभाग ने विकलांगजनों के लिए समकालीन साधन तथा सहायक उपकरणों की अक्षमतावार सूची अधिसूचित की है, जो इस प्रकार है :-

(I) दृष्टि बाधित

- (क) सहायक डिवाइसें जैसे कि स्मार्ट केन, ब्रेल घड़ी, क्वाडर्ज ब्रेल घड़ी (महिला एवं पुरुष) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्क्रीन-पठन साफ्टवेयर सहित स्मार्ट फोन, स्मार्ट फोन अथवा टेबलेट के लिए पाकेट साइज एक्सट्रनल की-बोर्ड, माउस-कम-वीडियो मोगनिफायर, हैंड हैल्ड इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मैगनिफायर, व्यक्तिगत डिवाइसों के टेबलेट, डेजी प्लेयर (आधुनिक मॉडल), रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्पले, स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर, स्क्रीन मैगनीफिकेशन सॉफ्टवेयर सहित स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप, क्यूबेरीथम, रेडियो, सीडी प्लेयर, टाकिंग ग्लूकोमीटर, टाकिंग ब्लड-प्रेसर मॉनीटर, आडियो लैबलर (17)
- (ख) (i) कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल छात्रों के लिए किटें, जिसमें सम्मिलित मुख्य मदें जैसे इंटरलाइन ब्रेल स्लेट दो सटाइलस सहित, पैकिंग बाक्स सहित अर्थमैटिक टाइप (250 ग्राम), वाले टेलर फ्रेम, ड्राइंग बोर्ड 20 शीटों सहित, पजल्स (इन्कलूसिव डिजाइन), प्रमुख स्मारकों की टेक्साइल ड्राइंग बुक, लम्बे पेड़ों के आकार, घरों, पुलों, डेम आदि के प्रकार, डिस्क सहित एक एडेप्टिड बोर्ड गेम, क्यूबेरीथम, टाकिंग कलाई घड़ी एवं किट बैग सहायक डिवाइसों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए स्कूल बैग (12)

16 तक के स्कूल छात्रों के लिए किटें, जिसमें सम्मिलित मुख्य मदें जैसे गाइड स्लेट, अलजेबरा प्रकारों सहित बड़े टेलर फ्रेम, (250ग्राम) पैकिंग बाक्स, 20 गं शीटों सहित टेक्टाइल ज्योमैटरी किट, 20 रेजिंग शीटों सहित ड्राइंग टेक्ल ड्रॉथ बोर्ड (इन्क्लूसिव डिजाइन), टेक्टाइल शतरंज बोर्ड (इन्क्लूसिव डिजाइन), सुगम्य बोर्ड गेम, विज्ञान शिक्षा के लिए टेक्टाइल डायग्राम सेट, ऑडियो रिकॉर्डर (इन्क्लूसिव डिजाइन) रुपया चेकर एवं वॉलेट सहित सिग्नेचर गाइड, ब्रेल कलाईन, फोल्डिंग केन, परिमाणन किट (इंच टेप, नीडल थ्रेडर, छोटा ब्रेल स्केल, गड स्ट्र, परिमाणन कप), टाकिंग टेबल घड़ी, पैकिंग बॉक्स (16)

17 सोक के स्कूली छात्रों के लिए किटों में मुख्य मदें, जैसे इंटरलाइन ब्रेल स्लेट, गाइड सहित, छोटी सफेद फोल्डिंग केन (पांच फोल्ड पैकिंग सहित), टाकिंग टेबल, टेलिफोन, रुपया चेकर वॉलेट सहित, पैकिंग बॉक्स (6)

18 तक के स्कूली छात्रों के लिए किटों में मुख्य मदें जैसे स्मार्ट केन एंड डेजीटल डिवाइस के लिए एक स्पीकर तथा कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए किटें, कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए माउस कम वीडियो मैगनीफायर एवं आवश्यकतानुसार अन्य कल और पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किए अनुसार नॉन ऑप्टिकल कल से (

(v) 19 तक के छात्रों के लिए किटें, जिसमें दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर, स्मार्ट एवं स्मार्टफोन अथवा टेबलेट के लिए पॉकेट साइज का ब्लूटूथ की-बोर्ड, कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए स्मार्टफोन मैगनीफायर ऐप सहित तथा आवश्यकता पर अन्य कल एवं जैसा भी पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए अनुसार नॉन ऑप्टिकल कल से (3)

(vi) 20 तक के छात्रों के लिए एडीएल किटें जैसे सिग्नेचर गाइड के साथ रुपए चेकर प्लास्टिक कप, फ्लैक्सिबल विड वॉलेट, स्मार्ट केन, टाकिंग बांडी थर्मामीटर, टाकिंग टेबल, घड़िके लैवल इंडीकेटर, पिल डिस्पेंसर, टाकिंग टेबल क्लाक जिसमें चार घंटे एवं वाच हो, ऑडियो लेबलर, टाकिंग कैलकुलेटर, परिमाणन किट एवं पैकिंग बॉक्स (10)

(vii) 21 तक के छात्रों के लिए निम्नलिखित डिवाइसों की सूची जैसा टेलीस्कोपिक ग्लास, ऑप्टिकल मैगनीफायर, क्लिपिंग मैगनीफायर, 5 इंच तक के हस्त सम्मलार्ड इलेक्ट्रॉनिक विडियो रिकॉर्डर, दृष्टि वालों के लिए मैगनीफायर ऐप वाले स्मार्टफोन (5)

- (viii) हाई-एंड डिवाइसों जैसे ब्रेलर (अपर प्राइमरी एवं उससे ऊपर के लिए), लेपटॉप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एवं भारतीय भाषा और भारतीय अंग्रेजी टीटीएस सहित, रिक्रेशेबल ब्रेल डिसप्ले (40 सैल अथवा अधिक) ब्रेल इंपुट की सहित, डेजी प्लेयर एडवांस मॉडल, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर (दृष्टिहीन) स्क्रीन मैगनिफिकेशन सॉफ्टवेयर (निम्नदृष्टि) (6)
- (ix) अन्य सामान्य डिवाइसों जैसे ब्रेलर (अपर प्राइमरी एवं उससे ऊपर के लिए), लेपटॉप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एवं भारतीय भाषा और भारतीय अंग्रेजी टीटीएस सहित, रिक्रेशेबल ब्रेल डिसप्ले (40 सैल अथवा अधिक) ब्रेल इंपुट की सहित, डेजी प्लेयर एडवांस मॉडल, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर (दृष्टिहीन) स्क्रीन मैगनिफिकेशन सॉफ्टवेयर (निम्नदृष्टि) (6)

कुल :-84

(II) कुष्ठ प्रभावित:

- (i) एडीएल किट जिसमें यूनिवर्सल कफ, नेल कटिंग डिवाइस, साबुन होल्डर, बटन हुक, जीपर पुल, राइटिंग एड अथवा अडेप्टिड पेन पोजिशनिंग स्प्लिंट के साथ, रबड़ के दस्ताने, इन्सुलेटिड कैंची, इन्सुलेटिड टम्बलर अथवा अडेप्टिड ग्लास होल्डर, बाइंडर ब्लिम प्लेट, लॉग हैडेलंड लीवर टेप, सैल फोन शामिल हैं। (12)
- (ii) व्यक्तिगत डिवाइसों (आवश्यकता के अनुसार विकल्प हैं) जैसे अडेप्टिड स्पून, बिल्ड अप स्पून, एन्जलड स्पून, ग्रीप ऐड, लैटेक्स प्रोसथिसिस, गटर स्प्लिन्ट, एक्सटेंशन आउटरिगर-छोटा, विस्तारित आउटरिगर-लम्बा, अगूँठा स्पाइका, वोलर/डोरसल कांक-अप, फिंगर लूपस, नुक्कल बेन्डर, एमसीपी ब्लॉक ओपोनेन्स स्ट्रेप, यूजर फ्रेंडली स्पून, बिल्ड-अप स्कू झाइवर, फुट डाप स्ट्रेप, फारमिंग ग्लव्स, पेडिड सेंड डिगर, एंटी कला पोजिशनिंग डिवाइस/नुक्कल बेडर स्प्लिन्ट, फिक्सड एनकल ब्रास, पेटलर टेंडन वियरिंग ब्रास (आधुनिक), पेटलर टेंडन बियरिंग ब्रास (मोल्डिड), फुट आर्थोसिस मोल्डिड इन्सोल, अस्थायी घुटने की नीचे की प्रोसथिसिस, स्थायी घुटने के नीचे की प्रोसथिसिस, पेटलर टेंडन बियरिंग ओर्थोसिस, फुट ड्राप स्प्रिंग, पेटलर टेंडन बियरिंग ओर्थोसिस वेरियेन्ट, मोल्डिड सैन्डल, एमसीआर सैन्डल, कस्टम मेड साइनस प्रोसथिसिस, एनकल फुट आर्थोसिस (एएफओ)/फिक्सड एनकल ब्रेस (एफएबी), एकोमोडेटिव फुट ओर्थोसिस(34)

कुल: 46

(III) बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता

- (i) आयु-वर्ग 0-3 वर्षों के लिए किट (अरली इन्टरवेंशन ग्रुप) जिसमें रैटल 3 प्रकार के, टीथर, एडीएल किटें (4 प्रकार की), पाल्म ग्रीप (चार प्रकार की), संवेदी फुटस्टैप, क्रिब

ने, छेड़ रिंग्स, लकड़ी के ब्लॉक, (6), संवेदी मेट, स्टीमुलेटिड खिलौने (3) अन्य तारि (3) संगीतमय पुस्तक, किट बैग आदि शामिल हैं (13)

(ii) बर्ग वर्ष के लिए बहु निःशक्तता के लिए टीएलएम किट जैसे रीसोनेंस बोर्ड, प्लेट, भिन्न टेक्सचर दस्तानें एवं मौजे, प्रि-ब्रेल पुस्तक(आकार) पिल/डेटरी/ओलफैक्टरी स्टीमुलेशन किट, प्रि-केन आदि, (6)

(iii) बर्ग 3 वर्ष के (प्राइमरी पूर्व समूह) के लिए किट जैसे नम्बर पिकचर ट्रे, बिल्डिंग स, एमोटर स्किल नेट, पेग बोर्ड, गुडिया (महिला एवं पुरुष), रेजू शेष ट्रे, पजल्स ट ए; संवेदी पुस्तकें, शब्द क्यूब, फेस पजलस, किट बैग आदि (12)

(iv) बर्ग 7-1 वर्ष के (प्राइमरी समूह) के किट, जिसमें पिकचर पजल, पिकचर एवं शब्द असेंब किट, नम्बर कार्ड्स, पाउण्ड खिलौने, जिगसा पजल्स, टेलिंग टाइम कार्ड्स, एलाफाबेट वार्म, बीडस, फंक्शनल लिटरेसी फिलप चार्ट, किट बैग शामिल हैं (12)

(v) 5 अं-18 वर्ष के आयु समूह के लिए किट (माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक) लब्लॉक के अक्षर युक्त, सुई काम किट अक्षर-लकड़ी क्यूब्स शब्द, फिटिंग ब्लॉक, संख्यात्मक टायलें, माप सेट, सामान्य भारत (चित्र कार्ड, शब्द कार्ड) गेम खेल, मोबाइल फोन, संख्यात्मक क्यूब्स, गुणात्मक टेकटाइल बोर्ड, किट शामिल हैं (12)

(vi) व्याप्त टीएलएम किट (आयु समूह 3-6 वर्ष के लिए) जिसमें संकेत भाषा किट प्रे-ब्रेल किताब या टाइपो स्कोप पढ़ाई और लिखित डिवाइस, उभरी हुई पुस्तक चिन्ह और कैलेंडर प्रणाली तथा ट्रेम्पोलाइन शामिल हैं (4)

(vii) व्याप्त टीएलएम किट (आयु समूह 6-10 वर्ष और अधिक के लिए) जिसमें भाषापक सेट प्रि-ब्रेल बुक या टाइपो स्कोप पढ़ना और लिखित उपकरण, हुईर पुस्तक, मूर्त चिन्ह और कैलेंडर प्रणाली तथा ट्रेम्पोलाइन एवं एंड्रोइड इत्यादि शामिल हैं (5)।

(viii) को संवेदी किट : बहु संवेदी समावेशी शिक्षा विकास (एमएसआईडी) किट आँध समनवय लूप/अनंत लूप युक्त, आरंभिक प्रयास मालिश गेंद लकड़ी, साँत, निचोड़ना, हवा तकिया, मेथुयल उपयोग और किट बैग शामिल हैं (8)

(vi) श्रवण बाधित

- (क) सहायक डिवाइसें जैसे शरीर स्तर श्रवण सहायक यंत्र, एनालॉग/गैर-कार्यक्रम योग्य—(कान के पीछे (बीटीई), कान में (आईटीई), कनल में (आईटीसी), कनल में पूरी तरह से (सीआईसी); डिजिटल/कार्यक्रम योग्य— (कान के पीछे (बीटीई), कान में (आईटीई), कनल में (आईटीसी), कनल में पूरी तरह से (सीआईसी); निजी एफएम श्रवण यंत्र ब्लूटूथ नेकलूप श्रवण यंत्र, कंपन एलार्म, बच्चे के रोने के कंपन वायरलेस उपकरण, दरवाजे घण्टी संकेत, आग धुआ एलार्म, दूरभाष संकेत, प्रवर्धित दूरभाष, दूरभाष प्रवर्धी, श्रवण इंडक्सन लूप, अवरक्त प्रणाली, हड्डी कंपन श्रवण यंत्र, शैक्षिक किट भाषा (शब्दावली) किताब, युक्त, अभिव्यक्ति ड्रिल किताब, कहानी की किताब, अन्य सामग्री (परिवार हस्त कठपुतलियां 5 पहेली, मोंटेसरी उपकरण/खिलौना, आकृति सॉर्टर घड़ी, शोर निर्माताओं का एक सेट, ब्लॉक सॉर्टर बक्से, क्रिया कार्डों के सेट, 5 मुलायम खिलौने।

कुल:-32

- (ख) कोकलियर इंप्लांट : प्रति यूनिट 6.00 लाख रु की अधिकतम सीमा के साथ दृष्टि बाधिता वाले 500 बच्चों के लिए कोकलियर इंप्लांट का प्रावधान है। इसकी परिणति 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जीवन भर राहत प्रदान करने में होगी।

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेन्सी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण और अपनी वेबसाइट www.adipeochlearimplant.in में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई की वेबसाइट पर विज्ञापन / व्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है। कॉकलेयर इम्प्लांट भारत कृत्रिम अंग निर्माण निगम (अलिम्को), कानपुर और नामांकित अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए अनुसार खरीदा जाएगा। सर्जरी अभिज्ञात सरकारी / राज्य सरकार अनुमोदित अस्पतालों में कराई जाएगी। कॉकलेयर इम्प्लांट सर्जरी कराने के लिए, मंत्रालय में 140 अस्पतालों (दोनों सरकारी एवं निजी) को अनुमोदित किया है। 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति अनुसार, देश में 500 कॉकलेयर इम्प्लांट सर्जरियाँ सफलता पूर्वक पुरी की गई हैं।

(v) अस्थि बाधित :

- (क) निचला सिरा प्रॉस्थेसिस :-

(I) ट्रांस-टाइबल प्रॉस्थेसिस (घुटने के नीचे) :- 7 प्रकार

प्रॉस्थेसिस के माध्यम से (टीके) :	—	2 प्रकार
-फेमोरल (घुटने के ऊपर) प्रॉस्थेसिस	:-	6 प्रकार
वेच्छेद प्रॉस्थेसिस	:-	1 प्रकार
प्रॉस्थेसिस	:-	1 प्रकार

— 17

(ख) सिंस्थेसिस :-

ह सिलिकॉन अंगूली प्रॉस्थेसिस

ह सिलिकॉन अंगूठा प्रॉस्थेसिस

ह सिलिकॉन आंशिक हाथ प्रॉस्थेसिस

रेडियल या कोहनी से नीचे / कलाई विच्छेद निश्क्रिय प्रॉस्थेसिस

शक्ति प्रॉस्थेसिस (ट्रांस रेडियल या कोहनी से नीचे / कलाई विच्छेद)

घटक ट्रांस रेडियल किट और सॉकेट शामिल है

हुमेरियल या कोहनी के ऊपर / कोहनी विच्छेद निश्क्रिय प्रॉस्थेसिस

शक्ति प्रॉस्थेसिस (ट्रांस हुमेरियल या कोहनी के ऊपर / कोहनी विच्छेद)

विच्छेद निश्क्रिय प्रॉस्थेसिस

विच्छेद शरीर शक्ति प्रॉस्थेसिस

— 9

(ग) इंड्डी सिरा प्रॉस्थेसिस :-

शक्ति कोहनी के नीचे या ट्रांस रेडियल / कलाई विच्छेद प्रॉस्थेसिस

शक्ति ट्रांस हुमेरियल / कोहनी विच्छेद प्रॉस्थेसिस

— 2

(घ) ग ऑर्थोसिस :-

र चाल ऑर्थोसिस

गोडर घुटने ऑर्थोसिस (इकाई मूल्य)

— 2

(ड) इस्पाईनल ओर्थोसिस :-

(i) हेलो ब्रास

कुल - 1

(च) गतिशील यंत्र :-

मोटर युक्त व्हील चेयर

कुल - 3

(i) ठोड़ी और सिर के नियंत्रण की चार पहियों वाली व्हील चेयर

(ii) जॉय स्टिक चार पहियों वाली व्हील चेयर

(iii) मोटर युक्त व्हील चेयर (हैंडल द्वारा चालित)

कुल : 34

कुल योग : 268

टिप्पणी :

वित्तीय सहायता की सीमा प्रत्येक विकलांगता के लिए 10,000 रु तक और दिव्यांग छात्रों के लिए 20000 रु की लागत की डिवाइस के संबंध में 12,000 रु तक सीमित होगी। 20000 रु की लागत से ऊपर की सभी महंगी मदों के लिए सरकार इन मदों की लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष या तो राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठन या किसी अन्य एजेंसी या इस योजना के अन्तर्गत बजट के 20 प्रतिशत तक सीमित मामला दर मामला आधार पर मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अधीन संबंधित लाभार्थी द्वारा योगदान किया जाएगा।



दिनांक 17.09.2016 को नवासारी, गुजरात में आयोजित किए गए कैंप के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कोकलियर इंप्लांट के लाभार्थी

एडीआई के अंतर्गत मोटरयुक्त तिपहिया तथा पहियादार कुर्सी का वितरण

- एडीआई के अंतर्गत से अंश लोटर अक्षमताओं जैसे कि क्वाड्रिपलेजिक (एससीआई), मांसपेशीय विकृति, प्रमासिद्धावर्गता और अन्य प्रकार की इसी तरह की स्थितियों जिनमें तीन/चार अंग शरीर का अंश रूप से विकृत हो, के लिए मोटरयुक्त तिपहिया तथा पहियादार कुर्सी के लिए आयत 25 है।
- आयत 16 से 7 आयु के लोगों को 10 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराई जाती है।
- एडीआई के अंतर्गत से विकृत रूप से अक्षम हैं, वे मोटरयुक्त तिपहिया व पहियादार कुर्सी के लिए आयत 25 हैं क्योंकि सस्ते दुर्घटनाओं/शारीरिक हानि की जोखिम होती है।



एडीआई स्कीम के अंतर्गत 016दिल्ली (शक्तिनगर) में संचालित वितरण कैंप में बैटरी प्रचालित मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल वितरण के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केन्द्रीय मंत्री, थावरचंद गेहलोत और प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मंत्री, डॉ० हर्षवर्धन

दिव्यांगजनों को 11.56 करोड़ ₹0 के सहायक डिवाइसें एवं सहायक यंत्रों के वितरण एवं अन्य लाभांश के लिए एक अन्य मेगा कैंप 17 सितंबर, 2016 को नवासारी, गुजरात में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में अवसर की शोभा बढ़ाई। यह अब तक का सबसे बड़ा, 159 वां एडिप कैंप था जिसमें 11330 दिव्यांगजन लाभार्थी लाभान्वित किए गए।



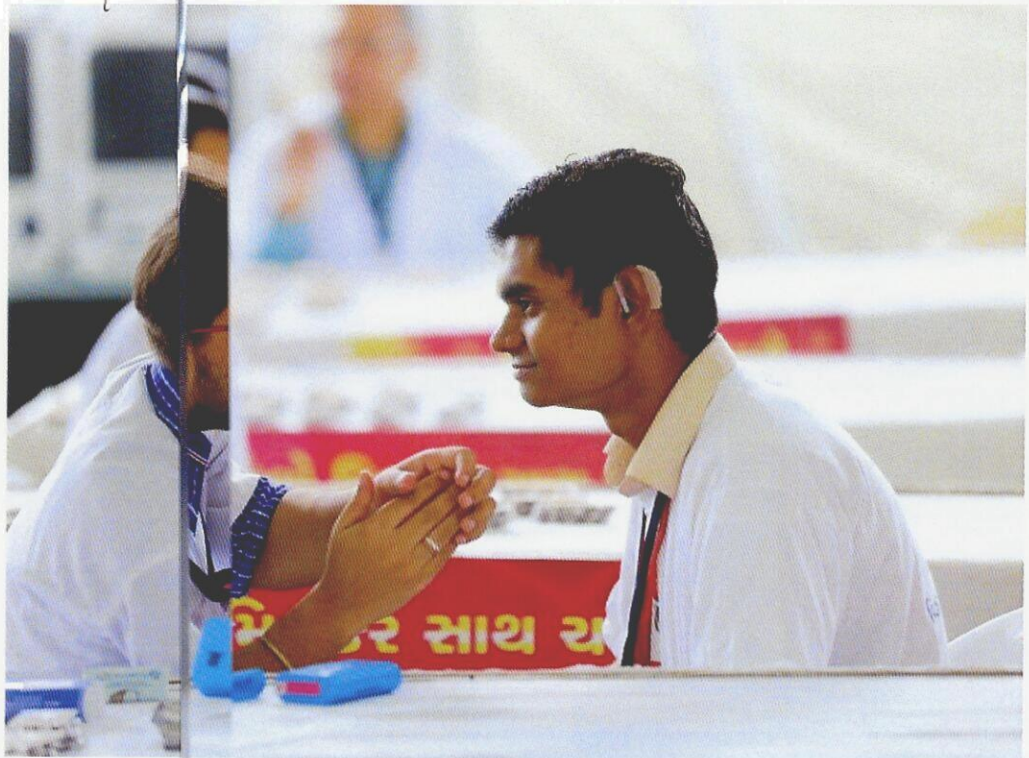
17 सितंबर, 2016 को नवासारी, गुजरात में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं सहायक डिवाइसें वितरित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एलिमको द्वारा नवासारी कैंप के दौरान, 3 गिनीज विश्व रिकॉर्ड सृजित किए गए



- प्रथमरिकॉर्ड 1000 दिव्यांगजनों द्वारा सबसे बड़ा व्हील चेयर/चित्र बनाया गया, जिसने समारोह को ऐतिहासिक बना दिया।

- एक ही स्थान पर कर 600 व्यक्तियों को 1200 श्रवण यंत्रों की फिटिंग द्वारा दूसरा विश्व रिकार्ड बनाया गया।



- 1000 दिव्यांगजनों द्वारा रथचालक लोगो/चित्र बनाकर तीसरा विश्व रिकार्ड, जिसने इस अवसर को ऐतिहासिक



वडोदरा, गुजरात में दिनांक 22.10.2016 को आयोजित मैगा कैंप में दिव्यांगजनों को 9.26 करोड़ रु. के सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराये गये। माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ायी जिसमें 10578 दिव्यांग लाभार्थी लाभान्वित हुए।



दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री सामाजिक अधिकारिता शिविर, वडोदरा में सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरण करते हुए।

8.2.2 निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु स्कीम का कार्यान्वयन (सिपडा)

1. निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 दिव्यांगजनों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त सरकारों को कुछ दायित्व दिए हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित राज्य सरकारों और अनेक अन्य निकायों को निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995, विशेषकर बाधा-मुक्त अभिगम के प्रावधान तथा पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन करने के अनुवर्ती क्रियाकलापों की सहायता करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायतानुदान उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा स्थापित जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) तथा सामाजिक पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी) को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी कार्यकलापों जिनके लिए सहायतानुदान बाधा मुक्त अभिगम के संबंध में उपलब्ध कराया जाता है, व्यापक है, जिनमें रैम्पस, लिफ्टें, स्पर्शीय पथ, नए उत्पाद विकास तथा अनुसंधान आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत 1999 से निधियां जारी की हैं। सचिव

(डीइपीडब्ल्यूडी वित्ति की अध्यक्षता में 04.01.2016 को आयोजित इसकी बैठक में स्कीम पर विचार किया गया। 2016 को अधिसूचित की गई।

2. स्कीम के अंतर्गत खियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं:

- (i) पीडब्ल्यूडी धारा 46 के अनुसार पीडब्ल्यूडी हेतु महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (राज्य सचिवन्यत्वपूर्ण राज्य स्तर के कार्यालयों, कलकटरेटों, राज्य विश्वविद्यालय भवनों, 1य मुख्यालयों पर चिकित्सा महाविद्यालयों तथा मुख्य अस्पतालों, अन्य महत्कारीतों) में बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। इसमें रेम्पो, रेलों, लिफ्टों, पहिरीकटेतु अनुकूल शौचालय, ब्रेल संकेत और श्रवण संबंधी संकेत, स्पर्शीय फ्लोरिंग आदिगान ल होंगे।
- (ii) भारत के प्रनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एवं पीजी विभाग) द्वारा जारी भारत र साइटें, जो उनकी वेबसाइट "<http://darpg.nic.in>" पर उपलब्ध हैं हेतु दिशा अन्राज्य तथा जिला स्तरों पर पीडब्ल्यूडी, सुलभ सरकारी वैबसाइटें बनाना।
- (iii) सरकल जों वाले जिला मुख्यालयों/अन्य स्थानों में शीघ्र निदान और हस्तक्षेप केन्द्र स्थाि जिउद्देश्य दृष्टि बाधित, शारीरिक दिव्यांग, श्रवण बाधित, मानसिक दिव्यांग शिशुवा को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान।
- (iv) दिव्य लिशल विकास कार्यक्रम पेश करना।
- (v) दिव्य सु आयुक्तों के कार्यालयों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकार टांट की पेशकश करना।
- (vi) पीडब्ल्यूडी विशेष मनोरंजन केंद्रों के निमाणार्थ जहां उपयुक्त सरकारों/ स्थानीय प्राधि पारस की भूमि है। इस संदर्भ में, पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अध्याय-VII, धारा 43(ग)हारा किए गए हैं।
- (vii) पीडब्ल्यूडी धारा 45 में कार्याकलाप आंकडे अर्थात व्हीलचेयर उपभोक्ताओं को आसान सुगमए : लगाने में कटौती और सतह में ढलान बनाना के कारण, अंधें अथवा अल्प दृष्टि के जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, अंधों अथवा अल्प दृष्टि दिव्य ए रेटेशन की सतह पर उत्कीर्णन और दिव्यांगता के उचित प्रतीक तैयार करना।

- (viii) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य किसी कार्यकलाप हेतु परंतु जिसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही हो/कार्य विभाग की मौजूदा स्कीमों द्वारा उसे कवर नहीं किया जा रहा हो, का मंत्रालय के अनुमोदन से मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम के लिए योजना के ट्रस्ट से सुगम्य भारत अभियान 03.12.2015 को शुरू किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्राक्कलन 193.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से दिनांक 31.12.2016 तक इस स्कीम के तहत 107.29 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान सहायता के ब्यौरे अनुलग्नक-8 (पृष्ठ सं. 202) पर दिए गए हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी अनुदान सहायता अनुलग्नक-9 – क, ख, ग, घ, ङ, च और छ (पृष्ठ सं. 204) पर दी गई है।

4. पिछले दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय

रु. करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	बीई आवंटन	जारी की गई राशि
1	2014-15	80.00	43.09
2	2015-16	135.00	69.42
3	2016-17 (31.12.2016 तक)	193.00	107.29

वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए विभिन्न प्रकार के निधियों के लिए जारी की गई निधियों का सार

क्र.सं.	निधियां	कुल राशि जारी (रु.लाख में)
1	सुगम्य भाषा में तर्गत बाधामुक्त वातावरण / सुगम्यता का सुगम्य भारत अभियान के अलावा	5286.85 537.42
2	कौशल प्रशिक्षण	2097.06
3	एससीपीडी के लिए सुदृढीकरण	48.06
4	सीआरसीए	2499.53
5	डीडीआरए	95.46
6	यूडीआईडी	157.58
7	एनपीसी डेप (त. पार्टी कौशल प्रशिक्षण के लिए)	7.54
	कुल	1072.95

6. सुत उन के अंतर्गत 31.12.2016 तक जारी निधियां

क्र.सं.	संयोजित क्षेत्र	राशि
1.	अवनेमें 21 भवन)	रु. 607-13 लाख
2.	त. (चैन 3 भवन)	रु.380.00 लाख
3.	च. (आर. 3 भवन)	रु.415.38 लाख
4.	रा. (आर. 16 भवन)	रु.1119.03 लाख
5.	म. (आर. 25 भवन, पुणे के नागपुर में और में 46 भवन (कुल-142 भवन)	रु. 1539.95 लाख
6.	9. (वैडिट के लिए अरनेट)	रु.1047.58 लाख
7.	ए. (डेटावनों के लिए भुगतान)	रु.144.04 लाख
	कुल	रु. 5253.11 लाख

8.2.3 दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस)

विभाग की दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) एक केंद्रीय स्कीम सेक्टर स्कीम है जिसमें दिव्यांगजनों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने की परियोजना शामिल है। स्कीम व्यक्तियों को सशक्तिकरण के लिए परियोजनाएं प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता के जरिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देकर और माहौल का सृजन करके निःशक्तजन अधिनियम (पीडब्ल्यूडी), 1995 के कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में परिचालित की गई।

डीडीआरएस दिशानिर्देश

वर्ष 2009 में संशोधित लागत मानकों के साथ दिनांक 1.4.2003 से लागू डीडीआरएस दिशानिर्देशों में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त क्षेत्र सेवाओं सहित, 18 मॉडल परियोजनाएं हैं जिन्हें सहायतानुदान के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। इन सेवाओं में शामिल हैं :

- (i) स्कूल-पूर्व तथा प्रारंभिक इंटरवेशन हेतु कार्यक्रम
- (ii) विशेष शिक्षा
- (iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट
- (iv) सामुदायिक आधारित पुनर्वास
- (v) जनशक्ति विकास
- (vi) मानसिक रुग्णता वाले व्यक्तियों का मनो-सामाजिक पुनर्वास तथा
- (vii) कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्तियों का पुनर्वास आदि।

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता-प्राप्त विभिन्न 18 प्रकार की मॉडल परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

- (i) स्कूल-पूर्व और प्रारंभिक कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण हेतु परियोजना
- (ii) विशेष स्कूल
- (iii) प्रमस्तिष्क घात बच्चों हेतु परियोजना
- (iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
- (v) आश्रय कार्यशालाएं

- (vi) कुष्ठ रोगमुक्ति के पु की परियोजना
- (vii) उपचारित तथा निनगिगी के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पुनर्वास हेतु हॉफ वे होम
- (viii) सर्वेक्षण, पहचान तथा संचेतना से संबंधित परियोजना
- (ix) गृह आधारित पुनर्क्रम प्रबंधित कार्यक्रम
- (x) समुदाय आधारित पसा
- (xi) निम्न दृष्टि केंद्रों का
- (xii) मानव संसाधन का पनाएं
- (xiii) संगोष्ठियां / का / ग्राशेविर
- (xiv) दिव्यांगों के लिए अन्तथा पारिस्थितिकी उन्नयक परियोजनाएं
- (xv) कम्प्यूटर हेतु अ
- (xvi) भवन का निर्माण
- (xvii) कानूनी परामर्श, विहार विम्लेषण तथा मौजूदा कानूनों के मूल्यांकन सहित कानूनी साक्षरता हेतु परियोजना
- (xviii) जिला विकलांग केंद्र ।

स्कीम के लागत तथा नेर्देश सरकार द्वारा संशोधित किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं। संशोधन में मान की मौर व्यय की अनावर्ती मदों के संशोधित लागत मानक शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न रेयों में जनशक्ति श्रेणियों की बुद्धिसंगत व्याख्या और विलयन किया गया है। मौलिक स्कीम 8 के 1, संशोधित सूची में 56 जनशक्ति श्रेणियां शामिल हैं। कम्प्यूटर अनुप्रयोगों और प्रोग्रामिंग, वैनिंगनेट प्रबंधन, मोबाइल मरम्मत आदि जैसे नए कौशल के लिए उभरती मांगों को समझते हुए प्रस्तुत जा सकने वाले कुल 14 नए ट्रेडों को इसमें शामिल किया जा सकता है। विभाग द्वारा स्थापित पुनर्वास केंद्र भी इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित हैं, बाद में जिन्हें पांच वर्ष की अवधि के मू एमीर अथवा पूर्वोत्तर में स्थापित केंद्रों हेतु) तथा बाकी देश में तीन वर्षों हेतु चलाया गया। इंत, केंद्र आगे सतत रूप से जारी रखने तथा रखरखाव हेतु जिले के प्रख्यात गैर-सरकारी सं सोंपए हैं।

डीडीआरएस स्वर्गत-14 से 2016-17 तक वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिए

(i) वित्तीय

रु. करोड़ में

वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
2013-14	90	63.64
2014-15	90	50.08
2015-16	60	50.19
2016-17 (31.12.2016 तक)	45	32 ^{८८८}

(ii) वास्तविक

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)		प्रतिशत उपलब्धि
	लक्ष्य	उपलब्धि	
2013.14	2.50	2.60	104
2014.15	2.60	1.81	69.61
2015.16	1.75	2.10	120
2016.17	2.00	1.36 (31.12.2015 तक)	68.00 (31.12.2015 तक)

वर्ष 2016-17 के दौरान डीडीआरएस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सूची अनुलग्नक-10 (पृष्ठ सं. 220) पर दी गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी सहायतानुदान का राज्यवार ब्योरा का सार अनुलग्नक-11 (पृष्ठ सं. 281) पर दिया गया है।

8.3 अन्य केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीमें

8.3.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

स्कीम के उद्देश्य तथा संक्षिप्त विवरण:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय में एम.फिल तथा पीएच.डी जैसी डिग्रियों से संबंधित उच्च शिक्षा के अनुवर्तन हेतु अक्षम छात्रों के अवसरों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति की स्कीम चलाई गई थी।

- यदि कोई दिव्यांग छात्रों को प्रति वर्ष 200 शिक्षावृत्तियां (जूनियर रिसर्च फेलोज, एफएफएफ) दी जाएगी। दिव्यांग छात्रों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के मामले में, यदि वादौरान प्राप्त न की गई शिक्षावृत्तियों की संख्या अगले शैक्षणिक सत्र में दी जाएगी।
- यदि उपपुरस्कारों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हो, यूजीसी उनकी कोशिका में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता पर आधारित अभ्यर्थियों को चुनना है।

फैलोशिप

- (i) एफएसआरएफ की फैलोशिप की दरें यूजीसी फैलोशिप के समकक्ष होंगी। इस प्रकार के अनुसार है :

1	निम्न और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज विज्ञान (कला/साहित्य सहित) में फैलोशिप	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की दर पर (जेआरएफ) शेष कार्यकाल के लिए प्रतिमाह 28,000 रुपये की दर पर (एसआरएफ)
2	वेकर्स सामाजिक विज्ञान (कला/साहित्य सहित) हेतु फैलोशिप	प्रारंभिक दो वर्षों हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से शेष कार्यकाल हेतु 20,500 रुपये प्रतिमाह की दर से
3	तकनीक, नेयरिंग तथा प्रौद्योगिकी में आकृति	प्रारंभिक दो वर्षों हेतु 12000 रुपये प्रतिमाह की दर से शेष कार्यकाल हेतु 25000 रुपये प्रतिमाह की दर से
4	अवसरिता (समस्त विषय)	अवसरिता उपलब्ध कराने हेतु मेजबान संस्थान के प्रति छात्र 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से
5	शारीरिक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक और दृष्टि बाधित वाले अभ्यर्थियों के मामले में 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से

***नोट:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22-9/2010-डीडी-III के अनुसार, इसे यूजीसी फ़ैलोशिप के बराबर बनाने के लिए फ़ैलोशिप की दरों में 01 दिसंबर, 2014 से संशोधित किया गया है। फ़ैलोशिप राशि की संशोधित दरें नीचे दी गई हैं:

	मौजूदा दर (प्रति माह)	संशोधित दर (प्रति माह)
प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान —कनिष्ठ अनुसंधान फ़ैलोशिप	— विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान शाखा के मामलों में रु. 16,000 /— — इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शाखा के मामले में रु. 18,000 /—	रु. 25,000 /—
शेष हुए तीन वर्षों के दौरान —वरिष्ठ अनुसंधान फ़ैलोशिप	— विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान शाखा के मामलों में रु. 18,000 /— — इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शाखा के मामले में रु. 20,000	रु. 28,000 /—

- (iii) मकान किराया भत्ता (एचआर) यूजीसी पैटर्न पर होगा तथा उन छात्रों को देय होगा जिन्हें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑफर किए गए होस्टल आवास से इन्कार किया जाता है, तो छात्र को एचआरए का अपना दावा छोड़ना होगा। चिकित्सा सुविधाएं, प्रसूति अवकाश सहित अवकाश सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाएं उनकी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के मामले में यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार शासित की जाएंगी।

फ़ैलोशिप की पात्रता

- (i) किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था में एम.फिल/पीएचडी डिग्री में प्रवेश प्राप्त कोई अक्षम छात्र।
- (ii) दो वर्ष उपरांत, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अनुसंधान कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो उसके/उसकी कार्यकाल को सीनियर रिसर्च फ़ैलोशिप (एसआरएफ) के रूप में आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन सदस्य समिति द्वारा अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। जेआरएफ और एसआरएफ के पुरस्कार की कुल अवधि पांच वर्ष की अवधि से अधिक होगी।

अवधि

पाठ्यक्रम का	कतम	जेआरएफ और एसआरएफ की अनुमेयता	
धे	जेआरएफ	एसआरएफ	
एम.फिल	₹	2 वर्ष	शून्य
पीएच.डी	₹	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष
एम फिल. पीए	₹	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

लाभार्थियों की तथ्य तक जारी राशि :

वर्ष	जारी राशि (करोड़ रुपए)	अभ्युक्ति
2012-13	शून्य	आगामी वर्ष में जारी राशि
2013-14	0.86	वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 दोनों वर्षों के अभ्यर्थी हेतु
2014-15	13.24	विगत वर्षों तथा 2014-15 के लाभार्थियों हेतु
2015-16	19.97	विगत वर्षों तथा 2014-15 के लाभार्थियों हेतु
2016-17	11.72	विगत वर्षों तथा 2016-17 के लाभार्थियों हेतु
कुल	45.79	

8.3.2 दिव्यांग के प्रि-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां

स्कीम के उद्देश्य/क्षिपरण:

- स्कीम प्रि-मैट्रिक स्तर (कक्षा 9 तथा 10) तथा पोस्ट-मैट्रिक स्तर (कक्षा 11, 12 तथा स्नातकोत्तर/मा स्तर तक) में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता देना है।
- वित्तीय-1 शौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा में दो स्कीमें चलाई गई हैं।

- वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कोर्ट / रीडर भत्ता आदि शामिल हैं।
- प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियां प्रि-मैट्रिक स्तर के लिए 46,000 तथा पोस्ट-मैट्रिक स्तर हेतु 16,650 हैं।
- इन दो छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुशंसा के उपरांत मेरिट के आधार पर किया जाता है।
- ये स्कीमें वर्ष 2015-16 से इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक वैब पोर्टल राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarship.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जा रही हैं।

छात्रवृत्तियों का मूल्य -

1 प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति:

प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति को मूल्य में पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (I) छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान;
- (ii) भत्ते, और
 - (i) छात्रवृत्ति और अनुदान की दरें:

मदें	दिवस स्कालर	छात्रावास
शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु देय छात्रवृत्ति (प्रतिमाह रुपए में) की दर	350	600
पुस्तक तथा तदर्थ अनुदान (वार्षिक रुपए में)	1000	1,000

- (ii) भत्ते:

भत्ते	राशि (रुपए में)
अंधता छात्रों हेतु मासिक रीडर भत्ते	160
मासिक परिवहन भत्ता, यदि ऐसे छात्र होस्टल जो शैक्षणिक संस्था के परिसर के भीतर हेतु, में नहीं रहते हैं	160

गंभीर दिव्यांगता (अर्थात् 80 प्रतिशत अथवा उच्च दिव्यांगता वाले) मिलस्यधिक अल्प दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए मंजूर	160
शैक्षणिक क्षेत्र में रहने वाले गंभीर रूप से अस्थि विकृत छात्रों को सहायक की जरूरत है, को सहायता देने के लिए किसी कर्मचारी को अनुमेय मासिक सहायक	160
मानसिक और शारीरिक रुग्णता के छात्रों को मासिक कोचिंग	240

2. पोस्ट-ग्रेजुएट

पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित शामिल हैं :-

- रखरखाव
- पाठ्यक्रम के लिए दिव्यांग छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता, तथा
- अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति (1.50 लाख रु. तक),
- सभी छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 1,500/- रु.

ब्यौरा निम्नानुसार

- रखरखाव

समूह		रखरखाव भत्ते की दर (प्रतिमाह रुपए में)	
		हास्टल	दिवस स्कालर
समूह I	किसी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी प्राप्त समस्त पीजी डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सौंपैथिक, चिकित्सा की भारतीय और अन्य मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, बिजनेस वित्त / प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान आदि	1200	550

समूह II फार्मसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा-मेडिकल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रेवल/पर्यटन/ मेजबान प्रबंधन, आंतरिक सास-सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जिसके लिए प्रवेश अर्हता कम से कम वरिष्ठ माध्यमिक ;102व्व है जैसे क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम	820	530
समूह III स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम समूह I तथा II अर्थात बीए/ बीएससी/बी.कॉम आदि के अंतर्गत नहीं आते	700	500
समूह IV समस्त पोस्ट-मैट्रिक स्तर गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम दोनों, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि हैं।	450	400

(ii) छात्रों की दिव्यांगता पर निर्भर करते हुए अतिरिक्त भत्ते

इसके अलावा, यह स्कीम अध्ययन भ्रमण प्रभार, पुस्तक भत्ता, पुस्तक बैंक, टंकण और मुद्रण प्रभार, रीडर भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, कोचिंग भत्ता और विशेष भत्ता आदि।

(iii) अनिवार्य गैर-प्रत्यार्पणीय फीस की प्रतिपूर्ति

स्कॉलरों को प्रवेश/पंजीकरण द्यूशन, खेलों, यूनियन, पुस्तकालय, मैगनीज, चिकित्सा परीक्षा देय होगी तथा ऐसी अन्य फीस स्कालर द्वारा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड को प्रतिवर्ष अधिकतम 1.50 लाख रु. की सीमा तक अनिवार्य रूप से देय होगी। तथापि, कॉशन मनी, सुरक्षा जमाराशि जैसी प्रत्यार्पणीय जमाराशि को बाहर रखा जाएगा।

कैसे आवेदन करें:

वर्ष 2015-16 से आगे के लिए : स्कीम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकीय विभाग द्वारा विकसित राष्ट्रीय ई-स्कालरशिप पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। अभ्यर्थी उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

8.3.3 दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की स्कीम मास्टर डिग्री तथा पीएचडी स्तर पर विदेश में अध्ययन कर रहे दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रत्येक वर्ष बीस (20) छात्रवृत्तियां दी जानी होती हैं जिनमें से छह महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। छात्रवृत्ति की राशि में रखरखाव भत्ता, आकस्मिकता भत्ता, ट्यूशन फीस और हवाई यात्रा आदि की लागत शामिल है। पैतृक आय सीमा प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपए है।

उक्त के अलावा, प्रतिवर्ष दो दिव्यांग छात्रों को “पैसेज अनुदान” का प्रावधान है। केवल वे दिव्यांग छात्र जिन्होंने किसी विदेशी सरकार/संगठन से स्नातकोत्तर अध्ययन, विदेश में अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण (संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, कांफ्रेंस में भाग लेने को छोड़कर) मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त की हैं अथवा अन्य किसी स्कीम, जिसमें पैसेज की लागत नहीं दी गई हो, पात्र होंगे। पैसेज अनुदान में एयर इंडिया के माध्यम से इकॉनामी क्लास में गृह नगर से विदेशी संस्थान तक आने-जाने का किराया शामिल है।

न्यूनतम अर्हता :

पीएचडी के लिए : प्रासंगिक मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड। **मास्टर डिग्री के लिए :** प्रासंगिक स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड।

आयु : स्कीम के विज्ञापन के माह के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार 35 (पैंतीस) वर्ष से कम।

आय सीमा : प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपए

परिवार में अधिकतम दो बच्चे : एक ही माता-पिता/संरक्षकों के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे पात्र नहीं होंगे।

वित्तीय सहायता

क्र.सं.	वर्ग	राशि
1	वाररखा	यू.के. हेतु - जीबीपी 9,900 / - अन्य देशों हेतु - 15,400 / - अमरीकी डालर
2	वकिस्ता	यू.के. हेतु - जीबीपी 1,100 / - अन्य देशों हेतु - 1,500 / - अमरीकी डालर
3	प्रगत्रा	अन्य देशों हेतु - 20 / - अमरीकी डालर
4	रुता	1500 / - रुपए
5	वस, पैसेज की लागत, सत्रा, कर, वीजा फीस, निमांश	वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी

अवार्ड की अवधि हेतु - 4 वर्ष (ख) मास्टर डिग्री हेतु - 3 वर्ष

कैसे आवेदन

स्कीम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। समाचार पत्रों और विभाग की वेबसाइट में विवरण प्रकट करके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग को प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है तथा प्रक्रिया है।

8.3.4 दिव्यांग के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

उद्देश्य

- निम्न वंश अक्षम छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर गुणवत्तापरक शिक्षा देना तथा मान्यता देना है।
- निम्न स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के स्तर पर अध्ययन करने की स्कीम को कवर करेंगी।
- निम्न, संस्था के रूप में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित 240 संस्थानों में प्रचालित की जाएगी।

1. पात्रता की स्थितियां

- (क) भारत का नागरिक हो।
- (ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता रखने वाला दिव्यांगजन हो तथा किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो।
- (ग) संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के स्तर पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु किन्हीं अधिसूचित संस्थाओं में चयन किया गया हो और प्रवेश पाया हो। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति किसी भी स्ट्रीम में डिस्टेंस लर्निंग/अंशकालिक/साप्ताहिक पाठ्यक्रमों को करने हेतु अनुमेय नहीं होगी।
- (घ) अभ्यर्थी भारत सरकार की किसी स्कीम के अंतर्गत कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- (ङ) **माता-पिता/अभिभावकों की आय-सीमा :** अभ्यर्थी के सभी स्रोतों तथा/अथवा उसके माता-पिता/अभिभावकों की कुल आय प्रतिवर्ष 6,00,000 से अधिक न हो (ऐसे भत्ते जिसे आयकर के प्रयोजनार्थ कुल आय के भाग के रूप में नहीं समझा जाता है, को छोड़कर)। नवीनतम कर-मूल्य निर्धारण तथा नियोक्ता से नवीनतम मासिक वेतन पर्ची की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किए जाने की अपेक्षा है।
- (च) किसी परिवार में दो बच्चे – एक ही माता-पिता/अभिभावक में दो से अधिक दिव्यांग बच्चे पात्र नहीं होंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी का स्व-प्रमाणन अपेक्षित होगा। बशर्ते, यदि दूसरा/तीसरा बच्चा जुड़वां हैं तो एक ही माता-पिता के दो से अधिक बच्चों को अनुमति दी जा सकती है।
- (छ) एक बार पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्तकर्ता पर दूसरी बार (अथवा उसके बाद के लिए विचार नहीं किया जा सकता) क्योंकि व्यक्ति को “एक बार ही पुरस्कार दिया जा सकता है।

2. वित्तीय सहायता की प्रमात्रा

छात्रवृत्ति में निम्नलिखित शामिल होगा :

क्र.सं.	छात्र क	प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता
क)	संसाधन ज्ञान किए जाने वाले गैर-मध्यम ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	2.00 लाख रुपए तक – प्रतिवर्ष (वास्तविक राशि के अधधीन)
ख)	रखवा	छात्रावास में रहने वाले को प्रतिमाह 3000/- रुपए दिवस छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिए प्रतिमाह 1500/-रुपए
ग)	विश्वरीक्षा, मार्गरक्षी भत्ता, सह आसे अक्षमता की प्रकारों से	प्रतिमाह 2000 रुपए
घ)	पुस्तकखनग्री	प्रतिमाह 5,000/-रुपए
ड.)	कंपरखरीद के लिए व्ययों की	पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 30,000/-रुपए
च.	चयर्थी वेशेष अक्षमता से संबंधित आवपटसहित सहायक भत्ता तथा सहकरण खरीद हेतु व्ययों की प्रति	पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 30,000/-रुपए

साधन तथा सहाकरणोन्मलिखित शामिल हो सकते हैं :-

अंधता / निम्न लिए

- ब्रैडपराइटर
- रीमाफ्टवेयर वाला लेपटॉप
- आसॉफ्टवेयर वाला लेपटॉप
- इल सुलभता वाला साफ्टवेयर
- रिक्ता प्लेयर

श्रवण शक्ति का ह्रास के लिए—

- (i) बटन सैलों के प्रावधान वाले द्विकर्णी डिजिटल कार्यक्रम के श्रवण सहायक यंत्र
- (ii) एसएमएस सिम कार्ड वाले सेलफोन
- (iii) वाई फाई (बल्यू टूथ) सुविधा वाले लेपटॉप

3. आवेदन और चयन की प्रक्रिया

- (क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्कीम के ब्योरे की घोषणा करेगा तथा प्रमुख समाचारपत्रों में तथा वेबसाइट और अन्य मीडिया आउटफिट के माध्यम से विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे।
- ख) आवेदकों को अपने आवेदन, आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए।
- ग) वह संस्थान जिसमें वह (पुरुष/स्त्री) अध्ययनरत हो, आयु, जन्म-तिथि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम की मान्यता, प्राप्त फीस आदि जैसे आवेदन में विहित तथ्यों का आवश्यक सत्यापन कराने के उपरांत संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को पोर्टल के माध्यम से आवेदन अग्रेषित किया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अपनी अनुशंसा से आवेदन अग्रेषित करने तथा संबंधित संस्थान की मान्यता सहित आवश्यक बुद्धिमत्तापूर्ण जांच करेगा।
- घ) अन्य बातों के साथ-साथ उस विशेष राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या पर विचार करते हुए, राज्य शिक्षा विभाग की अनुशंसा के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल पीडब्ल्यूडी आबादी की तुलना में उस राज्य की पीडब्ल्यूडी प्रतिशतता के आधार पर किसी राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या का निर्णय लिया जाएगा।
- ड.) यदि कोई अभ्यर्थी एक राज्य का स्थायी निवासी है परंतु किसी अन्य राज्य में अध्ययनरत है, उसके आवेदन पर उसके गृह राज्य के स्लाट में विचार किया जाएगा तथा उसके आवेदन को राज्य के शिक्षा विभाग, जिसका वह स्थायी निवासी है, की अनुशंसा की जरूरत होगी।
- च) चयन का मेरिट मापदंड : निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :

म में यथा प्रदत्त पात्रता शर्तों को पूरा करना

। शिक्षा विभाग की अनुशंसा

। को उपलब्ध स्लाटों की संख्या

ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के विषय में अभ्यर्थी की मेरिट

। का प्रतिशत बराबर-बराबर होने पर, पैतृक आय सीमा पर विचार किया
गा अर्थात् निम्न पैतृक आय सीमा वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी

यहां भी टाई होता है, अक्षमता के प्रतिशत पर विचार किया जाएगा अर्थात्
क अक्षमता प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

छ) स : यदि आवेदक अनुमेय छात्रवृत्ति की संख्या से अधिक हैं तो पात्रता पर
रितर्तियों के चयन हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव के अनुमोदन
क चमिति का गठन किया जाएगा।

4. कैसे करें

इलैक्ोर । प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए गए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
(www.shov.in) के माध्यम से योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभ्यर्थी उपर्युक्त
पोर्टल सेलाइन आवेदन कर सकते हैं।

8.3.5. दिव्य के निःशुल्क कोचिंग

1. दिव्य शक्ति विभाग ने दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की योजना हेतु केन्द्रीय क्षेत्रकगुरु।
2. योजना से कम 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के सक्षम बनाने और सरकारी क्षेत्र में एक उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सक्षम हो जाने हेतु कोचिंग मुहैया।
3. इस 3 निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांग छात्रों को कोचिंग प्रदान की जाए

- i) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित किये जाने वाली समूह 'क' और 'ख' की परीक्षाएँ।
 - ii) राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह 'क' और 'ख' की परीक्षाएँ।
 - iii) इसके अंतर्गत अधिकारी स्तर पदों के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएँ।
 - iv) (क) इंजीनियरिंग (अर्थात् आई.आई.टी.-जेईई एवं एआईईई), (ख) मेडिकल (अर्थात् एआईपीएमटी), (ग) व्यावसायिक कोर्सों-जैसे प्रबंध (अर्थात् कैट) और लॉ (अर्थात् कलाट) और (घ) ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनका मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारण किया जायेगा, प्रवेश हेतु प्रमुख प्रवेश परीक्षाएँ।
4. योजना प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। दिव्यांग छात्र, जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये अथवा इससे कम होगी, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
5. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार योजना की नियम व शर्तों के अनुसार और संबंधित कोचिंग संस्थान के साथ किए गए समझौतों के तहत चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए कोचिंग के पूरे खर्च की निधियों का भुगतान किया जाएगा। कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने हेतु स्थानीय छात्रों को 2500/- रुपये प्रति छात्र की दर से मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार से बाहरी छात्रों को 5000/- रुपये प्रति छात्र की दर से मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। रीडर भत्ते, एस्कोर्ट भत्ते, सहायक भत्ते आदि हेतु 2000/- रुपये प्रति छात्र की दर से प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रदान किया जायेगा।

8.3.6 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निजी सेक्टर नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

स्कीम के उद्देश्य तथा सारांश :

स्कीम का उद्देश्य कारपोरेट सेक्टर में दिव्यांगजनों के रोजगार को बढ़ाना है। निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की स्कीम वर्ष 2008-09 में चलाई गई।

स्कीम के अंतर्गत

स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक दिव्यांगजनों के संबंध में प्रथम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी संगठन की दिशा में नियोक्ताओं के अंशदान का भुगतान 25,000 /-रुपए तक मासिक पारिपदागत सरकार द्वारा दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत विविध उपलब्ध अधिनियमों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन के 1.1 प्रतिशत का प्रशासनिक प्रभार नियोक्ता द्वारा अदा किया जाता है। प्रारंभिक, 2008 से प्रभावी है।

लाभों को प्राप्त की वेधि : प्रथम बार जब ईपीएफ और ईएसआई के तहत ऐसे लाभों का दावा किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा दिव्यांग कर्मचारी को जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान सीधे उपलब्ध कराएंगी। इसे तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के संबंध में किया जाएगा। ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के वेतन के 1.1 प्रतिशत का प्रशासनिक प्रभार संबंधी नियोक्ताओं द्वारा अदा किया जाता रहेगा।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

- (क) पहली ईपीएफ और ईएसआई के तहत ऐसे लाभ का दावा किया जाता है, नियोक्ता, सक्षम प्राधिकार कर्मचारियों को जारी अक्षम प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (ख) सरकार के अधिनियमों के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान सीधे उपलब्ध कराएंगी। इसे तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए कर्मचारियों के संबंध में किया जाएगा। ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन के 1.1 प्रतिशत के प्रशासनिक प्रभार संबंधी नियोक्ताओं द्वारा अदा किया जाएगा।
- (ग) दिव्यांगता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एकमुश्त निधि कर्मचारी संगठन तथा अग्रिम के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को उपलब्ध कराएंगी। इसके अंतर्गत नियोक्ताओं से प्राप्त अलग-अलग दावों के समायोजन के प्रयोजन से किया जाएगा। संगठनों की राशि की आवधिक रूप से पुनःपूर्ति की जाएगी।

8.3.7 दिव्यांगजनों में कौशल प्रशिक्षणार्थ राष्ट्रीय कार्ययोजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। उक्त राष्ट्रीय कार्य योजना की संक्षिप्त विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क. पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करना अलग-अलग दिव्यांगजनों, उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बृहत्तर अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक लाभदायी है। अक्षम लोगों के लिए घटिया रोजगार अवसरों तथा परिणामों के कारण अलग-अलग व्यक्तियों तथा समाज को काफी कीमत चुकानी पड़ती है।

ख. **राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)** की योजना केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, पीएसयू तथा निजी क्षेत्र जैसे सभी मुख्य हितधारकों को एक मंच पर लाने की है। एनएपी में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे।

- (i) राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता सिपडा (निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीम) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ii) एमएसडीई के सहयोग से डीईपीडब्ल्यूडी में एक परियोजना प्रबोधन इकाई गठित की गई है। डीईपीडब्ल्यूडी और एमएसडीई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- (iii) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण साझेदारों की अगुवाई में कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क द्वारा व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पद्रान किया जाएगा।
- (iv) एमएसडीई के सहयोग से पीडब्ल्यूडी के लिए एक पृथक क्षेत्र कौशल परिषद स्थापित की गई।
- (v) ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण क्लस्टर हेतु, उनके निजी क्षेत्रीय संगठन तथा पीएसयू नक्शा तैयार करेंगे, जो उन्हें सीएसआर निधि और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा तथा नियोक्ता से जोड़ेगा।

- (vi) कं विकास निगम के साथ डीईपीडब्ल्यूडी इन प्रशिक्षण प्रदाताओं की रोजगार स्थिति सीएसआर सहायता प्राप्त कराने हेतु उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों तथा ग्रुप सेकर मदद करेगा।

(ग) एनएपीडाम के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।

8.3.8 जागरूकता प्रचार स्कीम (एजीएवंपी स्कीम)

उद्देश्य

जागरूकता सृजन रसितम्बर, 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के लिए प्रचालित है। इससे बेऔर कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए सरल बनाने तथा इसके उद्देपात्रता आदि को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में संशोधित किया गया।

स्कीम का उद्देश्यनेक, फिल्म मीडिया आदि के माध्यम से सरकार की स्कीमों/कार्यक्रमों का प्रचार करना; पीडब्ल्यूडी अधिकारों के बारे में सिविल समाज तथा पीडब्ल्यूडी को शिक्षित करना; पीडब्ल्यूडी की वियव पर नियोक्ताओं में संचेतना पैदा करना; दिव्यांगता से संबंधित कारणों पर समाज की जागरूकता बढ़ावा संचेतना पैदा करना; जॉब मेलों सहित पीडब्ल्यूडी हेतु कौशल विकास एवं रोजगार विवजागा अभियान में सहायता करना; सक्षम तथा अवरोध मुक्त माहौल जिसमें सुलभ भवन, सुलभ, वेबसाइटें शामिल हैं, का सृजन करके तथा सुलभ लेखापरीक्षा करके सार्वभौमिक सुलभता मेंरुकता फैलाने में सहायता करना; सक्षमता सेक्टर के क्षेत्र में पृथक-पृथक श्रेष्ठता को बढ़ाने की कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से सहायता की जानी है, में प्रतिभा और प्रोत्साहन करने के लिए खेलकूद तथा एबीलिमिंग क्रियाकलाप करना है।

अनुमेय घटक

1. स्कीम त त हेतु अनुमेय घटकों में पीडब्ल्यूडी की ऑनलाइन परामर्श के लिए हेल्पलाइनएकेस विषय-वस्तु; अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी अथवा गैर-सरकारी संगठन वसा समूहों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता देना; वाणिज्यिक स्थापनाओं में संचेतना पैदा करने के लिए स्वयंसेवक सेवा/आउटरीच कार्यक्रम; मनोरंजनयतामुदायिक रेडियो में भागीदारी; मीडिया क्रियाकलाप; जॉब मेलों सहित पीडब्ल्यूडी शकास तथा रोजगार सृजन हेतु जागरूकता अभियान में सहायता करना; समर्थ मुक्तल जिसमें सुलभ भवनों/सुलभ परिवहन, सुलभ वेबसाइटें शामिल हैं तथा सुलभता के सार्वभौमिक सुलभता के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करना; दिव्यांगता में वैयक्तिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देना; पीडब्ल्यूडी जिसकी कार्यक्रमों,

जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से सहायता की जानी है, में प्रतिभा और कौशल को बढ़ाने के लिए खेलकूद तथा एबीलिम्पिंग क्रियाकलाप शामिल हैं।

स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता

- (क) अल्पावधि परियोजनाएं (एकबारगी के कार्यक्रम) अथवा परियोजनाएं 6 माह की अवधि से ज्यादा के नहीं होने चाहिए); वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा :

75 प्रतिशत – अनुमोदन, स्वीकृति पर, आवश्यक बांड आदि के निष्पादन पर

25 प्रतिशत – मदवार व्यय के साथ लेखा की लेखापरीक्षा विवरण, प्रथम किस्त के लिए अंतिम रिपोर्ट और यूसी की प्राप्ति पर

- (ख) दीर्घावधि परियोजनाएं (6 माह तथा और अधिक अवधि की परियोजनाएं); अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति तथा बैंक गारंटी/बांड के कार्यकाल आदि भेजने पर

40 प्रतिशत – अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति तथा बैंक गारंटी/बांड के कार्यकरण आदि ले जाने पर

40 प्रतिशत – प्रगति समीक्षा, प्रथम किस्त के यूसी की प्राप्ति के बाद

20 प्रतिशत – अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए यूसी; तथा मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर

- (ग) जब स्कीम के अंतर्गत एक क्रियाकलाप केंद्र/राज्य सरकार के तहत सीधे ही संस्थाओं द्वारा शुरू किया जाता है, निधि वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार संस्वीकृत तथा जारी की जाएगी।

अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

- (I) स्व-सहायता समूह
- (ii) एडवोकेसी तथा सेल्फ – एडवोकेसी संगठन
- (iii) समाज के रवैये में परिवर्तन लाने तथा उसके संघटन हेतु कार्यरत माता-पिता एवं समुदाय
- (iv) मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक सहायता सेवा
- (v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन

- (vi) पीडब्ल्यूडी न तथा समाज से अलग-अलग रहने का उन्मूलन करके, सहायता सेवाएं उपलब्ध श्रमार्थ कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहित अक्षमता सेक्टर कार्यगठन
- (vii) विभागों, छात्रसंस्थाओं, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण।

पात्रता मानक

- (i) सोसायटी नियम, 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत कोई लक्ष्यार्थ और धर्मदा वृत्तिका अधिनियम, 1920 अथवा कंपनी अधिनियम आदि के धारा अंतर्गत कोई निगम अथवा केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम अंतर्गत सहित 4(क) के अंतर्गत संगठनों के लिए पंजीकृत संगठन के रूप में कम से कम 1।
 - (ii) संगठन लाभ तथा लाभ के लिए नहीं संगठन अथवा इसमें लाभ यदि कोई हो, अथवा धर्मार्थ देन्य आय का उपयोग करना चाहिए।
 - (iii) विभागों, छात्रसंस्थाओं, कॉलेजों आदि अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत निगम केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत केंद्रय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजी से छूट प्राप्त है।
 - (iv) विगत की ति लेखापरीक्षित और उचित रखरखाव के लेखाओं और आय कर रिटर्न तथा प्रकाशित रिप
 - (v) प्रासंगिक लासके लिए अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई एक क्रियाकलापों के रूप में समझौते में बित होना चाहिए।
 - (vi) संबंधित एक ट्रैक रिकार्ड होने के रूप में ऐसे संगठन पर अनुदान हेतु विचार किया जा सकता
 - (vii) गैर-संगठनमाले में, प्रस्ताव हेतु राज्य सरकार से संस्तुति अपेक्षित है।
2. जागरण पार स्कीम सितम्बर, 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के लिए है स्कीम को बेहतर और कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए जाने इसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में संशोधन

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण निधियां पूर्ण जारी नहीं की गई थी, स्कीम सितम्बर, 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के लिए प्रचालित है।
4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण निधियां पूर्ण जारी नहीं की गई थी, स्कीम को बेहतर और कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए सरल बनाने तथा इसके कार्य क्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में संशोधित किया गया।
5. वित्तीय वर्ष 2016-17 में, गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न परियोजनाओं/प्रस्तावों/कार्यक्रमों के लिए कुल स्वीकृत बजट 3.00 करोड़ रु. में से 1,76,70,276/- रु. की निधियां जारी की गई हैं।

वर्ष 2016-17 की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जिसके लिए स्कीम के अंतर्गत निधि जारी की गई।

- दिव्यांग युवाओं के लिए आईटी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एनआईटी, कुरुक्षेत्र को 10.18 लाख रु. की राशि जारी की गई थी।
- पहला टी-20 एशिया कप ब्लांड टूर्नामेंट जीतने पर 19 विजेता सदस्यों को नकद पुरस्कार के वितरण हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली को 28.50 लाख रु. की राशि जारी की गई।
- ब्राजील में रियो पैरा ऐबिलंपिक्स विजेताओं के सम्मान/नकद पुरस्कार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली को 90.00 लाख रु. की राशि जारी की गई।

वित्तीय लक्ष्य-

वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान अनुमानित और व्यय को दर्शाने वाले विवरण के ब्यौरे।

रु. करोड़ में

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
2014.15	3.00	2 ^{०००}	0.71
2015.16	5.00	4 ^{०००}	2.62
2016.17	3.00	.	1.81

शीर्षल और व्यय (2016-17) (24.01.2017 तक)				
	अजा	अजजा	एनईआर	कुल
बजट	0.48	0.24	0.30	3.00
व्यय	0	0	0	1.81
शेष	0.48	0.24	0.30	1.19

8.4 जिला विकलांगसद (डीडीआरसी)

जागरूकता विकास, ण और पुनर्वास व्यावसायिकों का मार्गदर्शन करने हेतु जिला स्तर पर अवसंरचना तथा ण जन को सुकर बनाने हेतु राज्य सरकारों की सक्रिया सहायता से मंत्रालय देश के सभी असे में विकलांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना करके दिव्यांगजनों को व्यापक सेवाएं उपलब्ध करा रहा णको जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और जिला स्तर पर बु णता निर्माण सुविधाजनक बनाने के लिए जागरूकता सर्जन पुनर्वास और पुनर्वास व्यावसायिक व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की आउटरीच गतिविधियों के णिवि पुनर्वास केन्द्र शुरू किया गया था। डीडीआरसी की स्थापना की स्कीम नौवी पंचवर्षीय यो रंभ ई थी।

डीडीआरसी के

डीडीआरसी को णराजकारों द्वारा वित्तीय, अवसंरचनात्मक, प्रशासनिक तथा तकनीकी उपलब्ध कराई जाती है त ढ्वंघित जिलों में दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। डीडीआरसी के ढू निमार है :-

- शिविर के ण से दिव्यांगजनों का पता लगाना तथा सर्वेक्षण;
- दिव्यांग णप्रोत्साहन देने हेतु जागरूकता विकास;
- शीघ्र ह
- सहाय णों रुरत का मूल्यांकन, सहायक उपकरणों का प्रावधान/फिटमेंट, सहायक उपकरण लो रमत;
- थेराप्यु ण अफेजियोथरेपी, व्यवसाय चिकित्सा, वाक चिकित्सा आदि;

- दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बस पास और अन्य छूट तथा सुविधाएं;
- सरकारी तथा धर्मार्थ संस्थान के माध्यम से चिकित्सीय करेक्शन हेतु रेफरेल और प्रबंधन;
- एनएचएफडीसी के राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों सहित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से स्व-रोजगार के लिए ऋणों का प्रबंधन;
- दिव्यांगजनों, उनके माता-पिता तथा परिवार के सदस्यों को परामर्श देना;
- बाधामुक्त वातावरण का उन्नयन;
- दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार बढ़ाकर सहायक और पूरक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अध्यापकों, समुदाय और परिवारों को अभिविन्यास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन तथा प्रारंभिक प्रेरणा हेतु दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त व्यवसायों का पता लगाना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की डिजाइनिंग और उन्हें उपलब्ध कराना तथा उपयुक्त जॉब्स का पता लगाना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।
- मौजूदा शैक्षणिक, प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक संस्थाओं हेतु रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराना।

स्कीम राज्य और केंद्रीय सरकार का संयुक्त उद्यम है। डीडीआरसी 3 वर्षीय प्रारंभिक अवधि (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली मामले में 5 वर्ष) के लिए “पीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्कीमों” के माध्यम से वित्तपोषित हैं तथा इसके उपरान्त क्षीणता के आधार पर दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम के माध्यम से निधियन किया जाता है।

258 डीडीआरसी की स्थापना की गई (अर्थात् कम से कम एक बार अनुदान सहायता दी गई) चालू वर्ष 2016-17 में कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दो नई डीडीआरसी की स्थापना की

वर्ष 2016-17 के डीडीआ को जारी निधियों के ब्यौरे अनुलग्नक-12 (पृष्ठ सं. 283)

डीडीआरसी को नि

दिशा निर्देशों की प्रस्तावों का है:-

- आवर्ती अर्ती के लागत मानक दिनांक 1.4.2010 से संशोधित किए गए हैं। हाई एट्रिटीय क्षेत्र स्टर्बर्ड क्षेत्रों एवं जनजातीय उप-योजना के क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों में स्थित डी केस व्यावसायिकों को शेष देश के लिए निर्धारित दरों की तुलना में 20 प्रतिशत मानका हक दिया जाएगा।

- सिपडा त र्ष प्रति डीडीआरसी वर्तमान लागत मानक

(लाख में)

म	लागत मानक (प्रतिवर्ष)	
	सामान्य	विशेष क्षेत्रों हेतु 20 प्रतिशत वृद्धि
कुल मान	8.10	9.72
कार्यालय कार्याएं	2.10	2.10
उपकरण (एक हेतु)	7.00	7.00
प्रथम व	17.2	18.82
द्वितीय कुल	10.2	11.82
तृतीय कुल	10.2	11.82
पीडब्लू नेय अंतर्गत कुल व्यय	37.6	42.46

स्तर शरि कुल व्यय प्रतिवर्ष 8.10 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली तथा जम्मू व कश्मीर के मामले में 9.7 रुपए थक नहीं किया जाएगा।

तय हैं, जब कभी जरूरत महसूस हो उनको उपलब्ध निर्णय में से डीडीआरसी को थवा जरूरतों की पूर्ति के लिए जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती हैं।

- **जिला विकलांग पुनर्वास अधिकारी (डीडीआरओ)**

जिला प्रबंधन टीम द्वारा यथानिर्णीत डीडीआरसी के मौजूदा व्यावसायिकों में से एक अथवा एक उपयुक्त राज्य सरकार का पदाधिकारी डीडीआरओ के रूप में पदनामित किया जाएगा।

दिन-प्रतिदिन आधार पर डीडीआरसी के समन्वयन, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए डीडीआरओ उत्तरदायी होगा तथा प्रतिमाह 2000/-रुपए की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

- **सिपडास के अंतर्गत डीडीआरसी को निधियन की अवधि**

पूर्व संशोधित स्कीम में, डीडीआरसी को निधियन की अवधि सभी राज्यों हेतु 3 वर्ष तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए 5 वर्ष थी। अब जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में एसआईपीडीए के अंतर्गत निधियन 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा।

- **डीडीआरसी के अंतर्गत अनुदान की टेपरिंग**

पूर्व संशोधित स्कीम में, 3/5 वर्षों के उपरान्त अनुदान की 10 प्रतिशत वार्षिक टेपरिंग की जाती है परंतु तत्कालीन संशोधित स्कीम में डीडीआरसी को अनुदान की टेपरिंग इसके बाद उन्होंने डीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत निधि प्राप्त करनी शुरू की, जो निम्नानुसार प्रतिबंधित की जाएगी :

क) 2 वर्षों के अंतराल पर अनुमेय सहायतानुदान में 5 प्रतिशत कटौती

ख) सहायतानुदान में टेपरिंग अनुमेय लागत का 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

ग) ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए टेपरिंग लागू नहीं होगी।

- **राज्य सरकार की भूमिका**

राज्य सरकारों से डीडीआरसी के कारगर कार्यकरण में और अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की प्रत्याशा है। राज्य/जिला प्रशासन की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार कारगर ढंग से उनको विभिन्न क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु डीडीआरसी की अन्य जरूरतों व मानदेय की उपयुक्त रूप से पूर्ति कर सकती है।

राज्य सरकारें डीडीआरसी स्कीम के बृहत अनुबंध के भीतर धरातलीय सच्चाई पर विचार करते हुए डीडीआरसी के कारगर कार्यों हेतु आशोधन करने के लिए डीएमटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता के तहत जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती है।

राज्य सरकारें केंद्रीय फंडों को जारी करने में कार्यविधि के क्षेत्र में कठिनाइयों से पार पाने के लिए उनके डिस्पोजल पर स्थानीय निधि में से अंतरिम अग्रिम राशि देने हेतु भी जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती हैं।

9

अध्याय

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसईज)

9.1 राष्ट्रीय विकलांग विकास निगम (एनएचएफडीसी)

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और निरनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1996 में हुई थी। यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8) के अधीन निरन कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा स्वाधिकृत है तथा इसकी 400 करोड़ रुपए (चौदह करोड़) की अधिकृत शेयर पूंजी तथा 342.58 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी हो। कम्पनी का प्रबंध भारत सरकार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

1. निगम के मुख्य नीए गए हैं:

1. दिव्यांग लाभार्थिक विकास गतिविधियों तथा स्व-रोजगार उद्यमों को प्रोत्साहन देना।
2. स्व-रोजगारमोसमुचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजनों के उद्यम-कौशल के कोटिकरण करना।
3. दिव्यांग वयिक/तकनीकी शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करना ताकि वे व्यवसायिक पुनर्वांगजसिल कर सकें।
4. स्व-रोजगार दिव्यांगजनों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता प्रदान करना।

2. कार्यप्रणाली है:

एनएचएफडीसी का द्वारा नामित राज्य चैनल एजेन्सियों (एससीएज) और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के प्रवाह हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।

(क) क्रेडिट आधारित गतिविधियां :

एनएचएफडीसी 40 प्रतिशत अथवा अधिक दिव्यांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्राह्य भारतीय नागरिकों को आय जननकारी इकाई स्थापित करने के लिए सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभिन्न स्कीमों का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	स्कीम	अधिकतम ऋण (लाख रुपए)	लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर	ऋण चुकाने हेतु अधिकतम अवधि
1	विक्रय/ व्यापार गतिविधि में छोटा व्यवसाय	5.00	5-6 प्रतिशत	10 वर्ष
2	सर्विस सेक्टर में छोटा व्यवसाय	7.50	5-7 प्रतिशत	10 वर्ष
3	वाणिज्यिक वाहनों का क्रय	10.00	5-7 प्रतिशत	10 वर्ष
4	विशेष संवर्ग के वाणिज्यिक वाहनों का क्रय	25.00	5-8 प्रतिशत	10 वर्ष
5	लघु औद्योगिक इकाई	25.00	5-8 प्रतिशत	10 वर्ष
6	कृषि गतिविधियां	10.00	5-7 प्रतिशत	10 वर्ष
7	मानसिक अवमंदता तथा ऑटिज्म पीड़ितों के लिए स्व-रोजगार	10.00	5-7 प्रतिशत	10 वर्ष
8	दिव्यांग युवा व्यवसायों के लिए ऋण	25.00	5-8 प्रतिशत	10 वर्ष
9	स्वयं की भूमि पर व्यवसाय परिसर विकसित करने हेतु स्कीम	3.00	5-6 प्रतिशत	10 वर्ष
10	सहायक उपकरणों के क्रय हेतु स्कीम	5.00	5-6 प्रतिशत	10 वर्ष
11	विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण	20.00	4 प्रतिशत (पुरुष) 3.5 प्रतिशत (महिला)	7 वर्ष
12	भारत में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण	10.00	4 प्रतिशत (पुरुष) 3.5 प्रतिशत (महिला)	7 वर्ष

13	व्यवसायिक ऋण	2.00	5-6 प्रतिशत	7 वर्ष
14	मानसिक तयों के लिए अभिभासियेऋण	5.00	5-6 प्रतिशत	10 वर्ष
15	सूक्ष्म उद्योग (एससी माध्य)	10.00 / एनजीओ (रु. 0.50 लाख / लाभार्थी)	5 प्रतिशत तक	3 वर्ष
16	दिव्यांगों में रक्षमता विस्तार के लिए एगोज हेतु स्कीम	5.00	5-6 प्रतिशत	5 वर्ष

दिव्यांगों की स्व-रोजगारों में ब्याज पर 1 प्रतिशत और शिक्षा ऋण स्कीम के अधीन ब्याज दो श छूट की अनुमति है।

वीएच / एको सभी स्व-रोजगारों में ब्याज पर 0.5 प्रतिशत की छूट की अनुमति है।

(ख) गैर ब्रेग्रास्तिविधियां :

एनएचएफडीसी की प्राप्ति के लिए दिव्यांगजनों को निधियां उपलब्ध कराता है तथा उनकी विविधियों का आयोजन भी करता है। ये हैं :

1. **शिक्षण कार्यक्रम** : कौशल एवं उद्यमिता विकास की स्कीम के तहत प्र संचालन / प्रायोजन के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है।
2. **रक्षणरुक्ता** : एनएचएफडीसी क्रियान्वन एजेन्सियों को एनएचएफडीसी को वीपन एवं प्रचार के लिए निधियां भी उपलब्ध कराता है।
3. **हो सहायता** : एनएचएफडीसी पंजीकृत संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने अथवा श्रमिकों में प्रवेश में पीडब्ल्यूडीज को सूचना प्रदान करने, प्रक्रिया को वेजी औपचारिकताओं हेतु सहायता प्रदान करने के लिए प्रति पीडब्ल्यूडीज / ए की हैंड-होल्डिंग सहायता भी प्रदान करता है।

3. छात्रवृत्ति योजना :

एनएचएफडीसी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए दिव्यांगजना सशक्तिकरण विभाग की छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रही हैं:-

4. प्रदर्शन और उपब्धियां (2016-17)

i) भौतिक और वित्तीय उपब्धियां

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31-12-2016 तक), एनएचएफडीसी की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या (*)
(i)	स्वीकृति	46.47	9916
(ii)	संवितरण	43.28	9870

*विमोचित अग्रिम निधि के विरुद्ध औसत ऋण आधार पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित

ii) ईडीपी तथा कौशल विकास प्रशिक्षण

2016-17 के दौरान (31-12-2016 तक) निगम 13010 दिव्यांगजनों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 15.29 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत कर चुका है।

5. पहलें :

निगम ने हाल की अवधि में इसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ पहल की हैं, ये निम्नानुसार हैं:

क) एनएचएफडीसी की ऋण प्रदाय नीति की प्रभावोत्पादकता एवं पहुंच बढ़ाने के लिए उदारीकरण :

- एससीए का प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल: एससीए के प्राधिकारी ने लाभार्थियों को ऋण प्रत्येक परियोजना 5.0 लाख रु. से 10.00 लाख रु. बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब एससीए प्राधिकारी के प्रतिनिधिमंडल के तहत अग्रिम निधियों से 10.00 लाख रु. तक का ऋण मंजूर और जारी कर सकता है।
- एनएचएफडीसी विक्री/सेवा गतिविधि स्कीमों के तहत उच्च ऋण सीमा का संवर्द्धन:-

ऋण निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत बढ़ाई गई है:-

सो।

1. और व्यापार के क्षेत्र में गतिविधि : रु. 3.00 लाख रु. 5.00 लाख

सैक्टर गतिविधि : रु. 5.00 लाख रु. 7.50 लाख

(iii) **सीडीसी शर्त में शिथिलता** :- अब पार्टनर बैंक स्व-रोजगार के लिए एचएफसी स्क्रीम के अधीन विकलांगजनों को 25.00 लाख रुपए तक का ऋण प्रतीफल प्रदान कर सकते हैं भले ही ये गतिविधियां सीडीसीएमएसई के अधीन त हों नहीं।

(iv) **तृष्ण (सीपी) शब्द के रूप में योजना में प्रदर्शित किया गया था, मानसिक मंदता, तृष्ण अथवा स्वलीनता व्यक्तियों से हटा दिया गया है।** प्रमस्तिष्क घात से ग्रस्त त क्य श्रेणियों अर्थात अस्थि विकलांग, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि दिव्यांग की निम्न अन्य सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता करने के लिए अनुमति दी है।

(ख) **गैर-वित्तकम्पनी-सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) इत्यादि के साथ**

एनएच ने एफसी-एमएफआई के व्यापक चैनल के माध्यम से दिव्यांगजनों को रियायती क्रेडिट हेतु एफसी-एमएफआई के साथ गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ की है क्योंकि वहां अतिवित्त हैं। इससे एनएचएफडीसी को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में पीडितों ने सहायता मिलेगी, और अन्य क्षेत्र जहां नियमित चैलेलाइजिंग एजेंसियां काम नहीं करती हैं।

(ग) **दिव्य के राष्ट्रीय स्तर पर जॉब पोर्टल :-**

दिव्य शक्ति विभाग के मार्गदर्शन में, एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल (www.disabilityjobs.gov.in) विकसित किया है। जॉब पोर्टल सिंगल प्लेटफॉर्म को जॉब के अवसर, स्वरोजगार ऋण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा ऋण आदि प्रदान करता है। पोर्टल दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(घ) **सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार** - एनएचएफडीसी ने स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए एनएचएफडीसी स्क्रीमों के तहत दिव्यांगजनों को रियायती क्रेडिट हेतु बैंक ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथ करार किए हैं।

(ड) राज्य/संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मानीटरिंग की प्रणाली:

एनएचएफडीसी में निगम की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के मानीटरिंग हेतु निम्नलिखित आंतरिक तंत्र मौजूद है:

i) ऋण का उपयोग :

क्रियान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग निधियां जारी करने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी राशि के उपयोग के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ii) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं:

एनएचएफडीसी इसकी राज्य चैनल एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करता है। एनएचएफडीसी स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में ऐसे सम्मेलन/कार्यशालाएं की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनएचएफडीसी स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में अवरोधों/समस्याओं पर विचार-विमर्श एवं मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त विचार-विमर्श के आधार पर नीतियों में एनएचएफडीसी के उद्देश्यों की सीमांतर्गत उपयुक्त संशोधन किया जाता है।

iii) आंतरिक समीक्षा बैठक :

विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी की स्कीमों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/अनुवीक्षण किया जाता है तथा स्कीमों के कारगर प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

6. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि में से वित्त पोषित दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम

निगम ने 2011-12 से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि में से वित्त पोषित दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम का कार्यान्वित की है

वर्ष 2011-12 से आगे और चालू वित्त वर्ष (31.12.2015 तक) के दौरान दिव्यांग छात्रों (न्यास निधि) दिव्यांग छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	शै	प्रदान की गई छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति राशि (रुपए में) (नवीनीकरण छात्रवृत्ति सहित)
1	20	1000	57649796
2	20	1000 नई (216 नवीनीकरण)	77748872
3	20	2000 नई (293 नवीनीकरण)	132416657
4	20	1414 नई (158 नवीनीकरण)	88200115
5	20	2500 नई (497 नवीनीकरण)	175217,229
6	20	2800 नई (72 नवीनीकरण)	19,72,79,505
	कुल	9000 नई और 1732 नवीनीकरण	63,59,49,002

7. एमओयू मूल्यांकन

डीपीई (लोक उद्योग) द्वारा द्विगम के प्रदर्शन/उपलब्धियों का 2015-16 के विभिन्न लक्ष्यों का मूल्यांकन 2015-16 हेतु करार किया गया था।

8. कौशल प्रशिक्षण

एनएचएफडीसी ने कौशल प्रशिक्षण पर बल दे रहा है। अब तक एनएचएफडीसी इसके फरीदाबाद केन्द्रों द्वारा सरकारी/प्रतिष्ठित भागीदारों में दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा है। हालांकि, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एनएचएफडीसी ने उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्वयं का कौशल केन्द्र प्रारंभ किया है।

9. प्रदर्शनी/जागरण विज्ञापन मेला/सम्मेलन/कार्यशालाओं के ब्यौरे

राष्ट्रीय विकलांग और अस निगम (एनएचएफडीसी) ने 2016-17 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम/जागरण व अभियानों दिव्यांगजनों के बीच में/सार्वजनिक के बारे में इसकी स्कीमों में भाग लिया है :-

क) जागरूकता शिविर

- 1) एनएचएफडीसी ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन, ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में 13.04.2016 से 15.04.2016 तक अंबेडकर पार्क ग्वालियर, मध्य प्रदेश में भाग लिया। निगम के अधिकारियों ने जनता के लिए अपनी स्कीमों के बारे में जानकारी दी।
- 2) एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लिए 26.04.2016 से 28.04.2016 तक स्पर्श मेला, बालाघाट, मध्य प्रदेश में भाग लिया और एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने निगम की स्कीमों के बारे में जानकारी दी।
- 3) एनएचएफडीसी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 07 मई, 2016 से 31 मई, 2016 तक मालवा व्यापार केन्द्र, सिंहस्त कुंभ, उज्जैन में भाग लिया। एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में प्रदर्शनी में जानकारी दी गई थी।
- 4) एनएचएफडीसी ने 04 जून, 2016 को ए-15/7, महाकाल वाणिज्य केन्द्र, नानाखेडा, उज्जैन में क्षेत्रीय केन्द्र-सह प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया। दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निगम की स्कीमों के बारे में आगुन्तकों/जनता के लिए समझाया गया।
- 5) एनएचएफडीसी ने निगम के पंजीकृत कार्यालय फरीदाबाद में 21 जून, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। फरीदाबाद कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में दिव्यांगजनों के लिए चलाये गए कौशल प्रशिक्षण और निगम के कर्मचारियों ने मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में प्रशिक्षुओं (दिव्यांगजन) के बीच बताया गया।
- 6) एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इंडिया गेट, नई दिल्ली में 17.07.2016 को आयोजित सुगम्य भारत अभियान (बाइक राइडर्स) में भाग लिया, दिव्यांगजनों के लिए एनएचएफडीसी स्कीमों की जानकारी दी गई।
- 7) एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने एलिम्को द्वारा आयोजित 06.08.2016 को मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश मेगा वितरण कैंप में एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में जानकारी दी।
- 8) एनएचएफडीसी ने 17 सितंबर, 2016 को नवसारी, सूरत, गुजरात में आयोजित मेगा कैंप में भाग लिया और एनएचएफडीसी स्कीमों की जानकारी दी।

- 9) एएफ ने 09.10.2016 को भावनगर, गुजरात में प्रभात इंटरप्राइजेस के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों/आगंतुकों के बीच एएफ की स्कीमों की जानकारी दी।
- 10) एएफ ने 15 अक्टूबर, 2016 को रायपुर, गुजरात में आयोजित मैगा कैंप में भाग लिया और एचएफडीसी स्कीमों की जानकारी दी।
- 11) एएफ ने 22 अक्टूबर, 2016 को वडोदरा गुजरात में आयोजित मैगा कैंप में भाग लिया और दिव्यांगजनों के लाभ के लिए स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।
- 12) एएफ ने एलिम्को, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरकार द्वारा 25.11.2016 को सैक्टर-12 फरीदाबाद में आयोजित मैगा कैंप में भाग लिया। दिव्यांगजनों के लाभ के लिए स्कीमों के बारे में शिविर में जानकारी दी गई थी।
- 13) एएफ ने समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 1.12.2016 आयोजित सामान्य दिव्यांगता शिविर में भाग लिया। एनएचएफडीसी के शिविर में आगंतुकों को एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।
- 14) एएफ ने क्षेत्रीय सह प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र उज्जैन में दो ट्रेडों में 106 प्रशिक्षणार्थी (50 हस्त कढ़ाई में + 56 मोबाईल रिपेयर में) टूल किट वितरित किए। श्री वृन्दावत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इस अवसर की अवसर एचएफडीसी की स्कीमों की प्रतिभागियों को जानकारी भी दी गई।

(ख) प्रदर्शनी मेले

- 1) एएफ ने 26 से 29 सितंबर, 2016 तक पंडित दीनदयाल कृषि उन्नति मेले में भाग लिया जिसमें श्री मनु मिश्रा, प्रबंधक (परियोजना) और श्री राजू कुमार, कनिष्ठ प्रबंधक एचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।
- 2) एएफ ने स्वदेशी जागरण मंच दशहरा मैदान, मोहाली, पंजाब द्वारा 19 से 23 अक्टूबर, 2016 तक आयोजित किए जा रहे स्वदेशी मेला में भाग लिया। जिसमें, एएफ के 03 लाभार्थियों और अधिकारियों कार्मिकों सहित उनके उत्पादों का प्रदर्शन किया और एनएचएफडीसी की स्कीमों की भी जानकारी दी गई।

- 3) एनएचएफडीसी ने 16 से 25 दिसंबर, 2016 तक गंगटोक में आयोजित 8वे हिमालय एक्सपो में भाग लिया, इसमें एनएचएफडीसी के कर्मचारियों ने एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।

(ग) रोजगार मेला:-

- 1) एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने 20 अगस्त, 2016 को आयोजित डिसेबिलिटी हैल्प लाईन फाउंडेशन द्वारा आशा विद्यालय आफ दी डीफ, जी.टी.रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित रोजगार मेला और कार्यशाला में एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।
- 2) एनएचएफडीसी ने 07 और 08 सितंबर, 2016 को प्रशिक्षण भागीदारों के साथ (भारतीय कौशल परिषद, नई दिल्ली, एचएआरडीआईसीओएन, वीआरसीएच, नई दिल्ली और एनएसआईसी, ओखला) रोजगार मेला आयोजित किया, जिसमें 213 दिव्यांगजनों को रोजगार मेले में 12 प्रतिभागी कंपनियों द्वारा चयनित किया गया और दिव्यांगजनों को एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारियां भी दी गई।
- 3) एनएचएफडीसी ने ब्लांड पिपुल एसोसिएशन द्वारा आयोजित अहमदाबाद में रोजगार मेले में भाग लिया। जिसमें एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।
- 4) एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने 16 और 17 जनवरी, 2017 को वीआरसीएच, कडकडडुमा नई दिल्ली द्वारा आयोजित रोजगार मेले में एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।

(घ) सम्मेलन/कार्यशालाएं:-

- 1) **राष्ट्रीय सम्मेलन:-** एनएचएफडीसी ने एनएचएफडीसी की स्कीमों की समीक्षा और कार्यान्वयन के मुद्दों के समाधान के लिए 15.01.2016 को एनसीयूआई आडियोटाओरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-16 में चैनेलाइजिंग एजेंसियों (कार्यान्वयन एजेंसियों) के साथ सम्मेलन का आयोजन किया। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इस अवसर का उद्घाटन और सम्बोधित किया।
- 2) **क्षेत्रीय सम्मेलन:-** एनएचएफडीसी ने पूर्वोत्तर में एनएचएफडीसी की स्कीमों की समीक्षा और कार्यान्वयन के मुद्दों के समाधान के लिए 05 जनवरी, 2017 को पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहटी में इसके भागीदारों के साथ एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

9.2 भारतीय कृत्रिमनेगम (एलिम्को)

1. निगमिता

एलिम्को "सूक्ष्म" लघुरत्न श्रेणी II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो कम्पनी अधिनियम की 3 (लाभ के लिए नहीं उद्देश्य), (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप संगठित है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्ति विभाग सार्वजनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत वात्सीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका उद्देश्य देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढ़ाने, प्रयोग, आपूर्ति और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित है। इसका लाभप्रद के संचालन का मकसद नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित बड़ी में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध है। इसने वर्ष 1976 में कृत्रिम सहायक यंत्रों का निर्माण शुरू किया था। इसके भुवनेश्वर, पुर (मध्य प्रदेश), बंगलुरु (कर्नाटक), और चानालोन (पंजाब) में स्थित चार आनुशोचन (एएपीसी) हैं। इस निगम के नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में चार केन्द्र गुवाहाटी में एक आउटरीच केन्द्र है।

2. वर्ष 20 के निगम के वित्तीय भौतिक प्रदर्शन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े नीचे दिए हैं।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16 की उपलब्धियां	2014-15 की उपलब्धियां	2014-15 का प्रतिशत
क	विवरण			
	क	189.36	162.70	16.39%
	उत्पन्न मूल्य	190.98	162.69	17.39%
	आ	46.20	31.65	45.97%
	नि	182.47	84.14	116.86%

ख	भौतिक प्रदर्शन (मुख्य उत्पादों का भौतिक प्रदर्शन)	उत्पादक (संख्या में)		2014-15 का प्रतिशत	बिक्री (संख्या में)		2014-15 का प्रतिशत
		2014-15	2015-16		2014-15	2015-16	
(i)	ट्राईसाइकिल	77,012	80490	4.52%	75,392	78,598	4.25%
(ii)	व्यहीलचेयर	34,722	41309	18.97%	37,939	44,536	17.39%
(iii)	क्रयचेज	63,341	62991	-0.55%	62,409	67,272	7.79%
(iv)	प्रोस्थेटिक अपर और लोअर किट और कंपोनेंटस	24,113	29180	21.01%	37,463	13,940	-62.79%
(v)	आर्थोटिक लोअर किटस और कंपोनेंटस	38,831	10379	-73.27%	57,273	67,352	17.60%
(vi)	श्रवण यंत्र	77,685	48544	-37.51%	79,228	49,367	-37.69%

3. बिक्री पैटर्न

वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री पैटर्न नीचे दिया गया है:

(रु. करोड. में)

खरीद श्रेणी	2015-16 की बिक्री	2015-16 का अंश प्रतिशत	2014-15 की बिक्री	2014-15 का अंश प्रतिशत
राष्ट्रीय संस्थान	5.93	3.13%	11.13	6.84%
एडिप और कोकलियर	84.45	44.60%	65.21	40.08%
एसएसए (60%)	35.65	18.83%	31.79	19.54%
एसएसए (40%)	22.83	12.06%	21.19	13.02%
राज्य सरकार सीधी खरीद	7.09	3.74%	9.47	5.82%

डीलरस,	12.74	6.73%	7.63	4.69%
सीएसआर, बिलाट्रलर अ	20.67	10.91%	16.28	10.01%
कुल	189.36	100%	162.70	100.00%

4. एडिप के

निगम द्वारा 2014-15 में 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संचालित 305 शिविरों के माध्यम से 707 लाभार्थियों, जिनमें 51244 (72.41 प्रतिशत) पुरुष तथा 19521 (27.59 प्रतिशत) थीं, सेवा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 387 शिविरों के माध्यम से कुल 118234 लाभार्थियों, 87469 (73.98 प्रतिशत) पुरुष तथा 30765 (26.02 प्रतिशत) महिलाएं थीं, को सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त, 2014-15 के दौरान 18,855 लाभार्थियों को एक से अधिक रूपक कृत्रिम अंग/बैसाखियां प्रदान की गई थीं।

2015-16 में 387 शिविरों में से 25 शिविर पूर्वोत्तर राज्यों में संचालित किए गए थे, जिनमें वर्ष 2015 में संचालित 59 शिविरों के माध्यम से कुल 8651 लाभार्थियों, जिनमें 5236 (60.29 प्रतिशत) पुरुष तथा 3415 (39.48 प्रतिशत) महिलाएं थीं, की सेवा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 2 लाभार्थियों, जिनमें 3576 (67.19 प्रतिशत) पुरुष तथा 1746 (32.81 प्रतिशत) महिलाएं प्रदान कर चुका है।



5. एडिप-हैंड

एडिप-हैंड की तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1189 शिविरों में 4 वयु वर्ग के विशेष जरूरतमंद बच्चों को कुल 74704 सीडब्ल्यूएसएन जिनमें 47237 पुरुष तथा 27467 (36.77 प्रतिशत) महिलाएं थीं, की सेवा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1810 शिविरों कुल 79926 लाभार्थियों, जिनमें 51200 (64.06 प्रतिशत) पुरुष तथा 28726 (35.94 प्रतिशत) महिलाएं थीं, को सेवाएं प्रदान कर चुका है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय

वर्ष 2014-15 के दौरान लाभार्थियों को एक से अधिक सहायता उपकरण/कृत्रिम अंग/बैसाखियां प्रदान की गई थीं, जिसमें कुल मिलाकर 88,399 लाभार्थियों को सहायता पर विचार किया गया था।

2015-16 के दौरान संचालित 1130 शिविरों में से 171 शिविर पूर्वोत्तर राज्यों में संचालित किए गए थे, जिनमें वित्तीय वर्ष 2014-15 में संचालित 125 शिविरों के माध्यम से कुल 5609 लाभार्थियों, जिनमें 2401 (63.80 प्रतिशत) पुरुष तथा 1362 (36.20 प्रतिशत) महिलाएं थीं, की सेवा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-1 में कुल 5609 लाभार्थियों, जिनमें 3381 (60.28 प्रतिशत) पुरुष तथा 2228 (39.72 प्रतिशत) महिलाएं थीं, को सेवाएं प्रदान कर चुका है।



6. गिनीज विश्व रिकार्ड

सामाजिक अधिकारिता शिविर और दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए स्कीम (एडिप) शिविर में 17 सितंबर, 2016 को नवसारी, गुजरात में तीन विश्व रिकार्ड बनाए गए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में अवसर की शोभा बढ़ाई।

1. **पहला रिकार्ड** – “एक ही स्थान पर सर्वाधिक तेल लैंपों की संख्या प्रज्वलित किए गए” मैगा शिविर में स्थापित किया गया था (16 सितंबर, 2016)। अविश्वसनीय 989 दिव्यांगजन एक सब नया रिकार्ड खिताब हासिल करने के लिए 500 प्रतिभागी उपलब्धि स्थापित करने के लिए एक साथ आए। प्रत्येक व्यक्ति को 30 सैकेंड के भीतर एक समान समय के साथ दीपक जलाने की चुनौती थी।
2. **दूसरा रिकार्ड** – “सबसे बड़ा व्यहील चेयर लोगो” 17 सितंबर, 2016 को नवसारी, गुजरात में तोड़ा गया था। 1000 प्रतिभागियों ने व्यहील चेयर तीन रंग में संदेश में कहा “जन्म दिन मुबारक हो प्रधानमंत्री”। यह 346 प्रतिभागियों के पिछले रिकार्ड से बेहतर था जो होप इंक इन मूरहेड, मिनीसोटा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा बनाया गया था।

3. एक " 8 घंटे में अधिकांश लोगों को श्रवण यंत्र लगाए गए" एक ही (60ण यंत्र) एक ही दिन में स्थापित किए गए। निःशुल्क सहायक उपकरण माह त में 1000 दिव्यांगजनों को दिए गए। इसके अलावा इस दौरान श्रवण वित्त प्रयास रिकार्ड है।

इसके बाद विश्व रिकार्ड बनाया गया जिसमें इंकाल में आयोजित श्रवण यंत्र वितरण समारोह में 3911 लोगों को श्रवण यंत्र लगाए गए। रोकथाम कार्यक्रम और बधिर नियंत्रण स्वास्थ्य मिशन मणिपुर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण (एलिम्को) और सामाजिक और गरिमा मंत्रालय के सहयोग से 5 नवंबर, 2016 को समारोह संयुक्त रूप से आयोजित गया। पूरे भारत में इस प्रकार का सबसे बड़ा समारोह है और मणिपुर ने 17 सितंबर को 8 घंटे में 600 व्यक्तियों को श्रवण यंत्र लगाने का पूर्व में बनाया गया विश्व रिकार्ड गुजरात की तुलना में मणिपुर का रिकार्ड 6.5 घंटे से अधिक का है।

एडिप शिविर तस्वीरों की झलक



माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में 22.01.2016 को आयोजित अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मैगा एडिप वितरण शिविर में भाग लिया। एलिम्को ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से ऐतिहासिक शिविर आयोजन किया।



माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22.01.2016 को वाराणसी में आयोजित मैगा एडिप वितरण शिविर में दिव्यांगजनों को मोटरकृत ट्राईसाइकिल की सुविधा प्रदान करते हुए।



माननीय केन्द्रसामाज्याय एवं अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत और अन्य गणमान्य नागरिकों ने 08 को गो मुख्यालय कानपुर में माननीय सांसद, डा. मुरली मनोहर जोशी कानपुर नगर की में एारोह में एडिप वितरण शिविर में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए थे। इसके दौी देवेन्द्र सिंह भोले, माननीय सांसद, अकबरपुर, डा. विनोद अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन विभाग और श्री डी.आर. सरिन, सीएमडी, एलिम्को भी उपस्थित थे।



माननीय केन्द्रसामाज्याय और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत 08.09.2015 को एडिप शिविर व (उ.प्र.) में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करते हुए।



माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत 19.06.2015 को एडिप वितरण शिविर तौहिरपुर दिल्ली में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करते हुए।



माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत 24.05.2015 को एडिप वितरण शिविर नासिक में मोटरीकृत ट्राईसाइकिल वितरित करते हुए।



माननीय केन्द्रीय मंत्री और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री शिवराज सिंह चौहान 2015 को एडिप वितरण शिविर रायसेन में दिव्यांगजनों को एलिम्को में कृत ट्राईसाइकिल की सुविधा प्रदान करते हुए।



माननीय केन्द्रीय मामलाधाय एवं अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत और अन्य गणमान्य नागरिकों ने एडिप को ले मुख्यालय कानपुर में माननीय सांसद, डा. मुरली मनोहर जोशी कानपुर नगर की में एडिप वितरण शिविर में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए थे। इसमें दौरे देवेन्द्र सिंह भोले, माननीय सांसद, अकबरपुर, डा. विनोद अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और श्री डी.आर. सरिन, सीएमडी, एलिम्को भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय संस्थान और केंद्र

10

अध्याय

दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल सात राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये सात संस्थान निम्नलिखित हैं—

- (i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईपीवीडी), देहरादून
- (ii) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई
- (iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता
- (iv) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक
- (v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली
- (vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईपीआईडी), सिकंदराबाद
- (vii) राष्ट्रीय बहु-विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईपीएमडी), चैन्नई

इन सात राष्ट्रीय की जानकारी नीचे सारणीबद्ध हैं:-

क्र.सं.	राष्ट्रीय	स्थापना वर्ष	परिसर क्षेत्र (एकड़ में)	क्षेत्रीय केंद्र (आरसी)/ क्षेत्रीय खंड यदि कोई है	समेकित क्षेत्रीय केंद्र, यदि राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत कोई है
1.	राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिस्थ (एनएसी), दून	1979	43	एक क्षेत्रीय केंद्र (चेन्नई) और दो क्षेत्रीय खंड (कोलकाता एवं सिकंदराबाद)	एक सुंदर नगर (हिमाचल प्रदेश)
2.	अली रा वाक्य दिन संस्था (एवाईएस), मुंबई	1983	4.77	चार क्षेत्रीय केंद्र (कोलकाता, सिकंदराबाद, नोएडा एवं भुवनेश्वर)	दो (भोपाल एवं अहमदाबाद)
3.	राष्ट्रीय दिव्यांग स्थान (एनएसी कोटा)	1978	3.0	तीन क्षेत्रीय केंद्र (देहरादून, आईजोल एवं अरुणाचल प्रदेश)	एक (पटना)
4.	स्वामी हर पुनर्वासि अं अनुसंधान, (एसवीआईटी), कटक	1975	26.66	कोई नहीं	एक (गुवाहाटी)

5.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	1960	1.5	एक (सिकंदराबाद)	दो (लखनऊ एवं श्रीनगर)
6.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईआईपीआईडी), सिकंदराबाद	1984	19.33	तीन क्षेत्रीय केंद्र (नोएडा, मुंबई और कोलकाता)	दो (नैल्लोर एवं देवनगरे)
7.	राष्ट्रीय बहु-विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईआईपीएमडी), चैन्नई	2005	15.2	कोई नहीं	दो (कोझीकोड एवं नागपुर)

1. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईआईपीवीडी), देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईआईपीवीडी), देहरादून एक स्वायत्त निकाय है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। दृष्टि बाधितों को सशक्त करना प्राथमिक उद्देश्य है और दृष्टि बाधितों को संपूर्ण सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए यह एक प्रमुख संस्थान है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, संस्थान ने तीन क्षेत्रों नामक एचआरडी और प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा उत्पादन एवं ब्रेल उपकरण और ब्रेल साहित्य के वितरण की गतिविधियों का आयोजन किया है। संस्थान 116 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड राज्य में स्थित है।

संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र, चैन्नई, (तमिलनाडु) में, और दो क्षेत्रीय खंड सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में दृष्टि बाधितों को उनके संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध प्रदान करते रहे हैं। यह दिव्यांगजन संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश से भी समन्वय करता है।

विशेष शिक्षा और दिव्यांगता अध्ययन विभाग के माध्यम से संस्थान दृष्टि बाधितों के क्षेत्र में विशेष शिक्षा, शिक्षकों और मोबिलिटी प्रशिक्षकों को योगदान देता है। संस्थान अब तक 11,361 विशेष शिक्षा शिक्षकों और मोबिलिटी प्रशिक्षकों को योगदान दिया है।

एनआईपीवीडी दिव्यांगता अनुरनिकाय के रूप में उभरा है। यह तीन तंत्र अनुसंधान सलाहकार समिति, भारतीय ब्रेल परिषद और निर्विडिकाई को बढ़ावा देने और अनुसंधान प्रायोजित करने के लिए है। पिछले 25 वर्षों से, संस्थान ने 125 अनुसंधानयोजनाओं पर काम किया है। इन परियोजनाओं में शिक्षा की गुणवत्ता, पुनर्वास कार्यक्रमों और कौशल में काफी सुधार हुआ है।

संस्थान की दृष्टि बाधितों की वृद्धिपूर्ण प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी भारी जिम्मेदारी है। इसके देहरादून अकंदराबाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रों के 22 कौशल विकास पाठ्यक्रमों को प्रदान और 100 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की क्षमता के बारे में पेशकश की है।

दृष्टि बाधितों को माडल प्लेसमेंट में और उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, संस्थान ने भी एक प्लेसमेंट सैल बनाए रखी। 2015-16 के दौरान 318 दृष्टि बाधितों को नौकरी प्राप्त करने में मदद मिली थी। एनआईपीवीडी दिव्यांगता अनुरनिकाय से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान भी करा रहा है, दृष्टि बाधितों के लिए इसके माडल प्लेसमेंट से जो केन्द्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। विद्यालय ने 250 दृष्टि बाधित बच्चों को सेवाएँ

संस्थान का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। पुस्तकालय इसे प्रिंट, ब्रेल और आडियो बुक सैक्शनों के माध्यम से लगभग 1000 सदस्यों को वार्षिक सेवा देता है। राष्ट्रीय टाकिंग बुक पुस्तकालय संस्थान द्वारा पेश की गई अक्षरों के बीच एक प्रमुख स्थान रखती है। बल्कि हाईटेक पहल के हिस्से के रूप में आडियो पुस्तकें डिजिटल फॉर्म में हैथान मुद्रण ब्रेल पाठ पुस्तक और पत्रिकाओं के लिए भी एक प्रभावशाली बुनियादी सुविधाओं के साथ ही हेतु ब्रेल प्रेस देहरादून में, क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस चैन्नई में और तीन छोटे पैमाने ब्रेल मुद्रण इकाई शिलौंग, गुवाहाटी में बुनियादी ढांचे सहित है। साथ ही पूर्ण 12 भारतीय भाषाओं में ब्रेल पुस्तकों का उत्पादन और 10000 व्यक्तियों की सेवाएँ की है।

भारत सरकार की प्लैगिनिंग क्वयन

सामाजिक न्याय और अधिकांशतः सरकार ने एनआईपीवीडी को तीन योजनाओं जैसे कि "दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/उपकरण/ग की सहायता स्कीम (एडिप), ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन की केन्द्रीय योजना और दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम" का कामकाज सौंपा गया है।

संस्थान की सफलता की

(क) श्री अजय अरोड़ा

हरियाणा के सावर्जनिक अजय अरोड़ा शक्ति स्तंभ और दूसरों का पालन करने के लिए एक रोशन उदाहरण है। श्री अरोड़ा मेहनत का साथ एक साथ दृढ़ संकल्प किया है और इस तरह की सफलता का इरादा



एक प्रतिभाशाली विद्वान है, उसकी ताकत उसकी कड़ी मेहनत और उपलब्धि में निहित है। वह राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून से मान्यता प्राप्त माडल स्कूल से सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त है।

इतिहास में बी.ए. (आनर्स) पास करने के बाद, उसने इतिहास में स्नातकोत्तर किया था। बाद में उसने कानूनी अध्ययन और प्रशासन के लिए जेएनयू के केन्द्र में प्रवेश लिया और उससे एम.फिल और पी.एचडी की। उसका अनुसंधान विकास और जलवायु परिवर्तन की राजनीति के क्षेत्र में अनुसंधान रहा है।

श्री अजय अरोडा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कालेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया है। उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलनों में, अपने भाषणों और वार्ताओं की हमेशा समीक्षात्मक सराहना की गई है।

श्री अजय अरोडा ने सिविल सेवा में दो बार भाग लिया। 2015 में उसे कैडर में शामिल नहीं किया गया था, उनकी इच्छा प्रोपर आईएस ज्वाइन की थी। अंत में वह सफल रहा वह वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनआईवीएच के माडल स्कूल से पास हुए हैं, उसने संस्थान को नाम और प्रसिद्धि दी है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में माडल स्कूल के छात्रों ने मात दी

मिशन में सफल होने के लिए, प्रत्येक को अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमागी तौर पर मजबूत होना चाहिए। क्या



यह वहीं संस्थान है जहाँ उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधिक गोल बनाए। उनके शिक्षक की मदद से फुटबॉल में स्टार दिग्गज बनाया है। उनके फुटवर्क और फूर्ति में सुधार से उन्होंने मीडिया आँसू से मिली।



12 वीं कक्षा के पढ़ाई के में जिनके रक्त में ही जीतने की विशिष्टता है। उसने सितंबर, 2016 में एशियाई ब्लाइंड फुटबॉल में भारत का नेतृत्व किया। वह एनआईवीएच फुटबॉल टीम का कप्तान था जो कोच्चि, केरल इन्वार्डेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में उपविजेता रहे। वे 01 से 04 दिसंबर, 2016 तक आठ तीन राष्ट्रों के फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत की तरफ से कप्तान भी रहे थे।

इसी तरह कक्षा 12वीं के छात्र संदीप सिंह मई, 2016 में कोच्चि, केरल में आयोजित आल इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में थे। उसने दिसंबर माह 2016 में कोच्चि, केरल में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया।

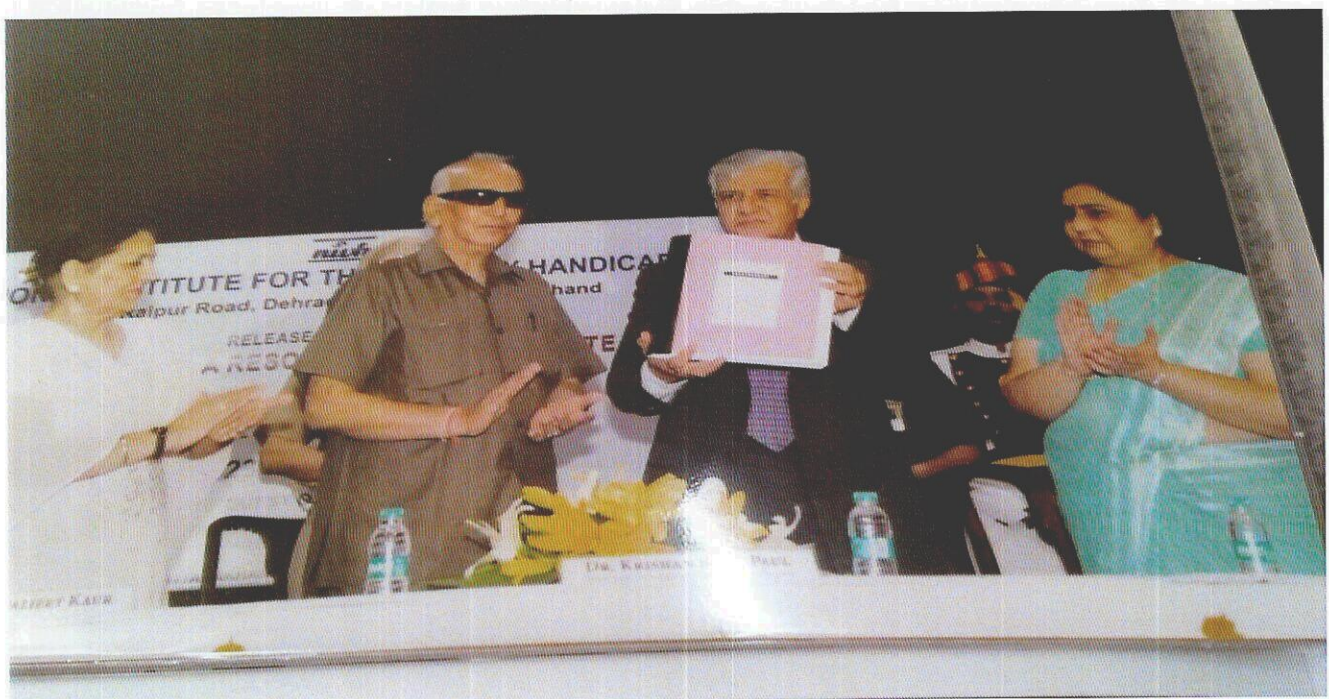
कक्षा 9वीं के एक छात्र सोवेन्द्र, को मई माह में कोच्चि, केरल में आयोजित आल इंडिया इनवाइटेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में "प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट" घोषित किया गया। उसने दिसंबर माह 2016 में कोच्चि, केरल में आयोजित उपर्युक्त तीन राष्ट्रों के फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया।

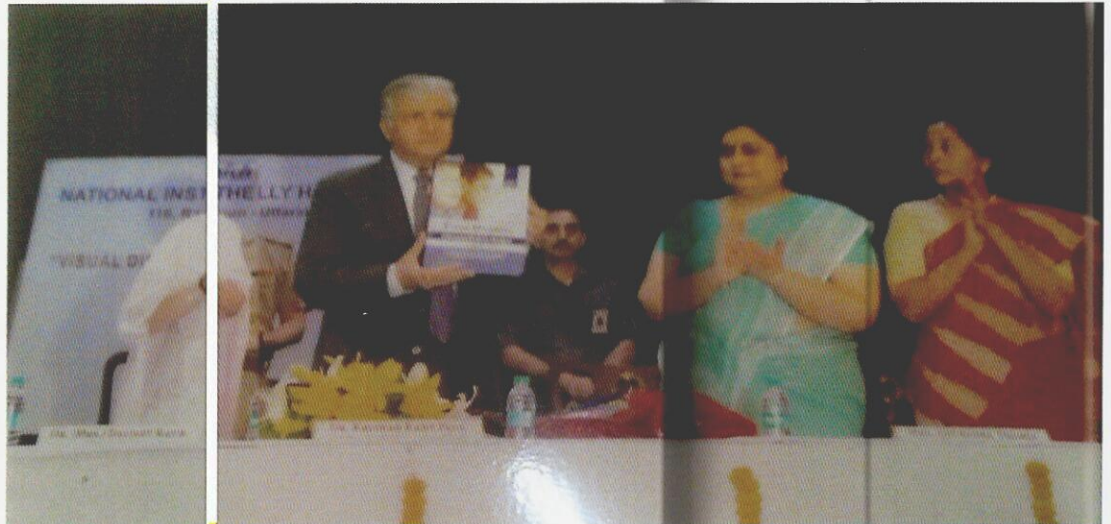
मास्टर नीरज चौहान और मास्टर संदीप घर का नाम रोशन किया जब उन्होंने 18 से 19 अक्टूबर, 2016 तक उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पैरालिंपिक्स में 200 और 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण और रजत पदक जीते।

2016-17 में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

(i) "दृष्टि बाधित – शिक्षकों के लिए एक संसाधन किताब" का विमोचन

माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड, डा. के.के.पाल ने 23.05.2016 को राजभवन आडियाटोरियम में "दृष्टि बाधित – शिक्षकों के लिए एक संसाधन किताब" का विमोचन किया। पुस्तक सुश्री अनुराधा मोहित डालमिया और श्री ए. के.मित्तल द्वारा सह संपादित की गई। पुस्तक का विमोचन शिक्षकों और विशेष शिक्षा के छात्रों के मार्गदर्शन में मील का पत्थर शामिल होगा। यह दोनों हिंदी और ब्रेल लिपि में प्रकाशित की गई है।





माननीय राज्यपाल न वसों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से दृष्टि बाधितों को शिक्षित और सगें असरी और शिक्षकों को इससे बहुत मदद मिलेगी।

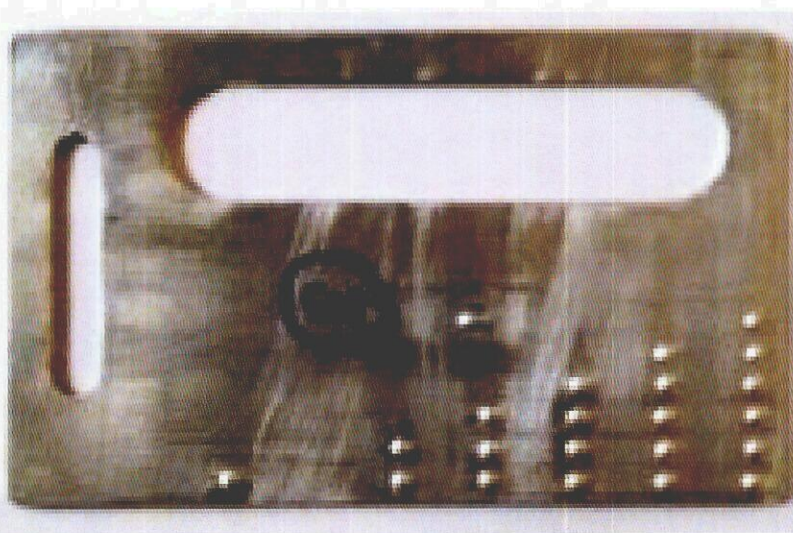
(ii) सुगम्य पुस्तकालय भार आन लाईन लाइब्रेरी"

एक निर्णायक और दिव 24 अगस्त को श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री, विधि और न्याय, सूचना प्रौद्योगिकी और को थावरचन्द गेहलोत, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार, मा, श्रीश जावडेकर, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, माननीय राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल गुर्जनक और अधिकारिता, भारत सरकार, और माननीय राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले, सामाजिक और गरिता, भारत सरकार की शुभ उपस्थिति में श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री, विधि और सूचोद्योगिकी, भारत सरकार, द्वारा विज्ञान भवन, दिल्ली में "सुगम्य पुस्तकालय-आन लाईन लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया था।



परियोजना राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून और भारत के डेजी फार्म का संयुक्त प्रयास था। आनलाइन लाइब्रेरी की शुरुआत दिव्यांगजनों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और अन्य सहायताओं का प्रिंट बनाएगी। यह सफल संयुक्त उद्यम एक भारत सरकार के सुगम्य भारत आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलु का सजोया और एहसास किया गया है। यह दिव्यांग प्रिंट की पहुंच के लिए सुगम्य प्रारूप में साक्षरता, शिक्षा, मनोरंजन और सूचना लाया है।

(iii) मुद्रा और हस्ताक्षर की पहचान के उपकरण



राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून ने मील का पत्थर सृजित किया जब एक प्रोटो टाइप का उपकरण विभिन्न संप्रदायों की मुद्रा की पहचान और हस्ताक्षर विकसित किया गया था। यह आमतौर पर महसूस किया गया है कि दृष्टि बाधितों को अपने दैनिक लेन देन में मुद्रा की पहचान करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हस्ताक्षर को लगाना भी बहुत दुश्कर है। सुगम्य भारत अभियान के मिशन को ध्यान में रखते हुए, मुद्रा और हस्ताक्षर की पहचान का उपकरण बनाया गया है।

(iv) पुनर्वास मनोविज्ञान में नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का परिचय (पीजीडीआरपी)

पुनर्वास मनोविज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए लंबे समय से सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी अंत में पूरा किया गया था, जब पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीआरपी) को अंत में उचित आकार दिया गया और 16 अगस्त, 2016 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का पहला बैच 25 उम्मीदवारों के साथ एनआईवीएच मुख्यालय में शुरू किया गया।

- (v) दृष्टि बाधितों के कम्प्यूटर सहायक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में नये व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का परिचय

वर्ष 2016-17 के दृष्टि बाधितों के लिए आईटी सैक्टर में रोजगार के उचित अवसर पैदा करने, कम्प्यूटर और प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में नये व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का परिचय। इस पाठ्यक्रम का पहला उर्म्म के साथ 14.12.2016 को एनआईवीएच मुख्यालय में शुरू किया गया।

- (vi) दृष्टि-बाधितों के कम्प्यूटर एवं सहायक तकनीक के प्रयोग में नए वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भरना

सूचना प्रौद्योगिकी जग उपयुक्त अवसर उत्पन्न करने के लिए संस्थान द्वारा वर्ष 2016-17 में दृष्टि-बाधितों के कम्प्यूटर सहायक तकनीक के प्रयोग में 6 मास की अवधि का नया वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है। इस पाठ्यक्रम का पहला बैच दिनांक 14.12.2016 को 10 छात्रों के साथ एनआईवीएच में किया गया।

- (vii) दृष्टि बाधितों को सामग्री आरबीडी सुविधाएं उपलब्ध कराके सशक्तिकरण की ओर उठाया गया कदम

संस्थान द्वारा अंधों व दृष्टि कमजोर व्यक्तियों के लिए देश सबसे बड़ा पुस्तकालय बनाया गया है। संस्थान द्वारा सेवा रहित एंग्रज ग्रों में 80 पुस्तकालय विस्तार काउंटर भी स्थापित किए गए और यह दृष्टि बाधित छात्रों एवं वरिष्ठों के लिए वरदान साबित हुई है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं कुल 70 आरबीडीएस (रिफ्रेशेबल ब्रेल डिटेम) उपलब्ध कराए गए, जिससे पुस्तकालय ओर अधिक समृद्ध हो गए।

2. अली यावर जंग श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई

एवाईजेएनआईएसएचडी), स्की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को की गयी। यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक अरिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंगतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान, बान्द्रा, ई. में है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में श्रवण हानि/वाक् भाषा के शीघ्र उपचार एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इस संस्थान के प्रमुख निदेशक, एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) है तथा इसमें आडियोलोजी, वाक् भाषा पैथोलोजी सिरीस, सूचना एवं प्रलेखीकरण, सामाजिक, आर्थिक पुनर्वास तथा आउटरीच एवं विस्तार के 08 विभाग हैं।

संस्थान के उद्देश्यों में श्रवण बाधितों की शिक्षा एवं पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कराना, इसे प्रायोजित करना तथा (ii) श्रवण बाधितों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए प्रशिक्षुओं एवं शिक्षकों, नियोक्ता अधिकारियों, वोकेशनल काउंसलरों का उत्तरदायित्व लेना अथवा उन्हें प्रायोजित करना (iii) श्रवण की पुनर्वास एवं शिक्षा के किसी भी पहलु को बढ़ावा के लिए प्रोटो टाइप के

निर्माण में सहायता देना तथा सभी प्रकार के अथवा किसी एक प्रकार डिजाइन किए गए यंत्रों, को विकसित करना एवं वितरित करना, है।

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र कलकत्ता (1984), नई दिल्ली (1986), सिकन्दराबाद (1986), बधिरों के शिक्षकों के लिए राज्य सहयोग से प्रशिक्षण केन्द्र, उड़ीसा (1986) तथा वयस्क बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद (1986) स्थापित किए गए हैं। भोपाल तथा अहमदाबाद में दिव्यांगजनों के केन्द्र क्रमशः 2006 एवं 2011 से एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों का लक्ष्य मानवशक्ति विकास एवं सेवाओं के अर्थों में स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।

जहां तक लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संबंध है, यह संस्थान डाक्टरल, स्नातकोत्तर, स्नातक, पूर्व-स्नातक, तथा शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा (श्रवण बाधित), वाक् एवं श्रवण (आडियोलोजी एवं वाक् भाषा पैथोलोजी) तथा मीडिया एवं दिव्यांगता संचार पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा डीटीपी श्रवण बाधितों के लिए कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भारतीय संकेत भाषा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

संस्थान श्रवण बाधितों को समेकित डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक, शिक्षा एवं वोकेशनल सेवाएं उपलब्ध कराता है। अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग भी है। एवाईजेएनआईएसएच (एवाईजेएनआईएचएच) नामक एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।

एववाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने अनेक उपलब्धियां हासिल की, जिसमें से कुछ हैं:

- सार्वभौमिक डिजाइन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार-2011
- सर्वोत्तम लघु फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-2011
- सुगम्य वेबसाइट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-2011
- ऑनलाइन श्रवण जांच के राष्ट्रीय पुरस्कार-2009
- सीआरओएस श्रवण यंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-2002
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सर्वोत्तम नियोक्ता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-1996

सहायक यंत्र एवं उडिप) के अंतर्गत कोकलियर इंप्लांट—नयी पहल:

एवाईजेएनएसएचडी के कोकलियर इम्प्लांट कार्यक्रम को लागू करने की नोडल एजेंसी है। कोकलियर इम्प्लांट कार्यक्रम में 140 अस्पतालों को पैनाल बनाया गया है। कोकलियर इम्प्लांट बधिर व्यक्तियों के लिए एक तकनीक है। सर्जरी के पश्चात बधिर बच्चे सुन पाते हैं तथा उपयुक्त प्रशिक्षण से वे बोल सम जाते हैं। भारत सरकार 15000/-रुपए से कम की मासिक आय वाले माँ-बाप को 6.00 ल प्रति की आर्थिक-सहायता उपलब्ध करा रही है।

अब तक—486 आप जा है।

एवाईजेएनआईएस) द्वि-श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए एडिप योजना के अंतर्गत इयर हियरिंग उपकरणों को प्रोग्रामेबल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सफलता की कहानी

1. सुश्री अनुशा गुनटूपल्ली

सुश्री अनुशा गुनटूपल्ली का जन्म बायलिटरल प्रोफाउंड सेन्सोरिन्यूरल हियरिंग लास की 100 प्रतिशत श्रवण विकलांग दिव्यांगता के साथ गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश में हुआ। उसके माता-पिता को श्रवण-दिव्यांगता की पहचान 9 मास की आयु में हुई 12 मास की आयु में एक्सटेंसिव वाक् एवं भाषा थेरेपी के साथ-साथ उसमें उपयुक्त श्रवण सहायक यंत्र फिट किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 6 वर्ष की आयु में उसे एक नियमित स्कूल में दाखिला मिल गया। कोकलियर इम्प्लांट साढ़े छः वर्ष की आयु में किया गया तथा बायें कानमें न्यूक्लस फ्रीडम कोकलियर इम्प्लांट के साथ फिट किया गया। स्विच ऑन करने के पश्चात सफल पोस्ट इम्प्लांट इंटरवेंशन तत्काल आरम्भ हो गया। उनमें सीबीएससी, नई दिल्ली से 10 वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, जहां उसे 10 में से 9.8 प्रतिशत प्राप्त हुआ। उसने आन्ध्रा प्रदेश राज्य बोर्ड 91.4 अंक प्राप्त करके 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने जीवन-कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, मनोवृत्ति एवं मूल्य, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा में भी 'ए' ग्रेड प्राप्त किया।



वह बीएसएलपी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए एबाईजेनआईएसएचडी (डी) मुंबई की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, में शामिल हुई और 150 में से 52 अंक प्राप्त करके 133 छात्रों में से मेरिट सूची में 11 स्थान पर रहीं। शारीरिक दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित सूची में वे शीर्ष स्थान पर रही। अब वे लिखित एवं प्रैक्टिकल दोनों में किसी भी प्रकार की कठिनाई अनुभव न करते हुए महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान से संबद्ध एफ.वाई. बीएसएलपी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। अतः वे श्रवण दिव्यांगता के संबंध में शीघ्र पहचान एवं शीघ्र उपचार का आदर्श उदाहरण हैं। वह जन्मजात दिव्यांगता वाले बच्चों के माता-पिता के लिए उपयुक्त मॉडल हो सकती हैं।

2. श्री सुविरोग

श्री सुवरो सेनगुप्ता पूरन विश्व में रह रहे हैं। वह अपने माता-पिता का छुत्र है जो 22 जुलाई 1982 को 100 प्रतिशत के पुत्र पैदा हुआ उन्हें उनकी माता द्वारा श्रमगोत्रे तत्कालीन अली यावर जंग राष्ट्रीय सं अगे यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, जो अब अजंगरीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान जाता है, में वोक्शनल मूल्यांकन एवं कैरियर मेंदर्शन के लिए लाया गया। उनमें कम्प्यूटर की प हुई और तत्पश्चात वे ईस्टर क्षेत्रीय केनताम्प्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिल हो गये। उन्ता विद्यालय से वर्ष 2008 में वाणिज्य-स्नातक पूरा करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया।



कम्प्यूटर पाठ्यक्रम पूरा कोत् वह महालेखा परीक्षक के कार्यालय में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त हुए। उन्त बी उन्हें सरल, विनम्र ईमानदार तथा एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति के रूप में पसंद करते हैं।

सुवरो ने वर्ष 1999 एक्मशेयर एवं सीनियर राष्ट्रीय स्तर की टेबल-टेनिस चैम्पियन जीती।

'रुपासी बंगला' नाम सिद्धली चैनल में "दस अवतार" नामक रियेलिटी शो में जज के रूप में कार्य करने के लिए उ अग्रकेया गया, जो जून एवं दिसम्बर 2009 में प्रसारित किया जायेगा।

उसकी सबसे बड़ी शक्ति स्वन एवं प्रकृति के अनुचित-न्याय को चुनौती देने की इच्छा है।



श्री रामदास अठावले, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिनांक 30.07.2016 के अपने दौरे के दौरान नारियल वृक्षारोपण करते हुए।



श्री राम व्यास, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2016 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय मंत्रालय की स्थाई समिति का एवाईजेनआईएसएचडी (डी) में दौरा।



↑
श्री थावरोत य केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भास्कार का दिनांक 17.12.2016 का दौरा।
↓



3. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी) कोलकाता

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), लोको मोटर जैसी विकलांगता विशिष्ट क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए देशभर में विकास एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में सेवा देने के प्रयोजन से कोलकाता, प. बंगाल में स्थापित किया गया था। एनआईओएच पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इस प्रकार यह लोको मोटर विकलांगजनों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास सेवाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति विकसित करता है। एनआईओएच लोको मोटर विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ समय पर और विशेष शल्य हस्तक्षेप और अन्यव उपचारात्मिक सेवाओं के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनशक्ति और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने वाला एक शीर्ष संगठन है।

उद्देश्य

इस संस्थान की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी :

- अस्थि दिव्यांगता जिसमें संयोजन अथवा गतिशीलता की समस्या के साथ तंत्रिका विकलांगता भी शामिल है, की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलूओं में अनुसंधान करना, प्रायोजित करना, समन्वय करना।
- जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी में प्रायोजन, समन्वय करना, जिससे सहायक यंत्रों अथवा उपयुक्ति शल्य/चिकित्सा प्रक्रियाओं अथवा नये सहायक यंत्रों के विकास का प्रभावी मूल्यांकन हो सके।
- अस्थि दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा जैसा आवश्यक समझा गया हो, प्रशिक्षुओं और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक सलाहकारों और इस तरह के अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण का संचालन या प्रायोजन के लिए।
- अस्थि दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के निर्माण के लिए विनिर्माताओं को वितरण, बढ़ावा अथवा छूट प्रदान करना।

गतिविधियों की एक झलक

इस संस्थान की गतिविधियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- 1) मानव संसाधन विकास
- 2) पुनर्वास सेवाएं
- 3) अनुसंधान और विकास

- 4) पुस्तकधन सूचना का प्रसार
- 5) गैर-साठननगरानी
- 6) जागरूकता
- 7) छात्रों के
- 8) अन्य

मानव संसाधन विकास

मूल विचार देश में गतिशीलताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मौजूदा मानव संसाधन के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान को सौंपे गए कार्य के लिए उपयोगिता के दृष्टिकोण से मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। सामान्यतया इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है :-

- क. दीर्घ उपक्रम
- ख. लघु उपक्रम

पुनर्वास सेवाएं

पुनर्वास सेवाएं अस्पताल में, बरिगियों और आम पहुंच से दूर क्षेत्रों के लोगों को संस्थान मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों, सीबीआर परियोजना अन्य की केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

- (क) संस्थागत से
- (ख) आम क्षेत्र सेवाएं
- (ग) समुदाय सेवाएं (सीबीआरएस) और
- (घ) क्षेत्रीय योग केंद्रों के माध्यम से सेवाएं।

क. संस्थागत सेवाएं

ये संस्थागत सेवाएं निम्नलिखित माध्यम से प्रदान की जाती हैं:-

- 1) चिकित्सा
- 2) फिजि
- 3) व्यावसायिक
- 4) प्रोसोपैक
- 5) सामर्थ्य

- 6) पुनर्वास नर्सिंग
- 7) पुनर्वास अभियांत्रिकी।

ख. आउटरीच सेवाएं

संस्थान अपने आउटरीच यूनिट के माध्यम से डिसेबिलिटी कार्य विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को (एडिप) स्कीम के कार्यान्वयन करने के लिए शिविरों का आयोजन करता है।

ग. समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएं (सीबीआरएस)

संस्थान के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास विभाग ने समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में सीबीआर परियोजनाएं आयोजित की हैं। इस वर्ष विभाग ने नवीन परियोजना क्षेत्र के रूप में इसे इंफाल पश्चिम, मणिपुर में आरंभ किया है।

घ. क्षेत्रीय और सहयोगात्मक केंद्रों के माध्यम से सेवाएं

क. क्षेत्रीय केंद्र—निम्नलिखित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- i. देहरादून, उत्तराखंड
- ii. आईजोल, मिजोरम
- iii. नाहरलागून, अरुणाचल प्रदेश
- iv. दिव्यांग अध्ययन केंद्र, मिजोरम विश्वविद्यालय परिसर

ख. एनआईएलडी ने एनटीपीसी फाउंडेशन (एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट) के साथ एनटीपीसी परियोजना स्थल के निकट शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने और सशक्त करने के लिए एनटीपीसी फाउंडेशन के सहयोग से एनटीपीसी फाउंडेशन एनआईएलडी दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (एनएफएनडीआरसी) शुरू किया है। एनएफएनडीआरसी का मूल उद्देश्य इस जिले और समीप के क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है।

अनुसंधान परियोजना

विश्व भारती (केंद्रीय विश्वविद्यालय), सामाजिक आर्थिक पुनर्वास विभाग, एनआईएलडी, कोलकाता के सहयोग से चलाई जा रही 'पश्चिम बंगाल में जनजातियों में दिव्यांगता की व्यापकता तथा उनका पुनर्वास' नामक एक परियोजना आरंभ की जा रही है।

नवीन गतिविधियां

1. एनआईएलडी, कोलकाता की सिपडा योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. आईजोल, मिजोरम में दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र का निर्माण कार्य।



आर.के.मिशन, एन.कोल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी दयानंद जी महाराज, का स्वागत।



श्री कृष्णपाल गुर्जर, माननीय न्यर अधिकारिता राज्य मंत्री, द्वारा एनआईएलडी के प्रशिक्षण सहयोगियों को कौशल प्रक्रियार्यक्रम के लिए प्रमाण पत्र वितरण करते हुए।



श्री कृष्णपाल गुर्जर माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा
एनआईएलडी कोलकाता में गेट लैब का उद्घाटन



श्री कृष्ण पाल गुर्जर, जेक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा एनआईएलडी, कोलकाता में नये शैक्षणिक व खंड का उद्घाटन



एनआईएलडी कोलकाता में आयोजित गैर-सरकारी संगठनों का उन्नतमुखीकरण कार्यक्रम

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के चित्र



विभाग सशक्तिकरण विभाग के चित्र



मिनटपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान,
नली में रक्त दान शिविर का उद्घाटन



रन्यास, स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के चित्र



निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 का उत्सव



दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के चित्र



4. स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (स्वनिरतार), कटक

यह संस्थान मानव संसाधन का विकास करने तथा सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों, अनुसंधानों और आऊटरीच कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्य करता आ रहा है। यह दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रॉस्थेटिस्टों, ऑर्थोटिस्टों, फिजियोथेरेपिस्टों, व्यावसायिक थेरेपिस्टों, बहुउद्देश्य पुनर्वास थेरेपिस्टों जैसे कार्मिकों तथा ऐसे ही अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का दायित्व ग्रहण करता है और उसे प्रायोजित एवं समन्वित करता है।

गतिविशयक निःशक्तता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए, यह संस्थान फिजियोथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी, प्रॉस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है।

व्यावसायिकों/गैर-सरकारी संगठनों को अधिकाधिक प्रेरित करने और समुदाय आधारित पुनर्वास के विषय में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, यह संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में लघु अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) पाठ्यक्रम, लगातार चलने वाले चिकित्सा, शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनार संचालित करता है।

संस्थान शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सेवाएं भी प्रदान करता है। इन सेवाओं में शारीरिक विकृतियों का सर्जिकल सुधार, फिजियोथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी शामिल हैं। इस संस्थान में कृत्रिम अंगों की फिटिंग की जाती है तथा यह अपने यहां और शिविरों के आयोजन द्वारा, न केवल ओडिशा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों में बल्कि जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, उ.प्र., बिहार, म.प्र., छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी व्हील चेयर और तिपहिया साइकिल जैसे चलने में मदद करने वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति करता है।

10



5. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूआईपीपीडी) नई दिल्ली

पंडित दीन दयाल दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में एक गैर-सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। इसे वर्ष 1975 में पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया और वर्ष 1976 में, शारीरिक विकलांगों का संस्थान, नई दिल्ली नाम से यह एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में परिवर्तित हो गयी।

यह गतिविशयक निःशक्तता जैसे पोलियो सुशुंन सृजन, प्रमांस्तशक घात, अभिघातक विकृतियां, मस्तशक-घात मामलें आदि से पीडित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का नाम वर्ष 2002 में बदल कर प0 दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान कर दिया गया। अब इस संस्थान का नाम दिव्यांगजन प0 दीन दयाल राष्ट्रीय संस्थान हो गया है।

पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा साढ़े चार वर्ष अवधि प्रत्येक के शारीरिक थैरेपी (बीपीटी), व्यासायिक थैरेपी (बीओटी) में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

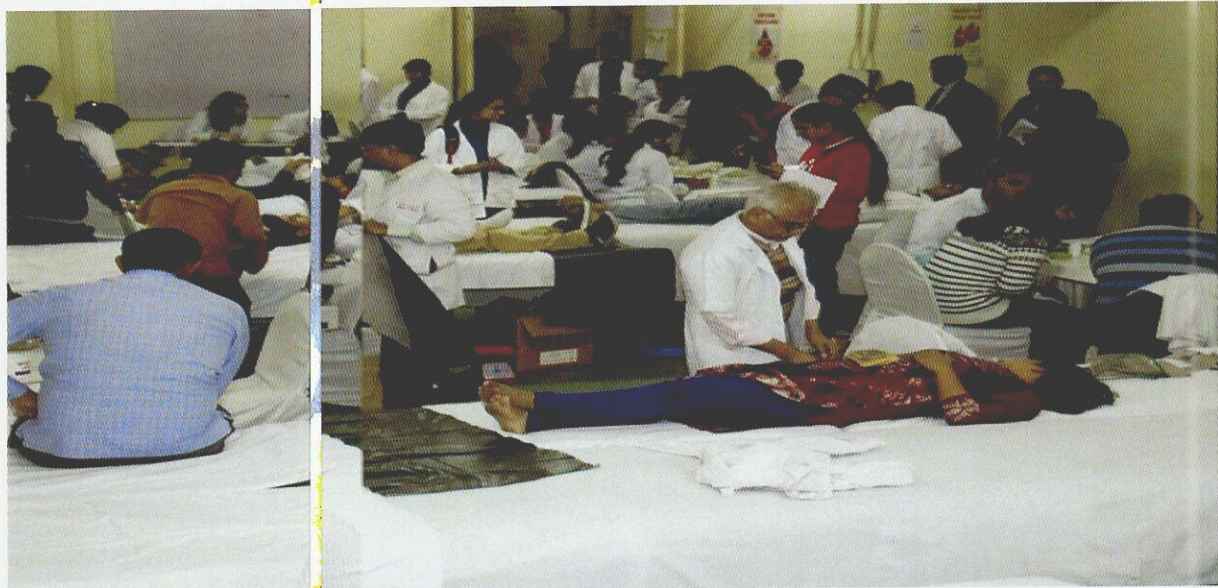
संस्थान में आने वाले दिव्यांगजनों को, उनकी क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा समेकित पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है। उनकी पुनर्वास अपेक्षाओं के लिए उनका मूल्यांकन आर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाइशियन/पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है।

संस्था सीआरसी लखनऊ एवं सीआरसी श्रीनगर के कार्य-कलापों में सहयोग प्रदान कर रही है। संस्था द्वारा बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय संस्थान सिकंदराबाद कैम्पस में अपना दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र (एसआरसी) भी स्थापित किया गया है और अब संस्थान डीडीआरसी टोंक भी स्थापित करने जा रहा है।

मुख्य घटनाक्रम:-

संस्थान द्वारा "प्रिवेंशन ऑफ फाल्ज इन एलडरली" पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को रोगी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 41 रोगियों ने भाग लिया, जो फाल्ज के लिए चुने गए तथा पंजीकृत हुए थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अनूप अग्रवाल विभागाध्यक्ष ओक्यूपेशनल थैरेपी द्वारा फाल्ज, उनके परिणाम एवं रोकथाम के संबंध में एक पावर प्वाइंट के प्रस्तुतिकरण सहित की गयी। प्रशिक्षुओं ने फाल्ज के मामलों में उठाए गए कदमों को व्यवहारिक प्रदर्शन द्वारा समझाया। वृद्धों में फाल्ज की रोकथाम के लिए करने तथा न करने योग्य बातों को उल्लेख करते हुए पर्चे बाटें गए एवं इस पर चर्चा भी की गई। फैकल्टी ने नियमित शारीरिक व्यायाम के महत्व तथा फाल्ज की रोकथाम में इसके प्रभाव पर भी विचार किया। इसके पश्चात प्रश्न-उत्तर सत्र हुआ, जिसमें भाग लेने वाले ने विशेषज्ञ पैनल एवं संस्थान के फैकल्टी सदस्यों से अपने प्रश्न पूछे। तत्पश्चात वृद्धों के लिए प्रश्नोत्तरी एवं खेलकूद का आयोजन हुआ।

संस्थान ने दिसम्बर 2016 में जेक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत की उपस्थिति में राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन (NACO) के सहयोग से अपने परिसर में एक रक्त दान कैंप आयोजित किया। रक्त दान कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने 214 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। (इसके फोटोग्राफ निचे दिए गए हैं।)



संस्थान द्वारा दिनांक 28.10.2016 को विज्ञान भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रियो पैरा अबिलपिक्स टी-20 एशिया कप इंडिया ब्लाइंड क्रिकेट टीम एवं इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडों टीम के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत ने मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल, राज्यमंत्री (प्रभारी) योजना, शहरी विकास मंत्रालय माननीय श्री इंद्रजीत सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय रामदास अठावले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय श्री विजय सांपला एवं डा० विनोद अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी सम्मिलित हुए।

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 19.09.2016 को इलाहाबाद, यू.पी. में एक कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत मुख्य अतिथि थे तथा इस कैम्प में पीडीयूएनआईपीडी के 10 कर्मचारी एवं सीआरसी लखनऊ के 19 कर्मचारी शामिल हुए। संस्थान द्वारा इसकी गतिविधियों के लिए प्रदर्शनी का एक स्टॉल भी लगाया गया। कुल 4773 लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए।

शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत, इटावा, सन्त कबीर, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश में पोलियो निवारक सर्जरी कैम्प का आयोजन किया गया। 321 लाभार्थियों द्वारा 429 अंगों का आपरेशन कराया गया। इन कैम्पों का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किया गया।

विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस तथा ओक्यूपेशनल थेरेपी दिवस का आयोजन फिजियोथेरेपी एवं ओक्यूपेशनल थेरेपी दिवस का आयोजन फिजियोथेरेपी एवं ओक्यूपेशनल थेरेपी विभाग के संबंधित विभागों द्वारा किया गया। यह दिन संपूर्ण देश के शारीरिक एवं ओक्यूपेशनल थेरेपिस्टों के लिए यह जागरुकता उत्पन्न करने का अवसर है कि व्यक्तियों का स्वस्थ, गतिशील एवं स्वतंत्र बनाये रखने में इस व्यवसाय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। यह पीटी एवं ओटी विभाग के व्यवसाय के संबंध में जागरुकता एवं स्वास्थ्य संबंधी आंदोलन है।

6. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजनशक्तिकरण संस्थान, (एनआईडीपीआईडी) सिकंदराबाद

इस संस्थान की स्थापना का ऐसव संसाधन तैयार करने के मूल उद्देश्य से की गई है जो जीवन चक्र की आवश्यकताओं के आधार पर उनके ना पूर्ण मॉडलों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने हेतु पूरी तरह से तैयार हो। यह संस्थान एक शीर्ष निकाश नसिक मन्दता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने, अनुसंधान कराने और सेवाएं प्रदान करने का त्रिपक्षीय कार्य करेगा। इसमें नवीनतम गतिविधियों और हाल के रुझानों के आधार पर, संस्थान अनुसंधान और विकास के माए त्मों के आयोजन तथा सृजनात्मक कार्यों के प्रयास कर रहा है।

संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय त्र में अपनी विभिन्न गतिविधियों में संगठन की वैशविक विशेषताओं को दर्शाता है। एनआईडीपीआईडी कार्यप दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अधिदेशों (यूएनसीआरपीडी), विधायी त्र दिव्यांगजनों के लिए प्रख्यापित राष्ट्रीय नीति के अनुसार नियोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजनकरण, (एनआईडीपीआईडी) का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। इस संस्थान में छह विभाग हैं यस्वतेवन, सामुदायिक पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय तथा सूचना सेवाएं, चिकित्सा विज्ञान, पु विज्ञौर विशेष शिक्षा। एनआईडीपीआईडी के तीन क्षेत्रीय केंद्र नोएडा, कोलकाता और नवी मुंबई, प्रत्येक में एनपीआईडी का एक माडल विशेष शिक्षा केंद्र (एमएसईसी) नोएडा में है। एनआईएमएच का अपना सद्र गं, सिक्किम राज्य में है। इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियोंको प्रशासनिक अनुभाग से सहयोग प्राप्त है।

एनआईएमएच के उद्देश्य

- मानसिकजसेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधनों का विकास तथा श्रम शक्ति का सृजन
- देश में विटन के देखरेख तथा पुनर्वास के लिए उपयुक्त मॉडलों का विकास करना
- भारतीय के उपयुक्त मानसिक विकृति जन के देखरेख तथा पुनर्वासन के लिए उपयुक्त मॉडल त्र।
- मानसि विन के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- मानसिशनत्र में दस्तावेज एवं सूचना केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना।

- ग्रामीण तथा निम्न आय श्रेणी, तथा जरूरतमंद लोगों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं का विकास
- मानसिक रिटार्डेशन के क्षेत्र में विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन

यह संस्थान मानसिक मन्दता, समुदाय-आधारित पुनर्वास, पुनर्वास चिकित्सा विज्ञान, आरंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास मनोविज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है। विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों की आवश्यकता के मद्देनजर, संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में एम.फिल. कार्यक्रम का भी संचालन करता है जो मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए छात्रों को तैयार करता है। एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान) कार्यक्रम से ऐसे व्यावसायिकों को तैयार किया जाता है जो मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान कर सकें।

मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य को आरंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे-फिजियोथेरेपी/ऑर्थो, बायोकेमिस्ट्री, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यवहार आशोधन, माता-पिता को परामर्श प्रदान करना तथा व्यावसायिक आकलन-संबंधी सेवाएं आदि। यह संस्थान पुनर्वास एवं देखरेख के लिए मॉडल भी विकसित करता है। संस्थान में एक विशेष शिक्षा केन्द्र (एसईसी) भी है जो संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त संस्थान नई दिल्ली में इसी प्रकार का एक मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र भी संचालित करता है जो नोएडा और नई दिल्ली से कार्य करता है। दोनों ही केन्द्र मानसिक मंदता की भिन्न-भिन्न मात्राओं से ग्रस्त बच्चों सहित 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पंजीकरण करते हैं।

ऐसे बच्चों के अभिभावकों को, जो दूरस्थ स्थानों से आते हैं और संस्थान की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, संस्थान के परिसर में पारिवारिक कुटीर उपलब्ध कराए जाते हैं जहां गृह-आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के लिए कार्यक्रम योजना प्रदान की जाती है। इन कुटीरों में अपने प्रवास के दौरान, अभिभावकों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपने रोजमर्रा के कामों से दूर रहते हुए बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इसके अतिरिक्त, एनआईडीपीआईडी ने विभिन्न जांच उपकरणों, जागरूकता सृजन सामग्रियों और प्रबंधन पैकजों को विकसित किया है, जिनका देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार प्लेसमेंट की सेवाओं के माध्यम से मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करती है। मानसिक मंद वयस्कों को जैनेरिक कौशलों तथा विशिष्ट कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और तत्पश्चात ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं व्यावसायिक कार्यों, मार्गदर्शन, काउंसलिंग तथा वर्कस्टेशनों के रूप में प्रदान की जाती हैं। वर्कस्टेशन प्रशिक्षण के उत्पादों जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकॉपींग, स्टेशनरी उत्पादों (राइटिंग पैड, फाइल पैड आदि) तथा ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग संस्थान द्वारा आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है। अन्य उत्पादों जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेंटिंग, सॉफ्ट टाय, क्राफ्ट वर्क आदि को आगंतुकों और स्टाफ के सदस्यों द्वारा खरीद लिया जाता है। इन लेनदेनों से होने वाली आय को प्रशिक्षु क्लाइंटों को वापस कर दिया जाता है जो कि उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति स्वरूप है।

इस संस्थान के पास बौद्धिकता संबंधित क्षेत्रों में 14000 से अधिक पुस्तकों और जर्नलों के संग्रह वाला एक सुसज्जित पुस्तकालय है। श्रीअने आज की तिथि तक 98 मौलिक प्रकाशन किए हैं। संस्थान इंटरनेट के माध्यम से जर्नल आट्रिकलो कॉप्लब्ध कराता है, एनआईएमएच के प्रकाशनों, वीडियो कैसिटों तथा फ्लैपियों का वितरण करता है, नैमी प्र स्रेदान करता है, तथा इंटरनेट के माध्यम से रीडिंग सूची तथा समाचारपत्रों की क्लिपिंग और सूचना से कर।

संस्थान वर्ष 2016-17 में 7 प्रेन ामों का संचालन कर रहा है। संस्थान बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर लोगों के लिए 60-कालार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रति वर्ष सामान्य सेवाओं के अंतर्गत औसतन 9000 से अधिक ामों 10000 हजार फौलो अप मामलों को देखा जाता है। संस्थान प्रति वर्ष एक राष्ट्रीय अभिभावक बैठक, अकि बैठकों और एक विशेष कर्मचारी राष्ट्रीय बैठक का आयोजन करता है। एनआईआईपीआईडी प्रत्येक ाम क्षेत्रागों में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

एनआईआईपीआईडी मानसिक से ग्यक्तियों एवं उनके कल्याण अनु.जा./अनु.जन.जा. अभिभावकों के लिए भी गहन कार्यक्रमों का आयोज है। ार्यक्रम में शामिल हैं :-

- अनु.जन.र संबंधित मानसिक मन्दाता से ग्रस्त व्यक्तियों को कंप्यूटर सहयोगी निदेश (सीएनथ ङ्क लैपटापों का वितरण।
- सीएअपर 11/अनु.ज.जा. से संबंधित व्यावसायिकों को प्रशिक्षण।
- अनु.ज.जसंबंधित दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रमों के छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क तथाप की प्रतिपूर्ति।
- मानसि से व्यक्तियों को यात्रा भत्ता, अध्यापन शुल्क, यूनिफार्म तथा पुस्तकों की प्रतिपू

एनआईआईपीआईडी ने संसर्गीयों पर एक सीडी विकसित की है, जिसे देश के विभिन्न भागों में एनआईआईपीआईडी द्वारा ामि कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया है। उपर्युक्त सीडी के अतिरिक्त, एनआईआईपीआईडी ने अनेकयर /वीडियो फिल्में भी विकसित की हैं जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक महत्व की हैं। ामि प्रेशन के माध्यम से मानसिक मंदता वाले बच्चों में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्रते र्ष के दौरान एनआईएमएच द्वारा मल्टी सेंसरी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। एनआईआईपीवेब (www.nimhindia.gov.in) को आशोधित किया गया है ताकि फ्लैश चित्रों के द्वारा उसे नया रूप प्रद ा और दिव्यांगजनों को सहिष्णु बनाया जा सके। संस्थान ने हिन्दी में भी अपनी वेबसाइट को विकसित कि

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएटीपी)

दिव्यांगजनों को लगातार देखभाल एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए एनआईडीपीआईडी ने वर्ष 2016-17 के दौरान 3 मास की अवधि का केयर एसोसिएट प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएटीपी) आरम्भिक प्रशिक्षण (बौद्धिक दिव्यांगताएं, स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, प्रमास्तिशक घात एवं बहु-प्रकारीय दिव्यांगताओं इन के परिवारों, संस्थानों, स्कूल एवं अस्पताल, एनजीओ आदि) कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देखभाल प्रशिक्षण उपलब्ध तथा की अत्यधिक आवश्यकता वाले स्वलीनता रोगियों की सहायता के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्रशिक्षुओं को आईडी, स्वलीनता, प्रमास्तिशक घात, एवं बहुप्रकारीय दिव्यांगताओं वाले बच्चों की देखभाल के दिशा निर्देश दिए जाते हैं।

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, देवनगिरी

मंत्रालय ने देवनगिरी, कर्नाटक में संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया तथा विभिन्न स्तरों पर 19 पद स्वीकृत किए गए। तदनुसार, एनआईडीपीआईडी, ने कर्नाटक सरकार द्वारा आवंटित-भवन का अधिग्रहण कर लिया संस्थान द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने स्टाफ की भर्ती करने का कार्य किया जा रहा है।

दीप प्रकाश—एमएस

दीप प्रकाश, 17 वर्षीय, निको एनआईआईपीआईडी मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर (एम) में किरके, हिट करके, ग्लासों को तोड़ने, छीन-झपटी, बड़ों के सुनारे बच्चों को मारने आदि की व्यवहार संबंधी शिकायतों के ग्राहक था। बहु अनुशासनिक टीम द्वारा पूरे आकलन के पश्चात एनआईआईपीआईडी की अल्प बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त पाया गया। उसे एमएसआईसी में सितम्बर 2014 में प्रि-वोकेशनल प्रभावित किया गया। अपनी व्यवहारगत समस्याओं के कारण वह पढाई के विधियों में ध्यान केन्द्रित नहीं पाता।



लगातार प्रशिक्षण के बाद स्वयं को अनुकूल बना लिया और उसमें सुधार दिखाई। शिक्षकों ने पाया कि वह चित्रकला एवं कम्प्यूटर परिचालन में विशेष रुचि दिखा रहा है। इन कलाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया। लगातार प्रयासों के कारण उसने स्कूल एनएस के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार दिखाया। उसने स्कूल स्तर की अनेक चित्रकला प्रतियोगिताओं और ओवला केन्द्र में आयोजित भारत के पर्वों पर आठवीं वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम प्राप्त किया। उसने मोड़क चित्रकारी की और अनेक पुरस्कार जीते उसने वायुसेना कैंपस द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय कार्यक्रम में कम्प्यूटर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम प्राप्त। दसवीं कक्षा की परीक्षा के लिए उसका पंजीकरण एनआईओएस के साथ हुआ और भी एं सफलतापूर्वक दी। वह एफ-टेक कम्प्यूटर एजुकेशन कार्यक्रम मालवीय नगर, नई दिल्ली में कम्प्यूटर संस्थान में भी पंजीकृत हुआ और एमएस ऑफिस एवं एमएस एक्सेल प्रमाणपत्र को प्राप्त पूर्वक पूर्ण किया। हम उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।



माननीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा 18 अक्टूबर, 2016 को नागदा, मध्य प्रदेश में टीएलएम के किटों का वितरण करते हुए



श्री कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारत सरकार, का दिनांक 04.09.2016 को क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता का दौरा

7. राष्ट्रीय बहु-व्यंगता जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईडीपीएमडी) चैन्नई

भारत सरकार के दिव्यांगजन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, के अधीन राष्ट्रीय बहु-विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान (एनआईडीपीएमडी) की स्थापना मुदुकाडू जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में वर्ष 2005 में बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। एक से अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्तजन अधिनियम, 1995 में किए गए उल्लेख तथा राष्ट्रीय न्याय (1999) अधिनियम के अंतर्गत आधारित पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देश में सेवाओं की उपलब्धता में कमी को ध्यान में रखते हुए संस्थान की स्थापना समूह भावना के माध्यम से अंतर्वेशन की सुविधा, बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण का सुनिश्चित किया जाने के मिशन को ध्यान में रखकर की गई थी।

उद्देश्यों का सारांश

- बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए प्रबंधन हेतु मानव संसाधनों का विकास, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, एवंजिक विकास को विकसित करने का कार्य।
- बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कराना एवं उसका संवर्धन।
- सामाजिक एवं अनुशासनात्मक मॉडलों एवं नीतियों को विकसित करना तथा बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सेवाओं एवं आउटरीच कार्यक्रमों को कराना।

दिव्यांगजनों को, जीवन का भरपूर जीवन व्यतीत करने का समान अधिकार है। ऐसा, प्रतिबद्ध व्यवसायिकरण सुगम्य वातावरण, समान अकार सोच तथा उपयुक्त, वहन करने योग्य, स्वीकार्य एवं उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप से प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसा, आवश्यकता आधारित निम्नोक्त प्रस्ताव सरलीकरण समावेश, बहु दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए विपर आधारित प्रमाणीकरण उपलब्ध कराकर संभव हो सकता है।

बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ग्राहकों, परिवारों, व्यावसायिक एवं सामुदायिक एजेंसियों के समान सहभागिता से उन्नत किया जा सकता है।

प्रदत्त सेवाएं

- चिकित्सा हस्तक्षेप
- शीघ्र हस्तक्षेप
- शारीरिक पुनर्वास

- फिजियोथैरेपी
- व्यवसायिक थैरेपी
- संवेदी इन्टीग्रेशन थैरेपी
- विशेष स्कूल
- प्रोसथेटिक्स एवं ओर्थोओडिक्स
- इन्क्लूसिव प्रिपेटरी स्कूल
- अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम
- आडियोगत विकास
- वाक् एवं भाषा हस्तक्षेप
- मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप
- मार्गदर्शन एवं परामर्श
- विशेष शिक्षा सेवाएं
- प्रौढ स्वतंत्र जीवन चर्चा कार्यक्रम
- मोबाइल सेवाएं
- डे-केयर सेंटर
- व्यवसायिक प्रशिक्षण
- स्मुदाय/आउटरीच कार्यक्रम
- सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण
- परिवार काटेज सेवाएं
- प्रलेखीकरण प्रसार सेवाएं
- विश्राम देखभाल सेवाएं
- टोल-फ्री हैल्पलाइन

संस्थान में एचआरडी, आर एवं डी एवं सेवा केन्द्र कार्यक्रमों को चलाने के लिए निम्नलिखित विभाग स्थापित किए गए हैं:

- शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग
 - शीघ्र हस्तक्षेप
 - फीजियोथैरेपी
 - ओक्युपेशन थैरेपी
 - प्रॉसथेटिक एवं आर्थोटिक्स

- क्लीनि विज्ञभाग
- विशेष ांग
 - भाला शिक्षा
 - अधि
 - ष्क
 - नतद्रम विकार
 - बहु गताएं
- वाक्, सप्रेषभाग
- प्रौढ सनचभाग
- सामाजिविभ
- सूचना लोकभाग



डा. विनोद अग्रवाल, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 08/2016 को सेवा गतिविधियों की समीक्षा और वृक्षारोपण करते हुए।



श्री थावरचन्द गेहलोत, केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, ने सिंहस्थ कुंभ मेला, उज्जैन, मध्य प्रदेश में मेले के दौरान 07 मई, 2016 को एनआईडीपीएमडी स्टाल का दौरा करते हुए



नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन री हैबिलेशन (एनबीईआर) – आरसीआई की 08 से 09 जून, 2016 की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समन्वयक बैठक



बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के समग्र प्रबंधक पर स्वास्थ्य प्रिमियम, उडिसा में 31 अगस्त से 01 सितंबर, 2016 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन

सफलता की कहानी

नाम: मास्टर मोहम्मद

सुपुत्र: मोहम्मद सादिक

2 वर्ष 10 माह, पुरुष, बै निव्यैन्नई

पूर्व इतिहास: मास्टर सादिक वर्ष 6 माह की आयु में सक्रिय एवं मिलनसार लड़का था। क्यूज थैरेपी से संबंधित समस्याओं की जांच के विस्तृत मूल्यांकन के लिए थैरेपी विभाग में आया।

दिव्यांगता: विकास में दे

हस्तक्षेप:

पहचान की गयी मुख्य व्ययक्त प्रदर्शन घटक निवल मोटर, फाइन मोटर, पूर्व लिखित ज्ञान-बौधात्मक कौशल, विजवोमोटर कौशल, एडीएल स्व: देशल स्वयं खाना एवं खेल कौशल आयु के अनुसार नहीं है।

व्यावसायिक थैरेपी यू मने, उसके ऊपर उल्लिखित कार्यात्मक दोशो के लिए व्यक्तिमूलक व्यावसायिक थैरेपी दी।

- न्यूनात्मपी (एनडीटी)
- प्रोटव नांसपेशीय फेसिलिटेशन (पीएनएफ)
- रूच
- बाल च
- बाउदी
- हैं थैरेपादि तथा आवश्यकता के आधार पर अन्य विविध ओटी तकनीकी

प्रबंधन

हस्तक्षेपों के माध्यम से गति कौशल जैसे ऊपरी अंग-समीपस्थ स्थिरता, जिहा नियंत्रण कौशल, उत्तम मोटर कौशल में सुधार हुआ है। इन कौशलों के द्वारा इसके हस्तकार्य कौशल जैसे पहुंच, पकड़, उठाना, धी में भी संतोशजनक विकास हो रहा है। ऐसा उसके लेखन कौशल अर्थात् घसीटने, दिये में रना, सहायता सहित छपाई करना आदि में दिखाई देता है। वह अपने आप बहुत देर तक बैठता है तथा गेंद फेकने, पैग बोर्ड खेलों, ज्ञानात्मक बोधात्मक कौशल में भी प्रदर्शन कर पाता है। क हस्तक्षेप प्रणाली से वह स्वतंत्र रूप से रेंगते हुए धरती से बिस्तर एवं बिस्तर से धरती आदि के गति कौशल में भी सुधार हो रहा है। वह अपने कार्यों को करने में, मूलभूत स्व देखभाल ए जन्मैसे खाद्य सामग्री प्रबंधन, पानी की बोतल को पकड़ना, और कम से कम सहायता लेकर क पीदि के कार्य कर रहा है। उसकी आयु उनके उपयुक्त विकास के लिए अभिभावकों को उपयुक्त दिया।



सफलता की कहानी

नाम: जी.सुरथा

सुपुत्र: श्री गोथनदम

22 वर्षीय थयार, कैलंबकम, चैन्नई, निवासी

पूर्व इतिहास:

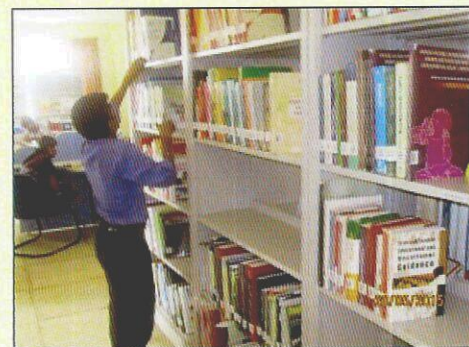
वह अपने परिवार का 02 वर्षीय पुत्र है। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है और उसकी हृदय शल्य चिकित्सा भी हुई है।

दिव्यांगता का कारण: उसकी वाक् कठिनाई स्थिति से संबद्ध औसत बौद्धिक दिव्यांगता के रूप में पहचान की गई।

हस्तक्षेप:

उसने 11 जून, 2012 को एनआईडीपीएमडी से संपर्क किया। उसका मूल्यांकन बहु-अनुशासनीय टीम द्वारा किया गया और स्वतंत्र जीवन कौशल विकसित किया। इसके बाद उसे प्रौढ़ स्वतंत्र जीवन विभाग में अग्रेषित किया गया। जहां एक विस्तृत व्यावसायिक प्रशिक्षण तैयार किया गया और व्यक्तिगत कौशल, घरेलू कौशल, सुरक्षा कौशल, शिक्षा ओरिएंटेशन और गतिशीलता, कार्य व्यवहार, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल का प्रशिक्षण दिया गया और निम्नलिखित व्यक्तिगत योग्यताओं और क्षमताओं की पहचान की गई और उसमें प्रशिक्षित किया।

तीन वर्ष की अवधि के भीतर वह व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सहायता से सुचारु प्रशिक्षण द्वारा सफलता के मार्ग पर पहुंचा। निजी स्वच्छता कौशल में प्रशिक्षण पर अधिक महत्व दिया गया। जो परिवार और समुदाय के सदस्यों में तत्काल स्वीकार्य है। उसके वर्तमान कौशल, को देखते हुए पुस्तकालय में किताबों को साफ रखने और क्रम में रखने के लिए पुस्तकालय सहायक के रूप में कार्य करने, पुस्तकालय की पुस्तकों को प्रतिदिन व्यवस्थित करने, दैनिक समाचार पत्रों से महत्वपूर्ण समाचारों को कार्यालय उद्देश्य से काट के रखने, दैनिक समाचार पत्र को व्यवस्थित रखने के उनके कौशल को देखते हुए वर्तमान में वह वर्तमान में वह एसएसएन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, तिरपूर, कांचीपुरम में अन्य माननीय स्टाफ सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है।



विभाग की विशेष उपलब्धियां एवं नये अवसर

अध्याय

11.1 सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत अभियान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 03 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया जिससे कि भवन वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर्यावरण प्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता सृजित की जा सके। अभियान दिव्यांगता के इस सामाजिक मॉडल के सिद्धांत पर आधारित है कि दिव्यांगता इस कारण कि समाज को संगठित किया जा सके न कि व्यक्ति की सीमाओं और बाधाओं को। शारीरिक, सामाजिक, ढाचागत एवं दृष्टिकोण मूलक बाधाएं दिव्यांगजनों को-सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में समान भागीदारी को सुकर बनाना है और स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन को बढ़ावा देता है। अभियान का विजन एक समावेशी समाज विकसित करना है जिसमें दिव्यांगजनों को वृद्धि एवं विकास के समान अवसरों की व्यवस्था हो ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।



(I) निर्मित वातावरण की सुगम्यता:

- i. 50 शहरों में कम से कम 25-50 अति महत्वपूर्ण भवनों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हें प्रथम चरण में जुलाई 2016 तक पूर्णतः सुगम्य बनाना।
संशोधित समय अवधि: दिसम्बर 2017
- ii. द्वितीय चरण में जुलाई 2018 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्य राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को पूर्णतः सुगम्य बनाना।
संशोधित समय अवधि: दिसम्बर 2018
- iii. लक्ष्य (i) और (ii) में कवर न किए गए राज्यों के 10 अति महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों को तृतीय चरण में जुलाई 2019 तक पूर्णतः सुगम्य बनाना।
संशोधित समय अवधि: दिसम्बर 2019

(II) परिवहन प्रणाली :

- (i) दिसम्बर तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हें पूर्णतः सुगम्य बनाना।
- (ii) मार्च, 2018 तक सरल हवाई अड्डों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हें पूर्णतः सुगम्य बनाना।
- (iii) दिसम्बर तक ए1, ए एव बी श्रेणी के स्टेशनों को सुगम्य बनाना और सभी स्टेशनों में से 50 प्रतिशत को 2018 तक पूर्णतः सुगम्य बनाना।
- (iv) मार्च, 2018 तक सा स्वामित्व के सार्वजनिक परिवहन कैरियरों में से 10 प्रतिशत को पूर्णतः सुगम्य बनाना।

(III) नॉलेज और आराम की सुगम्यता:

- (i) मार्च, 2018 तक के और राज्य सरकारों की कम से कम 50 प्रतिशत वैबसाइटों द्वारा सुगम्यता मानक। 2018 तक प्रलेखों के कम से कम 50 प्रतिशत सार्वजनिक प्रलेखों द्वारा सुगम्य पूरे।
- (ii) मार्च, 2018 तक रिक्त संकेत भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित करना और विकसित करना। (iii) सार्वजनिक विज्ञापन-जुलाई, 2016 तक कैपशनिंग और संकेत भाषा व्याख्या पर राष्ट्रीय मानक बनाने अंगीकरण करना। मार्च, 2018 तक सरकारी चैनलों पर कम से कम 25 प्रतिशत के वेब कार्यक्रमों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करना।

(IV) सुगम्य भारत की लक्ष्ययां

- (i) राज्य द्वारा भवनों की पहचान की गयी जिसमें से 1637 भवनों की लेखा परीक्षा का कार्य पूर्ण कर लिया गया।
- (ii) राज्य के 1293 सुगम्यता लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
- (iii) निःशुल्क मानस, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, (सिपडा) योजना के अंतर्गत स्थाव प्राप्त हुआ है तथा 225 भवनों के लिए 4061.49 लाख रु. की राशि की स्वीकृति।

(iv) विभाग ने मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, चैन्नई एवं रांची में जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें सुगम्य भारत अभियान के विभिन्न पहलुओं पर अंतर्दृष्टि डाली गयी। यह दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मिलित करने की सार्वभौमिक सुगम्यता की प्राप्ति की यात्रा में विभिन्न स्टैकहोल्डरों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर गहन विचार विमर्श सहित इनकियोन रणनीति निदेशों की पुष्टि में है।

(v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 39 भवनों को रैलिंग सहित रैंप, दिव्यांगता अनुकूल शौचालय, वाक् एवं दृश्य संकेत तथा बहु-मंजलीय भवनों के मामले में लिफ्टों में ब्रेल बटन सहित सुगम्यता उपलब्ध करायी गयी।

(vi) **हवाई अड्डे**

32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से 25 हवाई अड्डों में रैंप, सुगम्य शौचालयों, ब्रेल संकेतों एवं आडिटरी संकेतों सहित लिफ्टों के सुगम्य मानक उपलब्ध कराये गये। घरेलू हवाई अड्डों में दिसंबर, 2017 तक सुगम्यता मानक उपलब्ध करा दिये जायेगे। तथा दिव्यांगजनों के लिए हैल्प डेस्क का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) **रेलवे स्टेशन**

स्टेशनों के प्रकार	ए1	ए	बी	कुल
स्टेशनों की कुल संख्या	75	332	302	709
सुगम्य बनाए गए स्टेशनों की संख्या	75	305	221	601

(viii) अन्य सभी ए1, ए एवं बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में 31 मार्च, 2017 तक अल्प अवधि सुगम्यता सुनिश्चित की जायेगी जिसमें रैलिंग सहित रैंप, दिव्यांगों के लिए पार्किंग, पार्किंग से भवन तक न फिसलने वाला पथ, संकेत चिह्न, पीने के पानी की सुविधाएं, भूतल पर सुगम्य शौचालय एवं “मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ” बूथ की स्थापना शामिल हैं।

(ix) लंबी अवधि के सुगम्यता मानक जिसमें अंतर प्लेटफार्म स्थानांतरण एवं प्लेटफार्म की टैक्सटाइल फ्लोरिंग, शामिल है।

अन्य उपलब्धियाँ

- (i) सड़क एवं गार्ग मंत्रालय ने राज्यों एवं उपक्रमों के संगठनों के कार्यकारी निदेशकों को निदेश दिये कि वे मार्च, 2018 तक सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन का 10 प्रतिशत जनरेल पूर्णतः सुगम्य बनाना सुनिश्चित करें।
- (ii) सड़क एवं गार्ग मंत्रालय ने सितंबर, 2016 में बस बाडी कोड अधिसूचित किया जिसमें दिव्यांगों के प्रावधान किया गया है, जिसमें दो चरणों में, अर्थात् 01.01.2017 से प्रथम चरण 2018 तक चरण का कार्यान्वयन लागू है।
- (iii) सांख्यिकी मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टरों / जिलाधीशों को जनवरी, 2016 में निदेश जारी किया जिसमें दिव्यांगजनों के लिए एमपीएलएडी अनुकूलता के अंतर्गत भविष्य में टिकाऊ परिसरों का सृजन आवश्यक बनाने के लिए तथा एमपीएलएडी के अंतर्गत तैयार वर्तमान टिकाऊ परिसरों के फिटिंग कार्य को अनिवार्य किया गया है।
- (iv) पांच राज्यों में, मुरुगकर, अरुशि सामर्थ्यम एवं सुगम्य वातावरण राष्ट्रीय केन्द्र, श्री सुभाष चंद्र बोस सुश्री अनीता नारायण को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पैनल में लिया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक के द्वारा 100 सुगम्य लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया।
- (v) विशाखा पुर्ब नई दिल्ली में तीन कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः 05.01.2017, 11.01.2017, 18.01.2017 को किया गया जहां दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सीपीएसयू को इंपुट कराया।
- (vi) भारतीय ब्यूरो सृजित किया कि संशोधित राष्ट्रीय भवन कोड में दिव्यांगता पक्षों को शामिल किया गया।
- (vii) स्कूलों का विभाग ने सूचित किया कि सुगम्यता लैस से प्राइमरी स्तर पर संशोधित पाठ्यक्रमों का विकसित कर ली गयी है। दिव्यांग बच्चों की सुगम्यता के संबंध में एक विस्तृत योजना विकसित किया गया।
- (viii) सार्वजनिक सुगम्य करने के लिए सरकार के सुगम्य भारत अभियान को पूरा करने के अगले अध्याय में। ने प्रिंट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सुगम्य पुस्तकालय आरंभ प्रणालियों के लिए उच्च स्तर की टैक्टाइल मानचित्र पुस्तक प्रकाशित की गयी। डिजिटल सिबल इन्फार्मेशन सिस्टम में मानचित्र पुस्तक का आडियो हिन्दी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया।

- (ix) संकेत भाषा पर एक माड्यूल विकसित करने के लिए एक टॉस्क फोर्स स्थापित की गयी।
- (x) सितम्बर 2016 तक 98 संकेत भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा अन्य 200 को नये स्थापित भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा मार्च, 2018 तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।
- (xi) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य सरकार की 917 वेबसाइटों का कार्य आदेश ई आर एन ई टी इंडिया को दिनांक 28.12.2016 को जारी किया जो मई, 2017 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 19.11.2015 के परिपत्र द्वारा सभी विभागों को निदेश जारी किया कि वे अपनी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए उपयुक्त बजट आवंटित करें।
- (xii) आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि संबंधित मंत्रालय/विभागों को पब्लिक कार्यालय एवं वेबसाइटों की सुगम्यता उनके निजी बजट से करानी है।
- (xiii) एमईआईटीवाई ने सूचित किया कि सरकारी अधिसूनाओं/परिपत्रों आदि को सुगम्य बनाने, उन्हें ईपीयूबी अथवा ओसीआर आधारित पीडीएफ में डालने का, तथा खरीद के लिए आरएफपी में सुगम्यता के अनुपालन पर एक धारा को शामिल करने का निदेश जारी किया गया है।
- (xiv) एमईआईटीवाई ने आगे सूचित किया कि कन्टेन्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत 100 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना अनिवार्य है। 56 मंत्रालय/विभाग सी एम एफ की ओर आगे बढ़ गये हैं, अब तक 30 वेबसाइटों को जीवन्त कर दिया गया है तथा 26 वेबसाइटें अगले तीन मास में आरम्भ हो जायेगी।
- (xv) विज्ञान एवं तकनीक विभाग (डीएसटी) ने सूचित किया कि इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की विषय वस्तु दिव्यांगता है।
- (xvi) इस विभाग की राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत सुगम्यता पुरस्कारों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
- (xvii) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 9 अगस्त, 2016 को दिशानिदेश जारी किये गये कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अंतर्गत किया जाए। इसके संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा एक हैंडबुक जारी की गयी।
- (xviii) **राइड 4 सुगम्यता** "राइड 4 एन एक्सेसिबल इंडिया" पर दिनांक 24.7.2016 को इंडिया गेट, लोदी गार्डन बसन्त कुंज तथा साउथ एक्सटेंशन पर एक मोटर साइकिल रैली आयोजित की गयी, जिसमें 600 से अधिक मोटर बाइक सवार तथा 6000 युवाओं छात्रों ने भाग लिया। माननीय श्री थावरचन्द गेहलोत, केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने रैली का उदघाटन किया। मानव संसाधन

विकासननी प्रकाश जावेडकर, तथा विज्ञान एवं तकनीक मंत्री, माननीय डा० हर्शवर्धन, सामाजिक एवं कारिता राज्य मंत्री, माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर तथा समाज सेवक एवं अभिनेता भी समारोह में उपस्थित हुए। सुगम्य भारत अभियान के प्रति आम जन समूहों के लिए कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकप्रिय रंगमंच समूहों के तथा 'रंगरेज' रॉक बैंड के प्रदर्शन का आयोजन भी हुआ। सभी केन्द्रीय पुलिस भी उपदाधिकारियों को नामित करके तथा अपना बैंड उपलब्ध करवाकर अपना सहयोग समारोह को रंगीन बना दिया।

अभियान न केवल जनते उन सभी युवाओं और वृद्धों, जो इस अभियान में भाग लेने के लिए शामिल हुए, में उल्लास के जें सफल करा। अभियान की मीडिया रणनीति सतर्कता से इस उद्देश्य के साथ तैयार की के बनाने वालों तथा सामान्य व्यक्तियों में सुगम्यता को जागृत किया जा सके तथा वे अपने अपने दण में बाधामुक्त वातावरण तैयार कर सके। अभियान का उद्देश्य युवाओं और छात्रों को और अभियान का हिस्सा बनाना भी रहा।

11.2 शोध और वि

दिव्यांगजन सश विने 'दिव्यांगता संबंधी तकनीक, उत्पाद और मुद्दों पर शोध' पर एक नई केन्द्रीय योजना कि जनवरी 2015 में व्यक्तियों और उनके परिवारों के विकास व जीवन चक्र के आधार पर कई सर्विडल व कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य के संग कार्य किया जा रहा है और त ताओं व सहायक उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और तकनीक के अनुप्रयोग के विदेव से बचाव में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए व दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लि क्षमवरण का निर्माण कर रही है। इस योजना में दो घटक हैं: क. सहायक तकनीक और कारकरणों का शोध व विकास और ख. दिव्यांगता के संबंध में आंकड़ों के अध्ययन/शोध र्त्न और आवधिक एकत्रीकरण के लिए योजना। राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों के अंतों सेना के अनुपालन में उनके प्रस्तावों को जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

वर्ष 2016-17 व प्रस्तो पहले चरण में प्राप्त किया गया जिसमें से 3 प्रस्तावों को विभाग के द्वारा अनुमोदित किया गल, नआईएमएचएएनएस, बैंगलोर नामक एक एजेंसी ने उनके द्वारा ली गई परियोजना को के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, और एनआईएमएचएएनएस के लिए 6 लाख रूपयों की जा गई है। अन्य दूसरी टीआईएसएस, मुंबई नामक एजेंसी करार पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया में है में 4 प्रस्तावों के दूसरे चरण में, 2 प्रस्तावों को कुल 23.84 लाख की लागत के संग स्टीयरिंग र द्वारा मोदित किया गया है।

11.3 भारतीय संकेत भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना: (आईएसएलआरटीसी)

- सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है, शुरुआत में विभाग के सहायक के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रभाव के आदेश 28 सितंबर 2015 को जारी हो गए हैं।
- केन्द्र के मुख्य उद्देश्य भारतीय संकेत भाषा में अनुप्रयोग के लिए जनशक्ति का विकास, प्रशिक्षित और अनुसंधान करेगा।
- आईएसएलआरटीसी का पंजीकरण 01.02.2016 को सोसाइटी के रूप में किया गया। 33 पदों के सृजन के लिए आदेश 06.02.2016 को जारी किया गया। केन्द्र के लिए 33 पदों के अनुमोदन के मुकाबले, 10.12.2016 तक 16 ने पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय संकेत भाषा व्याख्या में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रथम बैच 15 छात्रों की क्षमता के साथ 28.10.2016 से चालू है। दूसरा बैच 14.12.2016 से शुरू किया गया है। लगभग 6000 शब्दों का संकेत भाषा शब्दकोश बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। आईएसएलआरटीसी भारत में आईएसएल व्याख्याओं की डायरेक्ट्री बनाने की योजनाबद्ध है।
- केन्द्र वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, 4, विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में स्थित है। केन्द्र का कार्यालय परिशर ओखला फेस-2, नई दिल्ली में किराया पर (6700 स्क्वायर फीट) लिया गया है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईएसएलआरटीसी के लिए बजट आवंटन 25 करोड़ रु. और योजना के अंतर्गत 2016-17 के लिए बीई 3 करोड़ रु. है। 31.12.2016 तक 75 लाख रु. की निधियां जारी की गई हैं।

11.4 समावेशी और सार्वभौमिक डिजाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआईयूडी):

1. मंत्रालय ने समावेशी और सार्वभौमिक डिजाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआईयूडी) को स्थापित करने का प्रस्ताव यूनिवर्सल डिजाइन के इंकलुसिव एजेंडा पर दिया है जो दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के द्वारा सुगम्यता के लिए ज्यादा महत्ता के माध्यम से हर किसी के लिए सुगम्य वातावरण पर जोर देगा। इस संबंध में 12वीं योजना अवधि में 40 करोड़ रुपए की एक रूपरेखा भी बनाई जा चुकी है।

2. मंत्रालय आईडी की स्थापना के लिए मार्गदर्शन और समन्वय के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के क्षेत्र में आईडी की स्थापना के लिए विभाग के सहयोग से प्रतिष्ठित 2-3 अंतराष्ट्रीय संस्थानों की प्रक्रिया में है। इंकलूशिव डिजाइन केन्द्र और सुगम्य पर्यावरण, यूनिवर्सिटी आफ न्यूयॉर्क पहचान की गई है जिसमें विभाग सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

11.5 दिव्यांगता खेल केन्द्र

दिव्यांगता हेतु खेल केन्द्र स्त करने का प्रस्ताव है जिनके लिये 12 वीं योजना अवधि हेतु 20.00 करोड़ रुपये आवंटित किए। व में यह विभाग 03 दिव्यांगता खेलकूद केन्द्र की स्थापना पर विचार कर रहा है, जिसमें जीरकली, राज्य सरकार, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, राज्य सरकार और ग्वालियर, मध्य प्रदेश राज्य शामिल कर ली है।

दिव्यांग खेलकूद अत्य उत्कृष्टता स्तर के केन्द्र स्थापित करने हेतु परामर्शन सेवायें प्रदान करने और स्थल विशेष परिणाम तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं के चयन करने की प्रक्रिया में है, तीन केन्द्रों को अंतिम चयन है।

राष्ट्रीय निधि से बना लिए व्यय का दायित्व पूरा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की अध्यक्षता सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय निधि प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

11.6 राज्य स्पाईन केन्द्र स्थापना पर केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

1. विभाग स्टेट नल इंजरी सेंटर के गठन के लिए एक योजना का निर्माण किया है जिसके लिए बजट 20 करोड़ रुपये की एक रूपरेखा को बनाया गया है। स्टेट स्पाइनल सेंटर ध्याय रूप से मेरुदंड की चोटों के उचित प्रबंधन पर होगा। इस योजना के अंतर्गत संघात क्षेत्रों की राजधानी में जिला अस्पतालों में एक विस्तृत पुर्नवास केन्द्र को बनाया और 12 बेड इसी के लिए होंगे।
2. योजना मार्क को अधिसूचित किया गया है। इस विभाग ने अपने राज्यों में केन्द्रों की स्थापना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति मांगी है। अभी तक राजस्थान, जम्मू कश्मीर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर (राजस्थान) मेडिकल कॉलेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रत्येक 2.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता अनुमोदित की गई है।

3. वर्ष 2016-17 के लिए कुल आवंटित बजट 4.00 करोड़ रु. में से, 31.12.2016 तक आईएसआईसी को 3.50 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं।

11.7 सार्वजनिक-निजी भागीदारी

1. दी इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली, एक गैर सरकारी संगठन मेरूदंड की चोट से पीड़ित लोगों को और संबंधित रोगियों को एक पूरी तरह से पुर्नवास की सेवाएं प्रदान करता है। इनमें पुर्नरचना सर्जरी, स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन, फिजिकल पुर्नवास, मनो-सामाजिक पुर्नवास और पेशेवर पुर्नवास सेवाएं शामिल हैं।
2. केन्द्रीय मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार, सरकार गरीब मरीजों के उपचार के लिए 25 बेड मुफ्त में देने का प्रस्ताव करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र गरीब मरीजों को 5 बेड प्रदान करती है।
3. पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईएसआईसी को विभाग द्वारा जारी किया गया अनुदान नीचे दिया गया है :-

रु. करोड़ में

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	जारी की गई राशि
2014.15	2.00	1.80
2015.16	2.00	2.00
2016.17 (31.12.2016 तक)	2.00	1.00

4. विभाग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली के आईएसआईसी को निधियों की प्रतिपूर्ति की प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन की योजना के संचालन के लिए अनुबंध प्रदान किया है। एनपीसी ने विभाग को अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट 24.08.2016 को प्रस्तुत कर दी है।

11.8 “ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता” की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

सरकार ने दृष्टि बाधितों के लाभ के लिए नवंबर, 2014 में “ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता” की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की है।

- परियोजनाएँ
 - (i) श्री ब्रेलों की सीपना
 - (ii) राज्य में 03 लघु स्तरीय ब्रेल प्रेसों की सीपना
 - (iii) श्रानी प्रेसों का आधुनिकीकरण
 - (iv) धुन्लि प्रिंटिंग प्रेसों की ब्रेल प्रिंटिंग क्षमता को बढ़ाना ।
- सरकार के 32016 तक निम्नलिखित ब्रेल प्रेसों को स्वीकृत किया ।

नयी ब्रेल प्रेस	—	6 संख्या
वर्तमान में कनिकीकरण	—	2 संख्या
ब्रेल प्रेसों का वृद्धि	—	3 संख्या
- योजनागत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में 31.12.2016 तक, के दौरान योजनागत प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए जारी अनुदानों का विवरण है:-

वर्ष	बजट आवंटन	जारी अनुदान
2014-	3.86 करोड़ रुपए	3.86 करोड़ रुपए
2015-	9.8 करोड़ रुपए	9.8 करोड़ रुपए
2016- (31.12.2016 तक)	9.1 करोड़ रुपए	8.4 करोड़ रुपए
	कुल	22.06 करोड़ रुपए

- 31.12.2016 तक जाधियों (श्रेणीवार) का विवरण अनुबंध 14 (पृष्ठ संख्या 291) के अनुसार है।

बजट अनुभाग की योजनाएँ

1. पांच क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए कालेज की स्थापना:-

योजना का उद्देश्य जाधियों को उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा उच्च शिक्षा द्वारा

बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। जो श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा में नामांकन के विषय में ढिलाई एवं आरक्षण उपलब्ध कराने के बावजूद अभी भी हासिल किया जाना है।

स्कीम, यूजीसी अनुमोदित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त एक कॉलेज में वित्तीय सहायता की परिकल्पना करती है, विद्यमान कॉलेज की अवसंरचना के विस्तार के लिए देश के पाँच क्षेत्रों में प्रत्येक में, सहायक यंत्र/उपकरण, कार्यालय उपकरण कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं स्थाई वस्तुएं आदि की खरीद और कॉलेज फेकल्टी, स्टाफ और संकेत भाषा रूपांतरकों के लिए वेतन एवं भत्तों की भुगतान की दिशा में कॉलेज द्वारा उठाई गई लागत की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की परिकल्पना करती है।

2. राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के पदधारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं सुग्राहीकरण

स्कीम का उद्देश्य राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर कार्याशाला के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन के कारण दिव्यांगता क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले नए एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के पदधारियों को प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों और दिव्यांगजनों की क्षमता के बारे में देखने वाले समूहों के मध्य जागरूकता करना है, दिव्यांगता संबंधी विधानों, विकास कार्यक्रमों/स्कीमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। प्रशिक्षण पंचायत स्तर/ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े मुख्य पदधारियों के लिए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की पुनर्वास परिशद स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। स्कीम के तहत अभी तक 3736 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

वित्तीय/वास्तविक प्रगति :-

वर्ष	वित्तीय/ वास्तविक (दर्शनी गई ईकाई)		उपलब्धी
	स.अ.	व्यय	वित्तीय/ वास्तविक लक्ष्य
2014-15	0.01	0.00	स्कीम 29.12.2014 को अनुमोदित की गई थी
2015-16	2.00	2.00	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्ण बजट आवंटन उपयोग में लाया गया था 2015-16 के दौरान 3736 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

2016-17 में लगभग 2500 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं।	2016-17 में लगभग 2500 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं।	आज की तारीख तक 1.68 करोड़ रु. की राशि बढ़ाई गई है।
---	---	--

3. दिव्यांगजन सशक्ति में कानून सेल

कानून सेल विभाग के न्यायलयों को समन्वित करेगा। विभाग के न्यायलय मामलों को संभालने के लिए मोडस अपरेन्डी संस्थान/अनुभाग/कार्यालय/निगम/ट्रस्ट की होगी जिसे न्यायलय मामलों का नोटिफिकेशन इसके बारे में तात्काल रूप से कानून सेल को अधिसूचित करेगा और तात्काल रूप से वकालत/याचिका की फोटोप्रति भी उपलब्ध कराएगा। उसके बाद विभाग का संस्थान/अनुभाग/निगम/ट्रस्ट कानून सेल को मामले की पृष्ठभूमि सहित निविष्टियां और पैरा-वार टिप्पणियां का ताकि वह वकील जो मामले का प्रतिवाद करेगा के लिए मसौदा प्रतिउत्तर तैयार करने में मदद करे। इसके अतिरिक्त कानून सेल की यह जिम्मेदारी होगी कि न्यायलय मामले प्रतिवाद में से एक वकील नियुक्त कराए। ये सुनिश्चित करेंगे कि न्यायलय मामले संभालने में कोई बाधा न हो और विभाग को न्यायलय में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तथापि संबंधित कार्यजैसे कि राष्ट्रीय संस्थान, अलीम्को, भारत पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ट्रस्ट, दिव्यांगजन मुख्य के बय और एनएचएफडीसी के न्यायलय मामले संभालने की प्रथम जिम्मेदारी संगठन के पास है। कानून केवल सहायक भूमिका अदा करेगा। इन संगठनों/अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि मामले/उपलब्धियों और मामले की तारीखों के बारे में कानून सेल को नियमित रूप से अद्यतन करे। संस्था/अरी अपने बताए गए कानून अधिकारी/कानून परामर्शदाता रखेंगे।

4. सांख्यिकीय सेल

विभिन्न अनुभागों/संगठनों के पास उपलब्ध डाटा को बढ़ाने के विषय में विभाग में एक सांख्यिकीय सेल प्रारंभ किया जा रहा है। यह है कि विभिन्न स्कीमों और विभाग की गतिविधियों पर ये डाटा विश्लेषण नीति निर्धारण प्रदान करेगा।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

दिव्यांगजनों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य में करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह के पुरस्कार संस्थापित करने का उद्देश्य जनभावना का ध्यान ऐसे व्यक्तियों की भलाई के लिए दिलाना है जो कि दिव्यांग हैं और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये पुरस्कार हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार 14 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं—

- I. श्रेष्ठ कर्मचारी/स्वरोजगार रत विकलांगय
 - II. (क) श्रेष्ठ कर्मचारी एवं (ख) श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी अथवा एजेंसीय
 - III. (क) श्रेष्ठ व्यक्ति तथा (ख) श्रेष्ठ संस्थान—दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वालाय
 - IV. आदर्श व्यक्तित्वय
 - V. दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ श्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकासय
 - VI. दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किया गया उत्कृष्ट कार्यय
 - VII. पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिलाय
 - VIII. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की श्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीय
 - IX. श्रेष्ठ सृजनशील व्यस्क दिव्यांगजनय
 - X. श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चाय
 - XI. श्रेष्ठ ब्रेल प्रेसय
 - XII. सर्वोत्तम “एक्सेसिबल” वेबसाइटय
 - XIII. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण संवर्धन में सर्वोत्तम राज्यय तथा
 - XIV. सर्वोत्तम दिव्यांग स्पोर्ट्सर्सन।
2. महामहिम भारत के राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2016 के लिए 78 व्यक्तिगत/संस्थागत को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची **अनुलग्नक-15 (पृष्ठ सं. 293)** पर दी गई है।

अनुबंध-1

विज्ञानाक्तिकरण विभाग को आबंटित कार्य

भारत सरकार (कार्य आवंटन नीति) के अनुसार, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग को आबंटित विषय हैं:-

1. निम्नलिखित विषयों की 7वीं अनुसूची की सूची I - संघ सूची के अन्तर्गत आते हैं :
दान में दी गई वस्तुआपूर्तियों के कर-मुक्ति आयात हेतु भारत-अमेरिका, भारत-यू.के., भारत-जर्मनी, भारत-जपान तथा भारत-स्वीडन अनुबंध तथा इस प्रकार की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामलों।
2. निम्नलिखित विषयों की 7वीं अनुसूची की सूची III - समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं (केवल विधान के अन्तर्गत)
"सामाजिक सुरक्षा योजना, किसी अन्य विभाग को आबंटित सीमा को छोड़कर"
3. संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II - राज्य सूची अथवा सूची III - समवर्ती सूची में आते हैं, जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं :
"विकलांगों और अनुप्राप्त व्यक्तियों को सहायता; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आबंटित नहीं है।"
4. विकलांगता और संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना :
टिप्पणी : विकलांगता विभाग विकलांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना तथा समन्वय के लिए होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।
5. विकलांगजनों के आर्थिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्व-रोजगार आदि।
6. पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण।
7. विभाग से संबंधित पराष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकलांग-जन अधिकार सम्मेलन।
8. विभाग को आबंटित के में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में धर्मार्थ और धार्मिक अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10. अधिनियम/विधान

- (i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);
- (ii) विकलांग-जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1);
- (iii) ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44)।

11. सांविधिक निकाय

- (i) भारतीय पुनर्वास परिषद।
- (ii) विकलांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।
- (iii) ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय

- (i) राष्ट्रीय विकलांग-जन वित्त एवं विकास निगम-कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।
- (ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

13. राष्ट्रीय संस्थान

- (i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईडीपीवीडी), देहरादून
- (ii) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई
- (iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता
- (iv) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक
- (v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली
- (vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईडीपीआईडी), सिकंदराबाद
- (vii) राष्ट्रीय बहु-विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईडीपीएमडी), चैन्नई
- (viii) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

अनुबंध-2

2011 की जनगणना अनुसार दिव्यांगों की राज्य-वार जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य	2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगों की कुल जनसंख्या
क	ख	ग
1	अंधा	12,19,785
2	अचल प्रमेश	26,734
3	अधम	4,80,065
4	अधम	23,31,009
5	अधम	6,24,937
6	अधम	2,34,882
7	अधम	33,012
8	अधम	10,92,302
9	अधम	5,46,374
10	अधम	1,55,316
11	अधम और कश्मीर	3,61,153
12	अधम	7,69,980
13	अधम	13,24,205
14	अधम	7,61,843
15	अधम	15,51,931
16	अधम	29,63,392
17	अधम	58,547
18	अधम	15,160
19	अधम	44,317

20	नागालैंड	29,631
21	उड़ीसा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडू	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखण्ड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	6,660
32	चंडीगढ़	14,796
33	पदमन एवं दीव	2,196
34	दादर एवं नागर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुडुचेरी	30,189
	कुल	2,68,14,994

अनुबंध-3

20.01.2017 तक गन्तमानपत्र जारी करने की नवीनतम राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	कुल दिव्यांगजन संख्या	दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या	
		कुल	प्रतिशता	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
1	आंध्र प्रदेश	1103789	938220	85.00
2	अरुणाचल प्रदेश	33315	2377	7.13
3	असम	480065	276030	57.50
4	बिहार	2331009	1235434	53.00
5	छत्तीसगढ़	624900	315833	50.54
6	दिल्ली	234882	134705	57.35
7	गोवा	33012	19164	58.05
8	गुजरात	1092302	489629	44.83
9	हरियाणा	455040	339190	74.54
10	हिमाचल प्रदेश	155316	78799	50.73
11	जम्मू और कश्मीर	361153	179385	49.67
12	झारखण्ड	769980	420895	54.66
13	कर्नाटक	1324205	972305	73.43
14	केरल	761843	422087	55.40
15	मध्य प्रदेश	810368	660313	81.48
16	महाराष्ट्र	2963392	1347949	45.49
17	मणिपुर	54110	NA	N.A.
18	मिजोरम	15160	9514	62.76
19	मेघालय	44317	33685	76.01

20	नागालैंड	29631	1752	5.91
21	उड़ीसा	1244402	842250	67.68
22	पंजाब	654063	358206	54.77
23	राजस्थान	1563694	449618	28.75
24	सिक्किम	18187	10533	57.91
25	तमिलनाडू	1179963	1119151	94.85
26	तेलंगाना	1046822	461970	44.13
27	त्रिपुरा	64346	71419	110.99
28	उत्तर प्रदेश	4157514	1943868	46.76
29	उत्तराखण्ड	185272	98881	53.37
30	पश्चिम बंगाल	2017406	1081316	53.60
31	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	6660	7019	105.39
32	चंडीगढ़	14796	22437	151.64
33	दमन एवं दीव	2196	328	14.94
34	दादर एवं नागर हवेली	3294	2523	76.59
35	लक्षद्वीप	1678	1302	77.59
36	पुडुचेरी	30189	26745	88.59
	कुल	25868271	14374832	55.57

अनुबंध-4

एडिप योजना के अंतर्गत 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों/राष्ट्रीय संगठनों/एलआईएमसीओ को जारी की गई निधि का विवरण

		2014-15		2015-16		2016-17	
		संख्या	(रु० लाख में)	संख्या	(रु० लाख में)	संख्या	(रु० लाख में)
	आंध्र प्रदेश	50	1147.19	37	421.49	17	567.41
2	बिहार	55	250.46	5	70.80	9	139.10
	छत्तीसगढ़	67	340.84	62	298.96	32	234.41
4	गोवा	5	12.67	3	8.53	2	3.59
	गुजरात	39	192.32	31	121.98	9	1572.16
6	हरियाणा	29	541.66	10	424.82	20	597.32
	हिमाचल प्रदेश	2	129.06	14	59.61	92	51.11
8	जम्मू और कश्मीर	14	76.28	4	85	20	136.8
	झारखण्ड	267	368.03	4	12.79		
10	कर्नाटक	24	218.18	20	443.46	13	221.32
							4557

11	केरल	24	207.68	3213	8	203.28	4574	4	57.37	706
12	मध्य प्रदेश	132	656.41	15318	189	848.38	17341	89	975.31	14995
13	महाराष्ट्र	108	972.97	22062	343	1651.3	27065	114	1054.22	18916
14	उड़ीसा	88	311.17	7921	179	758.83	13429	48	389.01	6353
15	पंजाब	13	228.92	2860	104	1271.83	13373	34	517.51	7306
16	राजस्थान	51	674.82	12712	44	551.19	9272	3	114.19	1263
17	तमिलनाडू	35	408.68	10183	61	853.29	9243	45	232.36	4443
18	उत्तर प्रदेश	403	2605.12	43324	326	3012.77	41309	148	3414.43	45375
19	उत्तराखण्ड	20	455.74	15168	34	327.73	5184	30	181.79	6134
20	पश्चिम बंगाल	188	476.58	16246	208	1150.98	18783	49	826.93	12862
21	अण्डमान एवं निकोबार	10	27.16	750				7	9.27	323
22	चंडीगढ़	1	2.75	59				1	1.32	391
23	दादर एवं नागर हवेली	3	12.36	342	2	1.51	58	3	2.04	54
24	दमन एवं दीव	2	3.81	83	2	3.9	35	2	2.94	60
25	दिल्ली	26	169.31	4208	7	88.48	3779	21	265.78	4029
26	लक्षद्वीप									
27	पुदुचेरी							1	1.14	82
28	अरुणाचल प्रदेश	2	5.22	60	1	7.92	353	3	8.43	198

29	असम	186	920.25	12962	147	685.21	9129	36	407.61	7111
30	मणिपुर	6	111.33	2908	5	42.31	348	2	484.72	6383
31	मेघालय	7	36.67	1015	3	16.26	120	4	31.26	439
35	त्रिपुरा	2	11.77	130	49	38.10	1386	14	64.32	1113
36	तेलंगाना	4	72.61	835	4	111.89	982	12	63.34	1719
	कुल	1889	11728.01	239560	1918	13661.19	205614	895	12681.58	190521

अनुबंध-5

वर्ष 2016-17 के दौरान एडिप स्कीम के अंतर्गत कैप/मुख्यालयी गतिविधियों हेतु एनजीओ/राज्य निगमों/आईआरसीएस को जारी अनुदान सहायता का राज्यवार विवरण (31.12.2016 तक)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कार्यान्वयन एजेंसियां	जिलें	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
1	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	उदयपुर	100.00
		कुल		100.00

अनुबंध-6

वर्ष 2016-17 (रा.12.2016 तक) एडीआईपी योजना के अंतर्गत एनआईएस/सीआरएसएल की विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी की गई निधि

जारी की गई निधि (रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	का	हेडक्वाटर गतिविधि	कैम्प गतिविधि	एडी आईपी - एस एसए	कोचि लियर इंप्लांट	वह राज्य जिनको कैम्प गतिविधियों के लिए निधि जारी की गई
1	उत्तराखंड	त रिगों य स एच6, ड, 24	225.00	175.00	.	.	पेन इंडिया
2	आंध्र प्रदेश	वि य स मए द, ग	15.00	466.00	.	.	पेन इंडिया
3	पश्चिम बंगाल	क रिगों य न एच ड, गो, 70	40.00	200.00	.	.	पेन इंडिया

4	महाराष्ट्र	बाधिर विकलांगों हेतु अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएचएच), के.सी. मार्ग, बांद्रा रीक्लेमेशन, बांद्रा, मुम्बई-400050	150.00	175.00	.	.	पेन इंडिया
5	दिल्ली	शारीरिक असक्षम विकलांगों हेतु संस्थान (आईपीएच), 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली	25.00	75.00	.	.	पेन इंडिया
6	उड़ीसा	पुर्नवास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय संस्थान (एसवीएनआईआरटी एआर), कटक, उड़ीसा	150.00	70.00	.	.	पेन इंडिया
7	बिहार	विकलांग जन हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी, भोपाल), गांधी मैदान पटना	20.00	10.00	.	.	पटना में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय (एनई) कैम्प गतिविधि
8	हिमाचल प्रदेश	पीडब्ल्यूडी हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र, महामाया मंदिर के समीप, सुरेंद्रनगर, जिला, मंडी, हिमाचल प्रदेश-175018	.	50.00	.	.	हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कैम्प गतिविधि

9	गुजरात	राज्य वि.पा. समद- स	10.00	10.00	.	.	गुजरात के अहमदाबाद जिले में कैम्प गतिविधि
10	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य जम्मू र	7.00	18.00	.	.	जम्मू एवं कश्मीर में कैम्प गतिविधि
11	छत्तीसगढ़	राज्य सब, र	20.00	20.00	.	.	छत्तीसगढ़ में कैम्प गतिविधि
12	उत्तर प्रदेश	कृत्रि निग	550.00	5898.00	2671.00	500.00	पेन इंडिया
		रमर उत्तरा	100.00	555.00	100.00	445.00	पेन इंडिया और पूर्वी क्षेत्र (एनई)
			1312.00	7722.00	2771.00	945.00	

अनुबंध-7

2016-17 के दौरान (31.12.2016 तक) एडीआईपी योजना के अंतर्गत आयोजित विशेष कैम्प

राज्य	क्र.सं.	कैम्प का स्थान	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
आंध्र प्रदेश	1	विजयवाड़ा	139	12.55
अरुणाचल प्रदेश	2	ईटानगर	89	7.12
छत्तीसगढ़	3	राजनंदगांव	220	25.00
	4	बलोदा बाजार	726	71.68
	5	रायपुर	726	71.68
दिल्ली	6	शक्ति नगर	976	147.31
	7	नार्थ ईस्ट और रूटरी कल्ब दिल्ली	1052	86.05
	8	द्वारका, दक्षिण-पश्चिम	77	7.19
	9	विश्वास नगर एसेम्बली	260	22.61
मध्य प्रदेश	10	सागर	369	40.7
	11	इंदौर	196	23.10
	12	मंदसौर	2655	162.38
	13	भोपाल	1278	114.24
	14	पंना कटनी	135	12.59
	15	उज्जैन	285	29.61
	16	टिकमगढ़	1055	86.13
	17	सिओनी	1233	105.83
	18	बैतुल	663	63.04
राजस्थान	19	सवाई मादोपुर	387	40.3
	20	टांग	347	35.66
	21	बरन और आत्रो	598	99.61

उत्तर प्रदेश	22	बरेली (उत्तर प्रदेश)	1576	122.17
	23	पीलीभीत	727	55.45
	24	अमरोहा, (उत्तर प्रदेश)	405	32.02
	25	महाराजपुर, (उत्तर प्रदेश)	193	13.83
	26	अमेठी	1043	87.26
	27	झांसी	1847	131.06
	28	लखनऊ	1079	86.09
	29	हरदोई	744	56.02
	30	कौशांबी	1032	75.07
	31	शाहजहानपुर	1040	80.79
	32	शाहजहानपुर	2897	215.73
	33	गोसी (मऊ)	530	34.77
	34	सुकुरतल, मुजफ्फरनगर	312	25.44
	35	हाथरस	346	26.30
	36	बाघपत	222	15.67
	37	फतेहपुर	1167	79.14
	38	संबल	1200.0	99.30
	39	मुजफ्फरनगर	1436.0	104.85
	40	मुरादाबाद	289	22.33
	41	इलाहाबाद और फूलपुर	4527	349.01
	42	शरस्वती	284	22.66
	43	आजमगढ़ (लालगंज)	1444	105.50
	44	जौनपुर	6621	403.46
	45	फैजाबाद	795	58.39
	46	गाजीपुर	1017	101.16
	47	फेफना, बलिया	584	45.45

	48	लखीमपुर खिरी	127	46.99
	49	रायबरेली	2907	214.9
	50	चित्रकूट	1009	74.56
	51	बिधुना, ओरईया	769	66.00
गुजरात	52	नवसारी	10217	765.86
	53	वडोदरा	8096	582.59
हरियाणा	54	सोनीपथ	1162	109.00
	55	अम्बाला	340	30.2
	56	पलवल	3412	288.00
	57	फरीदाबाद		
	58	कुरुक्षेत्र	2829	209.27
कर्नाटक	59	शिवमोंगा	140	11.91
	60	चिक्काबल्लापुर	324	24.85
	61	उदुपी और चिकमागलुरु	327	22.4
	62	मेसूर	1135	96.76
	63	बगलपुर	227	25.62
	64	शिवमोंगा	255	21.47
मणिपुर	65	इम्फाल	6383	444
पंजाब	66	जालन्धर	954	67.62
	67	लुधियाना	2371	272.21
	68	फरिदकोट	481	41.63
	69	फिरोजपुर	334	27.12
	70	सुमन, संगरूर	498	37.33
	71	होशियारपुर	207	14.95
बिहार	72	महाराजगंज, सिवान	274	18.43
	73	अराह	294	25.64

	74	पाटलीपुत्र (पटना)	799	50.93
महाराष्ट्र	75	बीद और पाली	411	34.41
	76	थाणे, महाराष्ट्र	512	50.78
	77	वरधा	571	33.45
	78	सिद्धगढ़	2714	234.86
	79	यावतमल, चन्द्रपुर	893	93.68
पश्चिम बंगाल	80	डार्जिलिंग	1216	116.08
	81	नेहाती और खरदाह	1087	97.16
	82	बिनपुर (पश्चिम मिदनापुर) डोमकाल (मुर्शीदाबाद) तारापथ (बिरभूम)	969	66.53
	83	बेनगांव	1373	93.03
	84	कुमारी, नदिया, गोपालपुरगाट	700	46.05
त्रिपुरा	85	अगरतला	538	50.00
तेलंगाणा	86	खम्माम	617	40.21
	87	मलकागिरी	239	24.63
मेघालय	88	हेपी वेली, सिलोंग	126	12.24
	89	तुरा (गरो हिल्लस)	191	16.41
		कुल	104851	8313.06

2016-17 के दौरान सिपडा स्कीम के तहत विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों को बाधामुक्त वातावरण के लिए जारी निधि

मुख्य शीर्ष "3601"

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्देश्य	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
1	मध्य प्रदेश सरकार	मंदसौर, मध्य प्रदेश में पालिका भवन में बाधामुक्त का सृजन (01 लिफ्ट)	19.37
2	तमिलनाडु सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत 03 राज्य सरकार भवनों में बाधामुक्त का सृजन	380.00
3	ओडिशा सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत 10 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन	115.43
		सुगम्य भारत अभियान के तहत 11 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन	491.71
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत 02 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन	19.03
		सुगम्य भारत अभियान के तहत 14 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन	1099.99
5	महाराष्ट्र सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत 91 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन	994.45
		सुगम्य भारत अभियान के तहत 51 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन	545.51
6	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	दिव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण	15.00

7	पंजाब सरकार	देव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण	5.60
8	उत्तर प्रदेश सरकार	देव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण	15.00
9	मेघालय सरकार	देव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण	12.46
		कुल	3713.53

अनुबंध-9

(क) 2016-17 के दौरान सिपडा स्कीम के तहत बाधामुक्त वातावरण के लिए संस्थानों/संगठनों के लिए जारी निधि

मुख्य शीर्ष "2235"

क्र.सं.	संगठन	उद्देश्य	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)
1	दिव्यांगजनों के लिए डा० अंबेडकर प्रौद्योगिकीकरण संस्थान (एआईटीएच), कानपुर, उत्तर प्रदेश	बाधामुक्त वातावरण सृजन	31.30
2	जीसस एंड मैरी कॉलेज, नई दिल्ली	बाधामुक्त वातावरण सृजन	34.37
3	एनआईओएच कोलकाता, पश्चिम बंगाल	बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए एनआईओएच को दूसरी किस्त	21.29
4	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बाधामुक्त वातावरण सृजन	307.75
5	चंडीगढ़ प्रशासन	चंडीगढ़ में 43 विभिन्न भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन	415.38
6	दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), नई दिल्ली	दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण सृजन	123.34
7	ईआरएनईटी भारत, नई दिल्ली	917 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना	1047.58
		कुल	1981.01

(ख) सिपडा के 2016-17 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु जारी की गई अनुदान सहायता

क्र. सं.	संगठन	उद्देश्य	जारी की गई जीआईए राशि (रु. लाख में)
1	राष्ट्रीय वित्त विकास नि. (एचसी), नई दिल्ली	17000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की तीसरी किस्त (जीआईए 2015-16)	617.00
		17000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एनएचएफडीसी को चौथी किस्त (जीआईए 2015-16)	563.20
		2016-17 के दौरान 20000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रथम किस्त	458.58
2	एनएसआर राबा	जीआईए 2013-14 की 430 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी एवं अंतिम किस्त	9.64
3	अली या. राष्ट्रीय एवं श्रवण दि. संस (दिव्यांग जे. ई. एस. एच. डी), मुंबई	3000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी किस्त	100.88
4	पंडित दी. उपा. शारीरिक दिव्यांगजन (गजन) (पीडीयूएफडी) दिल्ली	1470 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी किस्त (2015-16)	67.50

		1470 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तीसरी किस्त (2015-16)	45.00
		1780 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रथम किस्त (2016-17)	58.13
5	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनआईवीएच को दूसरी किस्त	109.77
7	पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिक उद्योग विकास निगम लि० (डब्ल्यूबीईआईडीसीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	850 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.13
8	हिमाचल कंस्लटैंसी संगठन लि० (एचआईएमसीओएन), शीमला, हिमाचल प्रदेश	150 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.12
9	हरडीकोन लिमिटेड, नई दिल्ली	540 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.10
10	मध्य प्रदेश कंस्लटैंसी संगठन लि० (एमपीसीओएन लि.), भोपाल, मध्य प्रदेश	840 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.88
11	उत्तर भारत तकनीकी कंस्लटैंसी संगठन लि० (एनआईसीटीसीओएन लि.) चंडीगढ़	100 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.97
12	पूर्व नगर निगम, समुदायिक सेवा विभाग, दिल्ली (ईडीएमसी/सीएसडी), दिल्ली	90 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.57

13	संयुक्त क्षेत्र (रसी), अहमदाबाद	295 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी किस्त (2015-16)	9.58
14	सेन्ट्रल तमिळु पंजाब	50 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.03
15	बंदीपोरा गवर्णमेंट कॉलेज (बीसीआर) तमिळु एम्वीर	220 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.29
16	राष्ट्रीय दिव्यांगसशक्तिकरण संस्थान, तमिळु एम्वीर चेन्नई, तमिळु	400 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एनआईडीपीएमडी को दूसरी किस्त	45.00
	कुल	24620 दिव्यांगजन	2159.37

(ग) सिपडा स्कीम के तहत 2016-17 के दौरान यूडीआईडी परियोजना के लिए जारी अनुदान

क्र. सं.	संगठन	उद्देश्य	जारी की गई अनुदान सहायता राशि (रु. लाख में)
1	नेशनल इनफार्मेटिक सेंटर सर्विसस इनकोर्पोरेटिड (एनआईसीएसआई), नई दिल्ली	यूडीआईडी प्रयोजना की परियोजना प्रबंधन ईकाई के लिए 2 सलाहकारों के प्रावधान के लिए एनआईसीएसआई के साथ संविदा विस्तार	52.82
2	जिला कलेक्टर, रतलाम, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
3	जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
4	जिला कलेक्टर, रायसन, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
5	जिला कलेक्टर, झाबुआ, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
6	जिला कलेक्टर, देवास, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
7	जिला कलेक्टर, अगार मालवा, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
8	जिला कलेक्टर, बारवानी, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
9	जिला कलेक्टर, इन्दौर, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
10	जिला कलेक्टर, जबलपुर, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
11	जिला कलेक्टर, सियोनी, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
12	जिला कलेक्टर, मंदसौर, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
13	जिला कलेक्टर, भिन्ड, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00

32	जिला कलेक्टर, चंदौली, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
33	जिला कलेक्टर, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
34	जिला कलेक्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
35	जिला कलेक्टर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
36	जिला कलेक्टर, जालान, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
37	जिला कलेक्टर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
38	जिला कलेक्टर, नंदूरबार, महाराष्ट्र	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
39	जिला कलेक्टर, गढचिराली, महाराष्ट्र	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
40	जिला कलेक्टर, यवतमल, महाराष्ट्र	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
41	जिला कलेक्टर, परभानी, महाराष्ट्र	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
42	जिला कलेक्टर, नयागढ़, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
43	जिला कलेक्टर, झारसुगुड़ा, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
44	जिला कलेक्टर, नबरंगपुर, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
45	जिला कलेक्टर, कटक, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
46	जिला कलेक्टर, बोध, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
47	जिला कलेक्टर, बालनगीर, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
48	जिला कलेक्टर, केन्द्रपारा, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
49	जिला कलेक्टर, गनजमा, ओडिशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25

50	जिला कलेक्टर, शा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
51	जिला कलेक्टर, आ	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
52	जिला कलेक्टर, पुरडेशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
53	जिला कलेक्टर, शा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
54	जिला कलेक्टर, शा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
55	जिला कलेक्टर, शा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
56	जिला कलेक्टर, मोहि	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
57	जिला कलेक्टर, आ	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
58	जिला कलेक्टर, आ	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
59	जिला कलेक्टर, डंडेशा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
60	जिला कलेक्टर, गढ़स्थान	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
61	जिला कलेक्टर, रान	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
62	जिला कलेक्टर, बंध, स्थान	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
63	जिला कलेक्टर, नगरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
64	जिला कलेक्टर, णा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
65	जिला कलेक्टर, हा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
66	जिला कलेक्टर, हा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
67	जिला कलेक्टर, बादयाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75

68	जिला कलेक्टर, भिवानी, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
69	जिला कलेक्टर, गुड़गांव, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
70	जिला कलेक्टर, नारनौल, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
71	जिला कलेक्टर, करनाल, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
72	जिला कलेक्टर, पंचकुला, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
73	जिला कलेक्टर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
74	जिला कलेक्टर, सीनीपथ, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
75	जिला कलेक्टर, मेवात, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
76	जिला कलेक्टर, जिन्द, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
77	जिला कलेक्टर, पलवल, हरियाणा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
78	जिला कलेक्टर, त्रिवल्लूर, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
79	जिला कलेक्टर, धर्मपुरी, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
80	जिला कलेक्टर, सालेम, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
81	जिला कलेक्टर, काम्बटूर, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
82	जिला कलेक्टर, नागापत्तीनाम, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
83	जिला कलेक्टर, इरोड, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
84	जिला कलेक्टर, करूर, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
85	जिला कलेक्टर, दिन्दीगुल, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25

86	जिला कलेक्टर, गंगानाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
87	जिला कलेक्टर, तमिळु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
88	जिला कलेक्टर, डी, ननाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
89	जिला कलेक्टर, लूर, लनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
90	जिला कलेक्टर, ताडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
91	जिला कलेक्टर, ताडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
92	जिला कलेक्टर, डि	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
93	जिला कलेक्टर, त्रिप्	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
94	जिला कलेक्टर, टी, रा	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	0.75
95	जिला कलेक्टर, के	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
96	जिला कलेक्टर, लमल	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
97	जिला कलेक्टर, की	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.00
98	जिला कलेक्टर, गोट, रात	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
99	जिला कलेक्टर, गार, रात	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
100	जिला कलेक्टर, गु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु	1.25
101	राष्ट्रीय डिजाइन, अहमदाबाद,	यूडीआईडी कार्ड के डिजाइन और ऑन लाइन आवेदन फार्म हेतु	2.76
		कुल	157.58

(घ) सिपडा स्कीम के तहत 2016-17 के दौरान समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों
(सीआरसी) को जारी निधियां

क्रं. स.	संगठन	उद्देश्य	जारी की गई जीआईए राशि (रु. लाख में)
1	सीआरसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सीआरसी लखनऊ, को प्रथम किस्त	64.7
		निर्माण के लिए सीआरसी लखनऊ, को प्रथम किस्त	467.7
		सीआरसी लखनऊ, को द्वितीय किस्त	115.00
2	सीआरसी, भोपाल, मध्य प्रदेश	सीआरसी, भोपाल, को प्रथम किस्त	59.84
		सीआरसी, भोपाल, को द्वितीय किस्त	34.63
		सीआरसी, भोपाल, को तृतीय किस्त	35.00
3	सीआरसी, गुवाहाटी, असम	सीआरसी, गुवाहाटी, को प्रथम किस्त	23.44
		सीआरसी, गुवाहाटी, को द्वितीय किस्त	23.00
		निर्माण के लिए सीआरसी गुवाहाटी, को द्वितीय किस्त	91.00
		सीआरसी, गुवाहाटी, को तृतीय किस्त	31.56
		सीआरसी, गुवाहाटी, को चतुर्थ किस्त	20.00
4	सीआरसी, पटना, बिहार	सीआरसी, पटना, को प्रथम किस्त	57.00
		सीआरसी, पटना, को द्वितीय किस्त	15.00

		सीआरसी, पटना, को तृतीय किस्त	241.36
		सीआरसी, पटना, को प्रथम किस्त (2016-17)	299.97
5	सीआरसी, सुहिम प्रदेश	सीआरसी, सुन्दरनगर, को प्रथम किस्त	52.50
		सीआरसी, सुन्दरनगर, को द्वितीय किस्त	25.00
		सीआरसी, सुन्दरनगर, को तृतीय किस्त	154.58
		सीआरसी, सुन्दरनगर, को चतुर्थ किस्त	92.50
6	सीआरसी, कोकर	सीआरसी कोजीकोड़े, को प्रथम किस्त	44.00
		निर्माण के लिए सीआरसी कोजीकोड़े, को प्रथम किस्त	100.00
		सीआरसी कोजीकोड़े, को द्वितीय किस्त	20.00
		सीआरसी, कोजीकोड़े, को प्रथम किस्त (2016-17)	28.00
7	सीआरसी, अहमदाबाद	निर्माण के लिए सीआरसी अहमदाबाद, को प्रथम किस्त	35.00
		सीआरसी, अहमदाबाद, को प्रथम किस्त	16.00
		सीआरसी, अहमदाबाद, को द्वितीय किस्त	26.00
8	सीआरसी, श्रीनगर	सीआरसी, श्रीनगर को प्रथम किस्त	179.40
9	सीआरसी, देवानगेर	सीआरसी, देवानगेर, को प्रथम किस्त	50.00

10	सीआरसी, नेलौर, आंध्र प्रदेश	सीआरसी, नेलौर, को प्रथम किस्त	34.85
		सीआरसी, नेलौर, को द्वितीय किस्त	10.00
11	सीआरसी, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	सीआरसी, राजनंदगांव, को प्रथम किस्त	38.00
12	सीआरसी, नागपुर, महाराष्ट्र	सीआरसी, नागपुर, को प्रथम किस्त	14.50
		कुल	2499.53

(इ) सिपडा स्कैम 16-17 के दौरान डीडीआरसी को जारी निधियां

क्र. स.	संस्था	उद्देश्य	जारी की गई जीआईए राशि (रु. लाख में)
1	डीडीआरसी, उत्तरा	द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त तृतीय वर्ष की प्रथम किस्त	2.76 3.24
2	डीडीआरसी, बिहार	द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त	3.28
3	डीडीआरसी, पुरु	तृतीय वर्ष सहायता अनुदान	1.08
4	डीडीआरसी, अर	पूर्ण एवं अन्तिम सहायता अनुदान 2015-16 वर्ष के लिए अन्तिम किस्त 2016-17 वर्ष के लिए प्रथम किस्त	8.38 2.79 6.47
5	डीडीआरसी, अस	पाँचवें वर्ष की पूर्ण एवं अन्तिम किस्त	3.87
6	डीडीआरसी, माचदेश	पूर्ण एवं अन्तिम प्रथम वर्ष अनुदान सहायता	17.20
7	डीडीआरसी, उत्तदेश	पूर्ण एवं अन्तिम प्रथम वर्ष अनुदान सहायता	17.20
8	डीडीआरसी, तार	द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त	4.42
9	डीडीआरसी, हार	द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त	1.93
10	डीडीआरसी, मारहार	तृतीय वर्ष अनुदान सहायता	1.91
11	डीडीआरसी, ए, जदेश	पूर्ण एवं अन्तिम द्वितीय वर्ष अनुदान सहायता	0.99
12	डीडीआरसी, जम्म कश्मीर	चतुर्थ वर्ष की प्रथम किस्त	3.75
13	डीडीआरसी, एम, प्रदेश	तृतीय वर्ष अनुदान सहायता की प्रथम किस्त	3.42
14	डीडीआरसी, महार	पूर्ण एवं अन्तिम तृतीय वर्ष अनुदान सहायता	1.33
15	डीडीआरसी, ध्य	पूर्ण एवं अन्तिम द्वितीय वर्ष अनुदान सहायता	2.62
16	डीडीआरसी, इश्चमपुर	प्रथम किस्त	5.30
17	डीडीआरसी, अ	प्रथम किस्त	3.52
		कुल	95.46

(च) सिपडा स्कीम के तहत 2016-17 के दौरान सुगम्य ऑडिट हेतु जारी निधियां

क्रं. स.	संगठन	उद्देश्य	जारी की गई जीआईए राशि (रु. लाख में)
1	समर्थयम ट्रस्ट, नई दिल्ली	भुवनेश्वर में 50 भवनों का सुगम्य संचालन	19.28
		पूणे में 50 भवनों का सुगम्य संचालन	13.06
		तिरुवनंतपुरम में 50 भवनों का सुगम्य संचालन	13.79
		चेन्नई में 25 भवनों का सुगम्य संचालन	7.94
		रायपुर में 58 भवनों का सुगम्य संचालन	15.62
2	कविता अभिजीत, मुर्गकार	पणजी में 31 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	7.84
		कायम्बटूर में 23 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	6.26
3	स्वाभिमान	पटना में 28 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	7.20
		जम्मू एवं श्रीनगर में 25 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	10.29
		गंगटोक में 36 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	9.02
4	द लेपरोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली	26 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	7.82
5	स्वयं, नई दिल्ली	26 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	1.96
		44 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	8.96
		47 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	9.72
		26 भवनों का सुगम्य ऑडिट संचालन	5.28
		कुल	144.04

(छ) स्कीमे तहत 2016-17 के दौरान विविध तिथियों के लिए जारी निधियां

क्र. सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
1	राष्ट्रीय उत्पादक (सी), नई दिल्ली	दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की तृतीय पक्ष निगरानी	7.54
		कुल	7.54

अनुबंध-10

वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के तहत एनजीओ को जारी की गई अनुदान सहायता के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान जारी की गई अनुदान सहायता के ब्यौरे		
				किस्त	वर्ष हेतु	राशि (रु.)
आंध्र प्रदेश						
1	आंध्र प्रदेश	एदी आंध्र शिक्षा समिति	एमआर एवं एमडी के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	506978
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र शिक्षा समिति	एचआई के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	70054
3	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकलांग एवं अन्य दिव्यांग के लिए अनसंधान एवं पुनर्वास हेतु अंजलि संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1152171
4	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकलांग एवं अन्य दिव्यांग के लिए अनसंधान एवं पुनर्वास हेतु अंजलि संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	373257
5	आंध्र प्रदेश	श्रवण एवं शारीरिक विकलांग एवं शिशु देखभाल केंद्र	श्रवण एवं ओएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	866478
6	आंध्र प्रदेश	दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र	एमआर एवं एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	168502
7	आंध्र प्रदेश	चेतना दिव्यांग कल्याण समिति	एमआर एंड सीपी के लिए आवास एवं दिवस देखभाल प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2015-16	622920

8	आंध्र प्रदेश	व्यां समि	एमआर एंड सीपी के लिए आवास एवं दिवस देखभाल प्रशिक्षण केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	622920
9	आंध्र प्रदेश	शिक्ष ना।न	एमआर एवं बधिर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	832266
10	आंध्र प्रदेश	हिडली	बधिर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1188297
11	आंध्र प्रदेश	हिडली	बधिर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	369099
12	आंध्र प्रदेश	हिडली	बधिर के लिए विशेष स्कूल	शेष	2015-16	27000
13	आंध्र प्रदेश	विव स	ओएच के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	342577
14	आंध्र प्रदेश	ल्लिनेन स्कूल	बधिर के लिए आवासीय स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2015-16	799623
15	आंध्र प्रदेश	पेट ऑफ सा	बधिर के लिए आवासीय विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	900236
16	आंध्र प्रदेश	य रे सोर ना	ओएच लड़कों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	564356
17	आंध्र प्रदेश	य रे सोर ना	ओएच लड़कों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	126739
18	आंध्र प्रदेश	र ए जे जे दया न	एमआर के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	481373
19	आंध्र प्रदेश	सिमिति	एचआई और मूक एवं बधिर के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	127281
20	आंध्र प्रदेश	म मंडली	पीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	394137

21	आंध्र प्रदेश	लीमा बधिर एवं मानसिक विकलांग कल्याण संघ	बधिर एवं एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	605792
22	आंध्र प्रदेश	लीमा बधिर एवं मानसिक विकलांग कल्याण संघ	बधिर एवं एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र	प्रथम	2015-16	946091
23	आंध्र प्रदेश	लीमा बधिर एवं मानसिक विकलांग कल्याण संघ	बधिर एवं एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	429889
24	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	284721
25	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2015-16	325125
26	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	सर्वे, आईडीईएन, अवार्ड, ई.आई.एच. बीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम	शेष	2014-15	687040
27	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	सर्वे, आईडीईएन, अवार्ड, ई.आई.एच. बीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रथम	2015-16	423045
28	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल (खमाम)	तीसरा एवं अन्तिम	2014-15	254175
29	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल (खमाम)	प्रथम	2015-16	542827
30	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल (खमाम)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	542828
31	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	प्री-स्कूल एवं माता-पिता काउंसिलिंग	शेष	2014-15	238668
32	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केंद्र	प्री-स्कूल एवं माता-पिता काउंसिलिंग	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	119993

33	आंध्र प्रदेश	क रि	एमआर के लिए केंद्र (विजयवाड़ा)	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	1485776
34	आंध्र प्रदेश	क रि	एमआर के लिए केंद्र (विजयवाड़ा)	प्रथम	2015-16	354938
35	आंध्र प्रदेश	र त	वीएच के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	761565
36	आंध्र प्रदेश	क रि र ल न इटी	बधिर के लिए विशेष स्कूल एवं घर	प्रथम	2015-16	725685
37	आंध्र प्रदेश	क रि	श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	339816
38	आंध्र प्रदेश	क रि	श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	877161
39	आंध्र प्रदेश	क रि	श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	582015
40	आंध्र प्रदेश	क रि क ए संस्थ	एमआर एवं बधिर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	554730
41	आंध्र प्रदेश	क के पलाशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	500445
42	आंध्र प्रदेश	क के पलाशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	349425
43	आंध्र प्रदेश	घेटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल (आवासीय)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	935813
44	आंध्र प्रदेश	घेटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल (आवासीय)	प्रथम	2015-16	850778
45	आंध्र प्रदेश	घेटी	एचएच के लिए स्कूल (आवासीय)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	699758
46	आंध्र प्रदेश	घेटी	एचएच के लिए स्कूल (आवासीय)	प्रथम	2015-16	644779

47	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	तिरुपति एवं चित्तूर में एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	378825
48	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	अनंतपूर में एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	328650
49	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	अनंतपूर में एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	328650
50	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	द्वितीय	2015-16	623092
51	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	तीसरा एवं अन्तिम	2015-16	676134
52	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	डीएमआर पाठ्यक्रम	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	208040
53	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र	प्रथम	2014-15	356874
54	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	324136
55	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र	प्रथम	2015-16	257625
56	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	257625
57	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सेवा समिति	कडपा में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र	प्रथम	2015-16	343069

58	आंध्र प्रदेश	सेमेति	कडपा में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	343069
59	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमएच के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	503602
60	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमएच के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	503603
61	आंध्र प्रदेश	भारत माह	बधिर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	365981
62	आंध्र प्रदेश	भारत माह	बधिर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	168767
63	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	611595
64	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमआर के लिए आवासीय विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	623448
65	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमआर बच्चों के लिए दिवस एवं आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	259641
66	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमआर के लिए आवासीय एवं दिवस देखभाल केंद्र	शेष	2014-15	36660
67	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमआर के लिए आवासीय एवं दिवस देखभाल केंद्र	प्रथम	2015-16	1249776
68	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमआर के लिए आवासीय एवं दिवस देखभाल केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1249776
69	आंध्र प्रदेश	भारत माह	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	462078

70	आंध्र प्रदेश	बधिर एवं अंध शिक्षा समिति	बधिर एवं हॉस्टल के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	399574
71	आंध्र प्रदेश	बधिर एवं अंध शिक्षा समिति	बधिर एवं हॉस्टल के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	1132207
72	आंध्र प्रदेश	बधिर एवं अंध शिक्षा समिति	बधिर एवं हॉस्टल के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	382458
73	आंध्र प्रदेश	मानसिक रूप से विकलांग के लिए हिडन सपराउटस विशेष स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	21600
74	आंध्र प्रदेश	सफूर्ती कल्याण समिति	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	597487
75	आंध्र प्रदेश	सफूर्ती कल्याण समिति	एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	589487
76	आंध्र प्रदेश	श्री विवेकानंद शिक्षा समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	665091
77	आंध्र प्रदेश	श्री दक्षिणा भाव समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1027969
78	आंध्र प्रदेश	संत अन्ना सामाजिक कल्याण समिति द्वारा चलाया गया संत अन्ना मनोविकास केंद्र	एमआर के लिए आवासीय स्कूल (कुर्नूल)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	883230
79	आंध्र प्रदेश	सनलाइट शिक्षा समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	33818
80	आंध्र प्रदेश	एम.एच. के कल्याण के लिए सूर्य किरण माता-पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (मेकराला)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	744863
81	आंध्र प्रदेश	एम.एच. के कल्याण के लिए सूर्य किरण माता-पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (पिडुगुराला)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	348653
82	आंध्र प्रदेश	एम.एच. के कल्याण के लिए सूर्य किरण माता-पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (नालगोंडा)	प्रथम	2015-16	503054

83	आंध्र प्रदेश	क्षितिं गे र देव्य केंद्र रर्स	डीडीआरसी पूर्व गोदावरी	पूर्ण एवं अंतिम	2015-16	590290
84	आंध्र प्रदेश	क्षितिं गे र नोर्ग	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	734070
85	आंध्र प्रदेश	क्षितिं गे र नोर्ग की	एमआर एवं शीघ्र हस्तक्षेप के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1120417
86	आंध्र प्रदेश	क्षितिं गे र नोर्ग (काकी)	एमआर एवं शीघ्र हस्तक्षेप के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	401498
87	आंध्र प्रदेश		एमएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1601949
88	आंध्र प्रदेश	ग्रा सा	बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	659701
89	आंध्र प्रदेश	ग्रा सा	बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1453050
90	आंध्र प्रदेश	ग्रा सा	बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1112022
91	आंध्र प्रदेश	गे वे कल	व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	622333
92	आंध्र प्रदेश	एवं के	एमआर के लिए स्कूल वीटीसी एवं हॉस्टल	प्रथम	2015-16	1211571
93	आंध्र प्रदेश	एजल टी	अंध एवं विकलांग बच्चों के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	446327
कुल						54342577

आरुणाचल प्रदेश						
1	आरुणाचल प्रदेश	मंजूश्री चेरिटेबल सोसाइटी (डीडीआरसी) तवांग	(डीडीआरसी) तवांग	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	387190
कुल						387190
असम						
1	असम	देस्टीनेशन	हाफ वे होम	प्रथम	2014-15	134190
2	असम	दिक्रोंग वेली इनवायरमेंट एवं ग्रामीण विकास समिति	हाफ वे होम	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	369410
3	असम	दिक्रोंग वेली इनवायरमेंट एवं ग्रामीण विकास समिति	हाफ वे होम	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	326914
4	असम	दुरपंग पिछला आचलिक विकलांग अनुस्थान	दिव्यांग व्यक्ति के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2014-15	167685
5	असम	वैश्विक स्वास्थ्य एवं शिक्षा केंद्र (जीएचईसी)	दिव्यांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2014-15	403025
6	असम	वैश्विक स्वास्थ्य एवं शिक्षा केंद्र (जीएचईसी)	दिव्यांग के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	127066
7	असम	ग्राम विकास परिषद	दिव्यांग के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	184793
8	असम	गुवाहाटी युथ सोसाइटी	हाफ वे होम	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	184473
9	असम	कच्चाजोली शारीरिक विकलांग स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र	बधिर एवं मूक तथा वीटीसी हेतु विशेष स्कूल	तीसरा एवं अन्तिम	2014-15	557165
10	असम	कच्चाजोली शारीरिक विकलांग स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र	बधिर एवं मूक तथा वीटीसी हेतु विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1056366

11	असम	वर्ग 5 स्वै	हाफ वे होम	प्रथम	2015-16	529551
12	असम	एआ गति काद्र ट व क	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	567218
13	असम		वीटीसी एवं सेल्टर्ड वर्कशाप	प्रथम	2015-16	486891
14	असम		वीटीसी एवं सेल्टर्ड वर्कशाप	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	135000
15	असम		कम दृष्टि केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	78516
16	असम		कम दृष्टि केंद्र	प्रथम	2015-16	140832
17	असम		हाफ वे होम	प्रथम	2015-16	531414
कुल						5980509
बिहार						
1	बिहार	मोस डीके म द पेला डी) के	आशा स्कूल, दानापुर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	88703
2	बिहार	धन मू पेद्या	एचएच लड़कियों के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	978925
3	बिहार	रीब ग	एचएच के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय	2014-15	273952

4	बिहार	बाबा गरीब नाथ विकलांग सहजन सेवा संस्थान	एचएच के लिए विशेष स्कूल	तीसरा एवं अन्तिम	2014-15	357520
5	बिहार	बिहार विकलांग कल्याण परिषद	पीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	130786
6	बिहार	ज्ञान नेत्रहीन विद्यालय	अंधे बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2014-15	244310
7	बिहार	कोशी छत्रीय विकलांग,विधवा, वृद्ध कल्याण समिति	पीएच के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी	प्रथम	2014-15	112793
कुल						2186989
छत्तीसगढ़						
1	छत्तीसगढ़	अंकुर	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	194894
2	छत्तीसगढ़	लाइनस चेरिटेबल ट्रस्ट	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	155375
3	छत्तीसगढ़	लाइनस चेरिटेबल ट्रस्ट	एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	153542
4	छत्तीसगढ़	नेत्रहीन व विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण एवं धर्मार्थ समिति	स्पेशल स्कूल फॉर वीआई	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	92334
5	छत्तीसगढ़	निशक्त जन कल्याण सेवा समिति	स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ चिल्डरन	प्रथम	2015-16	376323
6	छत्तीसगढ़	श्रवण मूक विकलांग अभिभावक संघ	स्कूल फॉर एचएच	प्रथम	2015-16	234592
कुल						1207060
दिल्ली						
1	दिल्ली	एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लूज़न	कम्यूनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	165450
2	दिल्ली	एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लूज़न	कम्यूनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन	प्रथम	2015-16	210000
3	दिल्ली	अक्षय प्रतिष्ठान	स्कूल फॉर द डिसेबल्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	393407

4	दिल्ली	विशेष	स्कूल फॉर द डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	551737
5	दिल्ली	विशेष	प्री स्कूल एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर द डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	319584
6	दिल्ली	विशेष	प्री स्कूल एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर द डिसेबल्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	215513
7	दिल्ली	विशेष	इंटेग्रेटेड स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1288761
8	दिल्ली	सिंह मा श्रव शिव संस्थ	स्पेशल स्कूल फॉर एचएच	प्रथम	2015-16	559000
9	दिल्ली	केंद्र	चाइल्ड गाइडलाइन सेंटर	प्रथम	2014-15	34915
10	दिल्ली	केंद्र	चाइल्ड गाइडलाइन सेंटर	प्रथम	2015-16	186848
11	दिल्ली	सोसाय लाइ	ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ब्रेली एंड लार्ज प्रिंट	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	328386
12	दिल्ली	सोसाय लाइ	ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ब्रेली एंड लार्ज प्रिंट	प्रथम	2015-16	282292
13	दिल्ली	सोसाय लाइ	होस्टल फॉर वीएच	तीसरा एवं अन्तिम	2014-15	295484
14	दिल्ली	साक्र मि	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	362979
15	दिल्ली	संघी मल शाल	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन	प्रथम	2015-16	478777
कुल						5673133

गोवा						
1	गोवा	विकलांग बच्चों के लिए लोक विश्वास प्रतिष्ठान स्कूल	मूक बधिर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	489853
कुल						489853
गुजरात						
1	गुजरात	अपंग मानव कल्याण केंद्र	वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम	प्रथम	2015-16	529615
2	गुजरात	भारत लोक हित सेवा समिति	स्पे. स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	14314
3	गुजरात	ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन	महिलाओं के लिए कौशल विकास इकाई	प्रथम	2014-15	45020
4	गुजरात	ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन	कम दृष्टि केंद्र	प्रथम	2015-16	109545
5	गुजरात	ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन	बीपीए समाचार अक्षर	प्रथम	2014-15	149175
6	गुजरात	डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	स्कूल फॉर ओएच	दूसरा	2015-16	344388
7	गुजरात	भारत विकलांग कल्याण ट्रस्ट	स्कूल फॉर ओएच	तीसरा एवं अंतिम	2015-16	536187
8	गुजरात	जिला विकलांग पुर्नवास केंद्र वडोदरा	डीडीआरसी, वडोदरा	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	207587
9	गुजरात	मानव विकास एवं अनुसंधान फाउंडेशन	एम आर के लिए घर आधारित पुनर्वास/व्यवसाय	प्रथम	2015-16	425898
10	गुजरात	मानव विकास एवं अनुसंधान फाउंडेशन	एम आर के लिए घर आधारित पुनर्वास/व्यवसाय	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	8849
11	गुजरात	खुद्दर एजुकेशन ट्रस्ट	एमआर के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	15004
12	गुजरात	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	351135
13	गुजरात	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	69507
कुल						2806224

हरियाणा						
1	हरियाणा	भारत हसंघ	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	799740
2	हरियाणा	भारत हसंघ	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	756810
3	हरियाणा	ति	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	42245
4	हरियाणा	लगा ल्या ई f	आशा स्कूल, अंबाला	प्रथम	2014-15	220800
5	हरियाणा	लगा	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	282087
6	हरियाणा	गं ल्या	आशा स्कूल, हिसार	प्रथम	2015-16	318855
7	हरियाणा	वा लि कट	सिरसा में एचएच के लिए आरकेजे कल्याण समिति	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	293802
8	हरियाणा	क्र (दि)	पीएच के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	169697
9	हरियाणा	क्र (रं)	एमआर बच्चों के लिए घर एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	276154
10	हरियाणा	क्र	एमआर बच्चों के लिए घर एवं वीटीसी	प्रथम	2015-16	630748
11	हरियाणा	क्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल (कलानोर)	प्रथम	2015-16	245201
12	हरियाणा	लफे	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्ड्रन	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	244530

13	हरियाणा	लोक कल्याण फाउंडेशन	स्पे. स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकेप चिल्डरन	प्रथम	2015-16	397971
14	हरियाणा	मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	525015
15	हरियाणा	मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	375624
16	हरियाणा	सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी	एमआर एवं एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	284850
17	हरियाणा	सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी	एमआर एवं एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	132235
18	हरियाणा	तपन रिहबिलिटेशन सोसाइटी	ट्रेनिंग, रिहबिलिटेशन एंड एज्युकेशनसेंटर फॉर एचएच एंड एमआर चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	639870
कुल						6636234
हिमाचल प्रदेश						
1	हिमाचल प्रदेश	आस्था वेलफेयर सोसाइटी	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	39269
2	हिमाचल प्रदेश	चेतना	डे केयर सेंटर फॉर एम.आर.	प्रथम	2015-16	517662
3	हिमाचल प्रदेश	चेतना	डे केयर सेंटर फॉर एम.आर.	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	479232
4	हिमाचल प्रदेश	चेतना	डे केयर सेंटर फॉर एम.आर.	प्रथम	2016-17	506280
5	हिमाचल प्रदेश	चेतना	सीबीआर प्रोग्राम	प्रथम	2015-16	168696
6	हिमाचल प्रदेश	चेतना	सीबीआर प्रोग्राम	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	168039
7	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (कुल्लू)	दृष्टिहीन के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	93888
8	हिमाचल प्रदेश	पेराडाइज चिल्ड्रन केयर सेंटर	एमआर के लिए दे केयर सेंटर	प्रथम	2014-15	119979
कुल						2093045

जम्मू एवं कश्मीर						
1	जम्मू एवं कश्मीर	आशा स्कूल, उद्यमपुर	प्रथम	2014-15	325374	
					कुल	325374
झारखण्ड						
1	झारखण्ड	स्पे. स्कूल फॉर एच.आई. एंड एम.आर.	प्रथम	2015-16	94213	
					कुल	94213
कर्नाटक						
1	कर्नाटक	रेसीडेंशियल स्कूल फॉर द डिसेबल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	127251	
2	कर्नाटक	रेसीडेंशियल स्कूल फॉर द डिसेबल	प्रथम	2015-16	261637	
3	कर्नाटक	रेसीडेंशियल स्कूल फॉर ओएच	प्रथम	2015-16	880875	
4	कर्नाटक	रेसीडेंशियल स्कूल फॉर ओएच	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	242325	
5	कर्नाटक	ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी)	प्रथम	2014-15	513792	
6	कर्नाटक	ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	476604	
7	कर्नाटक	ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी)	प्रथम	2015-16	525276	
8	कर्नाटक	वीएच के लिए स्कूल एवं वीटीसी (एसआरएमएबी)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	59106	
9	कर्नाटक	वीएच के लिए स्कूल एवं वीटीसी (एसआरएमएबी)	शेष	2014-15	390771	

10	कर्नाटक	श्री रमना महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड	डीएसई (प्राइमरी वीआई)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	182589
11	कर्नाटक	श्री रमना महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड	डीएसई (प्राइमरी वीआई)	प्रथम	2015-16	163853
12	कर्नाटक	श्री रमना महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड	डीएसई (प्राइमरी वीआई)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	163853
13	कर्नाटक	श्री रमना महर्षि दिव्यांगजन ट्रस्ट	एलपीसी का पुनर्वास	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	580367
14	कर्नाटक	श्री रमना महर्षि दिव्यांगजन ट्रस्ट	एलपीसी का पुनर्वास	प्रथम	2015-16	1112943
15	कर्नाटक	विश्वधर्म महिला माटू मकाला शिक्षण सेवाश्रम समिति	पीएच के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2014-15	1040099
16	कर्नाटक	येदीयू: श्री सिद्धालिंगेश्वर विद्यापीठ	पीएच के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2014-15	405011
17	कर्नाटक	येदीयू: श्री सिद्धालिंगेश्वर विद्यापीठ	ओएच के लिए आवासीय स्कूल (रेनूका)	प्रथम	2014-15	491973
कुल						7618325
केरल						
1	केरल	अल्फोन्स सोसल सेंटर	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	494316
2	केरल	अल्फोन्स सोसल सेंटर	एमआर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	411192
3	केरल	अनुग्रह सदन	बहु दिव्यांगता वाले सीपी बच्चें	प्रथम	2015-16	366885
4	केरल	अनुग्रह सदन	बहु दिव्यांगता वाले सीपी बच्चें	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	241414
5	केरल	आशा भवन	पीएच के लिए वीटीएस	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	145557
6	केरल	आशा भवन	पीएच के लिए वीटीएस	प्रथम	2015-16	328014

7	केरल	नयगल सेंटर	स्कूल फॉर एमआर (कोट्टायम)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	215820
8	केरल	के पु	पीएच लड़कियों के लिए वीटीएस	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	344957
9	केरल	के पु	पीएच लड़कियों के लिए वीटीएस	प्रथम	2015-16	335107
10	केरल	के पु	पीएच लड़कियों के लिए वीटीएस	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	258532
11	केरल	ट इके सोर्स	एमआर बच्चों के लिए केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	99000
12	केरल	ज्यो स्टी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	664467
13	केरल	के।ण टेब पी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	254180
14	केरल	के।ण टेब पी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	642611
15	केरल	क महेतु विशेष	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	830943
16	केरल	स्थ	गंभार रूप से दिव्यांग एलसीपी के लिए घर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	193849
17	केरल	सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	296491
18	केरल	सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	639580
19	केरल	वेल	मानसिक रूप से दिव्यांग हेतु विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	638395
20	केरल	वेल	मानसिक रूप से दिव्यांग हेतु विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	845451

21	केरल	इरनाकुलम महिला संघ	एमआर के लिए शिक्षा एवं वीटीसी	प्रथम	2015-16	240300
22	केरल	इरनाकुलम महिला संघ	एमआर के लिए शिक्षा एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	198300
23	केरल	फेथ इंडिया	वीटीसी	प्रथम	2014-15	102107
24	केरल	फेथ इंडिया	वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	83543
25	केरल	फेथ इंडिया	दिव्यांग प्रशिक्षण एवं पुनर्वास (इरनाकुलम)	प्रथम	2015-16	414351
26	केरल	फेथ इंडिया	दिव्यांग प्रशिक्षण एवं पुनर्वास (इरनाकुलम)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	409646
27	केरल	फेथ इंडिया	एमआर के लिए विशेष स्कूल (पालाकाड)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	962447
28	केरल	फेथ इंडिया	दिव्यांग के लिए पेलेसमेंट सेवा (इरनाकुलम)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	184225
29	केरल	हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड	वीटीसी फॉर वीएच	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	298656
30	केरल	हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड	वीटीसी फॉर वीएच	प्रथम	2015-16	424476
31	केरल	जेनी सेंटर	एमआर के लिए स्कूल एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	57014
32	केरल	दिव्यांग पुनर्वास हेतु जेकी सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	175568
33	केरल	दिव्यांग पुनर्वास हेतु जेकी सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	प्रथम	2015-16	374008
34	केरल	के वेलायुधन मेमोरियल ट्रस्ट	एमआर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	89996

35	केरल	ना	ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	412758
36	केरल	ना	ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2015-16	423524
37	केरल	चेरि	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	114822
38	केरल	ध न	वीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	338778
39	केरल	ध न	वीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2015-16	338461
40	केरल	गरीरूप वेत संर रोव	दिव्यांग के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	303624
41	केरल	गरीरूप वेत संर रोव	दिव्यांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2015-16	311018
42	केरल	चेरि टी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	759593
43	केरल	चेरि टी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	41352
44	केरल	गोम बल टी	एमआर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	359370
45	केरल	म हे वन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	244741
46	केरल	म हे वन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	579150
47	केरल	म हे वन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	579150

48	केरल	पोप जोन पाल पीस होम	गहन एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	632268
49	केरल	पोप जोन पाल पीस होम	गहन एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	615438
50	केरल	पोप जोन पाल पीस होम	गहन एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	533628
51	केरल	प्रतिक्षा चेरीटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी	प्रथम	2015-16	642975
52	केरल	प्रतिक्षा चेरीटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	612675
53	केरल	मानसिक मंदता बच्चों के लिए प्रतिक्षा भवन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	817215
54	केरल	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए रक्षा सोसाइटी	एमआर के लिए दे केयर सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	238632
55	केरल	पुनर्वास फाउंडेशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	422319
56	केरल	पुनर्वास फाउंडेशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	345632
57	केरल	पुनर्वास फाउंडेशन	विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रोटरी संस्थान	प्रथम	2016-17	396920
58	केरल	विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रोटरी संस्थान	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	1166951

59	केरल	खभी कता लिटरी	एमआर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1047642
60	केरल	अद	स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकेप	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	198990
61	केरल	क	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2014-15	845821
62	केरल	क	एमआर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	272355
63	केरल	क	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	786888
64	केरल	क	एमआर के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	687222
65	केरल	वनल	ओएच बच्चों के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	183357
66	केरल	वनल	ओएच बच्चों के लिए वीटीसी	प्रथम	2015-16	226950
67	केरल	र्ग र सेमेति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	398061
68	केरल	र्ग र सेमेति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	398061
69	केरल	केत	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	426030
70	केरल	केत	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	503184
71	केरल	भार. भेमो कान्ट	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	122845
72	केरल	भार. भेमो कान्ट	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	457485
73	केरल	भद	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	325619
74	केरल	भद	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	526905

75	केरल	स्नेहानिलयाम विशेष स्कूल (जिसस सोसाइटी के स्केयर्ड हार्ट के हैंड मेंडस द्वारा प्रबंधन)	एमआर बच्चों के लिए स्कूल	प्रथम	2014-15	118168
76	केरल	स्नेहराम चेरीटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	972941
77	केरल	समाज कल्याण केंद्र	एमआर गोनअप लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	761934
78	केरल	समाज कल्याण केंद्र	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1051965
79	केरल	मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के पुनर्वास हेतु सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	180715
80	केरल	सेंट जोसेफ सोशल सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	877486
81	केरल	विकास सामाजिक सेवा समिति	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	644242
82	केरल	विमला महिला समाज	एमआर बच्चों के लिए स्कूल	प्रथम	2014-15	932904
83	केरल	विमला महिला समाज	एमआर बच्चों के लिए स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	466452
84	केरल	महिला कल्याण केंद्र	एमआर के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	279404
85	केरल	यंग महिला ईसाई संघ	एमआर के लिए केंद्र	प्रथम	2014-15	199280
कुल						37385298
मध्य प्रदेश						
1	मध्य प्रदेश	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र	वीएच के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	384171
2	मध्य प्रदेश	दीन दयाल अंत्योदय मिशन, बालाघाट	डीडीआरसी, बालाघाट	प्रथम	2015-16	610956

3	मध्य प्रदेश	लक्ष्मण	डीडीआरसी, बालाघाट	पूर्ण एवं अंतिम	2015-16	189317
4	मध्य प्रदेश	रुद्रा	डीडीआरसी, रेवा	प्रथम	2015-16	294611
5	मध्य प्रदेश	टी. शर्मा	डीडीआरसी मंदसौर	प्रथम	2015-16	250425
6	मध्य प्रदेश	हेल	मूक बधिर के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	330444
7	मध्य प्रदेश	रेड	डीडीआरसी, जबलपुर	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	130107
8	मध्य प्रदेश	मनोर	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अंतिम	2014-15	372930
9	मध्य प्रदेश	कल	एमआर बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल	प्रथम	2014-15	221991
10	मध्य प्रदेश	सं	बधिर के लिए विशेष स्कूल एवं बहु उद्देश्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2014-15	365883
11	मध्य प्रदेश	नित	बहु दिव्यांग हेतु विशेष स्कूल	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	815105
12	मध्य प्रदेश	वि	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	25070
13	मध्य प्रदेश	सं	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अंतिम	2014-15	151500

14	मध्य प्रदेश	सीमा सोशल वेलफेयर सोसाइटी	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	241861
15	मध्य प्रदेश	श्री श्री उत्कर्ष समिति	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	117837
16	मध्य प्रदेश	श्री श्री उत्कर्ष समिति	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा	2015-16	292237
17	मध्य प्रदेश	श्री श्री उत्कर्ष समिति	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	तीसरा एवं अन्तिम	2015-16	267610
18	मध्य प्रदेश	वंदन पुर्नवास एवं अनुसंधान संस्थान	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	484330
19	मध्य प्रदेश	विकलांग सेवा भारती	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	480645
कुल						6027030
महाराष्ट्र						
1	महाराष्ट्र	अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल	श्रवण बाधित हेतु विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	831996
2	महाराष्ट्र	अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल	श्रवण बाधित हेतु विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	717275
3	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संघ	विकलांग हेतु व्यवसायिक स्कूल	प्रथम	2015-16	304920
4	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संघ	डीडीआरसी, अमरावती	प्रथम	2015-16	459000
5	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संघ	डीडीआरसी, अमरावती	दूसरा	2015-16	374922
6	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संघ	विशेष शिक्षा हेतु डी. एड कॉलेज	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	161550
7	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संघ	विशेष शिक्षा हेतु डी. एड कॉलेज	प्रथम	2015-16	267792
8	महाराष्ट्र	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट	दिव्यांग सेंटर	प्रथम	2014-15	321888
9	महाराष्ट्र	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट	दिव्यांग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	321889

10	महाराष्ट्र	गाँव	दिव्यांग सेंटर	प्रथम	2015-16	435120
11	महाराष्ट्र	शहर	रेसीडेंसियल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	292739
12	महाराष्ट्र	विकासस्था	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	13828
13	महाराष्ट्र	विकासस्था	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	497223
14	महाराष्ट्र	आर.त्यक	वीआई के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	20792
15	महाराष्ट्र	विकासस्था	दिव्यांग आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	268605
16	महाराष्ट्र	विकासस्था	दिव्यांग आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	492624
17	महाराष्ट्र	शहर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	190782
18	महाराष्ट्र	एल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	337500
19	महाराष्ट्र	स्वयं	एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	109121
20	महाराष्ट्र	स्वयं	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	364313
21	महाराष्ट्र		टाकिंग बुक	प्रथम	2015-16	600000
22	महाराष्ट्र		टाकिंग बुक	दूसरा एवं अन्तिम	2012-13	265845
23	महाराष्ट्र		टाकिंग बुक	पूर्ण एवं अन्तिम	2013-14	650000
24	महाराष्ट्र		टाकिंग बुक	प्रथम	2014-15	600000

25	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	प्रथम	2015-16	670191
26	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	दूसरा एवं अन्तिम	2012-13	447725
27	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	पूर्ण एवं अंतिम	2013-14	1350000
28	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	प्रथम	2014-15	1350000
29	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पलेसमेंट सेवा	प्रथम	2015-16	105000
30	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पलेसमेंट सेवा	दूसरा एवं अन्तिम	2012-13	51600
31	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पलेसमेंट सेवा	पूर्ण एवं अंतिम	2013-14	120000
32	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पलेसमेंट सेवा	प्रथम	2014-15	102600
33	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पुनर्वास विभाग	प्रथम	2015-16	240000
34	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पुनर्वास विभाग	दूसरा एवं अन्तिम	2012-13	210708
35	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पुनर्वास विभाग	पूर्ण एवं अंतिम	2013-14	450000
36	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे)	पुनर्वास विभाग	प्रथम	2014-15	360000

37	महाराष्ट्र	प्रबे	श्रवण बाधित	प्रथम	2015-16	416358
38	महाराष्ट्र	नेके	एमआर के पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2015-16	339340
39	महाराष्ट्र	बहु	डीडीआरसी, गोंदिया	प्रथम	2015-16	256745
40	महाराष्ट्र		एमआर एवं प्रमस्तिष्क घात बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	293422
41	महाराष्ट्र	देई हुउ संर	धुले में एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	77030
42	महाराष्ट्र	से शन	दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	383204
43	महाराष्ट्र	द प्रस्	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	185211
44	महाराष्ट्र	अप	रेसीडेंसियल स्कूल फॉर डेफ एंड डंब	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	253047
45	महाराष्ट्र	षि य कल्	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	343986
46	महाराष्ट्र	हुउ	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	416358
47	महाराष्ट्र	हुउ	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	416358
कुल						17738607

मणिपुर						
1	मणिपुर	ऑल मणिपुर डिसेबल्ड एंड हेंडीकेप पर्सन्स डवलपमेंट एजेंसी	वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	156868
2	मणिपुर	ऑल मणिपुर हेंडीकेप पर्सन्स वेलफेयर एसोसिएशन	वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	134783
3	मणिपुर	ऑल मणिपुर मेंटली हेंडीकेप पर्सन्स वेलफेयर ऑग्रेनाइजेशन	वीटीसी फॉर पर्सन्स विद सीपीएमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	522729
4	मणिपुर	बेटर लिविंग कंडीशन एंड रिसर्च ऑग्रेनाइजेशन	स्पेशल स्कूल ऑफ मेंटली हेंडीकेप चिल्डरन	प्रथम	2015-16	326165
5	मणिपुर	विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट रूरल सोशल वेलफेयर सोसाइटी	दिव्यांग विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	113292
6	मणिपुर	विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट रूरल सोशल वेलफेयर सोसाइटी	दिव्यांग विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	558228
7	मणिपुर	सेंटर फॉर डवलपमेंट एक्टीविटिस	हाफ वे हॉम	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	29097
8	मणिपुर	सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर कम वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	231248
9	मणिपुर	सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन	मेंटेनेंस ऑफ एमआर चिल्डरन	प्रथम	2015-16	509118
10	मणिपुर	सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन	मेंटेनेंस ऑफ एमआर चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	169707
11	मणिपुर	सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन	हाफ वे हॉम फॉर मेंटली इल पर्सन्स	प्रथम	2015-16	572265
12	मणिपुर	सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन	हाफ वे हॉम फॉर मेंटली इल पर्सन्स	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	190755

13	मणिपुर	ल ए ट ड ले एल	रेसीडेंसियल स्कूल फॉर पीएच	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	350502
14	मणिपुर	वं उ संग मर्	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	674311
15	मणिपुर	विव न भार	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	219531
16	मणिपुर	विव न भार	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2015-16	420336
17	मणिपुर	गा प्री	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	232011
18	मणिपुर	गा प्री	एमआर एवं बहु दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	967977
19	मणिपुर	गा प्री	प्री स्कूल एंड ई. आई. एंड ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	126454
20	मणिपुर	ट डवट कर	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2014-15	139227
21	मणिपुर	ट डवट करण	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	139228
22	मणिपुर	ट डवट कर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	797933
23	मणिपुर	ट डवट कर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	177319

24	मणिपुर	कहा-मणिपुर पेरेंट एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर एंड सीपी चिल्डरन	प्रथम	2015-16	438311
25	मणिपुर	कहा-मणिपुर पेरेंट एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर एंड सीपी चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	438311
26	मणिपुर	मणिपुर गाइडेंस सेंटर (एमएजीसी)	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	258489
27	मणिपुर	सामाजिक सेवा में अग्रणी लोग (पीएसएस)	मानसिक रूप से बिमार व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1101933
28	मणिपुर	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेंडीकेप पर्सन्स	दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	749414
29	मणिपुर	ग्रामीण विकास समिति, थौबाल, मणिपुर	हाफ वे हॉम	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	266526
30	मणिपुर	ग्रामीण शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास संगठन	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	713513
31	मणिपुर	सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	112545
32	मणिपुर	सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	हाफ वे हॉम	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	300339
33	मणिपुर	द डेवलपमेंट फॉर वूमन्स प्रोग्राम सेंटर	वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	424225
34	मणिपुर	द डेवलपमेंट फॉर वूमन्स प्रोग्राम सेंटर	वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	137214
35	मणिपुर	द वूमन्स इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	1130086

36	मणिपुर	ट्रेनिंग इंटर रामपे	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबलड	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1100395
37	मणिपुर	डलू	वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	202632
38	मणिपुर	डलू	वीटीसी	प्रथम	2015-16	348003
कुल						16081020
मेघालय						
1	मेघालय	मुनकेंद्र कल	आशा स्कूल, शिलोंग	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	301711
2	मेघालय	सो	हॉस्टल फॉर डिसेबलड	प्रथम	2015-16	804100
3	मेघालय	जिंगा फॉ रननीड स्पे केश	एज्युकेशन कम वीटीसी फॉर एमआर एंड स्पेस्टिक्स	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	349586
4	मेघालय	फोटर एल	विशेष स्कूल एवं हॉस्टल	प्रथम	2014-15	953552
5	मेघालय	फोटर एल	विशेष स्कूल एवं हॉस्टल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	856895
6	मेघालय	यांगगाण मति	श्रवण बाधित हेतु विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	344377
7	मेघालय	यांगगाण मति	विशेष शिक्षा हेतु मेरी राइस सेंटर	प्रथम	2015-16	703382
कुल						4313603

मिजोरम						
1	मिजोरम	समर्थन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	607541
2	मिजोरम	मिजोरम स्पास्टिक सोसइटी	सीपी, एमएच एवं एचएच के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	दूसरा एवं अंतिम	2014-15	130634
कुल						738175
ओडिशा						
1	ओडिशा	ऑल इण्डिया वूमन्स कॉन्फ्रेंस	स्पे. स्कूल फॉर मल्टीपल हैंडीकेप्ड	प्रथम	2015-16	391655
2	ओडिशा	ऑल इण्डिया वूमन्स कॉन्फ्रेंस	स्पे. स्कूल फॉर मल्टीपल हैंडीकेप्ड	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	328585
3	ओडिशा	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	356756
4	ओडिशा	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	257112
5	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड (जगतसिंहपुर)	प्रथम	2015-16	399600
6	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड (जगतसिंहपुर)	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	377275
7	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज	दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	950190
8	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज	दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	920164

9	ओडिशा	एशर एव	स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, डीफ एंड एमआर	प्रथम	2014-15	0
10	ओडिशा	एशर एव	स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, डीफ एंड एमआर	प्रथम	2014-15	84150
11	ओडिशा	एशर एव	रिहेबिलिटेशन ऑफ एलसीपी	प्रथम	2014-15	37673
12	ओडिशा	एशर एव	सीबीआर प्रोग्राम	प्रथम	2014-15	28158
13	ओडिशा	एलब	वीटीसी फॉर ओएच	प्रथम	2015-16	296352
14	ओडिशा	एलब	स्पेशल स्कूल फॉर मल्टीपल हैंडीकेप्ड	प्रथम	2015-16	623138
15	ओडिशा	एलब	रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ एलसीपी (हॉम फॉर द लेप्रोसी)	प्रथम	2015-16	308120
16	ओडिशा	एलब	सीबीआर प्रोग्राम	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	461934
17	ओडिशा	ज्यो	स्पेशल स्कूल फॉर हैंडीकेप चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1025250
18	ओडिशा	गॉर मेटे एंडर्व एस	स्पास्टिक बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	739377
19	ओडिशा	गॉर मेटेशर्विस मर्च	सीबीआर प्रोग्राम	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	491760
20	ओडिशा	रर्स र	डीडीआरसी, नबरंगपुर	प्रथम	2015-16	294204
21	ओडिशा	वेक कें	डीडीआरसी, फूलबानी	प्रथम	2015-16	221940
22	ओडिशा	ट ल्ड	स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल	प्रथम	2015-16	880032

23	ओडिशा	डिस्ट्रीक्ट डिसेबल्ड स्कूल	स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	818784
24	ओडिशा	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल (सहाया)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	205852
25	ओडिशा	जया किसान यूथ क्लब	रिहेबिलिटेशन ऑफ एलसीपी	प्रथम	2015-16	650902
26	ओडिशा	जीवनज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकेप्ड	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1033911
27	ओडिशा	महावीर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट	स्पेशल स्कूल फॉर डेफ	प्रथम	2014-15	1075507
28	ओडिशा	महाराजा कृष्णा चंद्रा गजपति स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ	स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	437835
29	ओडिशा	नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआरडीसी)	वीटीसी फॉर एलसीपी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	179798
30	ओडिशा	नेहरू सेवा संघ	पीएच के लिए औद्योगिक, संगीत संबंधी एवं सामान्य संस्थान	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	732971
31	ओडिशा	नेहरू सेवा संघ	पीएच के लिए औद्योगिक, संगीत संबंधी एवं सामान्य संस्थान	प्रथम	2015-16	414652
32	ओडिशा	नेहरू सेवा संघ	पीएच के लिए औद्योगिक, संगीत संबंधी एवं सामान्य संस्थान	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	414653
33	ओडिशा	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	दिव्यांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2015-16	304920

34	ओडिशा	ल	स्पेशल स्कूल फॉर डेफ एंड डंब	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	377204
35	ओडिशा	लि	प्रमस्तिष्क घात बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	482205
36	ओडिशा	लि	प्रमस्तिष्क घात बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	406455
37	ओडिशा	पुनएवं	स्पास्टिक बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	511565
38	ओडिशा	पुनएवं	एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	365239
39	ओडिशा	डवट	हाफ वे हॉम	प्रथम	2015-16	273483
40	ओडिशा	युव	वाक एवं श्रवण बाधित के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	562083
41	ओडिशा	ली	स्कूल फॉर एचएच / एमआर / ब्लाईंड	प्रथम	2015-16	381817
42	ओडिशा	टी	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1036161
43	ओडिशा	प्रशिएवं	दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1013039
44	ओडिशा	प्रशिएवं	दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	269684
45	ओडिशा	क	स्पेशल स्कूल फॉर डेफ एंड एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	902084

46	ओडिशा	विजया	दृष्टिहीन, मूक एवं बधिर लड़कियों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	651176
47	ओडिशा	वोलेंटी ऑग्रेनाइजेशन फॉर रूरल इम्प्रूवमेंट	स्पे. स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ	प्रथम	2015-16	541856
48	ओडिशा	महिला समुदाय प्रबंधन समूह	एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2015-16	629539
49	ओडिशा	महिला समुदाय प्रबंधन समूह	एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	541069
कुल						24687869
पुडुचेरी						
1	पुडुचेरी	श्री पतचेअप्पन सोसाइटी फॉर एज्युकेशन, रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड	स्पेशल स्कूल फॉर एचएच	प्रथम	2015-16	716820
कुल						716820
पंजाब						
1	पंजाब	आशा दीप कल्याण समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	391365
2	पंजाब	विकलांग बच्चों के लिए चेतक आशा स्कूल, भाटिन्डा	आशा स्कूल, भाटिन्डा	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	236175
3	पंजाब	विकलांग बच्चों के लिए चेतक आशा स्कूल, भाटिन्डा	आशा स्कूल, भाटिन्डा	प्रथम	2015-16	351870
4	पंजाब	इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी, (फरीदकोट)	दृष्टिहीन के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	218369
5	पंजाब	इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी, (फरीदकोट)	एमआर बच्चों के लिए स्कूल	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	286010

6	पंजाब	न गॅस टी, कोर	एमआर बच्चों के लिए स्कूल	षेष्ठ	2014-15	57203
7	पंजाब	न गॅस टी, रूर)	डीडीआरसी	प्रथम	2015-16	222270
8	पंजाब	न न	दृष्टिहीन बच्चों के लिए संस्थान	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	267907
9	पंजाब	विनीष स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	829463
10	पंजाब	के रेड स्कूल	मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	628116
11	पंजाब	यिक्वास ग र	दृष्टिहीन के लिए शिक्षा वीटीसी कार्यशाला	प्रथम	2015-16	579283
12	पंजाब	यिक्वास ग र	दृष्टिहीन के लिए शिक्षा वीटीसी कार्यशाला	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	576637
13	पंजाब	काआर्मी ज वेर एशेना ग र)	आशा स्कूल, चांदीमंदिर	प्रथम	2014-15	362062
14	पंजाब	काआर्मी ज वेर एशेना ग र)	आशा स्कूल, चांदीमंदिर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	120688
कुल						5127418
राजस्थान						
1	राजस्थान	आशूल	आशा स्कूल, जोधपुर	प्रथम	2015-16	298494
2	राजस्थान	बाकास	हॉस्टल एंड वीटीसी फॉर डेफ	प्रथम	2015-16	300570
3	राजस्थान	बाकास	हॉस्टल एंड वीटीसी फॉर डेफ	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	34395
4	राजस्थान	वि ए पोत	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	77152

5	राजस्थान	दिषा- विकलांग के लिए एक स्रोत केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	84781
6	राजस्थान	दिषा- विकलांग के लिए एक स्रोत केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	267919
7	राजस्थान	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, जालोर	डीडीआरसी, जालोर	पूर्ण एवं अन्तिम	2015-16	259084
8	राजस्थान	इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2014-15	403025
9	राजस्थान	इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	134342
10	राजस्थान	इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	362370
11	राजस्थान	जेमिनी शिक्षण एवं ग्रामिण विकास संस्था	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	282626
12	राजस्थान	कौशल सेवा संस्थान	वीटीसी फॉर डिसेबल्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	40928
13	राजस्थान	एलकेसी श्री जगदंबा अंध विद्यालय समिति	अंध एवं बधिर के लिए स्कूल एवं हॉस्टल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	929370
14	राजस्थान	मरूधारा बाल शिक्षण संस्थान	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	341400
15	राजस्थान	मर्सी रिहैबिलिटेशन सोसाइटी	स्पेशल स्कूल कम रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर मल्टी डिसेबिटी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	339565
16	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	332100
17	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान	वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	280147

18	राजस्थान	ग रे	सीबीआर प्रोग्राम	प्रथम	2015-16	189638
19	राजस्थान	तना क क विद	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	519489
20	राजस्थान	मके न म ग ग र गई)	दृष्टिहीन के लिए हॉस्टल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	28000
21	राजस्थान	संस्	रेसिडेंसियल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	648765
22	राजस्थान	सेंटर एपन केश	स्पेशल एज्युकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2015-16	493716
23	राजस्थान	सेंटर एपन केश	स्पेशल एज्युकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	374750
24	राजस्थान	गमता र रटी	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	166889
25	राजस्थान	सर्	वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	43099
26	राजस्थान	सर्	वीटीसी	प्रथम	2015-16	137133
27	राजस्थान	म ए लांगलिए स्कूल	आटिज्म एवं बहुविकलांग के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	275838
28	राजस्थान	तना वेज्ञाध	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	341614
29	राजस्थान	क रिंग प्राण	निर्मल विवेक स्कूल एवं हॉस्टल	प्रथम	2014-15	38685

30	राजस्थान	उमंग	मानसिक मंदता स्कूल एवं सीपी के लिए परियोजना	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	128497
कुल						8154381
तमिलनाडु						
1	तमिलनाडु	मानसिक मंदता के लिए कारमल सेंटर	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	504480
2	तमिलनाडु	क्रिस्टियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड-इण्डिया	ट्रेनिंग कम रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	209633
3	तमिलनाडु	क्रिस्टियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड-इण्डिया	ब्रेली प्रेस फॉर द वीएच	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	337659
4	तमिलनाडु	क्रिस्टियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड-इण्डिया	ब्रेली प्रेस फॉर द वीएच	षेष्ठ	2014-15	260008
5	तमिलनाडु	डेवलपमेंट एज्युकेशन	स्पेशल स्कूल फॉर एम.आर.	प्रथम	2014-15	394273
6	तमिलनाडु	अंध के लिए आई.ई. एल.सी. स्कूल	हॉस्टल एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	488153
7	तमिलनाडु	इण्डियन एसोसिएशनन फॉर द ब्लाइंड	ब्रेल लाइब्रेरी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	27000
8	तमिलनाडु	कोंगू अरीवालायम स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	843183
9	तमिलनाडु	लाइफ ऐड सेंटर फॉर द डिसेबल्ड	रेसिडेंसियल स्कूल फॉर द डेफ	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	330118
10	तमिलनाडु	लाइफ ऐड सेंटर फॉर द डिसेबल्ड	रेसिडेंसियल स्कूल फॉर द डेफ	प्रथम	2015-16	496686
11	तमिलनाडु	मधुरम नारायण सेंटर फॉर एक्ससेप्शनल चिल्डरन	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	50115

12	तमिलनाडु	नार फॉर शन त	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	436177
13	तमिलनाडु	स्कूल चित	स्पेशल स्कूल एंड टीआरजी फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	133308
14	तमिलनाडु	भार प्रेइय एवं ल गन	श्रवण बाधित के लिए स्कूल	प्रथम	2014-15	102391
15	तमिलनाडु	ते	वीटीसी फॉर हैंडीकेप एंड एमआर	प्रथम	2014-15	53160
16	तमिलनाडु	सेमेति	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्ड्रन	प्रथम	2015-16	403945
17	तमिलनाडु	री स	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2014-15	440754
18	तमिलनाडु	फग लडाल (म)	स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	370305
19	तमिलनाडु	फग लडाल (म)	स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड	प्रथम	2015-16	367278
20	तमिलनाडु	टक पी 3 डू	सीपीएमआर के लिए वीटीसी	प्रथम	2015-16	264838
21	तमिलनाडु	टक पी 3 डू	जनशक्ति विकास परियोजना	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	84231
22	तमिलनाडु	पपत य क	फिजियोथेरेपी उपचार यूनिट	प्रथम	2014-15	82031

23	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली बहुउद्देश्य सामाजिक सेवा समिति	फिजियोथेरेपी उपचार यूनिट	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	75469
24	तमिलनाडु	विजय मानव सेवा	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2014-15	157466
25	तमिलनाडु	विजय मानव सेवा	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	52489
कुल						6965150
तेलंगाना						
1	तेलंगाना	दिव्यांग आशा ज्योति कल्याण संघ	मानसिक एवं बहु विकलांग के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	181609
2	तेलंगाना	दिव्यांग आशा ज्योति कल्याण संघ	मानसिक एवं बहु विकलांग के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	771694
3	तेलंगाना	बीआरईएसएच भद्राचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एज्युकेशनसोसाइटी फॉर हेंडीकेप	रेसिडेंसियल स्कूल फॉर एचआई, एमआर, एंड वीटीसी	प्रथम	2015-16	1244700
4	तेलंगाना	बीआरईएसएच भद्राचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एज्युकेशन सोसाइटी फॉर हेंडीकेप	रेसिडेंसियल स्कूल फॉर एचआई, एमआर, एंड वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1162890
5	तेलंगाना	देवनार अंध फाउंडेशन	अंध के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	2479055
6	तेलंगाना	इको क्लब ब्रह्मा इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हेंडीकेड	स्पेशल स्कूल फॉर एमएच	पूर्ण एवं अंतिम	2015-16	798343

7	तेलंगाना	एवं नक बच्चों के लिए दिवस एवं आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	942173
8	तेलंगाना	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	667269
9	तेलंगाना	ना स्पे स्कूल फॉर एमआर पर्सन	प्रथम	2015-16	668145
10	तेलंगाना	बो स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	1041900
11	तेलंगाना	एस्शन मेंट ड एमएच	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	60075
12	तेलंगाना	प स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	623771
13	तेलंगाना	प (री) स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	814804
14	तेलंगाना	प (री) स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	728925
15	तेलंगाना	प वीटीसी फार एमआर	प्रथम	2015-16	628473
16	तेलंगाना	प स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फार एमआर	प्रथम	2014-15	538522
17	तेलंगाना	प स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फार एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	323084
18	तेलंगाना	प वीटीसी फार एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	79102
19	तेलंगाना	प वीटीसी फार एमआर	प्रथम	2015-16	233650
20	तेलंगाना	कय एयों पेता एमआर के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2015-16	260187
21	तेलंगाना	प वीटी एवं सेल्टर्ड वर्कशॉप (मनोचेतना)	प्रथम	2015-16	844537
22	तेलंगाना	लि अंध के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2014-15	1005375

23	तेलंगाना	अंध के लिए आवासीय स्कूल	अंध के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1058400
24	तेलंगाना	सबिथा एज्युकेशन सोसाइटी	मानसिक विकलांग हेतु विशेष शिक्षा एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	166601
25	तेलंगाना	सबिथा एज्युकेशन सोसाइटी	मानसिक विकलांग हेतु विशेष शिक्षा एवं वीटीसी	प्रथम	2015-16	398131
26	तेलंगाना	श्री साई एज्युकेशन सोसाइटी	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	तीसरा एवं अन्तिम	2014-15	72711
27	तेलंगाना	श्री साई एज्युकेशन सोसाइटी	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	519187
28	तेलंगाना	श्री साई एज्युकेशन सोसाइटी	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	519188
29	तेलंगाना	विशेष बच्चों के लिए श्री विद्या केंद्र	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	345595
30	तेलंगाना	विशेष बच्चों के लिए श्री विद्या केंद्र	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	1478012
31	तेलंगाना	स्वर्णा स्वयंकरुशि सोसाइटी	स्पेशल स्कूल एंड वोकेशनल सेंटर फॉर एमएच	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	526448
32	तेलंगाना	स्वयंकरुशि	हॉम फॉर एज्ड एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	68957
33	तेलंगाना	द करीमनगर जिला फ्रिडम फाइटर्स ट्रस्ट	एम आर के लिए स्कूल एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	530412
34	तेलंगाना	थेरेसा मेंटली चैलेंज्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	629235
35	तेलंगाना	वेर्गेसा फाउंडेशन	स्कूल फॉर पीएच	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	915678
36	तेलंगाना	वेर्गेसा फाउंडेशन	स्कूल फॉर पीएच	प्रथम	2015-16	1045647
37	तेलंगाना	आत्मीय मानसिक विकास केंद्रम	स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	950842

38	तेलंगाना	देश फॉर भक्तिकर	रेसी. स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	278007
39	तेलंगाना	हयू	वीटीसी फार एमआर	प्रथम	2015-16	210450
40	तेलंगाना	हयू	वीटीसी फार एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	210450
41	तेलंगाना	हयू	रेसी. एंड डे केयर सेंटर फॉर एमआर.	प्रथम	2015-16	878595
42	तेलंगाना	हयू	रेसी. एंड डे केयर सेंटर फॉर एमआर.	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	878595
43	तेलंगाना	स्पेशल	रेसीडेंसियल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	648018
44	तेलंगाना	गिदर	स्पेशल स्कूल	प्रथम	2015-16	1696887
45	तेलंगाना	गिदरेंद्र	स्पेशल स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1479303
46	तेलंगाना	गस संघ	वीएच के लिए हॉस्टल एवं विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1113635
47	तेलंगाना	देश ल ३ ब. ३ (हिमा), ३	वोके. ट्रेनिंग / रिहबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकेप्ड	तीसरा एवं अंतिम	2014-15	284552
48	तेलंगाना	देश ल ३ ब. ३ (हिमा), ३	वोके. ट्रेनिंग / रिहबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकेप्ड	प्रथम	2015-16	827685

49	तेलंगाना	दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (आंध्रा महिला सभा), हैदराबाद	स्पेशल एज्युकेशनसेंटर फॉर एमआर/एचएच	प्रथम	2015-16	1127497
50	तेलंगाना	दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (आंध्रा महिला सभा), हैदराबाद	स्पेशल एज्युकेशनसेंटर फॉर एमआर/एचएच	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	1056248
51	तेलंगाना	ग्रेसी ऑग्रेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विस	स्कूल फॉर डेफ एंड डंब	प्रथम	2015-16	541265
52	तेलंगाना	मानव संसाधन विकास समिति	पीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	726276
53	तेलंगाना	मानव संसाधन विकास समिति	पीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2015-16	1254937
54	तेलंगाना	लक्ष्य साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हैंडीकेप्ड	रेसीडेंसियल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	530175
55	तेलंगाना	लक्ष्य साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हैंडीकेप्ड	रेसीडेंसियल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	530175
56	तेलंगाना	पामेनकेप	स्पेशल स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	622773
57	तेलंगाना	पामेनकेप (सिकंदराबाद)	वीटीसी फार एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	233651
58	तेलंगाना	पामेनकेप	वी.टी. एवं सेल्टर्ड वर्कशॉप (मनोचेतना)	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	281513

59	तेलंगाना	युव	एमआर के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र (मनोकुरुशि)	प्रथम	2015-16	2045493
60	तेलंगाना	युव	वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैब. सेंटर फॉर डिसेबल्ड	प्रथम	2015-16	465570
61	तेलंगाना	स्टीफॉर रेटा	स्पे स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	173703
62	तेलंगाना	स्टीफॉर रेटा	स्पे स्कूल फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	331492
63	तेलंगाना	सोर्टली	स्पे स्कूल फॉर एंड वीटीसी फार एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	490894
64	तेलंगाना	सोर्टलीकेपड	रेसिडेंसियल स्पेशल स्कूल फॉर एमआर एट नालगोंडा	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	670323
65	तेलंगाना	वा	स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर	प्रथम	2015-16	628326
66	तेलंगाना	केत	मानसिक विकलांग हेतु आवासीय संस्थान	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	928849
67	तेलंगाना	केत	मनौवेज्ञानिक-सामाजिक पुनर्वास के लिए ऑफ वे होम और उपचार	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	265645
68	तेलंगाना	फान	दिव्यांग के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	939495
69	तेलंगाना	ग्रामिण	स्पे स्कूल फॉर एमआर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	575569
70	तेलंगाना	ग्रामिण	दृष्टिबाधित के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	297607

71	तेलंगाना	सोसाइटी फॉर एज्युकेशन एंड रेह ऑफ विजुअली हेंडीकेप्ड	सीबीआर प्रोग्राम	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	493925
72	तेलंगाना	सोसाइटी फॉर एज्युकेशन एंड रेह ऑफ विजुअली हेंडीकेप्ड	सीबीआर प्रोग्राम	प्रथम	2015-16	431616
73	तेलंगाना	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस	बधिर शिक्षक हेतु प्रशिक्षण संस्थान	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	65663
74	तेलंगाना	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस	स्पे स्कूल फॉर एमआर चिल्ड्रन	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	915522
75	तेलंगाना	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस	स्पेशल स्कूल फॉर डेफ	प्रथम	2015-16	2481000
76	तेलंगाना	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन। मानसिक विकलांगों हेतु	स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर एमआर (हैदराबाद)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	1194530
77	तेलंगाना	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन। मानसिक विकलांगों हेतु	स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर एमआर (हैदराबाद)	प्रथम	2015-16	1047132
78	तेलंगाना	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन। मानसिक विकलांगों हेतु	डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	83888

79	तेलंगाना	डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 5 विद्यालयों	डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम	प्रथम	2015-16	243870
80	तेलंगाना	डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 5 विद्यालयों	डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम	प्रथम	2015-16	98963
81	तेलंगाना	डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 5 विद्यालयों	डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम	प्रथम	2015-16	97650
82	तेलंगाना	डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 5 विद्यालयों	डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम	प्रथम	2015-16	354420
83	तेलंगाना	डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 5 विद्यालयों	डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम	प्रथम	2015-16	168750
84	तेलंगाना	एनएच पीएच के लिए वीटीसी	पीएच के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	597384
85	तेलंगाना	एनएच पीएच के लिए आवासीय स्कूल	पीएच बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	298435
कुल						58119728

त्रिपुरा						
1	त्रिपुरा	अभय मिशन	एमआर वाले बहु विकलांगता के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	32228
2	त्रिपुरा	अभय मिशन	एमआर वाले बहु विकलांगता के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	6446
3	त्रिपुरा	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, उत्तर त्रिपुरा	प्रथम	2015-16	507565
4	त्रिपुरा	त्रिपुरा बाल कल्याण परिषद	सीपीएमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	138486
कुल						684725
उत्तर प्रदेश						
1	उत्तर प्रदेश	आदर्श मूक बधिर विद्यालय	एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	155836
2	उत्तर प्रदेश	आदर्श मूक बधिर विद्यालय	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	548156
3	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय कल्याण समिति	शिक्षा एवं वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	847905
4	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर शिक्षा समिति	दिव्यांगों के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	214681
5	उत्तर प्रदेश	आर्या सुगंध स्थान (पूर्व में अपंग आशा जन विकास संस्थान के रूप में)	दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2014-15	555830
6	उत्तर प्रदेश	आर्या सुगंध स्थान (पूर्व में अपंग आशा जन विकास संस्थान के रूप में)	दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	514250
7	उत्तर प्रदेश	आर्या सुगंध स्थान (पूर्व में अपंग आशा जन विकास संस्थान के रूप में)	दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	702900

8	उत्तर प्रदेश	गंधन अपंगा स्थान (में)	दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	583467
9	उत्तर प्रदेश	बलास	मूक बधिर के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	364313
10	उत्तर प्रदेश	से	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	179867
11	उत्तर प्रदेश	से	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2015-16	550834
12	उत्तर प्रदेश	चौ	विकलांगों के लिए शिक्षा और वीटीसी	प्रथम	2015-16	835065
13	उत्तर प्रदेश	चौ	विकलांगों के लिए शिक्षा और वीटीसी	शेष	2014-15	67318
14	उत्तर प्रदेश	ग्रा संर	विकलांगों के लिए शिक्षा और वीटीसी	प्रथम	2014-15	326461
15	उत्तर प्रदेश		एमआर के लिए विद्यालय	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	273289
16	उत्तर प्रदेश	धेरी प्र	मूल और बधिरों का विद्यालय	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	910128
17	उत्तर प्रदेश	ट लेट ए	डीडीआरसी, बलिया	प्रथम	2015-16	697125
18	उत्तर प्रदेश	ऑप ड इ	बधिरों व मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2015-16	965705
19	उत्तर प्रदेश	जवा	एचआई के लिए विशेष विद्यालय	तीसरा एवं अन्तिम	2015-16	344538
20	उत्तर प्रदेश	डुट द ड	रेसिडेंशियल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड	प्रथम	2015-16	758250
21	उत्तर प्रदेश	डुट द ड	रेसिडेंशियल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	506052

22	उत्तर प्रदेश	इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड	रेसिडेंशियल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	566654
23	उत्तर प्रदेश	जॉनसन एकेडमिक इंस्टीट्यूट	सुनने में अक्षम बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2015-16	632258
24	उत्तर प्रदेश	केएसजे हाई स्कूल	विकलांग के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	1213335
25	उत्तर प्रदेश	किरण सोसाइटी, वाराणसी, यू.पी.	दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	388308
26	उत्तर प्रदेश	मंगलम	विकलांगों के लिए वीटीसी	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	48193
27	उत्तर प्रदेश	मनीष सेवा संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल (ग्रामीण परियोजना)	प्रथम	2014-15	248071
28	उत्तर प्रदेश	मेरठ बाल कल्याण न्यास	एमएच बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2015-16	569095
29	उत्तर प्रदेश	निर्वाण	एमआर के लिए शिक्षा एवं वीटीसी	प्रथम	2014-15	69859
30	उत्तर प्रदेश	पावाहारी स्मृति परिषद	वीएच के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2015-16	335858
31	उत्तर प्रदेश	पावाहारी स्मृति परिषद	मूक बधिरों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2015-16	536842
32	उत्तर प्रदेश	प्राग नारायण मूक बधिर विद्यालय समिति	बधिरों के लिए विद्यालय	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	379845
33	उत्तर प्रदेश	रचना (विकलांगों के लिए एकीकृत संस्थान की शाखा)	मानसिक विकलांगों और विविध विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2015-16	615728
34	उत्तर प्रदेश	रावत शिक्षा समिति	एचआई एवं वीआई के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	623536

35	उत्तर प्रदेश	संटी, शाख	डीडीआरसी, रायबरेली	पूर्ण एवं अंतिम	2015-16	182585
36	उत्तर प्रदेश	विव	प्रीस्कूल और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर	प्रथम	2014-15	139236
37	उत्तर प्रदेश	एन टी	दिव्यांग हेतु एचएच एंड वीटीसी के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	450996
38	उत्तर प्रदेश	उ	एचएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अंतिम	2014-15	200957
39	उत्तर प्रदेश	मेवाान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	दूसरा	2014-15	100611
40	उत्तर प्रदेश	मानद अं य	देखने में अक्षम के लिए आवासीय विद्यालय	शेष	2014-15	428366
41	उत्तर प्रदेश	मानद अं य	देखने में अक्षम के लिए आवासीय विद्यालय	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	701379
42	उत्तर प्रदेश	थोर्टी	श्रवण बाधित के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अंतिम	2014-15	841779
43	उत्तर प्रदेश	थोर्टी	श्रवण बाधित के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	1822230
44	उत्तर प्रदेश	क्र ने ग कों याण उत्तरा प्रकाान	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय और वीटीसी	प्रथम	2014-15	381880
45	उत्तर प्रदेश	मा र	डीडीआरसी, रामपुर	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	165913
46	उत्तर प्रदेश	प्रदेश विद्य	बधिर के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	1790257
47	उत्तर प्रदेश	प्रदेश विद्य	बधिर के लिए आवासीय स्कूल	दूसरा एवं अंतिम	2015-16	1701653
कुल						26037394

उत्तराखण्ड						
1	उत्तराखण्ड	हैपी फैमिली हेल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशन	डीडीआरसी हरिद्वार	दूसरा	2014-15	423300
2	उत्तराखण्ड	रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	एमआर के लिए वीटीसी एवं हॉस्टल तथा डे केयर सेंटर	प्रथम	2014-15	385760
3	उत्तराखण्ड	रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	एमआर के लिए वीटीसी एवं हॉस्टल तथा डे केयर सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	385760
4	उत्तराखण्ड	रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	एमआर के लिए वीटीसी एवं हॉस्टल तथा डे केयर सेंटर	प्रथम	2015-16	606203
5	उत्तराखण्ड	रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	एलसीपी के लिए केंद्र	प्रथम	2014-15	129786
6	उत्तराखण्ड	रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	एलसीपी के लिए केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	129787
7	उत्तराखण्ड	विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति	एमएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	382953
कुल						2443549
पश्चिम बंगाल						
1	पश्चिम बंगाल	अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल	वीटीसी उपकरणों सहित एमआर हेतु विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	89009
2	पश्चिम बंगाल	अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल	एमआर हेतु विशेष स्कूल एवं वीटीसी (जैमो यूनिट)	पूर्ण एवं अन्तिम	2014-15	1206954
3	पश्चिम बंगाल	अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल	एमआर हेतु विशेष स्कूल एवं वीटीसी (मुख्य यूनिट)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	157416
4	पश्चिम बंगाल	अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल	मैन पावर डेवलपमेंट टीचयर्स ट्रेनिंग	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	73134

5	पश्चिम बंगाल	भव	एचएच के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी	प्रथम	2014-15	226791
6	पश्चिम बंगाल	भव	अस्थी विकलांग हेतु पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2014-15	257836
7	पश्चिम बंगाल	गोलदम	विशेष बाल विकास केंद्र	प्रथम	2014-15	263352
8	पश्चिम बंगाल	गोलदम	विशेष बाल विकास केंद्र	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	263353
9	पश्चिम बंगाल	आओ	एमआर बच्चों और थेरेपी पाठ्यक्रमों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	68085
10	पश्चिम बंगाल	आओ	एमआर बच्चों और थेरेपी पाठ्यक्रमों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	68085
11	पश्चिम बंगाल	भा संटी	पीएच के लिए उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र और फिजि.डेप. (झारग्राम)	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	534242
12	पश्चिम बंगाल	यन	एमआर के लिए डे केयर सेंटर	प्रथम	2015-16	597772
13	पश्चिम बंगाल	यन	एमआर के लिए डे केयर सेंटर	दूसरा एवं अन्तिम	2015-16	585773
14	पश्चिम बंगाल	न व गोल	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	457252
15	पश्चिम बंगाल	न व गोल	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	440940
16	पश्चिम बंगाल	न र सेद्र	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	166814
17	पश्चिम बंगाल	न्द्र मुकर	मूक एवं बधिर हेतु शैक्षणिक संस्थान	प्रथम	2014-15	839613
18	पश्चिम बंगाल	न्द्र मुकर	मूक एवं बधिर हेतु शैक्षणिक संस्थान	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	657081

19	पश्चिम बंगाल	डम डम डीप डैफ एवं डंब एंड डंब स्कूल क्रेच	श्रवण विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	325953
20	पश्चिम बंगाल	ईस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी वाइक्स वेलफेयर एसोसिएशन	आशा स्कूल, कोलकाता, (आर्मी वेलफेयर सोसायटी)	प्रथम	2014-15	173705
21	पश्चिम बंगाल	मालदा हेदरपुर सेल्टर	डीडीआरसी, मालदा	प्रथम	2015-16	276575
22	पश्चिम बंगाल	होप	वीटीसी घटक सहित एच.एच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	544397
23	पश्चिम बंगाल	होप	वीटीसी घटक सहित एच.एच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	388855
24	पश्चिम बंगाल	इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडिकैप्ड एंड बैकवर्ड पीअुपल	विकलांगजन हेतु विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	540840
25	पश्चिम बंगाल	इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडिकैप्ड एंड बैकवर्ड पीअुपल	विकलांगजन हेतु विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	540840
26	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	एमआर/एचएच/वीआई के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	228159
27	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	एमआर/एचएच/वीआई के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	535365
28	पश्चिम बंगाल	कोरक प्रतिबंधी कल्याण केंद्र	एमएच के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	258437
29	पश्चिम बंगाल	कोरक प्रतिबंधी कल्याण केंद्र	एमएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	236400
30	पश्चिम बंगाल	कोवाली सलेहा मेमोरियल स्कूल फॉर हियरिंग एंड मेंटली हैंडिकैप्ड	एमएच/एचएच के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण एवं अंतिम	2014-15	219580

31	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	85501
32	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	168430
33	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	148201
34	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	दूसरा एवं अन्तिम	2014-15	28502
35	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014-15	301499
36	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	पहली	2014-15	151481
37	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	पहली	2014-15	661957
38	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अन्तिम	2014-15	157468
39	पश्चिम बंगाल	कास मेटेण्ड इंस्टि हैंड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अन्तिम	2014-15	100500

40	पश्चिम बंगाल	मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर्म द हैंडीकैप्ड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	50494
41	पश्चिम बंगाल	मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर्म द हैंडीकैप्ड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	56143
42	पश्चिम बंगाल	मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर्म द हैंडीकैप्ड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	पहली	2015-16	138950
43	पश्चिम बंगाल	मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर्म द हैंडीकैप्ड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	220652
44	पश्चिम बंगाल	मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर्म द हैंडीकैप्ड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	पहली	2015-16	398131
45	पश्चिम बंगाल	मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर्म द हैंडीकैप्ड	एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल	पहली	2015-16	183206
46	पश्चिम बंगाल	मोयोना रामाकृष्णन एसोसिएशन	एचएच के लिए विशेष स्कूल	पहली	2014-15	283548
47	पश्चिम बंगाल	निमतोरी तालुक उन्नयन समिति	दिव्यांगो के लिए वीटीसी	पहली	2014-15	364312
48	पश्चिम बंगाल	निमतोरी तालुक उन्नयन समिति	दिव्यांगो के लिए वीटीसी	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	121438
49	पश्चिम बंगाल	निमतोरी तालुक उन्नयन समिति	दिव्यांगो के लिए वीटीसी	पहली	2015-16	365805
50	पश्चिम बंगाल	निमतोरी तालुक उन्नयन समिति	दिव्यांगो के लिए वीटीसी	पहली	2014-15	110534
51	पश्चिम बंगाल	नार्थ बंगाल पुनर्वास समिति	एचएच एवं एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	868766

52	पश्चिम बंगाल	बच्चों के लिए प्रेतामेत्व क	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	पहली	2015-16	268086
53	पश्चिम बंगाल	गानाफ	हॉफ वे होम	पहली	2014-15	118702
54	पश्चिम बंगाल	गानाफ	हॉफ वे होम	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	118702
55	पश्चिम बंगाल	गानाफ	कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	373095
56	पश्चिम बंगाल	गानाफ	कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण	पहली	2015-16	356295
57	पश्चिम बंगाल	गानाफ	स्वीमिंग पूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	72253
58	पश्चिम बंगाल	गानाफ	स्वीमिंग पूल	पहली	2015-16	75815
59	पश्चिम बंगाल	गानाफ	ब्रेल प्रेस मैनटेनेंस	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	886724
60	पश्चिम बंगाल	गानाफ	ब्रेल प्रेस मैनटेनेंस	बकाया राशि	2014-15	737422
61	पश्चिम बंगाल	गानाफ	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	219458
62	पश्चिम बंगाल	गानाफ	विशेष बाल विकास केंद्र	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	501875
63	पश्चिम बंगाल	गानाफ	विशेष बाल विकास केंद्र	पहली	2015-16	332550
64	पश्चिम बंगाल	गानाफ	वीटीसी घटक के साथ एचएच एवं एमआर के लिए विशेष स्कूल	पहली	2014-15	175608

65	पश्चिम बंगाल	सेवायतन कल्याण केंद्र	मूक, बधिर एवं एमआर हेतु विशेष स्कूल	पहली	2014-15	265345
66	पश्चिम बंगाल	सेवायतन कल्याण केंद्र	मूक, बधिर एवं एमआर हेतु विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	747793
67	पश्चिम बंगाल	सेवायतन कल्याण केंद्र	मूक, बधिर एवं एमआर हेतु विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	98457
68	पश्चिम बंगाल	सेलटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	पहली	2014-15	118621
69	पश्चिम बंगाल	सेलटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	350159
70	पश्चिम बंगाल	सेलटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	पहली	2015-16	413430
71	पश्चिम बंगाल	सेलटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2015-16	413431
72	पश्चिम बंगाल	सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	पहली	2014-15	254576
73	पश्चिम बंगाल	सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	दूसरी एवं अंतिम	2014-15	254577
74	पश्चिम बंगाल	सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर	डीआरएस (एमआर) शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	पहली	2014-15	134212
75	पश्चिम बंगाल	युवा उन्नयन सेवा समिति	सीपीएमआर बच्चों के लिए विशेष जस्कूल एवं पुनर्वास केंद्र	पहली	2015-16	306606
75	पश्चिम बंगाल	युवा उन्नयन सेवा समिति	सीपीएमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र	पहली	2015-16	23781918
कुल						47563836

अनुबंध-11

2016-17 दौलतपुर विकलांग पुनर्वास योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों को दी अनुदान सहायता के राज्य-वार विवरण का सार 1.12.2016 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (रु. लाख में)	सहायता किए गए गैर-सरकारी संस्थान	सहायता की गई परियोजनाएं	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	543.42	45	60	9807
2	बिहार	21.86	6	6	657
3	छत्तीसगढ़	12.07	5	5	422
4	गोवा	4.89	1	1	86
5	गुजरात	28.00	8	10	5505
6	हरियाणा	66.36	13	14	1063
7	हिमाचल प्रदेश	20.93	4	5	279
8	जम्मू एवं कश्मीर	3.25	1	1	58
9	झारखंड	0.94	1	1	70
10	कर्नाटक	76.18	6	9	1357
11	केरल	373.85	47	51	6423
12	मध्य प्रदेश	60.27	16	17	1078
13	महाराष्ट्र	177.38	21	26	15721
14	ओडिसा	246.87	29	38	6347
15	पंजाब	51.27	9	10	1092
16	राजस्थान	81.54	21	23	2608
17	तमिलनाडू	69.65	17	19	2481
18	तेलंगाना	581.19	42	55	9857
18	उत्तर प्रदेश	260.37	35	37	5026

19	उत्तराखंड	24.43	3	4	319
20	पश्चिम बंगाल	237.81	30	38	13180
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्य					
1	अरुणाचल प्रदेश	3.87	1	1	27
2	असम	59.80	10	12	1367
3	मणिपुर	160.81	20	28	2419
4	मेघालय	43.13	5	6	676
5	मिजोरम	7.38	2	2	221
6	नागालैंड	0.00	0	0	0
7	सिक्किम	0.00	0	0	0
8	त्रिपुरा	6.84	3	3	129
संघ शासित प्रदेश					
1	अंडमान एवं निकोबर	0.00	0	0	0
2	चंडीगढ़	0.00	0	0	0
3	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0	0	0
4	दमन एवं दीव	0.00	0	0	0
5	दिल्ली	56.73	8	10	2589
6	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0
7	पुडुचेरी	7.16	1	1	108
	डीडीआरसी		0	0	45000
	कुल	3288.25	410	493	135990

अनुबंध-12

2016-17 वर्ष के दौरान डीडीआरसी के अंतर्गत डीडीआरसीएस को जारी की अनुदान सहायता

16.01.2017 तक)

क्र. सं.	डीडीआरसी	राज्य/संघ राज्य	स्कीम	जारी की गई राशि (रु.)
1	देवरिया	यु.पी.	सिपडा	275775
2	पुरनिया	बिहार	सिपडा	327626
3	कराईकल	पुडुचेरी	सिपडा	107961
4	लखीमपुर	असम	सिपडा	838065
5	जोरहाट	असम	सिपडा	387091
6	कुल्लु	हिमाचल प्रदेश	सिपडा	1720000
7	बरेली	यु.पी.	सिपडा	441651
8	नागपुर	महाराष्ट्र	सिपडा	193300
9	वाराणशी	यु.पी.	सिपडा	1720000
10	पश्चिम चंपारण	बिहार	सिपडा	191143
11	उदयपुर	राजस्थान	डीडीआरएस	332100
12	वडोदरा	गुजरात	डीडीआरएस	207587
13	बलिय	यु.पी.	डीडीआरएस	697125
14	फूलबनी	ओडिशा	डीडीआरएस	221940
15	अमरावती	महाराष्ट्र	डीडीआरएस	459000
16	हरिद्वार	उत्तराखंड	डीडीआरएस	423300
17	नवरंगपुर	ओडिशा	डीडीआरएस	294204
18	संगरूर	पंजाब	डीडीआरएस	222270
19	बालाघाट	एम.पी.	डीडीआरएस	610956
20	तवांग	आंध्र प्रदेश	डीडीआरएस	387190

21	देवरिया	यु.पी.	सिपडा	324342
22	कुशीनगर	यु.पी.	सिपडा	98515
23	उद्यमपुर	जे. और के.	सिपडा	375000
24	ईस्ट गोदावरी	आंध्र प्रदेश	डीडीआरएस	590290
25	जालौर	राजस्थान	डीडीआरएस	259084
26	विजयानगर	आंध्र प्रदेश	सिपडा	342000
27	मंदसौर	एम.पी.	डीडीआरएस	250425
29	अमरावती	महाराष्ट्र	डीडीआरएस	374922
30	गोंदिया	महाराष्ट्र	सिपडा	132913
31	गोंदिया	महाराष्ट्र	डीडीआरएस	256745
32	मालदा	पश्चिम बंगाल	डीडीआरएस	276575
33	रेवा	एम.पी.	डीडीआरएस	294611
34	सेहोर	एम.पी.	सिपडा	262383
35	इम्फाल वेस्ट	मणिपुर	सिपडा	530200
36	गेलाघाट	असम	सिपडा	351768
37	राय बरेली	यु.पी.	डीडीआरएस	182585
38	नार्थ त्रिपुरा	त्रिपुरा	डीडीआरएस	507565
39	रामपुर	यु.पी.	डीडीआरएस	165913
40	बलाघाट	एम.पी.	डीडीआरएस	189317
41	बैदून	यु.पी.	सिपडा	443603
42	लखीमपुर	असम	सिपडा	926095
43	जबलपुर	एम.पी.	डीडीआरएस	130107
44	सागर	एम.पी.	डीडीआरएस	304560
45	उज्जैन	एम.पी.	डीडीआरएस	233397
कुल				17861199

अनुबंध-13

राष्ट्रीय संस्थान केन्द्रीय केंद्र द्वारा संचालित दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों (एक वर्ष से अधिक) का विवरण

1. अली यावर जंग राण गांग संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई
एवाईजेएनआईएसएचडी कार्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	मास्टर ऑफ ऑनर्स- लैंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	19
2.	मास्टर ऑफ एज्युकेशन (एज्युकेशन)	2 वर्ष	23
3.	बैचलर ऑफ ऑनर्स ओच-लैंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	43
4.	बैचलर ऑफ एज्युकेशन (एज्युकेशन)	2 वर्ष	39
5.	साइन लैंग्वेज इंटरनेशनल डिप्लोमा	1 वर्ष	15

ईआरसी, कोलकाता केंद्र

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	मास्टर ऑफ ऑनर्स- लैंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	15
2.	मास्टर ऑफ एज्युकेशन (एज्युकेशन)	2 वर्ष	10
3.	बैचलर ऑफ ऑनर्स ओच-लैंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
4.	बैचलर ऑफ एज्युकेशन (एज्युकेशन)	2 वर्ष	23
5.	बैचलर ऑफ एज्युकेशन (एज्युकेशन) डिस्टेंस मोड	2 वर्ष	40
6.	डिप्लोमा इन एज्युकेशन (एज्युकेशन)-डीएचएच)	2 वर्ष	31
7.	साइन लैंग्वेज इंटरनेशनल डिप्लोमा	1 वर्ष	15
8.	कंप्यूटर एप्लिकेशन डिप्लोमा	1 वर्ष	20

एसआरसी, सिकंदराबाद केंद्र

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, स्पीच - लैंग्वेज पैथोलॉजी)	2 वर्ष	15
2.	बैचलर ऑफ साइकोलॉजी, स्पीच - लैंग्वेज पैथोलॉजी)	4 वर्ष	33

3.	बैचलर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	31
4.	डिप्लोमा इन स्पेशन एजुकेशन (डीएचएच)	2 वर्ष	31

एनआरसी, नोएडा में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
2.	डिप्लोमा इन स्पेशन एजुकेशन (डीएचएच)	2 वर्ष	31
3.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	31
4.	साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स में डिप्लोमा	1 वर्ष	15
5.	श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	1 वर्ष	20

टीसीटीडी, जनला, ओडिसा में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन स्पेशन एजुकेशन (डीएचएच)	2 वर्ष	31
2.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	31

2. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिसा

एसवीएनआईआरटीएआर, कटक में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4) वर्ष	62
2	बैचलर ऑफ ऑकोपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4) वर्ष	62
3	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)	4) वर्ष	46
4	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी)	02 वर्ष	15
5	मास्टर ऑफ ऑकोपेशनल थेरेपी (एमओटी)	02 वर्ष	15
6	डिप्लोमेट इन फिजीकल मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन	02 वर्ष	04

3. राष्ट्रीय बहुविध अरिता संस्थान (एनआईपीएमडी, चेन्नई)
एनआईपीएमडी में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड. स्पेशल (ए)	2 वर्ष	25
2	डी.एड. स्पेशल (स)	2 वर्ष	25
3	डी.एड. स्पेशल (ड)	2 वर्ष	25
4	डी.एड. स्पेशल (ए)	2 वर्ष	25
5	बी.पी.टी.*	4½ वर्ष	25
6	बी.एकू स्पेशल (ए)*	2 वर्ष	30
7	बी.एकू स्पेशल (ड)	2 वर्ष	30
8	बी.एकू स्पेशल (ए)	2 वर्ष	30
9	एम.एकू स्पेशल (ए)*	2 वर्ष	20
10	एम.एकू स्पेशल (ए)	2 वर्ष	20
11	एम.फिल (कला)	2 वर्ष	06
12	पीजीडीडीटी (ड)	1¼ वर्ष	25
13	पीजीडीआई	1 वर्ष	25

*पाठ्यक्रम नवम्बर 2016 से प्रारंभ किए गए

4. राष्ट्रीय मानविलासस्थान (एनआईपीआईडी), सिकंदराबाद
एनआईपीआईडी में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.फिल इन शिक्षणकला (एमआर)	2 वर्ष	14
2	एम.एड इन स्पेशल (एमआर)	2 वर्ष	25
3	पोस्ट ग्रेजुएशन इनी इंटरवेंशन	1 वर्ष	20
4	बी.एकू इन स्पेशल (एमआर)	2 वर्ष	25
5	डिप्लोमा इन डिजिटल एजुकेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

6	बी.एकृ स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	25
7	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

एनआईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	30

एनआईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	25
2.	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	1 वर्ष	25
3.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

एनआईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	25
2.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	31
3.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	31

5. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता

एनआईओएच, कोलकाता में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी)	2 वर्ष	6
2	मास्टर इन ऑकोपेशनल थेरेपी (एमओटी)	2 वर्ष	6
3	मास्टर इन साइंस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स	2 वर्ष	6
4	डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डीएनबी (पीएमआर)	3/2 वर्ष	2

5	पोस्ट ग्रेजुएट फिन मीलिट्री रिहैबीलिटेशन एंड मैनेजमेंट (पीजीएम)	1 वर्ष	15
6	एम.एससी. रिहै (आरहैबीलिटेशन)	2 वर्ष	10
7	बैचलर ऑफ डिप्लोमा (डी)	4 एवं ½ वर्ष	52
8	बैचलर ऑफ डिप्लोमा (बीओटी)	4 एवं ½ वर्ष	51
9	बैचलर ऑफ डिप्लोमा (बीपीओ)	4 एवं ½ वर्ष	34
10	पोस्ट ग्रेजुएट फिन इंजीनियरिंग	1 वर्ष	10

क्षेत्रीय केंद्र, आईजोलयक्र

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डिप्लोमा इन डिप्लोमा (डी)	2½	10

क्षेत्रीय केंद्र, देहरादून

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डिप्लोमा इन डिप्लोमा (डी)	2 ½	10
2	सीपीओ	1 वर्ष	10

6. पंडित दीनदय्याशारीरिक विकलांग संस्थान, (पीडीयूआईपीएच), नई दिल्ली
पीडीयूआईपीएचदितें पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	बैचलर ऑफ डिप्लोमा (डी)	4½ वर्ष	54
2	बैचलर ऑफ डिप्लोमा (डी)	4½ वर्ष	54
3	बैचलर ऑफ डिप्लोमा (डी)	4½ वर्ष	31

7. राष्ट्रीय दृष्टि बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थान(एनआईआईपीवीडी), देहरादून
एनआईआईपीवीडी, देहरादून में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	20
2	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	150
3	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	550
4	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी	1 वर्ष	15
	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (VI एंड डीबी)	2 वर्ष	2150
ग)	स्कील डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम		
क	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट	1 वर्ष	21
ख	प्रैक्टिशनर कोर्स इन जैपनीज़ मेडिकल मैनुअल थेरेपी	2 वर्ष	30 (15x2 वर्ष)
ग	ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी)	1 वर्ष	16

- ग) क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
क)	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	40
ख)	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	50
	स्कील डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम		
क)	एकजीक्यूटिव सेक्रेटरी-सिप फार द ब्लाइंड	1 वर्ष	15

अनुबंध-14

ब्रेल प्रेसों व आधुनिकीकरण / क्षमता बढ़ाने की सहायता हेतु
केत जारी की गई निधियों के ब्यौरे

(i) 6 नयी ब्रेल प्रेस प्राप

क्र.सं.	संगठन/संस्थान	जारी की गई कुल अनुदान सहायता
1	संयुक्त क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस, हिमाचल प्रदेश	1,60,18,000 रु.
2	आंध्र प्रदेश विकास निगम, हैदराबाद	1,29,77,000 रु.
3	समाजिक कल्याण संसद सरकार, रायपुर	56,42,000 रु.
4	जोरहाट बलाइ सरकार	31,95,913 रु.
5	डिपार्टमेंट ऑफ़ री, मेघालय सरकार, शिलोंग	63,84,000 रु.
6	शुभम (एजीओ), पुर, र	79,61,000 रु.
7	राष्ट्रीय दृष्टिहीन रिद हरियाणा	84,24,000 रु.

(ii) 12 विद्यमान ब्रेल आधुनिकीकरण

1	सेंट्रल ब्रेल प्रेस, एचरादून	1,53,05,000 रु.
2	राजस्थान नेत्रहीन संयुक्त, राजस्थान	1,50,00,000 रु.
3	तेलंगाना स्टेट ब्रेल निगम, हैदराबाद	92,56,076 रु.
4	रामकृष्ण मिशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	97,07,605 रु.
5	मित्रा ज्योति चैरिटी, कर्नाटक	1,83,64,450 रु.
6	समाजिक कल्याण संसद सरकार, बिलासपुर	1,89,90,000 रु.
7	सामाजिक सुरक्षा एवं विकास विभाग, पंजाब सरकार	1,00,00,000 रु.
8	सामाजिक कल्याण, ब्रेल प्रेस, भोपाल, मध्य प्रदेश	97,38,000 रु.
9	राष्ट्रीय दृष्टिहीन समिति, गुजरात	37,61,000 रु.

10	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, मुम्बई, महाराष्ट्र	86,56,789 रु.
11	केरल दृष्टिहीन परिसंघ, तिरुवनंतपुरम	91,40,500 रु.
(iii) 3 ब्रैल प्रेसों की क्षमता बढ़ाना		
1	एनआईवीएच क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई	1,72,67,000 रु.
2	राष्ट्रीय दृष्टिहीन परिसंघ, नई दिल्ली	49,50,000 रु.
3	अखिल भारत दृष्टिहीन परिसंघ, दिल्ली	84,51,162 रु.
	कुल	21,91,89,495 रु.

(iv) 31.12.2016 तक क्षेणी-वार जारी की गई कुल निधियां:-

नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना	ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण	ब्रेल प्रेसों की क्षमता बढ़ाना
5,52,05,989 / -रु.	3,06,68,162 / - रु.	13,33,15,344 / -रु.

(v) 31.12.2016 तक जारी की गई सकल अनुदान सहायता 21,91,89,495 / -रु.

पुर, 2016 के प्राप्तकर्ताओं की सूची

I. सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी दिव्यांग

संख्या	पुरस्कार श्रेणी एवं	पुरुष / महिला	नाम	पता
1	दृष्टि बाधित	पुरुष	श्री कृणाल राजेन्द्रभाई जोशी	अहमदाबाद, गुजरात
		पुरुष	श्री रक्षित सेठी	आईबीएलयूआर जंगसन, बैंगलूरु, कर्नाटक
		महिला	श्रीमति सीमा पाहुजा	सोनीपत, हरियाणा
2	निम्न दृष्टि	पुरुष	श्री थामस हुसेन एम.जे.	विल्लूपूरम, तमिलनाडु
		पुरुष	गजानन विनायक राव बेल्लाले	लातूर, महाराष्ट्र
		महिला	—	.
3	कुष्ठ रोग	पुरुष	श्री पटेल नरवतभाई मंगाभाई	वडोदरा, गुजरात
		पुरुष	श्री के. गणेशन	विल्लूपूरम, तमिलनाडु
		महिला	—	.
4	श्रवण बाधित	पुरुष	श्री बाबू सी	स्लेम, तमिलनाडु
		महिला	कुमारी रंजनी रामानुजन	बैंगलूरु, कर्नाटक
5	गतिविधयत्न	पुरुष	डॉ. मौहम्मद इरफानूर रहीम	नागपुर, महाराष्ट्र
		महिला	श्रीमति विमला एन.	चेन्नई, तमिलनाडु
6	प्रमस्तिशक	पुरुष	श्री ऋशि भुट्टन	नई दिल्ली
		पुरुष	श्री विवेक जोशी	जलंधर पंजाब
		महिला	—	.

7	मानसिक मंदता	पुरुष	श्री जितेश बी	तिरुवेन्द्रम, केरल
		महिला	ए. पुनीता	श्रीपेरुम्बुदूर, तमिलनाडु
			कुमारी देवांशी जोशी	नई दिल्ली
8	मानसिक रूग्णता	पुरुष	.	.
		महिला	श्रीमति टीएमटी मलार	विल्लूपूरम, तमिलनाडु
9	स्वलीनता	पुरुष	दृ	.
		महिला	दृ	.
10	बहु निःशक्तता	पुरुष	श्री कृष्ण कुमार पी. नायर	इर्नाकुलम, केरल
			श्री मेहतो दिलीप कुमार	सूरत, गुजरात
			श्री निशाद पोपटलाल शाह	पुणे, महाराष्ट्र
		महिला	.	.

II सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी/एजेंसी

सं.	उप-श्रेणी	
1	सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता	(i) सरकारी संगठन
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त/ स्थानीय सरकारी निकाय
		(iii) निजी/गैर सरकारी संगठन
		कोई पात्र नहीं पाया गया
		1 केरल साइन्स एंड टेक्नोलॉजी संग्रालय, तिरुवेंदरम, केरल
		2 स्टेट बैंक आफ इंडिया, कॉरपोरेट ओफिस, स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट सेंटर, मेडम कामा मार्ग, मुम्बई, महाराष्ट्र
		1 सनराइज केंडल्स, वेक्स म्युजियम, जिला सतारा महाराष्ट्र

			2 बैथनी सोसाइटी, लेडी वेरोनिका लेन लिथुमखरा शिलौंग, मेघालय
			3 लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड लेमन ट्री प्रिमियर-दिल्ली एयरपोर्ट, आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली
			4 आछी मसाला, चेन्नई, तमिलनाडू
			5 एजिस लिमिटेड, कुरला (पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र
2	सर्वश्रेष्ठ नि अधिकारी	(i) स्वायत्त सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	श्री भारत सिंह गौर, इंदौर, मध्य प्रदेश
		(ii) निजी/गैर सरकारी संगठनों/ कार्यालय	विशेष लर्निंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडू

III. सर्वश्रेष्ठ नि एस्थान सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत

सं.		उप-श्रेणी	नाम
1	सर्वश्रेष्ठ नि	व्यवसायिक	1 सुश्री यमुनाम इबेचोबी देवी, इम्फाल, मणिपुर 2 श्री पंकज मारु, उज्जैन, (मध्य प्रदेश)
		गैर व्यवसायिक	1 श्रीमति राधा बोर्डे, नागपुर, महाराष्ट्र 2 श्री प्रीतेश अशोक कुमार शाह, अहमदाबाद, गुजरात

2	सर्वश्रेष्ठ संस्थान	(i) ऐसे संगठन जो विकलांगजनों को संपूर्ण व्यापक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।	<p>1 एनआईएमएचएनएस, बेंगलूरु, कर्नाटक</p> <p>2 नेशनल फेडरेशन आफ द ब्लाइंड, नई दिल्ली</p> <p>3 स्पार्स्टिक सोसाइटी आफ सिविकम, गेंगटाक, सिविकमए</p> <p>4 स्पर्श फाउंडेशन, हैदराबाद, तेलंगाना</p> <p>5 जनकल्याण समिति लातूर (महाराष्ट्र)</p>
		(ii) ऐसे संगठन जो बच्चों/विकलांगजनों की सम्मिलित शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं	<p>1 सेवा इन एक्शन (एएसएसएन), कोरामंगला, बेंगलूरु, कर्नाटक</p> <p>2 रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्याइज एकेडमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल</p>

IV रोल मॉडल पुरस्कार

सं.	उप-श्रेणी		नाम	पता और दूरभाष सं / ई-मेल
1	दृष्टि बाधिता / निम्न दृष्टि	पुरुष	श्री दीपित सतीस जैन	नई दिल्ली
		महिला	श्रीमती ममता शर्मा	पश्चिम मिदिनीपुर, पश्चिम बंगाल
2	कुष्ठ रोगमुक्ति	पुरुष	श्री ए. गुणाशेखरन	चेन्नई, तमिलनाडु
3	श्रवण बाधित	पुरुष	श्री के. मुराली	कोयम्बटूर, तमिलनाडु
		महिला	कुमारी अश्वनी मेलवानी	पुणे, महाराष्ट्र
4	गतिविशयक निःशक्तता / प्रमस्तिष्क घात	पुरुष	डॉ. बिपीन कुमार तिवारी	नई दिल्ली

			श्री पी. जनार्दन राव, हैदराबाद	कंचनबाग, हैदराबाद, तेलंगाना
		महिला	सुश्री आभा खेतरपाल मौर्य	नई दिल्ली
5	मानसिक बहु पुरुष निःशक्तता		श्री प्रसाद बासवराज, गोलासंगी	बासवन गुडी गोकाक, कर्नाटक
		महिला	कुमारी टी.जे. नवेदिता	बैंगलूरु, कर्नाटक

V दिव्यांग कोन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवाचार/विक

क्र.सं.	उप-श्रेणी	पुरस्कार विजेता
1	विकलांगजन अनुधार के लक्ष्यार्थ अनुसंध प्रौद्योगिकी	श्री आर.हरि, महाप्रबंधक, एचआर, लैमन ट्री होटल लि., एरोसिटी हास्पिटलिटी डिस्टिक, नई दिल्ली
2	विकलांगजन अनुधार के लक्ष्यार्थ प्रोत्त रोनतम उत्पाद के में स हेतु	1. श्री अनुप नारंग, निदेशक, विपणन एवं श्री आलोक नारंग, निदेशक तकनीकी, एएलपीएस श्रवण अनुसंधान, आशीवाद कांपलैक्स, ग्रीन पार्क, दिल्ली 2. श्री राजेश शर्मा, निदेशक, आनंद मोटर, कृष्णा कालोनी, जयपुर

VI. दिव्यांग के बाधामुक्त वातावरण सृजन में उत्कृष्ट कार्य

क्र.सं.	उप-श्रेणी	पुरस्कार विजेता
1	सरकारी विभाग/कार्यालय/ सार्वजनिक उपस्वायत्त निकाय	जिला कलक्टर, कन्नूर, केरल 1 जिला कलक्टर, झालावार, राजस्थान 2 जिला कलक्टर, डेदौर 3 अधीक्षक आर्कोलोजिस्ट, आर्कोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय, केंद्रीय सदन, 5वां तल, एफ विंग, कोरामंगला, बैंगलूरु, कर्नाटक- 560034 (क्रम सं. 1 से 3 को केवल प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुए)
2	स्थानीय वि	---

3	निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठन		आशा भवन केन्द्र, केथिला, बैनिटेबल, उलूबेरिया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल,
VII.	सर्वश्रेष्ठ जिलों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु पुरस्कार		इलाहाबाद जिला (यू.पी.) 1 तिरुचिलापल्ली (तमिलनाडु) 2 बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 3 जबलपुर (मध्य प्रदेश) 4 संबलपुर (ओडिशा) 5 झाबुआ (मध्य प्रदेश) 6 चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) (क्रम सं. जिला 1 से 6 प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला)
VIII.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चेनालाइजिंग एजेंसी		1 तमिलनाडु राज्य शीर्ष, सहकारी बैंक लि. 2 मेघालय शीर्ष, सहकारी बैंक लि. 3 महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम सहकारी लि., मुम्बई 4 हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, शिमला 5 राजस्थान एससी/एसटी राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम सहकारी लि., (आरएससी/एसटीएफडीसीसी), जयपुर 6 छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त आवाम विकास निगम 7 जे एंड के राज्य महिला विकास निगम (क्रम सं. जिला 4 से 7 प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला)
IX	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उत्कृष्ट रचनात्मक व्यस्क व्यक्ति	पुरुष	श्री प्रशांत सी., परिवंचरम, केरल
		महिला	कुमारी योगिता अरुन थामले, मुम्बई, महाराष्ट्र

X	सर्वश्रेष्ठ दिव्य रचनात्मक ब	इका	श्री उद्देश्य सिंह, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
		इकी	कुमारी थोकचोम शाहू देवी, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर
XI	सर्वश्रेष्ठ ब्रेट		रामकृष्ण मिशन क्षेत्रीय ब्रैल प्रेस, पी. ओ., नरेन्द्रपुर, कोलकाता - 700 103
XII क्र.सं. 1.	श्रेष्ठ एक्सेसाउट		पुरस्कार विजेता
	उप-श्रेणी		
	सरकारी		
2.	पीएसयू/		
3.	निजी क्षेत्र		
XIII	दिव्यांगजन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ		कर्नाटक
XIV	सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी	पुरुष	श्री बी. आनंद कुमार, बैंगलूरु, कर्नाटक
		महिला	कुमारी प्रज्ञा गिलडीयल, नई दिल्ली

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)
अधिनियम, 1995 में परिभाषित पदों की शब्दावली

(क) "अंधता" उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित है, अर्थात:-

- i दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
- ii सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो, या
- iii दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर है

(ख) "निःशक्तता" से अभिप्रेत है

- (i) अन्धता;
- (ii) कम दृष्टि;
- (iii) कुष्ठ रोग मुक्त;
- (iv) श्रवण शक्ति का ह्रास;
- (v) चलन निःशक्तता;
- (vi) मानसिक संदता;
- (vii) मानसिक रुग्णता;

(ग) "स्थापन" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम अथवा सरकार अथवा किसी स्थानीय अथवा कम्पनी के स्वामित्वधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और सरकार के विभाग भी सम्मिलित हैं;

(घ) "श्रवण" शक्ति का ह्रास" से अभिप्रेत है आवृत्ति की संवाद संबंधी रेंज में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि;

(ङ) "विकलांगजनों के लिए संस्था" से अभिप्रेत हैं विकलांगजनों के प्रवेश, देखरेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास या किसी अन्य सेवा के लिए संस्था;

(च) "कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया है किन्तु-

- i. हाथों या पैरों में सवेदना की कमी और नेत्र और पलक में कमी, सवेदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्त है किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नहीं है;

- ii. प्रकट और क घात से ग्रस्त है, किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह क क्रियाकलाप कर सकता है;
 - iii. अत्यन्त विर और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने के अंद "कुष्ठ रोगमुक्त" का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा;
- (छ) "चलन निःशक्तता ड्रयड्रो या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर सीर का प्रमस्तिष्क घात हो;
- (ज) "चिकित्सा प्राधिकारी पस्पताल या संस्था अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के के निनिर्दिष्ट की जाए;
- (झ) "मानसिक रुग्णता प्रेत ई मानसिक विकार जो मानसिक मंदता से भिन्न हो;
- (ञ) "मानसिक मंदता" त हैं व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से बुद्धिमत्ता वान्यरा अभिलक्षित होती है;
- (ट) "विकलांगजन" से व्यभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम चालत त है;
- (ठ) "कम दृष्टि वाला" ऐ ई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि ध्वसाया है किन्तु जो समुचित सहायक मुक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है;
- (ड) "पुनर्वास" ऐसी प्र संस्करता है जिसका उद्देश्य विकलांगजनों को, उनका सर्वोत्तम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसाक कार्यात्मक स्तर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में समर्थ बनाना है;
- (ढ) "विशेष रोजगार" से ऐसा कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा रजिस्टर रखकर अन्यथा निम्नलिखित ऋरी का संग्रहण करने और देने के लिए स्थापित और अनुरक्षित किया गया है:-
- i. ऐसे व्यक्ति शक्से ग्रस्त व्यक्तियों में से कर्मचारियों को काम में लगाना चाहते हैं;
 - ii. ऐसे विक जो जन चाहते हैं; और
 - iii. ऐसे रिक जेनए नियोजन चाहने वाले विकलांगजनों की नियुक्ति की जा सकती है

ओटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुविकलांग ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में परिभाषित पदों की शब्दावली

- (क) "ओटिज्म" स्वप्राणयता का अर्थ है असमानता निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है और बांरबारता मूलक और विधिवादी व्यवहार से चिंहित करती है;
- (ख) "बहुनिश्क्तता" का अर्थ है दो या अधिक निश्क्तताओं का सहयोजन, जैसा कि अशक्तताओं वाला व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा (2) के खंड ;पद्ध में परिभाषित किया जाता है;
- (ग) "निश्क्तता वाले व्यक्ति" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो स्वप्राणयता का मस्तिष्क का घात, मानसिक मंदता अथवा किसी स्थिति या ऐसी दो या दो से अधिक निष्क्रियता से ग्रस्त है और इसमें गंभीर बहुनिश्क्तता वाला व्यक्ति भी शामिल होता है,
- (घ) "पेशेवर" का अर्थ किसी क्षेत्र में विशेष दक्षता रखने वाले व्यक्ति से है जो निश्क्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देगा;
- (ङ) "गंभीर निश्क्तता" का अर्थ ऐसी निश्क्तता है जो एक या अधिक बहुनिश्क्तताओं का 80 प्रतिशत या अधिक भाग रखती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 में परिभाषित पदों की शब्दावली

- (क) "मान्यताप्राप्त पुनर्वास अर्हता" से आरसीआई अधिनियम अनुसूची में सम्मिलित कोई अर्हता अभिप्रेत है।
- (ख) "पुनर्वास पेशेवर" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं
 - (i) श्रवण वैज्ञानिक और वाक् चिकित्सक;
 - (ii) नैदानिक मनोविज्ञानिक;
 - (iii) श्रवण सहाय और कर्णसंच तकनीशियन;
 - (iv) पुनर्वास इंजीनियर और तकनीशियन;
 - (v) असुविधाग्रस्त को शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए विशेष अध्यापक;
 - (vi) असुविधाग्रस्त से संबंधित व्यवसाय परामर्शी, रोजगार अधिकारी और स्थानन अधिकारी;
 - (vii) बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक, तकनीशियन; अथवा
 - (viii) पेशेवरों के ऐसे अन्य प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार, परिषद् के परामर्श, से समय-समय पर, अधिसूचित करे।

महत्वपूर्ण और सामान्य शब्दों तथा संक्षिप्त अक्षरों की शब्दावली (एनआईएमएच)

शब्द	संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
एक्टिव रेंज ऑफ मोशन	एआरओएम	रेंज ऑफ मोशन एक शब्द है जिसका अर्थ है शरीर का एक जोड़ अथवा हिस्सा जो सामान्य गति से काम करता है।
एक्टिविटीज ऑफ डेली ली	एडीएल	इसका तात्पर्य दैनिक स्वयं के क्रियाकलापों से है जैसे खाना, नहाना, कपड़े पहनना आदि।
ऐसिसटेंस टू डिसेब्ल्ड फॉर परचेज/फीटिंग ऑफ अपलार्नसिस	एडीप	विकलांगजनों को चलाने फिरने में मदद करने के लिए देश में अच्छी गुणवत्ता वाले यंत्रों एवं सहायक उपकरणों की आपूर्ति योजना।
एटेंशन डेफिसिट हाइपरडिस्टर्बेंस	एडीएचडी	एक ऐसी कमी जो बचपन में विकसित होती है, ध्यानहीनता, अतिसक्रियता, आवेशशीलता के रूप में चिन्हित की जाती है।
ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्टर्बेंस	एएसडी	यह एक विकास संबंधी कमी है जो सामान्यतः तीन वर्ष की आयु से पहले होती है तथा सामाजिकरण, बातचीत और एक समान व्यवहार के मिलने के रूप में चिन्हित की जाती है।
क्रोनोलोजिकल एज	सीए	व्यक्ति के जन्म से अब तक कि शारिरिक आयु (समय)।
कम्युनिटी बेस्ड रिहाबिलिटेशन	सीबीआर	विकलांगजनों का और पुनर्वास, अवसरों की सामान्यतः सामाजिक व्यवहार के विकास के लिए समुदाय विकास के भीतर एक योजना।
कम्पोजिट रिहाबिलिटेशन	सीआरसी	देश में फोकस किए गए क्षेत्रों में विकलांग पुनर्वास गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए डिसेबिलिटी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय संस्थान का एक विस्तार केंद्र।

डेवलेपमेंटल कोशिएन्ट	डिक्यू	जब किसी व्यक्ति की विकासात्मक आयु वास्तविक आयु द्वारा विभाजित करके 100 से गुणा की जाती है तब बनाया गया एक तरीका
डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहाबिलिटेशन सेन्टर	डीडीआरसी	जिला स्तर पर विकलांगजनों हेतु पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए डिसेबिलिटी कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना।
डॉउनस सिन्ड्रोम	डीएस	डाउन सिन्ड्रोम क्रोमोसोमल ऐबरेन्ड स्थिति है जो बौद्धिक विकलांगता से जुड़ी है। शैशव काल में फेशियल एम्पीयल्स और कमजोर मस्ल के रूप में दिखाई देता है। इससे ग्रसित सभी व्यक्ति संज्ञात्मक विलम्ब महसूस करते हैं परन्तु बौद्धिक विकलांगता आमतौर पर कम अथवा मामूली होती है।
इन्डीविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम	आईईपी	किसी विशेष व्यक्ति की समग्र योग्यता के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करता हैं।
इन्टेलीजेन्स कोशियन्ट	आईक्यू	मानसिक आयु और वास्तविक आयु को 100 से गुणा करने पर प्राप्त औसत/ मानसिक आयु इन्टेलीजेन्स जांच द्वारा प्राप्त की जाती है।
लर्निंग डिसेबिलिटी/स्पेसिफीक लरनिंग डिसेबिलिटी	एलडी/एसएलडी	सामान्य बौद्धिक कार्यचालन औसत अथवा औसत अथवा से ऊपर होने पर भी अधिग्रहण तथा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तार्किक तथा गणितीय योग्यता के प्रयोग में कठिनाइयां द्वारा विकसित कमी।
मेन्टल एज	एमए	इन्टेलीजेन्ट टेस्ट से प्राप्त
सोशल एज	एसए	एसए एक कार्य सक्षमता है जो बातचीत स्वयं निर्देशक, सामाजिक संदर्भ में इस उम्र में ऐसे लक्षण से प्राप्त की जाती है।

सोशल स्कील ट्रेनिंग	एसएसटी	सामाजिक कौशल बढ़ाने के लिए थेराप्युटिक स्ट्रियुलेशन दिया जाता है।
वोकेशनल रिहाबिलिटेशन	वीआरसी	श्रम मंत्रालय के अंतर्गत वीआरसी में विकलांगजन के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार हेतु श्रमताओं का मूल्यांकन किया जाता है।
वोकेशनल ट्रेनिंग	वीटी	वयस्क विकलांगों को स्वतंत्र जीवन यापन के लिए विभिन्न रोजगारों उन्मुख गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है

एलिम्को
महत्वपूर्ण संक्षिप्त अक्षर

संकेत अक्षर/ संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
एलिम्को	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम
जीआईए	अनुदान सहायता
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन
टी/सी	ट्राईसाइकिल
एच/ए	श्रवण यंत्र
एएफओ	एंकल फुट ऑर्थोसिस (लघु पैर ब्रेस)
एचकेएएफओ	हिप-नी फुट ऑर्थोसिस
आरसीआई	भारतीय पुनर्वास परिषद्
एएण्डए	यंत्र एवं उपकरण
पीएण्डओ	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोसिस
डब्ल्यू/सी	व्हीलचेयर
बीटीई	बिहाइन्ड द इयर हिअरिंग एट
केएचएफओ	नी एंकल फुट ओरथोसिस
बीआईएल	द्विपक्षीय
एमआर	मानसिक मंदता
सीडब्ल्यूएसएन	विशेष ध्यान दिए जाने हेतु बच्चा

दिंग प्रबंधन- संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एएसी	न्टेटिव एंड आलटरनेटिव कम्यूनिकेशन
एबीआर	री ब्रेनस्टैम्प रेस्पॉन्स
एआईआएसएच	व भारतीय वाक श्रवण संस्थान
एआईपीएमआर	व भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान
एवाईजेएनआईएवए	व्यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान
बीएमएफ	मि मिलेनियम प्रेमवर्क
सीसीसी	व समन्वय समिति
सीसीपीडी	दिंगों हेतु मुख्य आयुक्त
सीईओ	व कार्यकारी समिति
सीआरई	व पुनर्वास शिक्षा
डीआईएसई	टिल एक्सेसिबल इंफोरमेशन सिस्टम
डीडीआरसी	विकलांगता पुनर्वास केंद्र
डीएफए	कॉर ऑल
डीपीईपी-आईईडी	क्ट प्राइमरी एज्यूकेशन प्रोग्राम – इंटिग्रेडिट एज्यूकेशन फॉर सेबल
डीपीओ	दिंगों हेतु संस्थान
डीआरसी	व पुनर्वास केंद्र
आईईडी	दिंगों हेतु समेकित शिक्षा
आईईडीसी	दिंग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा
आईपीएच	पदयाल इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप
आईएसआईसी	न स्पाइनल इंजुरी सेंटर
एमआरडब्ल्यू	बदेशीय पुनर्वास कामगार
एनएचएफडीसी	व विकलांग वित्त एवं विकास निगम

एनआई	राष्ट्रीय संस्थान
एनआईएमएच	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
एनआईएमएचएएनएस	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान
एनआईओएच	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान
एनआईआरटीएआर	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
एनआईवीएच	राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान
एनपीआरपीडी	विकलांगों के लिए पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
पीपीआई	स्थायी शारीरिक क्षति
पीडब्ल्यूडी एक्ट	विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
आरआरटीसी	क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र
आरएसआईसी	क्षेत्रीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर
एसई	विशेष शिक्षा

लांगता संबंधी शब्दकोष

क्र. सं.		परिभाषा
1.	एडेप्टिव बि (केलएस)	किसी व्यक्ति की, उसके वातावरण के साथ समुचित व्यवहार के संबंध में, योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटारडेशन द्वारा विकसित एक पैमाना
2.	एकोस्टीक	किसी व्यक्ति को सुनने में मदद के लिए कोई माध्यम
3.	एक्टिविटीज ली T (एडीएलसी)	मौलिक निजी गतिविधियां जिसमें नहाना, खाना, कपड़े पहनना, चलना, बिस्तर से चेयर पर लाना, प्रसाधन का इस्तेमाल, दवाई आदि देना, सामाजीकरण, कार्यात्मक संप्रेक्षण, कार्य संबंधी चलना फिरना, यौन अभिव्यक्ति शामिल है।
4.	एटेंशन डेफॉर्ड	(एडीडी) एटेंशन डेफीसिट अथवा हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर
5.	एलजाइमर्स	एक प्रगामी अपरिवर्तनीय बीमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के अधःपतन तथा याददाश्त के खो जाने से होती है और जिसके कारण व्यक्ति अकार्यशील हो जाता है और अपनी मूलभूत जीवनयापन संबंधी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है।
6.	एम्बुलेट्री	सहायक उपकरणों के साथ अथवा उनके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम
7.	अमेरिकन साइजेसएल)	श्रवण बाधित व्यक्तियों की एक दृष्टिगत भाषा (हाथ की मुद्राओं का प्रयोग करते हुए), जिसकी अपनी शब्दावली, व्याकरण, मुहावरे और वाक्य रचना होती है। एएसएल अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली सबसे सामान्य सांकेतिक भाषा का रूप है। यह संकेत अंग्रेजी अथवा किसी अन्य बोलचाल की भाषा पर आधारित नहीं है।

8.	एटेक्सिया	एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति फाइन एंड ग्रास मोटर मूवमेन्ट एण्ड बैलेन्स को नियंत्रित करने में बेहद परेशानी महसूस करता है, जिसके कारण सैरेबेलम का नुकसान होता है।
9.	एटेन्शन डेफीसिट डिऑर्डर (एडीडी)	सामान्यतः एडीडी के रूप में जानी जाती है जो न्यूरोलोजिकल अशक्तता है और इसके लक्षणों में अनुचित ध्यान कौशल में कमी, आवेगी व्यवहार और कुछ मामलों में अतिसक्रियता। एडीडी को जीर्ण व्यवहार के रूप में जाना जाता है जो कम से कम छः महीने तक रहता है और सात वर्ष की आयु से पहले दिखाई देता है। व्यवहार में—व्यग्रता, बैठे रहने में मुश्किल, निर्देशों का पालन करने में मुश्किल, काम को अपूर्ण छोड़ना और जब दूसरे बोल रहे होते हैं, तब उन्हें नहीं सुनना।
10.	कैलिपर	स्कीनफोल्ड थिकनेस को मापने के लिए कैलिब्रेटिड डिवाइस
11.	क्लेफ्ट लिप एण्ड/ऑर पेलेट	मुंह की ऊपरी सतह और सॉफ्ट पेलेट के बीच में गैप जो कभी कभी ऊपरी होठ तक होता है। परिणामस्वरूप होठ के विभिन्न हिस्से अथवा पेलेट एक साथ नहीं बढ़ पाते और एक होठ अथवा सक्त पेलेट नहीं बना पाते जो सामान्यतः सुधार योग्य होता है। इसका प्रभाव खाने, बोलने सुनने और दांतों के निर्माण पर पड़ता है।
12.	कोकलियर इम्प्लांट	जो एक प्रकार का इलैक्ट्रोड और इलैक्ट्रोड्स जो कोकलियर में रखा जाता है और कान के पास स्कीन के अन्दर एक इन्डक्शन कोइल से जुड़ा होता है। दूसरा यूनिट शरीर पर लगाया जाता है जो ध्वनि को इलैक्ट्रिकल स्टीमुलस में परिवर्तित करता है जिससे आठवीं नर्व के न्यूरोन्स को इलैक्ट्रिकली स्टीमुलेट्स किया जाता है। इससे उन व्यक्तियों को सीमित रूप में सुनने की सुविधा प्रदान की जाती है जो परंपरागत श्रवण यंत्रों के माध्यम से लाभ नहीं उठा सकते।

13.	डीफ-बिलाइड		कॉनकमीटेन्ट हियरिंग और दृष्टि बाधिता जिसके कॉम्बिनेशन से ऐसी गंभीर बातचीत और अन्य विकासात्मक और शैक्षिक जरूरतें होती हैं।
14.	डेमेंशिया		एक जैविक मानसिक कमी जिसमें पूर्व अर्जित बौद्धिक योग्यता में कमी आती है, जिसके कारण सामाजिक और व्यवसायिक कार्यों में, व्यवहार में कमी आती है, स्मृति व्यवधान इसका प्रमुख लक्षण है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट रूप से सोचने, निर्णय लेने, इम्पल्स नियंत्रण और/अथवा व्यक्तित्व में परिवर्तन बाधित होता है। डेमेंशिया प्रगामी, स्टैटिक अथवा रिवर्सिबल हो सकता है जो उपयुक्त इलाज की उपलब्धता सहित पैथोलॉजी पर निर्भर करता है।
15.	डाउन-सिन्ड्रोम		ऐसी अवस्था जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलटी मुख्यतः एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होती है।
16.	डाइसथ्रिया		वाक समस्याओं का समूह जब ध्वनि अस्पष्ट हो जाती है और वाक स्पीच में भी कमी होती है। पिच, लाउडनेस, रिदम और स्पीच की मुणवत्ता में परिवर्तन को देखा जा सकता है।
17.	डाइस्कैलक्यू		गणितीय प्रतिकों अथवा कार्य को समझने और प्रयोग करने में कठिनाई
18.	डिसप्लूऐंसी		स्पीच, स्ट्रिंग के सरल प्रवाह में अवरोध
19.	डिसगिसिया		स्वाद को समझने में अक्षमता
20.	डिसग्राफिया		लिखने की एक कमी, जिसके कारण लोगों को शब्द बनाने अथवा एक निर्धारित जगह के भीतर लिखने में परेशानी होती है।

21.	डिसकिनेसिया	वॉलियन्टरी मसल्स के समन्वय में आंशिक बाधता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति जिससे कलम्सी मूवमेंट और कम शारीरिक नियंत्रण हो पाता है।
22.	डिसलेक्सिया	एक प्रकार की अधिगम विकलांगता, जहां परम्परागत कक्षा अनुभव के बावजूद कोई व्यक्ति लिखित अक्षरों, अंकों तथा शब्दों, पीछे की ओर से पढ़ने की समस्या तथा गंदी लिखावट से ग्रस्त होता है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर तब होता है जब पढ़ने में अक्षमता के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का संदेह होता है।

पहचाने गए पद 2013 की प्रयोग किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर

एस	ना
एसटी	ना हे
डब्ल्यू	ना
बीएन	ना
सीआरएल	ना
सीएल	ना
जेयू	ना
एल	ना
केसी	ना
आरडब्ल्यू	ना लेखना
एमएफ	लेय सहायता से समझाना
पीपी	ना गिरना
एसई	ना
सी	वीत्ता
एच	ना
ओए	भुज
बीए	भु
ओएल	भुज एक पैर
बीएलए	पैर भुजा
बीएलओए	पैर एक भुजा
ओएल	पैर
बीएल	पैर
सीपी	तष्ट
एलसी	उत्त
ओएच	य त्ति
वीएच	बा
बी	हीन
एलवी	दृष्टि
एचएच	बार्

विकलांगजन हेतु मुख्य आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 1988-99)

बेहतर भाषा बोलने की ओर एक कदम

विकलांगजनों को संबोधित करते समय समुचित ढंग / भाषा का प्रयोग करने के लिए, कृपया निम्नलिखित पर विचार करें:

कहने की बजाए	ऐसा कहें
विकलांग अथवा अपंग बच्चा	निःशक्त बच्चा
पालसीड अथवा सी.पी. अथवा स्पॉस्टीक	प्रमस्तिष्क घात से ग्रसित व्यक्ति
व्यथित अथवा से ग्रसित, विकिटम	ऐसा व्यक्ति जो
मूक अथवा गूंगा	वाकरहित
धीमा	विकास संबंधी विलम्ब
सनकी अथवा पागल	भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित अथवा मानसिक रूप से बीमार
बहरा अथवा गूंगा	कम सुनने वाला अथवा श्रवण संबंधी कमी वाला व्यक्ति
मंद बुद्धि	मंदिता से ग्रसित व्यक्ति
मंगोलोइट	निम्नोतर लक्षण
सुस्त, मूर्ख	सीखने संबंधी विकलांगता
अपंग	शारीरिक विकलांगता वाला
जन्मजामत कमी	जन्मजात विकलांगता
दौरा पड़ना	उद्वेग
लंगड़ा	चलनबाधित
अमान्य अथवा लकवाग्रस्त	स्तांभित
बौना	छोटे कद का

विकलांगजनों के साथ बात करने हेतु मार्गदर्शिका

जब आप किसी विकलांगजन से हैं उनके मन में क्या विचार आता है? क्या आप सोचते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते बल्कि यह सोचने के बकवास करते हैं। क्या विकलांग मनुष्य भगवान के अभाग्य बच्चे हैं? तो क्यों हम उन्हें भिन्न मानते हैं?

अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से तो उनसे समानता का भाव रखें। इसके कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

- यदि आप नहीं के कैसे तोड़नी है और बातचीत कैसे शुरू करनी है, तो शांत रहें और विकलांगजन के साथ बात करें।
- विकलांगों के प्रति आत्मबोध रखें। उनसे आपसी ताल-मेल बढ़ाएं। आप अवश्य ही कुछ रोचक व्यक्तित्व पाएंगे।
- यदि सहायता वक्तो ही प्रदान करें, पर अति-उत्साही नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता के ब्यापि सम्मान करें।
- व्यक्ति द्वारा दुर्घटना (बैर) बिना मांगें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।
- व्यक्ति को वहील बैसा अन्य प्रकार की सहायता बिना मांगे नहीं दें।
- विकलांगता के प्रति कर्कशता ना करें पर स्वतः ही चर्चा हो जाए तो विचार बांट सकते हैं।
- पूर्ण सहयोग का मांगे बात करने के लिए ज्यादा समय या स्थान की आवश्यकता हो सकती है।
- विकलांगजन जरूर है, उसकी प्रशंसा करें। उन कष्टों को याद रखें जो व्यक्ति को उसकी विकलांगता से आज वहार के कारण उसके सामने उत्पन्न हो सकते हैं।
- विकलांगता के ब्यापि सीधी बात करें। बातचीत करने के लिए किसी मध्य व्यक्ति की सहायता न लें।
- किसी विकलांगजन के समय उसकी बात पर पूरा ध्यान दें। उनके दृष्टिकोण को सम्मान दें। विकलांगजन से करते आपका रवैया उनके दृष्टिकोण में सुधार करने की अपेक्षा उनको प्रोत्साहित करने चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति को नि मेंनाई हो, उससे ऐसे प्रश्न करें जिनके जवाब छोटे रूप में या हाव-भाव के संकेत से दिए जा सकें।
- सुनने की कठिन अविताराम से, धीरे और स्पष्ट शब्दों में बात करें।
- विकलांगजन के भोजन समय, जरूरत होने पर या अनुमति मांगे जाने पर ही भोजन करने में उनकी मदद करें। लोआदा आरामदेय हो सकता है यदि व्यक्ति अपना भोजन स्वयं ही रसोई में करना चाहता है। प ने व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं तो उसे टेबल पर रखें बर्तनों और पकवानों की स्थिति में।

संदर्भ:

1	निःशक्तजन (सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995
2	राष्ट्रीय न्यास व्यक्ति के सुधार ऑटिज्म के साथ, मानसिक विकलांगता और बहु विकलांगता अधिनियम 1999
3	भारतीय सुधारात्मक परिषद् अधिनियम, 1992
4	महत्वपूर्ण एवं सामान्यतया प्रयुक्त शब्दों और संक्षिप्तियों की शब्दावली – राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान (एनआईएमएच)
5	महत्वपूर्ण संक्षिप्तियां – भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
6	भारतीय विकलांगता प्रबंधन (सी.एस. मोहापात्रा)
7	विकलांगता शब्दकोश (अरुण सेनगुप्ता)
8	अधिसूचना संख्या 16-15/2010-DD.III दिनांकित 29 जुलाई, 2013
9	दिव्यांगजन हेतु मुख्य आयुक्त की वर्ष 1988-99 की वार्षिक रिपोर्ट।



अला कवर फोटो : नवाशारी, 17 सितम्बर 2016 को मेगा कैप



भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अछिरिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तित्ण विभाग